राष्ट्रीय संस्करण

दुनिया की सौ शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला 34वें पायदान पर >>10

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 186

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 14 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ब्रेक्जिट पर अडिग बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन में बड़ी जीत

लंदन, एजेंसियां : मध्यावधि चुनाव कराने का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दांव चल गया। उनकी कंजरवेटिव पार्टी ने 650 सदस्यीय संसद में 364 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। इन नतीजों को ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने) पर ब्रिटिश मतदाताओं की मुहर के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद जॉनसन ने समर्थकों से कहा कि उन्हें नया जनादेश मिला है। ब्रिटेन 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन (ईयू) से अलग हो जाएगा। ब्रेक्जिट पर दोबारा जनमत संग्रह की पैरवी करने वाली विपक्षी लेबर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर भारत का विरोध करने वाली यह पार्टी 203 सीटों पर सिमट गई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनियाभर के नेताओं ने जॉनसन को जीत पर बधाई दी है।

आम चुनाव में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी की जीत ब्रेक्जिट विरोधी दलों के लिए करारा झटका मानी जा रही है। लेबर पार्टी समेत कई दलों ने संसद में यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया था। इसी के बाद जॉनसन ने इस उम्मीद के साथ मध्यावधि चुनाव का एलान किया था कि वह चुनाव जीतकर 31 जनवरी को 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन से अपने देश को अलग करने में सफल होंगे। गत जुलाई में प्रधानमंत्री बनने वाले जॉनसन ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सिर्फ उनकी ही पार्टी देश को ब्रेक्जिट के जाल से निकाल सकती है जबकि जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व वाली विपक्षी लेबर पार्टी ने वादा किया था कि वह ब्रेक्जिट पर दोबारा जनमत संग्रह कराएगी। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट पर 2016 में जनमत संग्रह कराया गया था। तब ब्रेक्जिट के पक्ष में 52 फीसद वोट पड़े थे।

वर्ष 1935 के बाद सबसे बड़ी हार का सामना करने वाली लेबर पार्टी को उन सीटों पर भी मुंह की खानी पड़ी है, जिन पर वह पारंपरिक तौर पर जीतती आ रही थी। नॉर्थ लंदन सीट से चुनाव जीतने वाले लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा, 'मैं अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व नहीं करूंगा।'

जॉनसन का भारत कनेक्शन : 55 वर्षीय जॉनसन लंदन की अक्सब्रिज सीट से संसद के लिए चुने गए। न्यूयॉर्क में पैदा हुए, लेकिन ब्रिटेन में बसे जॉनसन का भारत से भी जुड़ाव रहा है। उनकी पूर्व पत्नी मरीना व्हीलर की मां भारतीय मूल की थीं।

भारत-ब्रिटेन के रिश्तों में खास गर्माहट आने के आसार पेज>>13

- आम चुनाव में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ने जीतीं 364 सीटें
- कश्मीर पर भारत का विरोध करने वाली लेबर पार्टी 203 सीटों पर सिमटी
- पीएम मोदी और ट्रंप समेत कई देशों के नेताओं ने जॉनसन को दी बधाई

लंदन में शुक्रवार को आम चुनावों में जीत के बाद जश्न के दौरान समर्थकों को संबोधित करते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। एएफपी

इस चुनाव के साथ हमने ब्रेक्जिट पर गतिरोध को दूर कर दिया है। हमने दूसरे जनमत संग्रह के खतरे को भी खत्म कर दिया है। अब कोई अगर-मगर नहीं। 31 जनवरी तक ब्रेक्जिट को अंजाम तक पहुंचा देंगे।
–बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री

चुनाव नतीजों के मायने

- ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन में पिछले कई माह से जारी सियासी संकट का दौर खत्म हो जाएगा
- प्रधानमंत्री जॉनसन अब ब्रेक्जिट पर आसानी से अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे
- 31 जनवरी तक ईयू से ब्रिटेन अलग हो सकेगा

चुनाव परिणाम

दल	2019	2017
कंजरवेटिव पार्टी	364	317
लेबर पार्टी	203	262
स्कॉटिश नेशनल पार्टी	48	35
लिबरल डेमोक्रेट्स	11	12

ब्रिटिश संसद में बढ़ा भारतवंशियों का कुनबा

लंदन : ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के सांसदों का कुनबा बढ़ गया है। गुरुवार को हुए चुनाव में भारतीय मूल के 11 सांसद दोबारा चुनाव जीतने में सफल रहे। चार नए चेहरे भी संसद पहुंचे हैं। 2017 के चुनाव में 12 भारतवंशी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। पहली बार चुनाव जीतने वालों में गगन मोहिंदर, क्लेयर कूटिन्हो, नवेंद्रु मिश्रा और मुनीरा विल्सन हैं। मोहिंदर ने कंजरवेटिव पार्टी के टिकट पर हार्टफोर्डशायर साउथ वेस्ट सीट से जीत दर्ज की। इसी पार्टी की उम्मीदवार और गोवा से ताल्लुक रखने वाली क्लेयर ने सरे ईस्ट सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। (पेज-13)

मोदी-शिंजो की गुवाहाटी वार्ता टली

एहतियात ▸ दोनों देश आपसी बातचीत से जल्द करेंगे नई तिथि की घोषणा

नागरिकता कानून के विरोध में असम की हिंसा बनी वजह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो ने 15 दिसंबर से शुरू होने वाली अपनी भारत यात्रा स्थगित कर दी है। इसके साथ ही 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित भारत-जापान सालाना बैठक भी टाल दी गई है। यह बैठक गुवाहाटी में होनी थी और वहां नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में पिछले तीन दिनों से भारी हिंसा हो रही है। दोनों देशों के बीच पिछले दो दिनों से जारी गहन विचार-विमर्श के बाद इस महत्वपूर्ण बैठक को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। गुरुवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने भी अपनी भारत यात्रा रद कर दी थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया, 'जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो की आगामी भारत यात्रा के संदर्भ में दोनों देशों ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आपसी बातचीत से जल्द ही किसी सुविधाजनक तिथि का चयन किया जाएगा।' जापान के विदेश मंत्रालय ने भी एक संक्षिप्त जवाब में कहा, 'कई वजहों से प्रधानमंत्री एबी शिंजो की यात्रा आगे बढ़ा दी गई है।' जापान सरकार के चीफ कैबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा ने एक दूसरे संक्षिप्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री एबी शिंजो भारत जाना चाहते हैं, लेकिन हमें राज्य के हालात का भी ख्याल रखने की जरूरत है।

दिल्ली में नहीं हो सका होटलों का प्रबंध : विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो दिनों में दोनों पक्षों के बीच मोदी-शिंजो की सालाना बैठक को किसी दूसरे शहर में ले जाने के विकल्प पर भी बात हुई, लेकिन कई वजहों से बात नहीं बनी। दरअसल, इस तरह की बैठक के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। बैठक को नई दिल्ली में स्थानांतरित करने के विकल्प पर भी चर्चा हुई, लेकिन यहां होटलों की व्यवस्था नहीं हो सकी।

साल की शुरुआत में वार्ता पर सहमति : अब दोनों पक्षों के बीच बैठक को अगले वर्ष की शुरुआत में करने पर सहमति बनी। लिहाजा अब अगले साल भारत-जापान सालाना बैठक दो बार हो सकती हैं। गुवाहाटी में जापान के प्रधानमंत्री के साथ सालाना बैठक की अपनी खास अहमियत थी। पहली बार किसी अहम रणनीतिक साझेदार देश के प्रमुख को पूर्वोत्तर के राज्य में बुलाया गया था। इसका कूटनीतिक मकसद चीन को एक संदेश देना था जो रह-रहकर पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर टिप्पणी करता रहा है।

शाह का पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा रद : पूर्वोत्तर में हिंसा के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह की भी इस क्षेत्र के दो राज्यों की यात्रा रद कर दी गई है। शाह पहले शिलांग जाने वाले थे, जहां वह नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने वाले थे। इसके बाद उन्हें तवांग (अरुणाचल प्रदेश) जाना था।

नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पेज>>5

पाकिस्तान में बढ़ी बौखलाहट पेज>>5

मोदी और एबी शिंजो की इस वार्ता का कूटनीतिक मकसद चीन को संदेश देना था। फाइल

नागरिकता कानून लागू करने से इन्कार नहीं कर सकते राज्य

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 लागू करने से इन्कार करने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी वजह बताते हुए कहा कि इस कानून को संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची के तहत बनाया गया है। दरअसल, यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने एलान किया है कि यह कानून असंवैधानिक है और उनके राज्यों में इसका कोई स्थान नहीं है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में स्पष्ट कर चुके हैं कि यह कानून सभी राज्यों में लागू होगा। संविधान विशेषज्ञ व वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा भी कहते हैं, 'संविधान के अनुसार हर राज्य को संसद के कानून का पालन करना ही होगा। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र के अधीन है। कोई राज्य इसे रोक नहीं सकता।'

राहुल के 'रेप इन इंडिया' बयान पर भड़की संसद

- लोकसभा में उठी कांग्रेस नेता की माफी की मांग
- राजनाथ ने भी 'रेप' बयान पर जताई नाखुशी, कहा-क्या इस सदन में ऐसे भी लोग चुनकर आ सकते हैं
- कांग्रेस नेता ने दोहराया विवादित वक्तव्य, लगाया आरोप : असम हिंसा से ध्यान भटकाने में जुटी भाजपा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'रेप इन इंडिया' बयान के विरोध में शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा सांसदों ने हंगामा किया। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के चलते संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसद का माहौल गरमाया रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह जैसे ही शुरू हुई राहुल के 'रेप इन इंडिया' के बयान पर संसद के अंदर मामला इतना भड़का कि शोर शराबे के बीच ही कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। भाजपा की ओर से जहां राहुल से माफी की मांग की गई, वहीं कांग्रेसी इतने उग्र थे कि स्पीकर के बयान के वक्त भी शांत नहीं हुए।

एक दिन पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विवादित बयान में कहा था कि 'मेक इन इंडिया' नहीं बल्कि 'रेप इन इंडिया' हो रहा है।' शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में भाजपा सदस्यों ने इसका विरोध किया। यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल पर तीखा हमला करते हुए कहा, 'क्या सदन में ऐसे भी लोग चुनकर आ सकते हैं जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? उन्हें इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।' उन्होंने उदाहरण भी दिया कि निरंजन ज्योति या अनंत हेगड़े जैसे भाजपा नेताओं ने जब भी आपत्तिजनक बयान दिया उन्हें संसद में आकर माफी मांगनी पड़ी है। राहुल को भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उस वक्त भी लोकसभा में राहुल गांधी मुस्कुराते हुए देखे गए। इस दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने पूर्वोत्तर की स्थिति को लेकर नारेबाजी की और सरकार से सफाई मांगी। दोनों ही सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही को कई बार स्थगित किया गया।

'विदेशी मां की संतान देशभक्त नहीं' : लोकसभा में संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल से माफी मांगने की मांग की। उसके बाद महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, लॉकेट चटर्जी समेत कई भाजपा सदस्यों ने कहा कि राहुल ने ऐसा बयान देकर ना सिर्फ महिलाओं का अपमान किया, बल्कि देश को भी अपमानित किया है। भाजपा सदस्यों ने 'राहुल गांधी माफी मांगों' के नारे लगाए। इस बीच भाजपा सदस्य संजय जायसवाल ने राहुल पर हमला करते हुए कहा, 'चाणक्य ने दो हजार पहले कहा था-विदेशी मां की संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती। यह हम आज देख रहे हैं।'

सदन के बाहर भी विवादित बयान : हंगामे के बीच राहुल ने सदन से बाहर निकलकर फिर अपनी बात दोहराई। उन्होंने माफी मांगने से इन्कार करते हुए फरमाया, 'मैंने कहा कि यहां 'मेक इन इंडिया' का नारा दिया जा रहा है। लेकिन 'रेप इन इंडिया' हो रहा है।' इसे और राजनीतिक रंग देते हुए राहुल ने कहा-कोई भी भाजपा शासित राज्य नहीं है जहां दिनभर महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं हो रहा।' उन्होंने रघुराम राजन का हवाला देते हुए कहा कि वह आज ही बता रहे थे कि अमेरिका, यूरोप में अब हिंदुस्तान की चर्चा अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि अत्याचार, हिंसा और बंटवारे जैसी चीजों पर होती है।'

स्मृति ने चुनाव आयोग में शिकायत की : वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन से बाहर निकलकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उनके बयान को घिनौना बताया। साथ ही उनके नेतृत्व में भाजपा की महिला सांसदों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता के खिलाफ झारखंड की रैली में 'रेप इन इंडिया' बयान पर कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायत विशेषाधिकार समिति को भेजी पेज>>3

शालीनता से परहेज (संपादकीय) पेज>>8

आंध्र प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों का निपटारा 21 दिनों में, मौत की सजा का प्रावधान भी

- विधानसभा में आइपीसी व सीआरपीसी में संशोधन का प्रस्ताव पास
- हैदराबाद कांड के बाद त्वरित न्याय की दिशा में बढ़ने वाला पहला राज्य बना

अमरावती, एजेंसियां : आंध्र प्रदेश में अब दुष्कर्मियों को 21 दिनों में मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश की विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से इससे संबंधित दो विधेयकों को पारित कर दिया। हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के बाद देश भर में त्वरित न्याय की उठ रही मांगों के बीच कानून में संशोधन करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह विधेयक राज्य और केंद्र की समवर्ती सूची में है और इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।

पहले बिल को आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक-आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक-2019 का नाम देते हुए हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई है। हैदराबाद पुलिस ने पीड़िता की पहचान छुपाते हुए उसे दिशा नाम दिया था। इसके तहत भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) व आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन करके महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों (खासकर यौन हिंसा से संबंधित) की त्वरित जांच व सुनवाई के साथ-साथ मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस क्रम में आइपीसी में नई धाराएं 354ई, 354एफ और 354जी जोड़ी जाएंगी। निर्भया अधिनियम-2013 और आपराधिक (संशोधन) अधिनियम-2018 के तहत आरोपित के लिए चार महीने में सजा के प्रावधान की अवधि घटाकर 21 दिन कर दी गई है। अधिनियम के तहत सात कार्यदिवसों में मामले की जांच पूरी होगी, जबकि 14 कार्यदिवसों में सुनवाई पूरी कर ली जाएगी।

सीएम रेड्डी ने कहा कि निर्भया के दोषियों को अब भी सजा मिलनी बाकी है। इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते हुए हालिया दिशा मामले को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने वेटनरी डॉक्टर से दुष्कर्म व उनकी हत्या के चारों आरोपितों को घटना के 10 दिनों बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने और इससे हुई लोगों की खुशी का भी जिक्र किया। विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए सरकार ने कहा, 'आंध्र प्रदेश सरकार ने पुष्ट साक्ष्य होने पर दुष्कर्मी के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है। कोई विकल्प नहीं रखा गया है। आइपीसी-1860 की धारा 376 के संशोधन के जरिये यह प्रावधान लाया गया है।'

दूसरे बिल को आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक नाम दिया गया पेज>>6

राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना मार्च तक हो जाएगी पूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना अगले वर्ष मार्च तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसके लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस से हाथ मिलाया है। शुक्रवार को दिल्ली में भी इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। यह अपनी तरह की सातवीं जनगणना है और पहली बार पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है। इसके लिए विशेष तरह का एप्लीकेशन बनाया गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ डाटा की सुरक्षा भी संभव हो सकेगी।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के महानिदेशक एके साधु ने बताया कि दिल्ली में पूरी प्रक्रिया तीन महीने में संपन्न हो जाएगी। साधु ने बताया कि आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया 20 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही जारी है। सीएससी ई-गवर्नेंस के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि अब सिर्फ तीन राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात बचे हैं, जहां इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है।

सरोकार

महिला शौचालयों में पैड मुहैया करा रहा यह 'पैड हीरो'

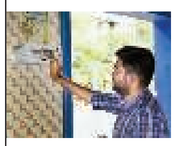

कोलकाता : कोलकाता के शोभन मुखर्जी की प्रेरक कहानी। कोलकाता नगर निगम के 70 शौचालयों में लगा चुके हैं सैनेटरी पैड बॉक्स। इनमें नियमित पैड रखने का जिम्मा भी खुद ही संभाल रहे हैं। महिला सहकर्मी की परेशानी देखकर शुरू की थी मुहिम। (पेज-10)

जागरण विशेष

बोर्ड में 80 प्रतिशत अंक लाओ हवाई सैर का मौका पाओ...

रायपुर : छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव मुसुरपुट्टा की बड़ी पहल, बोर्ड परीक्षा के मेधावियों को गांव वाले चंदा जोड़ कराते हैं हवाई यात्रा। गांव में बढ़ रही 80 फीसद से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

जारी रहेगी इंडिया फर्स्ट की नीति : मालदीव

नई दिल्ली : मालदीव की इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी इंडिया फर्स्ट की नीति स्थाई है और आगे भी बनी रहेगी। हिंद महासागर में रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस देश ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व की सरकार ने चीन के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया था उसे लागू नहीं किया जाएगा।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 7

सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश देने से इन्कार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में पुलिस सुरक्षा में प्रवेश की मांग करने वाली दो महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और वह नहीं चाहते की स्थिति विस्फोटक हो जाए।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

सभी प्रकार के वाहनों का आकार बढ़ाएगी सरकार

नई दिल्ली : बड़े आकार के वाहनों से परिवहन लागत में कमी के मद्देनजर सरकार ने सभी प्रकार के वाहनों, खासकर टू-एक्सल बसों के आकार में बढ़ोतरी का फैसला किया है। पहली बार दोपहिया वाहनों के आकार भी तय किए जा रहे हैं। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव सदन में आया

वाशिंगटन : अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की कानूनी मामलों की समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शुक्रवार को समिति में पार्टीलाइन पर मतदान हुआ और 23-17 के बहुमत से प्रस्ताव को सदन की राय के लिए भेज दिया गया। सदन में अगले सप्ताह प्रस्ताव रखकर महाभियोग चलाने पर सांसदों की राय जानी जाएगी।

कोर्ट ने पूछा

आयकर विभाग ने हाई कोर्ट को बताया, डेरे से वसूलने हैं 350 करोड़, लेकिन संपत्ति अटैच किए जाने के कारण नहीं हो पा रही वसूली

डेरों को कैसे नियमों के दायरे में लाया जाए

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा से आयकर विभाग को 350 करोड़ वसूलने हैं, लेकिन डेरे की संपत्ति अटैच किए जाने के कारण विभाग इसकी वसूली नहीं कर पा रहा है।

पंचकूला हिंसा प्रकरण में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। मामले की सुनवाई कर रही पूर्ण पीठ (जस्टिस राजीव शर्मा, जस्टिस आरके जैन एवं जस्टिस एजी मसीह) ने सभी पक्षों से पूछा कि ऐसे डेरों को कैसे नियमों के दायरे में लाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। कोर्ट ने कहा न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के फैसलों की समीक्षा कर जानकारी दें। उनके आधार पर तय किया जा सके कि दंगों में हुए नुकसान की भरपाई कैसे और किससे की जाए? पीठ के पूछने पर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने तत्काल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी थी। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने कहा कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया। इस पर पीठ ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते तो हाई कोर्ट के दखल की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाजन ने बताया कि इन दंगों में हरियाणा में 126 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ।

हाई कोर्ट ने जब पूछा कि इन दंगों में पंजाब का कितना नुकसान हुआ था तो पंजाब की ओर से अदालत में मौजूद वकील ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह का जवाब कैसे दिया जा सकता है, लगता है पंजाब इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) अतुल नंदा को यहां मौजूद होना चाहिए थे। अगली सुनवाई पर पंजाब के एजी को पेश होने का आदेश दिया गया हैं।

सिरसा डेरा की संपत्ति : डेरा सच्चा सौदा का पुराना भवन, एसी मार्केट, नया भवन और उनमें स्कूल और कॉलेज, क्रिकेट स्टेडियम, फाइव स्टार होटल, डेरा बाबा की गुफा, एमएसजी इंटरनेशनल स्कूल, शाह सतनाम सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, विभिन्न फैक्ट्रियां, एसएमजी प्रोडक्ट्स, फिल्म सिटी सेंटर, माही सिनेमा, कशिश रेस्तरां, ऑर्गेनिक खेती के बाग-बगीचे, डेरे की शिक्षण संस्थाओं की वैन, शाही बेटियां आश्रम और खेल गांव (निर्माणाधीन)।

हाई कोर्ट में दी गई राम रहीम की प्रॉपटी की कीमत

जगह	कीमत
सिरसा	1453 करोड़
अंबाला	32.20 करोड़
झज्जर	29.11 करोड़
फतेहाबाद	20.70 करोड़
जींद	19.33 करोड़
सोनीपत	17.65 करोड़
कैथल	11.16 करोड़
कुरुक्षेत्र	7.42 करोड़
हिसार	7.03 करोड़
भिवानी	3.87 करोड़
यमुना नगर	3.14 करोड़
करनाल	6 करोड़
पानीपत	2.82 करोड़
फरीदाबाद	1.56 करोड़
रोहतक	47 लाख
रेवाड़ी	37 लाख

हाई कोर्ट ने जताई हैरानी, प्रदर्शनकारी छात्रों के बारे में नहीं जानता जेएनयू प्रशासन

- छात्रों व पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई
- पीठ ने छात्रों के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ मांगा शपथपत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट तब हैरान रह गया कि जब प्रदर्शनकारी छात्रों के शैक्षिक सत्र से लेकर नाम तक के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ नहीं बता सका। न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि हैरानी की बात है कि आपने अवमानना याचिका दायर की है, लेकिन ऐसे छात्रों के संबंध में कुछ नहीं जानते, जबकि इसमें से एक छात्रा को साल भर पहले भी अवमानना का दोषी करार दिया गया था।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल मोनिका अरोड़ा ने बताया कि छात्रा गीता कुमारी को हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष भी प्रशासनिक ब्लॉक में प्रदर्शन करने पर अवमानना का दोषी करार दिया था। पीठ ने गीता के बारे में जानकारी मांगी तो कोर्ट में मौजूद जेएनयू रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी कुछ नहीं बता सके। इस पर पीठ ने कहा कि गीता कुमारी कब से जेएनयू में पढ़ रही हैं। गीता और अन्य प्रदर्शनकारी छात्रों का पाठ्यक्रम क्या है, यह तो रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए। यह तो सामान्य जानकारी है। पीठ ने जेएनयू प्रशासन को निर्देश दिया कि वह प्रदर्शनकारियों का नाम, पाठ्यक्रम और कब से वह कैंपस में रह रहे हैं, इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से उपलब्ध कराएं। याचिका पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश स्टैंडिंग काउंसल रमेश सिंह ने कहा कि याचिका के दायर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसी को धमकाना है। आखिर पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका कैसे दायर हो सकती है। ऐसे मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। हालांकि पीठ ने रमेश सिंह की दलीलों से असहमति जताई और कहा कि सर्विस मामलों में अक्सर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को पक्षकार बनाया जाता है। जहां जरूरत है, वहां आप संवेदनशील रहें, यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मोनिका अरोड़ा ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने पूरी तरह से प्रशासनिक ब्लॉक को बंद कर दिया है और वे प्रदर्शन नहीं करने वाले छात्रों को परीक्षा नहीं देने दे रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 10 दिसंबर को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद छात्रों ने 11 दिसंबर को प्रशासनिक भवन के 100 मीटर के दायरे को खाली किया था।

150 इकाइयों को सील किया है दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने। ये इकाइयां रिहायशी इलाकों में चल रही थीं। इसके साथ ही 1652 इकाइयों ने खुद ही फैक्ट्री को बंद करने का हलफनामा निगम को दिया है।

महिलाओं को मदद नहीं, मौका देने की जरूरत : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को मंडी हाउस में फिक्की महिला संघ के तत्वावधान में महिला उद्यमियों को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र के सर्वे का हवाला देकर बताया कि सर्वे में सामने आया है कि उस विधानसभा क्षेत्र में 90 फीसद महिलाएं आम आदमी पार्टी को पसंद करती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें महिलाओं के सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन इतना जबरदस्त समर्थन मिलने से वह बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि महिलाओं को मदद नहीं मौके की जरूरत है। आज हमारा सिस्टम उन्हें मौका नहीं देता। अगर उन्हें बेहतर मौका मिले तो वह चौका लगा देंगी।' हालांकि मुख्यमंत्री ने देश में महिला सुरक्षा पर चिंता जताई।

उन्होंने 49 दिन की सरकार का उदाहरण देकर बताया कि अगर 49 दिन में दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है तो देश के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि देश की पुलिस बहुत अच्छी है। बस सिस्टम में गड़बड़ी के कारण महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। इस दौरान फिक्की महिला संघ की अध्यक्ष हरजिंदर कौर ने कहा कि जो लोग उद्योग और राजनीति में काम नहीं करेंगे, वे अपने आप बाहर हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कराए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि देश में लिंग समानता नहीं है। महिलाओं को बराबरी का अवसर नहीं मिलता है। दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं, उसमें सिर्फ 11 फीसद वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। मेट्रो में केवल 33 और डीटीसी में 30 फीसद महिलाएं यात्रा करती हैं। हालांकि मुफ्त बस सेवा करने के बाद एक माह में डीटीसी बसों में सफर करने वाली महिलाओं का फीसद 30 से बढ़कर 42 तक पहुंच गया है।

सीएम ने कहा महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत काम किए। हमने सभी पांच हजार बसों में 13 हजार मार्शल नियुक्त किए। उन्होंने मार्शल द्वारा महिलाओं को दी जा रही सुरक्षा का भी जिक्र किया। मार्शल अरुण का जिक्र किया जिसने अपहृत की गई बच्ची को बचाया। वहीं मार्शल गीता का जिक्र किया जिसने जेब काट रहे एक बदमाश को पकड़वाया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी दिल्ली में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है। इससे अपराध में कमी आएगी।

आम आदमी पार्टी को पसंद करने के महिलाओं ने गिनाए कई कारण : कार्यक्रम में केजरीवाल ने महिलाओं से सवाल पूछे। उन्होंने महिला उद्यमियों से आम आदमी पार्टी को बेहद पसंद करने का कारण पूछा। इस पर महिलाओं ने अलग-अलग कारण बताए। किसी महिला उद्यमी ने बताया कि हम इसलिए आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं कि क्योंकि आप सबके लिए काम करते हैं। एक महिला ने कहा कि आप दिल से बात करते हैं। एक ने बताया कि आप स्कूल सिस्टम को सुधार रहे हैं। एक ने बताया कि आप बेसिक समस्या को खत्म करते हैं, इसलिए महिलाएं आम आदमी पार्टी को पसंद करती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी को धन्यवाद दिया।

अन्य मुख्य सिफारिशें : जनऔषधि सुविधा, सरकार द्वारा शुरू की गई ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन को जनऔषधि केंद्रों के अलावा मोहल्ला क्लीनिकों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह गठित करने और सेनेटरी पैड बनाने में मदद करने के लिए सरकार के साथ निजी क्षेत्र सहयोग करे।

फिक्की सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में फिक्की महिला संघ की अध्यक्ष हरजिंदर कौर। सौजन्य : फिक्की

महिला उद्यमियों ने पूछे सवाल, सीएम ने दिए जवाब

आप अपनी वर्तमान भूमिका के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं ?

सीएम : 6-7 साल पहले अरविंद केजरीवाल को कौन जानता था, कोई नहीं। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन जीने की पीड़ा को महसूस किया है। आज भी हमने एक परिवार के रूप में उसी तरह के जीवन को बनाए रखने की कोशिश की है।

- एक बार मेरे साथ एक घटना हुई और पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। इस कारण मैं देश छोड़कर जाने की सोच रहीं हूं।

सीएम : देश छोड़कर बाहर जाने की बात कभी न सोचें। मैं आइआइटी में पढ़ा। मेरे बैच के 70-80 फीसद लोग विदेश चले गए। मैं भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया क्योंकि देश तो अपना ही है। मैं भी इस बात से चिंतित हूं कि महिलाएं आपात स्थिति में किसको फोन करें। पुलिस हमारी दोस्त नहीं है, यह अंग्रेजों के समय का सिस्टम है। इसे ठीक करना होगा। दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है, इस कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन, हमें पूरे देश में इस सिस्टम को ठीक करना होगा।

अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करेगा पीड़ित परिवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

निर्भया कांड

पीड़िता की मां ने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उनका पक्ष सुने जाने का किया आग्रह

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता निर्भया की मां दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगी। अक्षय ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को पीड़िता की मां की ओर से अर्जी दाखिल कर अक्षय की पुनर्विचार याचिका में उनका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया गया।

निर्भया की मां के वकील ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होकर कहा कि वह दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध कर रहे हैं। पीठ ने उनसे कहा कि 17 दिसंबर को अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के समय कोर्ट उनका पक्ष भी सुनेगा। दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी की सजा को चुनौती दी है। याचिका में अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट से उसे फांसी की सजा सुनाने के पांच मई 2017 के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस दौरान छात्रा को गंभीर चोटें पहुंचाई गई थीं, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तीन अभियुक्तों मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट गत वर्ष नौ जुलाई को खारिज कर चुका है। लेकिन अक्षय ने अभी तक पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी। अक्षय ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि दोषी में क्रमवार सुधार किए जाने चाहिए। इतना ही नहीं याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है। यहां का पानी जहरीला हो चुका है। प्रदूषित हवा और पानी के चलते पहले ही लोगों की उम्र कम हो रही है, तो फिर फांसी की सजा की क्या जरूरत है।

निर्भया के दोषियों को फांसी देने में लगेगा वक्त, कई कानूनी प्रक्रिया बाकी

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटकाने में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि कई कानूनी प्रक्रिया बाकी है। इस मामले में सरकार, जेल प्रशासन व अदालतों के स्तर पर गुनहगारों को फांसी पर लटकाने के लिए देरी नहीं की जा रही है, बल्कि चारों गुनहगार ही जानबूझ कर कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करने में देरी कर रहे हैं।

दरअसल, गुनहगार चार हैं और इन सभी के पास पुनर्विचार व दया याचिका दायर करने के अलावा उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर करने जैसे अधिकार हैं। चारों विनय शर्मा, पवन, अक्षय व मुकेश एक साथ किसी भी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल न कर अलग-अलग कर रहे हैं। इसलिए देरी हो रही है। चारों जब उक्त तीनों प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद डेथ वारंट की प्रक्रिया बचेगी।

डेथ वारंट के बाद भी 14 दिन का वक्त : जेल प्रशासन द्वारा डेथ वारंट जारी करने पर भी 14 दिनों का वक्त मिलता है। इन 14 दिनों के अंदर चारों के परिजन जितनी जल्दी मुलाकात कर लेंगे, उसके अगले दिन ही चारों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। हालांकि यह परिजनों पर निर्भर करता है कि वे गुनहगारों से मिलना पसंद करेंगे भी अथवा नहीं। चारों गुनहगारों में अभी केवल अक्षय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की उच्च पीठ में पुनर्विचार याचिका दायर की है। वहीं, उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) भी चारों में किसी ने भी अब तक सुपीम कोर्ट में नहीं डाली है। उपचारात्मक याचिका ऐसी याचिका है, जो कभी भी डाली जा सकती है।

परिजनों को सूचना देना अनिवार्य : 2001 में भारतीय लोकतंत्र यानी संसद पर हमला करने वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकी अफजल गुरु के मामले में गोपनीय तरीके से डेथ वारंट जारी कर परिजनों को बिना बताए 2013 में फांसी दे दी गई थी। 26 नवंबर 2008 में मुंबई के ताज महल पैलेस पर हमला करने वाले जैश आतंकी अफजल कसाब के मामले में भी गोपनीय तरीके से डेथ वारंट जारी कर बिना परिजनों को सूचित किए 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवडा जेल में फांसी दे दी गई थी। उक्त दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद निर्देश दिए गए कि डेथ वारंट जारी करते ही परिजनों को हर हाल में सूचित किया जाना अनिवार्य है।

न्यूज गैलरी

सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जुड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इसके लिए 12 घंटे का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है और पाठ्यक्रम सीबीएसई स्कूलों को भेजा जा चुका है। पहले चरण में इस विषय को कक्षा नौवीं से लागू किया जाएगा। इसके बाद कक्षा आठ और दस में भी इसे पढ़ाने की योजना है। केंद्र सरकार की ओर से देश के विभिन्न भागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए कोर्स को लागू करने के लिए अब तक 40 से अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जा चुके हैं। वहीं, सरकार ने इसे विद्यालयों में लागू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, आइबीएम जैसी कंपनियों से समझौता किया है। ये कंपनियां पहले दौर में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करेंगी। सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में पहली यूनिट में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का परिचय है। (जासं)

'केंद्र सरकार खत्म कराए स्वाति का अनशन'

नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद का अनशन राजघाट पर 11वें दिन भी जारी रहा। डॉक्टर के अनुसार, दिन-प्रतिदिन स्वाति की हालत बिगड़ती जा रही है। उनका शुगर लेवल भी बहुत कम है। वहीं, निर्भया के माता-पिता ने शुक्रवार को अनशन स्थल पहुंच कर स्वाति से अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वाति लगातार 11 दिनों से अनशन कर रही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई उनसे मिलने तक नहीं आया। स्वाति की हालत देख निर्भया की मां भावुक हो गईं और उन्हें गले लगाकर बोली, हम इस देश में तो दुष्कर्म पीड़िताओं को नहीं बचा पा रहे, लेकिन जो उन पीड़िताओं के लिए जंग लड़ रही हैं, उन्हें बचाने का फर्ज हमारा बनता है। इस देश का सिस्टम इस प्रकार खराब हो गया है कि हमारी ही बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और हमारी ही एक बेटी को उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ती है। स्वाति जैसी महिलाएं इस देश में बहुत कम हैं और यह देश उन्हें खो नहीं सकता। (जासं)

हर जिले में नियुक्त किए जाएंगे पुनर्वास अधिकारी : गौतम

नई दिल्ली : दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार के इस दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगता मामलों के लिए अलग से एक निदेशालय बनाया जा रहा है। विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग और एक अन्य संस्था के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस निदेशालय के तहत प्रत्येक जिले में पुनर्वास अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। (जासं)

अनधिकृत कॉलोनियों का माफ होगा बकाया संपत्ति कर

राहत ▶ दक्षिण दिल्ली नगर पर 1400 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा

925 अनधिकृत कॉलोनियों के नौ लाख परिवारों को लाभ होगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कॉलोनी के संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत देने का एलान किया है। निगम ने इन कॉलोनियों के संपत्ति मालिकों से बकाया संपत्ति कर न लेने की घोषणा की है। दक्षिणी निगम के करीब नौ लाख संपत्ति मालिकों को बकाया संपत्ति कर नहीं देना होगा। इस फैसले से दक्षिणी निगम पर करीब 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। निगम सदन की शुक्रवार को हुई बैठक में वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों को पेश करते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने यह घोषणा की।

उनके अनुसार, इस फैसले से निगम इलाके की 925 अनधिकृत कॉलोनियों के नौ लाख परिवारों को लाभ होगा। गुप्ता ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में अब तक निगम फंड का उपयोग नहीं कर पाता था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली के 40 लाख लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित होने का लाभ मिलेगा। ऐसे में हमने फैसला किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों से वर्ष 2004 से 2018 तक का बकाया संपत्ति कर नहीं लेंगे। लोगों को वर्ष 2019-20 का बकाया संपत्ति कर देना होगा। स्थायी समिति अध्यक्ष ने बताया कि कॉलोनियों के नियमित होने के बाद से इनसे निगम को हर वर्ष करीब 100 करोड़ रुपये का संपत्ति कर आने का अनुमान है।

निगमायुक्त की ओर से प्रस्तावित कर वृद्धि खारिज : निगमायुक्त ने संपत्ति कर की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के साथ पेशेवर और संपत्ति कर के हस्तांतरण का शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसे स्थायी समिति अध्यक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि हमने विभागों से कहा है कि वे संपत्ति कर बढ़ाने की बजाय वर्तमान में संपत्ति कर न देने वाले लोगों को कर के दायरे में लाएं।

50 करोड़ रुपये विकास का रखा था फंड : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इससे पूर्व अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। इससे इन कालोनियों और शहरीकृत गांवों का विकास किया जा सकेगा।

प्रस्ताव को लागू करने की यह होगी प्रक्रिया : स्थायी समिति के अध्यक्ष की ओर से बजट प्रस्तावों में घोषणा के बाद नेता सदन इसे अंतिम रूप देगी। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस दल के नेता इस बजट प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके बाद नेता सदन कमलजीत सहरावत इसे बजट प्रस्ताव में शामिल करेंगी। इसकी मंजूरी के बाद निगम की ओर से आदेश निकालने के बाद यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा।

दक्षिणी निगम के संपत्ति कर दाता

- दक्षिणी निगम के सर्वे के अनुसार 12 लाख संपत्ति धारक हैं
- पिछले वित्त वर्ष में निगम ने 944 करोड़ रुपये का वसूला था संपत्ति कर
- 4,41,776 संपत्ति करदाताओं से वसूला गया था कर
- वर्ष 2018-19 में 31,223 बढ़े थे संपत्ति करदाता
- इस फैसले से करीब नौ लाख संपत्ति मालिकों को होगा लाभ
- निगम पर पड़ेगा 1400 करोड़ रुपये बोझ

घंटों विमान में फंसे रहे स्पाइस जेट के यात्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : खराब मौसम और विमान में तकनीकी खराबी के कारण आइजीआइ एयरपोर्ट से जाने वाली स्पाइस जेट की दो उड़ानों के यात्रियों को शुक्रवार को घंटों परेशानी उठानी पड़ी। आइजीआइ से कोयंबटूर जाने वाली उड़ान में खराबी आने से 190 यात्री ढाई घंटे तक विमान के अंदर फंसे रहे। वहीं, अन्य मामले में मौसम खराब होने के कारण दूसरी फ्लाइट को लेकर आ रहे पायलट को देरी हो गई। इसकी वजह से मुंबई जाने वाली उड़ान को करीब दो घंटे देरी से उड़ाया गया। कंपनी ने यात्रियों को हुई इस परेशानी पर खेद जताया है।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह स्पाइस जेट की उड़ान एसजी-8561 को कोयंबटूर के लिए रवाना होना था। इसके यात्री साढ़े आठ बजे विमान में बैठने शुरू हो गए थे। यात्रियों के बैठने के बाद जब विमान रनवे की तरफ बढ़ा तो पायलट को उसमें तकनीकी खराबी का पता चला। बाद में दूसरे विमान से यात्रियों को करीब दो घंटे बाद रवाना किया गया।

उधर, स्पाइस जेट की ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी-8723 ने पायलट न होने से करीब दो घंटे देरी से उड़ान भरी। दरअसल, मौसम खराब होने से किसी अन्य फ्लाइट को लेकर आ रहे पायलट को आने में देरी हो गई। इसके बाद साढ़े आठ बजे जाने वाली उड़ान को करीब साढ़े दस बजे रवाना किया गया। देरी की वजह से यात्रियों को खासी परेशानी हुई।

घर बैठे पा सकेंगे 30 और सेवाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली परिवहन निगम के पास की सेवा के साथ ही विधवा महिला पेंशन के आवेदन की भी अब होम डिलीवरी होगी। दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा में छह विभाग की 30 नई सेवाओं को जोड़ दिया है। इसके साथ ही अब सेवाओं की संख्या 70 से बढ़कर 100 हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को नई सेवाओं को जोड़ने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में आवेदनों पर कार्रवाई का फीसद अच्छा है। उन्होंने बताया कि अब तक सेवा के तहत आने वाले 95 फीसद आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। बाकी पांच फीसद पर की जा रही है। बता दें पहले फेज में 40 सेवाओं के साथ डोर स्टेप डिलीवरी को 10 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसके बाद अगस्त 2019 में नई 30 सेवाओं को दूसरे फेज में जोड़ा गया और अब तीसरे फेज में 30 नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

डोर स्टेप डिलीवरी में सफलता का फीसद 91: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली में तीन तरह से काम करा सकते हैं। पहला, सरकारी दफ्तर में जाकर खिड़की पर खड़े होकर, दूसरा ऑनलाइन और तीसरा डोर स्टेप डिलीवरी के जरिये काम करा सकते हैं। अब तक खिड़की पर जाकर काम करने का सक्सेज रेट 57 फीसद है और 43 फीसद लोगों के आवेदन किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिए। ऑनलाइन मे 45 फीसद काम होता पाया गया है और 55 फीसद लोगों के फार्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वहीं डोर स्टेप में 91 फीसद लोगों के काम हुए हैं। सिर्फ नौ फीसद लोगों के काम को ही रिजेक्ट किया गया है।

इस दौरान अभी तक दो लाख 89 हजार 762 कॉल पर सेवा बुक की गई हैं। इसमें से दो लाख 78 हजार कॉल पर मोबाइल सहायक ने कॉलर के घर पर पहुंच कर सेवा के आवेदन सबमिट किए। अब तक दो लाख 64 हजार 927 आवेदनों को सेवा का लाभ दे कर खत्म किया जा चुका है। योजना के तहत अब तक कुल 16 लाख 31 हजार 772 कॉल रिसीव की गईं।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन : सेवा का लाभ लेने के लिए दिल्ली के लोग 1076 नंबर पर 24 घंटे कभी भी कॉल कर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद मोबाइल सहायक आपकी सुविधा के अनुसार घर आकर संबंधित सेवा के दस्तावेज टेबलेट से अपलोड कर देगा। इसके अलावा आरटीओ/एसडीम ऑफिस पर हेल्प डेस्क की मदद से भी अपनी सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

रैली की तैयारी पूरी

रामलीला मैदान में आज होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने दावा किया कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। रैली स्थल के चारों ओर सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के बड़े-बडे होर्डिंग लगाए गए हैं। चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर बाहर से आने वाले लोगों को व्यवस्थित ढंग से रामलीला मैदान तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की 100 टीमों का गठन किया गया है। जागरण

हवाई यात्री बोर्डिंग एरिया में खरीद सकेंगे पसंद का भोजन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फूड जिनी नाम की सेवा शुरू की गई है। इसके तहत बोर्डिंग गेट के समीप पहुंच चुके यात्री अब सेल्फ-ऑर्डरिंग कियोस्क से पसंद का खाना मंगा सकेंगे। अधिकतम 20 मिनट में यात्रियों को मनचाहा भोजन प्राप्त हो जाएगा। यदि वे चाहें तो इसे विमान में भी ले जा सकते हैं। आर्डर के लिए इंटरनेशनल और डोमस्टिक डिपार्चर एरिया में दो-दो कियोस्क स्थापित किए हैं।

दरअसल आइजीआइ एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले कई यात्री विमान छूट जाने के डर से चेकइन के बाद बोर्डिंग एरिया में चले जाते हैं। भूखे होने के बावजूद वे समय लगने की वजह से बोर्डिंग एरिया से बाहर नहीं जाते। ऐसे यात्रियों को आसानी से भोजन उपलब्ध कराने के लिए टर्मिनल-3 के डिपार्चर एरिया में कियोस्क बनाए गए हैं। वहां लगे डिजिटल स्क्रीन पर यात्री एयरपोर्ट पर स्थित किसी भी आउटलेट से अपना मन पंसद खाना आर्डर कर सकेंगे। ऑर्डर देने के अधिकतम 20 मिनट बाद पास पिक-अप पॉइंट पर इलेक्ट्रिक स्कूटर से डिलीवरी कर्मी खाने की आपूर्ति करेंगे। यह सेवा यात्रियों को सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध होगी।

योजना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के छह राष्ट्रीय स्मारकों को मस्ट-सी मॉन्यूमेंट्स योजना में किया शामिल, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

दिल्ली के इन छह स्मारकों को जरूर देखें

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

दिल्ली स्थित छह राष्ट्रीय स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने मस्ट-सी मॉन्यूमेंट्स योजना में शामिल किया है। एएसआइ इसके लिए प्रचार करेगा कि दिल्ली घूमने आएं तो इन स्मारकों को जरूर देखें। इसके अलावा यहां पर पर्यटकों की सुविधा के लिहाज से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन स्मारकों में तीन विश्व धरोहर स्मारक लालकिला, कुतुबमीनार व हुमायूं का मकबरा के अलावा खान ए खाना का मकबरा, सुल्तान गारी का मकबरा व तुगलकाबाद का किला शामिल हैं।

बता दें कि एएसआइ ने भारत में 3693 स्मारकों में से 138 स्थलों की पहचान मस्ट-सी मॉन्यूमेंट्स के रूप में की है। इनमें 22 विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हैं। एएसआइ चाहता है कि लोग प्रमुख स्मारकों को देखने तो जाते ही हैं, इन स्मारकों को भी देखने जाएं। इसी लिहाज से यहां सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पीने के पानी के अलावा विश्वस्तरीय शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा लाइटिंग का इंतजाम किया जा रहा है ताकि पर्यटक रात में भी इन्हें निहार सकें।

खान ए खाना मकबरा। (फाइल)

सुल्तान गारी का मकबरा : सुल्तान गारी का मकबरा भारत में उन पहली इमारतों में से एक है, जिन्हें तोड़कर मकबरे का रूप दिया गया। मूलरूप से हिंदू शैली में बने इस मंदिर को बाद में इस्लामिक शैली में ढाला गया। मुख्य प्रवेश द्वार पर अंकित लेखों से पता चलता है कि गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने 1231 में अपने बड़े बेटे नसिरुद्दीन महमूद उर्फ मुहम्मद गारी के मरने के बाद इसे मकबरा का रूप दिलाया।

तुगलकाबाद का किला : दक्षिणी दिल्ली में स्थित यह किला 1321 का है। उस समय में मुबारक शाह का शासन था। उस समय मंगोल बहुत सक्रिय थे। उनसे बचने के लिए पंजाब सूबे के गवर्नर गाजी मलिक ने पहाड़ी पर किला बनाकर राजधानी स्थापित करने का सुझाव मुबारक शाह को दिया। उस समय राजधानी का संचालन हौजखास स्थित सीरीफोर्ट से होता था। इस पर मुबारक शाह ने उसका मजाक बनाया और ऐसा करने से मना कर दिया। मगर वक्त में ऐसा पलटा खाया कि मुबारक शाह की मौत के बाद यही गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। उनसे यह किला बनवाया।

खान ए खाना मकबरा : मुगलकाल में किसी महिला का पहला मकबरा खान ए खाना का मकबरा है। रहीम का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान-ए-खाना था। यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी माह बानु के लिए 1598 में यह मकबरा बनाया गया। मुगलकाल में किसी महिला के लिए बनाया गया यह पहला मकबरा था। यहीं रहीम को भी 1627 में दफनाया गया।

'महिला सम्मान की दिलाई जाएगी शपथ'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा निर्णय लिया है। अब दिल्ली के सभी स्कूलों व कॉलेजों में छात्रों को महिला सम्मान की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें छात्रों को इस बात की कसम दिलाई जाएगी कि वे किसी महिला के साथ दुर्वयवहार या दुराचार नहीं करेंगे। ऐसा कक्षा छह से शुरू किया जाएगा। साथ ही सभी स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने-अपने भाइयों से बात करें कि वे महिलाओं का सम्मान करेंगे। ऐसा करने के बाद छात्राओं को इसकी जानकारी स्कूल व कालेज में भी देनी होगी। इसके अलावा सभी स्कूल व कॉलेज में महिला सुरक्षा पर एक घंटे की क्लास चलेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए सभी स्कूल व कालेज की हर क्लास में चर्चा होगी। यह पूरे समाज के लिए जरूरी है। एक घंटे की चर्चा होगी। इसे एक समय अंतराल पर लगातार कराया जाएगा। क्लास में समाज में क्या हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। सीएम ने कहा कि हम निजी स्कूलों को बोलेंगे। सारे कॉलेजों को बोलेंगे, जिससे पूरे दिल्ली में ऐसा हो सके। उन्होंने कहा महिला सुरक्षा पर आपस में चर्चा की जरूरत है। बहन को भाई को कहने की जरूरत है कि गलत किया कि बात करना बंद हो जाएगा।

अनशन पर राजघाट पर बैठीं स्वाति जयहिंद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि वह अनशन तोड़ दें। केजरीवाल ने कहा कि स्वाति जुझारू महिला हैं, उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। हम सब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि स्वाति की इस देश को जरूरत है। उन्होंने अपील की वह अनशन तोड़ दें।

सभी स्कूलों-कालेजों में ये तीन काम होंगे

सभी स्कूलों और कालेजों में विशेष क्लास : स्कूलों व कॉलेजों में एक घंटे की विशेष क्लास लगेगी, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अपराध पर बात होगी। इस रोकने के उपाय पर बच्चों की राय जानी जाएगी।

सभी छात्रों को शपथ : दिल्ली के सभी स्कूलों व कालेजों में छात्रों को कसम खिलाएंगे कि जिंदगी में किसी लड़की के साथ गलत नहीं करेंगे। कभी किसी लड़की पर गलत नजर नहीं डालेंगे। किसी लड़की से दुराचार या दुर्वव्हार नहीं करेंगे।

छात्राएं घर जाकर भाइयों से बात करेंगी : दिल्ली के सभी सरकारी व निजी स्कूल-कालेज की लड़कियों को कहा जाएगा कि वे भाई से बात करें। उनको कहना होगा कि किसी लड़की के साथ गलत न करे। फिर क्लास में लड़की को आकर बताना होगा कि उसने अपने भाई से बात कर ली है।

3.62 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं है शौचायल की व्यवस्था जबकि 1.59 लाख केंद्रों में पीने के पानी का प्रबंधन नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दी।

111 फीसद चली लोकसभा 92 फीसद राज्यसभा में हुआ काम

18 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का 13 दिसंबर को समापन हुआ। इसी सत्र के दौरान संविधान के 70 साल पूरे होने के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में ऐतिहासिक समारोह हुआ। संसद के विधायी कामकाज पर गहरी नजर रखने वाली संस्था पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च के अनुसार अपना 250वां सत्र मना रहा उच्च सदन यानी राज्यसभा में तय समय का 92 फीसद काम हुआ जबकि लोकसभा ने 111 फीसद काम किया। हालांकि पेट्र के अनुसार लोकसभा में तय कामकाज का 116 फीसद जबकि राज्यसभा में 99 फीसद काम हुआ। पीआरएस के अनुसार राज्यसभा के 250वें सत्र की शुरुआत के समय की गणना में अंतर के चलते यह फर्क है। सत्र के समापन पर दोनों सदनों के विधायी कामों पर पेश है एक नजर :

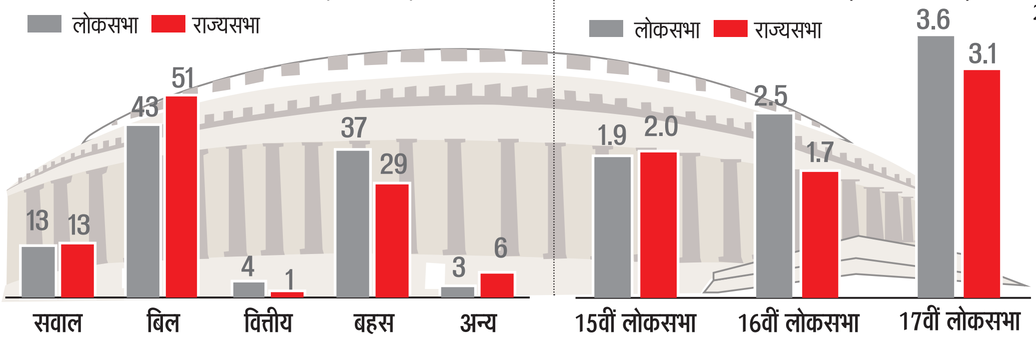

- गैर विधायी बहसों के तहत लोकसभा में वायु प्रदूषण मसले पर आठ घंटे बहस हुई और फसल नुकसान पर 7.5 घंटे की बहस हुई।
- गैर विधायी मसलों के तहत राज्यसभा में आर्थिक हालात पर 4.5 घंटे बहस हुई।
- 17वीं लोकसभा के दोनों सत्रों में औसतन किसी बिल पर 3.6 घंटे बहस हुई। राज्यसभा के लिए यह आंकड़ा 3.1 घंटे का रहा। यह औसत पिछले दो लोकसभाओं से अधिक रहा।
- सत्र के दौरान 17 बिल संसद में पेश किए गए। 14 पारित हुए।
- इस सत्र में 10 बिल पेश और पारित किए गए।
- 13 बिल लोकसभा से और 14 बिल राज्यसभा से पारित हुए। औसतन एक बिल पर लोकसभा में चार घंटे और राज्यसभा में 3.4 घंटे बहस हुई।

सवालों के मौखिक जवाब का बना रिकॉर्ड

250वां सत्र मना रहे संसद के उच्च सदन ने सवालों के मौखिक जवाब का रिकॉर्ड बनाया। 60 फीसद सवालों के जवाब दिए गए। यह पिछले बीस वर्षों का रिकॉर्ड रहा।

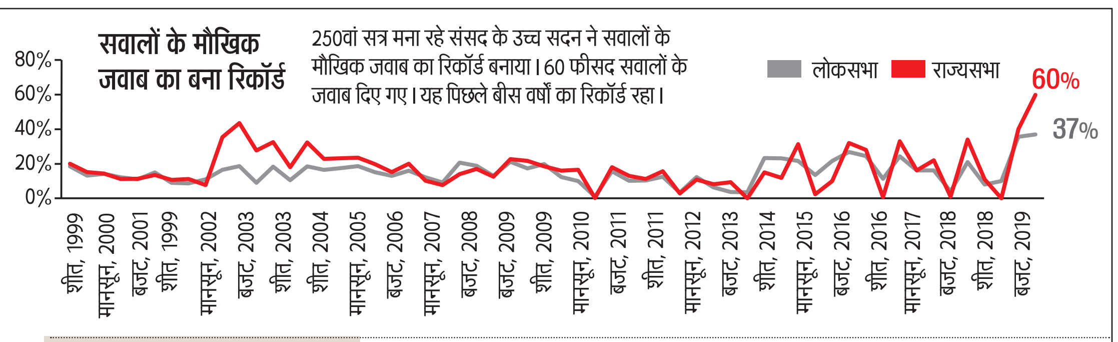

179 दिन बाद चुने गए उपाध्यक्ष

संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के गठन के तुरंत बाद जितना जल्दी संभव हो, सदन के दो सदस्यों को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। 12वीं लोकसभा के लिए उपाध्यक्ष चुनने में अब तक का सबसे अधिक समय 269 दिन लगे थे।

पहली लोकसभा से अब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने में लगा समय

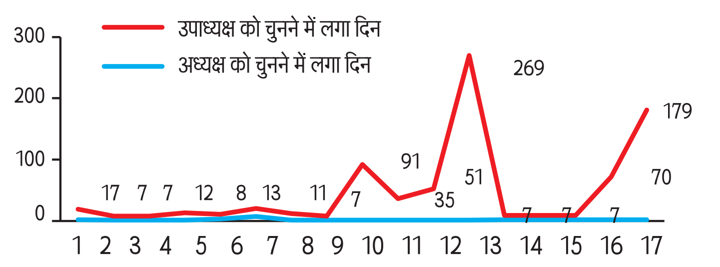

स्रोत : पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

दूसरे सत्र में भी हुए कई बड़े विधायी काम

17वीं लोकसभा ▸ नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करने के लिए याद किया जाएगा सत्र

कामकाज की कसौटी पर भी संसद के दोनों सदनों ने शत-प्रतिशत सफलता के गाड़े झंडे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

17वीं लोकसभा का दूसरा सत्र सियासी रूप से चर्चित नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करने के लिए याद किया जाएगा। इस तरह नई लोकसभा के गठन के बाद यह लगातार दूसरा सत्र रहा, जिसमें व्यापक जनसमुदाय को प्रभावित करने के वाले बड़े विधायी बदलाव को अंजाम दिया गया। कामकाज के लिहाज से भी संसद के दोनों सदनों ने अपने तय समय से ज्यादा देर तक काम कर संसदीय व्यवस्था की सकारात्मक झलक दिखाई है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शीत सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सत्र की कामयाबी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसका श्रेय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिया। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने भी कहा कि उच्च सदन का 250वां ऐतिहासिक सत्र एक-दो छोटे मौके को छोड़ पूरी तरह सफल रहा और यह सत्र साहस व गंभीरता के लिए याद किया जाएगा। बिरला ने कहा कि हमने फिर साबित किया है कि हमारा संसदीय लोकतंत्र उच्चकोटि का है। दुनिया के कई देश लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था की खूबियों को अपना रहे हैं। इसीलिए 1858 से लेकर अभी तक की सभी बड़ी चर्चाओं और भाषणों को हमने डिजिटल कर दिया है। बिरला ने कहा कि आजादी के बाद पहली संसद से पूर्व 1858 से इस दिशा में शुरू हुई पहल और विधायी चर्चाओं को इसमें शामिल किया गया है।

ओम बिरला फाइल

संसदीय कामकाज की उत्पादकता का आंकड़ा चाहे जो रहे मगर राजनीतिक और विधायी इतिहास के नजरिये से नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित कर कानून बनाने का कदम सत्र का सबसे बड़ा काम रहा। नई लोकसभा के पहले सत्र में तत्काल तीन तलाक, आरटीआइ संशोधन के साथ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का अभूतपूर्व कदम उठाया गया। दूसरे सत्र में नागरिकता विधेयक कुछ उसी तरह रहा। कई मायनों में नागरिकता विधेयक के विरोध में खड़े विपक्षी दलों की मुखरता और संख्या 370 हटाने का विधेयक पारित कराने से भी ज्यादा थी। इस लिहाज से मोदी सरकार के लिए यह सत्र बेहद अहम ही नहीं बल्कि उसके राजनीतिक वादे के एजेंडे का बड़ा पड़ाव साबित हुआ है।

स्पीकर ने सवालों के जवाब में स्वीकार किया कि सांसदों ने रियायती खाने के आरोपों से छवि पर आ रहे आंच से बचने के लिए खुद ही सब्सिडी खत्म कराई है। उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा बन रही थी कि सब्सिडी का सांसद ही केवल फायदा उठाते हैं, जबकि हकीकत में संसद के कर्मचारी, आगंतुक और मीडिया सभी को इसकी सुविधा थी। इसीलिए सभी दलों के नेताओं के सामने जब उन्होंने कैंटीन सब्सिडी हटाने का प्रस्ताव रखा तो सबने इस पर सहमति दे दी।

नए संसद भवन में होगा 2022 का पहला सत्र : बिरला ने कहा कि संसद और उसके कामकाज को संपूर्ण रूप से डिजिटल करने का लक्ष्य संसद भवन की नई बिल्डिंग बनने के साथ ही पूरा हो जाएगा। उनके अनुसार संसद की नई इमारत बनाने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री से चर्चा हो चुकी है। अधिकतर लोग नई बिल्डिंग बनाने के पक्ष में हैं। संसद का नया भवन कहां बनेगा इस पर बिरला ने कहा कि अभी मंत्रणा चल रही है। मगर उम्मीद है कि आजादी के 75वें साल 2022 में संसद का पहला सत्र नई बिल्डिंग में होगा।

राहुल के खिलाफ शिकायत विशेषाधिकार समिति को भेजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से की गई विशेषाधिकार हनन की शिकायत को विशेषधिकार समिति के पास भेज दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने विभिन्न सदस्यों के खिलाफ शिकायतों को संबंधित समितियों के पास भेज दिया है और अब इन समितियों को फैसला करना है कि मामला बनता है या नहीं। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की सराहना से जुड़ी प्रज्ञा की एक विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें 'आतंकवादी' बताया था। इस पर प्रज्ञा ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। ठाकुर ने अपने बयान पर माफी मांगने के बाद राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर फाइल

जारी रहेगी इंडिया फर्स्ट की नीति : मालदीव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पूर्व राष्ट्रपति व स्पीकर ने कहा, चीन के साथ एफटीए भी नहीं करेगा उनका देश

▸ स्पीकर के साथ विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भी भारत दौरे पर

मालदीव की इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी इंडिया फर्स्ट की नीति स्थाई है और आगे भी बनी रहेगी। इसके साथ ही हिंद महासागर में स्थित रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस देश ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व की सरकार ने चीन के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया था उसे लागू नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर आए मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति व वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी।

नशीद के साथ मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भी भारत की यात्रा पर आए हैं। आज उनके और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में दोनों देशों के संयुक्त आयोग की बैठक भी हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच तीन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में शाहिद और नशीद ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने मोहम्मद सोलिह सरकार की पहली वर्षगांठ पर बधाई दी और आश्वस्त किया कि मालदीव को मजबूत, लोकतांत्रिक, संपन्न व शांतिपूर्ण बनाने में भारत हरसंभव मदद मुहैया कराएगा। शाहिद ने पीएम को बताया कि उनकी सरकार इंडिया फर्स्ट नीति को लेकर कृतसंकल्प है और द्विपक्षी रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। सनद रहे कि सोलिह सरकार से पहले की मालदीव की सरकार ने एक तरह से चीन फर्स्ट की नीति अपना ली थी। तब भारत के साथ वादे के बावजूद चीन के साथ एफटीए किया गया था। एफटीए के बारे में पूर्व राष्ट्रपति व स्पीकर नशीद ने बताया कि मौजूदा सरकार इसे लागू करने नहीं जा रही है।

मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद (दाएं) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रेट्र

नागरिकता कानून भारत का आंतरिक मामला : पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने नागरिकता कानून में बदलाव को भारत का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था जताते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से दूसरे देशों में उत्पीड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों की मदद करता रहा है।

मालदीव ने जाकिर नाइक को नहीं दी शरण : नशीद ने बताया कि विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक मलेशिया छोड़कर मालदीव आना चाहता था। लेकिन मालदीव ने उसे अपने यहां आने की इजाजत नहीं दी। भारत में प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 53 वर्षीय नाइक की तलाश है। उसके खिलाफ मनी लांड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज हैं। वह 2016 में भारत से फरार हुआ था और उसके बाद से मलेशिया में शरण लिए हुए है। भारत उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में है।

संसदीय समिति के सामने पेश हुए फेसबुक इंडिया के प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : फेसबुक इंडिया के प्रमुख आंखी दास वाट्सएप जासूसी मामले में संसदीय समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने संसदीय समिति को बताया कि सोशल प्लेटफॉर्म के संदेशों का शुरू से अंत तक एन्क्रिप्शन किया जाता है। इसके चलते इसके संदेशों का किसी अन्य के पास पहुंचने की संभावना नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने शुक्रवार को नागरिकों की डाटा सुरक्षा और निजता के मुद्दे पर विचार के लिए साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों को भी बुलाया। संसदीय पैनल ने वाट्सएप जासूसी मामले के गैर आधिकारिक गवाह भाजपा के पूर्व संगठन सचिव केएन गोविंदाचार्य को भी बुलाया। गोविंदाचार्य की ओर से उनके वकील समित के सामने पेश हुए। इसके अलावा दूरसंचार और गृह मंत्रालय के अधिकारियों और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी संसदीय समिति ने बुलाया था।

संसदीय समिति के सदस्यों को लिखे पत्र में थरूर ने कहा था कि साइबर सुरक्षा हमारे एजेंडे में प्रमुख है। हम सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगेंगे। उल्लेखनीय है कि फेसबुक के स्वामित्व वाली वाट्सएप ने अक्टूबर में कहा था कि इजरायली स्पायवेयर के जरिये दुनियाभर में जिन लोगों की जासूसी की गई, उनमें भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी संसद पर हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

▸ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं अन्य नेताओं ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन

▸ 13 दिसंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले में चली गई थी नौ लोगों की जान

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं विभिन्न दलों के नेताओं ने 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भी श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल थे।

अठारह साल पहले 13 दिसंबर को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों ने संसद परिसर पर हमला किया था। गोलीबारी में नौ लोगों की जान गई थी। ऐसे लोगों में दिल्ली पुलिस के पांच जवान, सीआरपीएफ की एक महिला ट्रूपर, संसद के दो वाच एंड वार्ड स्टाफ और एक माली भी शामिल थे। हमले में घायल एक पत्रकार की बाद में मौत हो गई। मुकाबले में पांचों आतंकी मारे गए।

श्रद्धांजलि देने के बाद राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, 'कृतज्ञ राष्ट्र अदम्य साहस प्रदर्शित करने वाले शहीदों, जिन्होंने 2001 में आतंकियों से संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया उन्हें सलाम करता है। हम आतंकवाद के हर रूपों और तरीकों को पराजित और खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हैं।'

नई दिल्ली में शुक्रवार को संसद हमले की 18वीं बरसी पर संसद परिसर में श्रद्धांजलि सभा के दौरान, बाएं से, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

गृह मंत्री शाह ने हिंदी में ट्वीट किया है, 'भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद की रक्षा करते हुए शहीद हुए बहादुर सिपाहियों और उनके परिवार के लोगों के प्रति श्रद्धांजलि। आपका बलिदान हर किसी के लिए हमेशा प्रेरक बना रहेगा।' केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, 'आज हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने आतंकी हमले से संसद की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था।'

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रकाश जावडेकर के अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एवं अन्य नेताओं ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी।

रवि मित्तल बने सूचना प्रसारण सचिव, अमित खरे को उच्च शिक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दर्जन भर से ज्यादा सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें रवि मित्तल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि अमित खरे को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। साथ ही उनके पास स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी को भी यथावत रखा गया है।

कार्मिक मंत्रालय ने इसके साथ ही जिन अधिकारियों के तबादले किए हैं, उनमें आर. सुब्रह्मणयम को उच्च शिक्षा से हटाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही टीवी सोमनाथन को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं कैबिनेट सचिवालय ने सचिव रहे राजेश भूषण को ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे अमरजीत सिंहा का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार ने इसके अलावा और जिन प्रमुख अधिकारियों के तबादले किए है, उनमें अरुण गोयल को संस्कृति मंत्रालय के सचिव से हटाकर भारी उद्योग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। वहीं सुनील कुमार को पंचायती राज मंत्रालय में सचिव, बरुण मित्रा को कानून मंत्रालय में ओएसडी और वीपी जॉय को कैबिनेट सचिवालय में सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इसके अतिरिक्त करीब दर्जन भर अधिकारियों को विशेष सचिव के स्तर पर पदोन्नत किया गया है।

'नाबालिगों की गैरकानूनी हिरासत के आरोप सही नहीं'

▸ जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट का दिया हवाला

▸ कमेटी में शामिल चार जजों ने किया था प्रदेश की सभी जेलों का दौरा

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को नाबालिगों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने के सुरक्षा बलों पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं मिली है।

पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा ने एक याचिका दाखिल कर जम्मू-कश्मीर में नाबालिगों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया था। याचिका में प्रमुख अमेरिकी अखबारों में छपी खबरों का हवाला भी दिया गया था। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सवाल किया, 'हमें हाई कोर्ट के हमारे चार जजों की तथ्य परक रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए या वाशिंगटन के अखबार में छपी कुछ खबरों पर?' हाई कोर्ट की रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में शामिल हाई कोर्ट के चारों जजों ने सभी जेलों का दौरा किया था और संबंधित लोगों से बात की थी। उन्हें कोई भी नाबालिग गैरकानूनी रूप से हिरासत में नहीं मिला। गांगुली के वकील हुजेफा अहमदी ने जब हाई कोर्ट रिपोर्ट की जांच की दलील दी तो जस्टिस रमना ने कहा, 'हमने बड़े ध्यान से रिपोर्ट देखी है, उसमें नाबालिगों की गैरकानूनी हिरासत जैसी कोई चीज नहीं है... हम मामले को लंबित नहीं रख सकते और हम जजों की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर पुनर्विचार की अनुमति भी प्रदान नहीं कर सकते।' जस्टिस गवई ने कहा कि आपने रिपोर्ट की मांग की थी और हाई कोर्ट के चार जजों ने अदालत के समक्ष सही तथ्य रख दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर व्यक्तिगत शिकायतें हो तो वह उन्हें रिपोर्ट दे देगा और जो पीड़ित हैं वे उचित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जस्टिस रमना ने जोर देकर कहा कि इन प्रक्रियाओं में न्यायपालिका की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

कह के रहेंगे

माधव जोशी

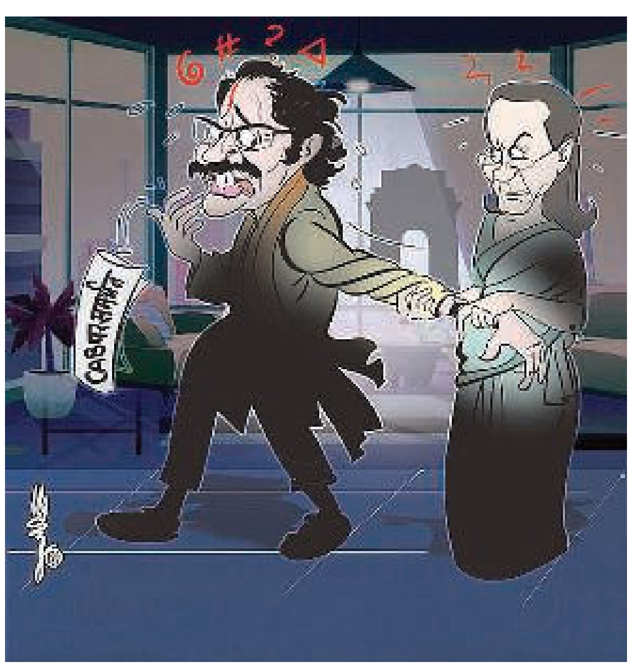

उम्मीद

सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी से लोजपा नेता ने किया हुआ है परहेज, हालांकि नागरिकता संशोधन कानून पर संसद में शाह के संबोधन को ट्विटर अकाउंट पर कर रखा है पोस्ट

अब कैबिनेट में भी पासवान की जगह ले सकते हैं चिराग

राज्य ब्यूरो, पटना

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर लोजपा की चुप्पी का सियासी अर्थ निकाला जा रहा है। लोजपा ने अभी तक सार्वजनिक रूप से सीएए के पक्ष या फिर विपक्ष में कुछ नहीं कहा है। यह समझा जा रहा कि मौन रहकर लोजपा ने इसे अपनी सहमति दे रखी है। सियासी हलके में इस बात की चर्चा है कि रामविलास पासवान स्वास्थ्य वजहों से जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट से मुक्ति पा सकते हैं। उनकी जगह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में लोजपा किसी तरह की टिप्पणी के साइड इफेक्ट नहीं झेलना चाह रही है।

चिराग पासवान और रामविलास पासवान नियमित रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। ट्वीट कर छोटे से बड़े मसले पर दोनों अपनी राय रखते रहे हैं, पर सीएए का मामला जब से आया है, इस मसले पर दोनों ने परहेज किया है। हालांकि चिराग ने सीएए मसले पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का वीडियो क्लिप अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किया हुआ है।

चिराग पासवान। फाइल

बतौर एक्टर फ्लॉप रहे थे चिराग

लोक जनशक्ति पार्टी की दूसरी पीढ़ी की अगुआई कर रहे चिराग पासवान की राजनीति में पहचान रामविलास पासवान के बेटे के रूप में है। वैसे चिराग ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह यहां सफल नहीं हो सके। एक ही फिल्म फ्लॉप होने के बाद वह बॉलीवुड को छोड़कर राजनीति में चले आए और पिता की पार्टी का काम संभालने लगे।

लोकसभा चुनाव में लोजपा की सारी बातें एनडीए में मान ली गई थीं। उसके छह सांसद हैं। तय हुआ था कि रामविलास पासवान लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हें असम से राज्यसभा भेजा जाएगा। पर बाद में बिहार में सीट उपलब्ध हो जाने के बाद उन्हें बिहार से ही राज्यसभा भेजा गया। केंद्र में मंत्री पद भी बरकरार रहा। ऐसे में लोजपा के सामने धर्मसंकट यह है कि वह एनडीए में अपने पुराने स्टैंड के कारण कोई विवाद उत्पन्न नहीं करे। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी होना है। यह भी चर्चा है कि रामविलास पासवान को एनडीए के संयोजक का पद देकर सम्मान दे दिया जाएगा। अगर लोजपा कोई स्टैंड लेती है, तो इसका असर उसकी सेहत पर पड़ेगा इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

यास्मीन कपूर को मिली जमानत

नई दिल्ली : कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की सहयोगी और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित यास्मीन कपूर को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाकर निजी विमान कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप में ईडी ने गत 3 अक्टूबर को कपूर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दीपक तलवार और यास्मीन कपूर के अलावा कई अन्य आरोपित हैं। अदालत ने जमानत मंजूर करने के साथ ही कपूर पर कई पाबंदियां भी लगाई। कहा कि दीपक तलवार या अन्य किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की जाए। (जासं.)

DR. RAMASWAMY IAS ACADEMY
FREE COACHING
IAS, SSC, JUDICIARY AND GROUP-A, B & C
SC/ST/EWS/OBC DELHI RESIDENCE ONLY
9350933144, 9958589406
1418, Dr. Mukherjee Nagar, 4th Floor, Main Road, New Delhi-09
4-A/17, Old Rajendra Nagar Main Market, New Delhi-110060

16 दिसंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 15 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 221 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 75 उम्मीदवार दागी हैं, जबकि 60 करोड़पति हैं।

‘गंगा निर्मल, नहीं तो आचमन कैसे करतीं प्रियंका’

चुनावी रण ▸ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमहल व गोड्डा में कीं सभाएं

कहा, गंगा सफाई अभियान भाजपा की देन

▸ बोले, राजमहल–मानिकचक के बीच गंगा पर बनेगा पुल

▸ साहिबगंज में रिवर पोर्ट निर्माण का भी दिया आश्वासन

डॉ. प्रणेश, राजमहल (साहिबगंज)

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को झारखंड के राजमहल व गोड्डा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। गोड्डा में उन्होंने कहा कि गंगा सफाई अभियान भाजपा सरकार की देन है। गंगा निर्मल हो चुकी है। इसी का उदाहरण है कि प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान नाव पर सवार होकर प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा नदी पर पहुंची थीं और जल आचमन किया। अगर गंगा निर्मल न होतीं, तो प्रियंका चल आचमन कैसी करतीं।

राजमहल से भाजपा प्रत्याक्षी अनंत कुमार ओझा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए उन्होंने कहा, यहां के विधायक ओझा ने कई बार उनसे मिलकर राजमहल-मानिकचक के बीच गंगा पर पुल निर्माण कराने का अनुरोध किया है, जिसे वे जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने साहिबगंज में भी रिवर पोर्ट निर्माण कराने की घोषणा करते हुए कहा कि सड़कें बन रही हैं। वाहन नया हो, तो चालक भी अनुभवी चाहिए। उन्होंने दोनों जगह अपने भाजपा प्रत्याशी को अनुभवी चालक बताते हुए कहा कि वे आपको सुरक्षित आगे पहुंचा सकते हैं।

झारखंड के राजमहल में चुनावी सभा को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जागरण

मां गंगा के दर्शन किए बिना कैसे जा सकता हूं : निर्धारित समय से करीब आधा घंटा देरी से राजमहल पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे तो राजमहल की निर्मल व अविरल गंगा को देखने चले गए थे। दरअसल, उनके विभाग द्वारा गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की गई। इसके तहत यहां भी काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा, राजमहल आया हूं, तो मां गंगा के दर्शन किए बिना कैसे जा सकता हूं।

भारत की विरासत संरक्षित रखने का दम सिर्फ भाजपा में : योगी

जागरण संवाददाता, गिरिडीह/ देवघर

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

▸ उप्र के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, राजद और झामुमो पर किया प्रहार

▸ कहा, राम मंदिर निर्माण का कर रहे थे विरोध

भाजपा के फायर ब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को झारखंड के देवघर के मधुपुर और गिरिडीह के बगोदर व बेंगाबाद में चुनावी सभाएं कीं। उन्होंने कहा, भाजपा ही वह पार्टी है, जो भारत की विरासत को संरक्षित रखने का दम रखती है।

गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय से आधा किमी दूर सर्कस मैदान में जयश्री राम एवं भारत माता के जयकारे के बीच योगी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अनुच्छेद 370 का राम नाम सत्य कर दिया गया है। कांग्रेस, झामुमो, राजद जैसी पार्टियां राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रही थीं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को विकास और गरीबों के कल्याण के लिए मील का पत्थर बताया। इसके पूर्व योगी ने बगोदर में चुनावी सभा को संबोधित किया।

देवघर के मधुपुर में योगी ने भाजपा प्रत्याशी राज पलिवार के पक्ष में सभा की। कहा, भारत की विरासत संरक्षित रखने का दम सिर्फ भाजपा में है। कांग्रेस, राजद और झामुमो देश की संस्कृति व धार्मिक विरासत संरक्षित नहीं कर सकते, इससे उनकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। हम आतंकवाद व नक्सलवाद को जड़ से साफ करेंगे। मधुपुर बाबा बैद्यनाथ की धरती है, वे अयोध्या, मथुरा और काशी होते हुए यहां पहुंचे हैं। यह उनका सौभाग्य है। अनुच्छेद 370 को हटाने व नागरिकता संशोधन विधेयक का श्रेय मोदी सरकार को है। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा नहीं करती है।

भाजपा ने जुमलों में ही निकाल दिए पांच साल : सचिन पायलट

जागरण संवाददाता, धनबाद

▸ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने धनबाद के भूली और झरिया में की चुनावी जनसभा

भाजपा ने पांच साल जुमलों में ही निकाल दिए। यह सरकार भाषणों व घोषणाओं तक सिमट गई है। जनता जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, उस महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करती। विकास से ज्यादा चेहरा चमकाने और ढिंढोरा पीटने पर ध्यान है। जाति-धर्म के मुद्दों पर लोगों को बांटकर और झूठ फैलाकर वोट मांगे जा रहे हैं। यह बातें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहीं। वह शुक्रवार को धनबाद के भूली और झरिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री रघुवर दास पर निशाना साधते हुए सचिन ने कहा कि पांच साल में रघुवर दास की सरकार ने विकास का सिर्फ सपना दिखाया। झारखंड में बेरोजगारी और पलायन का बोलबाला है। इसे दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास दागियों के खास हैं। प्याज सवा सौ रुपये किलो है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते।

उन्होंने कहा कि झारखंड से भाजपा सरकार का जाना तय है। पूछना चाहता हूं कि राज्य व केंद्र की सरकार से कि पिछले पांच वर्षों में देश व राज्य में कितने कल-कारखाने खोले, कितनों को रोजगार दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया कि वह जो चाहेगी, वही होगा। कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा अपने वादे को पूरा करती है। इसलिए हमें मौका दें और इस बार झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार बनाएं।

सचिन पायलट फाइल

फड़नवीस ने कहा, सबसे बड़ी अपेक्षा तोड़ी उद्धव ठाकरे ने

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का कहना है कि अपेक्षा तोड़ने का जैसा काम उद्धव ठाकरे ने किया है, वैसा देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें यह उम्मीद कतई नहीं थी कि सत्ता के लिए शिवसेना बालासाहब ठाकरे के विचारों से किनारा कर कांग्रेस के साथ भी जा सकती है।

सरकार जाने के बाद शुक्रवार को पहली बार एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अतिविश्वास था कि शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती है। हालांकि, उद्धव बार-बार कह रहे थे कि उन्होंने अपने पिता बालासाहब ठाकरे को वचन दिया था कि वह महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य पाने के लिए वह अपने पिता के ही विचारों की तिलांजलि देकर कांग्रेस के साथ सरकार बना लेंगे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। फड़नवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन ही सभी विकल्प खुले होने की बात कह दी थी। हमें उम्मीद थी कि देर हो रही है, लेकिन बात बन जाएगी। हमारा अंदाजा यहां चूक गया। साथ मिलकर लड़ने के बाद छोड़ देने का इतिहास इससे पहले देश में नहीं मिलता। वह यह भविष्यवाणी करने से भी नहीं चूके कि कांग्रेस-राकांपा के साथ मिलकर बनी शिवसेना की अगुआई वाली सरकार अपने अंतर्विरोधों के कारण ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अजीत पवार के साथ मिलकर बनी अपनी 80 घंटे की सरकार पर फड़नवीस ने कहा कि अजीत ने उन्हें बताया था कि भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से चर्चा की थी। उन्होंने अपनी पार्टी के 36 विधायकों के भी अपने साथ होने की बात कही थी। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी के ज्यादातर लोगों का मानना है कि शिवसेना-कांग्रेस की खिचड़ी के साथ जाना उचित नहीं होगा, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से बात कर उनके साथ सरकार बनाई गई, लेकिन जब उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की इच्छा जताई तो हमने भी जोड़तोड़ करने की जगह इस्तीफा देना ही उचित समझा। हार के बाद पार्टी में दिखाई दे रहे असंतोष पर फड़नवीस ने कहा कि एकनाथ खड़से का टिकट राज्य नेतृत्व ने नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व ने काटा था, लेकिन उनकी पुत्री को टिकट दिया गया था। पंकजा मुंडे को भी अपनी बहन सरीखी बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार बनी होती तो यह सब नहीं होता। सरकार नहीं बन सकी, इसलिए इस प्रकार के विचार उठने शुरू हो गए हैं।

सरयू राय के सौंपे इस्तीफे को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री रघुवर को भिजवाया

राज्य ब्यूरो, रांची

भाजपा से बागी होकर जमशेदपुर पूर्वी से मुख्यमंत्री रघुवर दास के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सरयू राय ने शुक्रवार को विधिवत रूप से मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इधर, राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन सचिवालय ने शुक्रवार शाम को ही उनका त्यागपत्र मुख्यमंत्री रघुवर दास को यथोचित और आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। अब अगर सीएम इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो वे इसे राजभवन को भेजेंगे और इस्तीफा स्वीकार करने की अनुशंसा करेंगे।

राज्यपाल को महज डेढ़ लाइन के सौंपे गए त्यागपत्र में सरयू राय ने इस्तीफा देने के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ तात्कालिक प्रभाव से अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध राज्यपाल से किया। इस्तीफा देकर राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा देना उनका नैतिक दायित्व था। उन्होंने यह भी कहा कि सही तो यह होता कि मुख्यमंत्री स्वयं उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देते। सरयू राय के अनुसार, उन्होंने 17 नवंबर को ही फैक्स व ईमेल से अपना इस्तीफा राजभवन को भेज दिया था, लेकिन राजभवन ने 11 दिसंबर को स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा राजभवन को मिला ही नहीं था।

रांची स्थित राजभवन में शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपते सरयू राय। जागरण

विधानसभा की सदस्यता से सरयू राय के इस्तीफे को विधानसभा सचिवालय ने अस्वीकार कर दिया है। इस बाबत विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने सरयू राय को पत्र भेजकर सूचित किया है। पत्र में उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि फैक्स से त्यागपत्र नियमों के आलोक में स्वीकार करने योग्य नहीं है। सरयू राय ने बीते 17 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष को फैक्स के जरिये त्यागपत्र भेजा था।

कर्नाटक में पांच डिप्टी सीएम बना सकते हैं येदियुरप्पा

▸ सरकार बनाने में मदद करने वाले 11 बागियों को भी बनाना चाहते हैं मंत्री

नई दिल्ली, आइएएनएस : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पांच डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। पहले से तीन डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वह और दो उप मुख्यमंत्री चाहते हैं। यही नहीं जिन बागियों की मदद से वह मुख्यमंत्री बने थे, उनमें से 11 को अपने मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं। येदियुरप्पा अगले हफ्ते दिल्ली आने वाले हैं और माना जा रहा है कि वह अपने इन प्रस्तावों पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अनुमति लेने की कोशिश करेंगे।

अगर पार्टी अध्यक्ष येदियुरप्पा को और दो डिप्टी सीएम बनाने की अनुमति दे देते हैं तो पांच उप मुख्यमंत्रियों वाला भाजपा शासित कर्नाटक पहला राज्य होगा। इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पांच डिप्टी सीएम बनाए हैं।

येदियुरप्पा बागियों को उनके किए के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं। इन बागियों के चलते ही वह पूर्व की कांग्रेस-जदएस सरकार को गिराने में सफल रहे थे और खुद मुख्यमंत्री बने थे। उप चुनाव में भाजपा ने इन बागियों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 12 जीत कर भी आए हैं। अब इनमें से वह 11 को मंत्री बनाना चाहते हैं।

इस साल अगस्त में येदियुरप्पा ने गोविंद मक्थप्पा कारजोल, अश्वत नारायण सीएन और लक्ष्मण संगप्पा सवादी को डिप्टी सीएम बनाया था। अब कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण साधने के लिए वो दो और डिप्टी सीएम नियुक्त करना चाहते हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि दो में से एक डिप्टी सीएम अनुसूचित जनजाति का होगा।

येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। वह सभी प्रमुख जातियों को खुश कर अपना जनाधार भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर दो में से एक एसटी और एक कुरुबा समुदाय का डिप्टी सीएम बन जाता है तो वह अपने पांच उप मुख्यमंत्रियों के जरिये ही राज्य की 70 फीसद आबादी को प्रतिनिधित्व दे देंगे।

बीएस येदियुरप्पा फाइल

हरियाणा–उत्तर प्रदेश सुलझाएंगे यमुना से लगती जमीन और नहरी पानी के मसले

सुधीर तंवर, चंडीगढ़

▸ लखनऊ में आज सीएम मनोहर और योगी के बीच बैठक में होंगे अहम समझौते

▸ राजस्व, सिंचाई, जल संसाधन, परिवहन से जुड़े मुद्दों पर होगा मंथन

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने और नए समझौतों के दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाथ बढ़ाए हैं। शनिवार को लखनऊ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठेंगे तो मुख्य एजेंडे में यमुना से लगती दोनों राज्यों की करीब दस हजार एकड़ कृषि भूमि होगी। इस जमीन को लेकर चार दशकों से टकराव चला आ रहा है। बैठक में राजस्व, सिंचाई, जल संसाधन, परिवहन तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बेहतर तालमेल के चलते दोनों राज्यों से जुड़े कई मुद्दे सुलझने की उम्मीद जगी है। विधानसभा चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे।

दोनों राज्यों में यमुना से लगती जमीन और नहरी पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। खासकर कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर लगातार बढ़ते खूनी संघर्ष के चलते दोनों राज्यों की सरकारों ने 44 साल बाद इसे विवाद के पटाक्षेप का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पिछले महीने शीर्ष अधिकारियों की संयुक्त बैठक के बाद दोनों राज्यों के राजस्व अधिकारियों की टीमें पैमाइश में लग गई हैं। जल्द ही सीमा पर पत्थर लगाकर क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाएगा।

1975 में दीक्षित अवॉर्ड के तहत यमुना के साथ पत्थर गाड़े गए थे, जिसके हिसाब से जमीन की पैमाइश की जाती थी। अब यह पत्थर गायब हो चुके हैं। सीमा विवाद को लेकर फरीदाबाद, करनाल, पानीपत और सोनीपत में कई बार किसानों में खूनी संघर्ष हुए हैं। यही वजह है कि विवाद सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के राजस्व अधिकारियों के अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भू स्थानिक आंकड़ा केंद्र चंडीगढ़ के अधिकारियों की मदद से 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना से लगती जमीन क पैमाइश कराई गई।

योगी आदित्यनाथ फाइल

मनोहर लाल फाइल

सुखबीर तीसरी बार संभालेंगे अकाली दल की कमान

जागरण टीम, चंडीगढ़/अमृतसर : शिरोमणि अकाली दल के मौजूदा अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल लगातार तीसरी बार पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। पार्टी के अंदर से उन्हें कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही है। माना जा रहा था कि पार्टी के सामने पैदा हुई चुनौती को देखते हुए पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल फिर कमान संभाल सकते हैं, लेकिन 93 वर्षीय बादल प्रधानी की जिम्मेदारी संभालने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के मुख्यालय तेजा सिंह समुद्री हाल में शनिवार को अकाली दल के नए प्रधान का चुनाव होना है। पंजाब व देश के अलग-अलग राज्यों से पार्टी के करीब 600 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं।

शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है जिससे सुखबीर के अध्यक्ष चुने जाने के रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो। वह दो बार पहले भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। बादल व मजीठिया परिवार का विरोध करने वाले नेताओं की नाराजगी भी इस बार खुलकर सामने नहीं आई है।

रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अगस्ता वेस्टलैंड डील के मनी लांड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चुनौती याचिका का विरोध किया। ईडी ने दो दिसंबर को निचली अदालत द्वारा पुरी को दी गई जमानत को रद करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

हाई कोर्ट में पुरी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुबूतों से छेड़छाड़ एवं गवाहों को प्रभावित करने जैसे तथ्यों को ईडी बार-बार अदालत के सामने पेश कर रही है। उन्होंने दलील दी कि पहले तो जांच एजेंसी ने कहा कि पुरी के पीछे जाने का कारण दुबई से प्रत्यर्पण करके लाए गए राजीव सक्सेना थे और अब वह सक्सेना को अविश्वसनीय बताते हुए उसका स्टेटस व उसे दी गई जमानत रद करने की मांग कर रही है। वहीं, ईडी की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल अमित महाजन ने कहा कि पुरी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह गवाहों को प्रभावित करने के लिए सक्षम हैं। ईडी ने यह भी कहा कि पुरी की अग्रिम जमानत इसी आधार पर खारिज हुई थी।

मोजर बेयर कंपनी से जुड़े बैंक लोन घोटाले मामले में रतुल पुरी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। पुरी को घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जमानत मिली है। हालांकि, रतुल पुरी सीबीआइ के केस में न्यायिक हिरासत मे हैं। विशेष अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि पुरी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। जांच एजेंसी ने पुरी को गत 20 अगस्त को गिरफ्तार था।

रतुल पुरी फाइल

विधायकों की नाराजगी में लटक सकता है पंजाब कैबिनेट का विस्तार

कैलाश नाथ, चंडीगढ़ : पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक का असर कैबिनेट के विस्तार पर पड़ सकता है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट का विस्तार करके अपने पुराने विश्वासपात्र राणा गुरजीत सिंह को पुनः कैबिनेट में लाना चाहते है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार और गहरी होती जा रही है। इसे देखते हुए कांग्रेस सरकार कैबिनेट विस्तार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे राणा गुरजीत सिंह को पुनः कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री इस संदर्भ में पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में कैबिनेट से बाहर जाने वाले राणा गुरजीत सिंह की जांच की रिपोर्ट भी सोनिया गांधी ने मंगवाई थी। हालांकि, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से कैप्टन को हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि वर्तमान में पंजाब में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार का जोखिम नहीं उठा सकते है।

एक माह से पटियाला जिले के विधायक सरकारी कामकाज पर सवाल उठाते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले से संबंधित ये विधायक खुल कर बगावती बयान जारी कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने सरकार के कामकाज पर सीधे-सीधे अंगुली उठाई है। वहीं, पूरी पार्टी में इस बात को लेकर रोष है कि कांग्रेस सरकार में ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि कांग्रेस विधायकों व नेताओं की नहीं चलती है।

कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी इस बात को लेकर खासे नाराज चल रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक इस बगावती सुर को शांत करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, तो यह बगावत और बढ़ सकती है। पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 18 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा इस्तीफा देने के बाद से ही एक मंत्री का पद खाली पड़ा हुआ है।

दावेदारी

भाजपा के सांगठनिक चुनाव दिलचस्प मोड़ पर, अजय भट्ट, नवीन चंद्र दुम्का, केदार जोशी, बंशीधर भगत, कैलाश पंत दावेदार

जिसने साधा संतुलन, वही बनेगा उत्तराखंड भाजपा का मुखिया

विकास धूलिया, देहरादून

उत्तराखंड भाजपा के सांगठनिक चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। मंडल और जिलाध्यक्षों के बाद अब पूरी कवायद प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव पर सिमट गई है। 30 दिसंबर तक उत्तराखंड भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में सांसद, विधायक से लेकर संगठन से जुड़े पदाधिकारी और मौजूदा सरकार में मंत्री तक मैदान में खम ठोक रहे हैं। यह लगभग तय माना जा रहा है कि संगठन के मुखिया का पद फिर कुमाऊं मंडल के हिस्से ही जाएगा।

मिशन 2022 फतह करने के लिए उत्तराखंड में भाजपा संगठन की बागडोर किस दिग्गज को सौंपी जाएगी, अब यह जल्द सामने आने जाएगा। यूं तो उत्तराखंड के अलग राज्य बनने से पहले ही अविभाजित उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में भाजपा की जड़े खासी गहरी रही हैं, लेकिन पिछले साढ़े पांच सालों के दौरान पार्टी अजेय नजर आ रही है। लगातार दो लोकसभा चुनावों में पांचों सीटों पर जीत और विधानसभा चुनाव में तीन-चौथाई से ज्यादा बहुमत भाजपा के स्वर्णिम सफर को बयां करते हैं। इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनावों में भी भाजपा का ही वर्चस्व रहा।

यही वजह है उत्तराखंड में संगठन के मुखिया पद को लेकर दावेदारों की कतार खासी लंबी है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष व नैनीताल से सांसद अजय भट्ट फिर दावेदारी पेश कर रहे हैं। नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से विधायक नवीन चंद्र दुम्का को भी अध्यक्ष पद की होड़ में आगे बताया जा रहा है। इनके अलावा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व दायित्वधारी केदार जोशी, नैनीताल जिले की कालाढूंगी सीट के विधायक व पूर्व मंत्री बंशीधर भगत और पूर्व प्रदेश मंत्री कैलाश पंत भी दावेदारों की कतार का हिस्सा हैं। दरअसल, अध्यक्ष पद के फैसले में सबसे अहम भूमिका क्षेत्रीय और जातीय संतुलन की रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल से हैं और राजपूत हैं, लिहाजा संतुलन के लिहाज से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद कुमाऊं मंडल और ब्राह्मण नेता के हिस्से जाएगा। अजय भट्ट, नवीन दुम्का, केदार जोशी, कैलाश पंत और बंशीधर भगत इस पैमाने पर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री धनसिंह रावत व प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी को भी अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा है लेकिन इनका नंबर उसी स्थिति में आएगा, अगर पार्टी क्षेत्रीय व जातीय संतुलन को दरकिनार कर दे।

अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी : प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लाबिंग तेज हो गई है। दावेदार अब अंतिम चरण में देहरादून से दिल्ली की दौड़ में जुट गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दावेदारों के साथ ही उनके समर्थक विधायक और संगठन के पदाधिकारी या तो दिल्ली पहुंचे हैं या फिर दिल्ली में आलाकमान तक अपने संपर्कों के जरिये अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि 20 दिसंबर के बाद पार्टी नेतृत्व अपने दो वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड भेज कर प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों को लेकर रायशुमारी करेंगे।

उत्तराखंड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय। फाइल

चार जिलाध्यक्षों पर अभी भी पेच

सांगठनिक चुनावों के तहत भाजपा 14 में 10 जिलों के जिलाध्यक्षों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन चार में अभी भी पेच फंसा हुआ है। पार्टी सूत्रों के अनुसार देहरादून महानगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी व ऊधमसिंहनगर के जिलाध्यक्षों के नाम करीब–करीब फाइनल हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रीय समेत अन्य समीकरणों को भी देखा जा रहा है। इस कारण ही इनके एलान में विलंब हो रहा है।

केंद्र ने मानी मप्र की मांग मिलेगा 2.88 लाख टन यूरिया का अतिरिक्त कोटा

राज्य ब्यूरो, भोपाल : केंद्र सरकार ने आखिरकार मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की बात को मानते हुए दो लाख 88 हजार मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त कोटा जारी करने का फैसला किया है। अब प्रदेश को मांग के अनुरूप 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही यह भी बताया कि दो-तीन दिन में 15 रैक यूरिया राज्य को मिल जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार को वितरण व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश भी दिया है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तोमर को पत्र लिखकर रबी सीजन के लिए प्रदेश की मांग 18 लाख मीट्रिक टन के अनुरूप यूरिया देने की बात उठाई थी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 15 लाख 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया देने पर ही सहमति जताई थी। दो लाख 60 हजार मीट्रिक टन यूरिया की कटौती किए जाने के साथ ही आपूर्ति भी लक्ष्य से कम हो रही थी।

7 राज्य हैं भारत के पूर्वोत्तर में। इन्हें सात बहनों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, असम शामिल हैं। इनमें से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में ही इनर लाइन परमिट लागू है।

नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

बड़ा मामला ▶ जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा व अन्य ने दायर की याचिकाएं

नए कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद करने की मांग की गई

▶ इसे अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करने वाला भी घोषित करने का अनुरोध किया है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी है। शुक्रवार को इन दोनों के अलावा भी कई याचिकाएं दाखिल की गईं। करीब आधा दर्जन दाखिल याचिकाओं में नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद करने की मांग की गई है।

जयराम रमेश ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए उसे रद करने की मांग की है। यह भी कहा है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के सर्बानंद सोनोवाल मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लंघन करता है इसलिए इसे रद किया जाए। जयराम रमेश ने इसे अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करने वाला भी घोषित करने का अनुरोध किया है, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान में प्राप्त बराबरी (अनुच्छेद 14) और जीवन (अनुच्छेद 21) के अधिकारों का

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

सीधा उल्लंघन करता है। इस कानून को तैयार करने में संयुक्त संसदीय समिति की 7 जनवरी 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। इसके अलावा यह कानून केंद्र सरकार, आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और आल असम गण संग्राम परिषद (एएजीएसपी) के बीच 15 अगस्त 1985 को हुए असम समझौते में शामिल विदेशी नागरिक मुद्दे का उल्लंघन करता है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस कानून के जरिए मूल कानून में संशोधन करके अवैध रूप से देश में घुसे लोगों (घुसपैठिए) की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए देश में निवास करने की अवधि घटा दी गई है।

यह कानून भेदभाव करता है क्योंकि इसमें मनमाने तरीके से सिर्फ तीन देशों के छह धर्मावलिंबयों को शामिल किया गया है और विशेषतौर पर एक धर्म और भाग को छोड़ दिया गया है। इस कानून में भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया है जबकि कानून के समक्ष समानता मौलिक अधिकार है।

इन्होंने भी दाखिल कीं याचिकाएं

जयराम के अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, आसू, पीस पार्टी, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन अगेंस्ट हेट, एहतशाम हाशमी और सिब्योसिस के ला स्टूडेंट, जन अधिकार पार्टी, असम में नेता विपक्ष देबब्रत और वकील एमएल शर्मा ने भी शीर्ष अदालत में शुक्रवार को याचिकाएं दाखिल की। इसके अलावा केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गुरुवार को ही याचिका दाखिल कर दी थी।

भारत के नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र रख रहा नजदीक से नजर : गुतेरस

▶ महासचिव के प्रवक्ता बोले, जनता की नाराजगी से हैं वाकिफ

▶ यूएनएचआरसी ने कहा, नए कानून में मुसलमानों से भेदभाव

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस के प्रवक्ता ने बताया कि भारत के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उपजे हालात पर वह काफी नजदीक से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि यूं तो इस वैश्विक निकाय के वैश्विक मानवाधिकार घोषणापत्र समेत कई मूलभूत सिद्धांत हैं, लेकिन इन्हें निरंतर आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने संवाददाताओं से कहा कि वह भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन बिल के पारित होने से वाकिफ हैं। वहां की जनता की नाराजगी से भी वह वाकिफ हैं। और वह इन चिंताओं पर नजर रखते हुए हालात का विश्लेषण कर रहे हैं।

इस बीच रायटर के अनुसार, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने भारत में नए नागरिकता कानून पर चिंता जताई है। उसने इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाला बताया है। यूएनएचआरसी के प्रवक्ता जरमी लारेंस ने कहा कि वह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा।

ध्यान रहे कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पड़ोसी इस्लामिक देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय नागरिकता के हकदार यह वह अल्पसंख्यक हैं जो पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए थे। अब इन लोगों को अवैध आव्रजक के बजाय कानून सम्मत तरीके से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।

नागरिकता संशोधन बिल (कैब) को बुधवार को राज्यसभा और सोमवार को लोकसभा से पारित किया जा चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद गुरुवार देर रात को यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के मुताबिक इन छह समुदायों के शरणार्थियों के भारत में पांच सालों तक रहने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। पहले यह शर्त 11 सालों तक रहने की थी।

हिंसा के कारण कई देशों ने अपने नागरिकों को किया आगाह

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : पूर्वोत्तर राज्यों में हालात को देखते इजरायल, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे फिलहाल भारत के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जाने से बचें।

ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक संक्षिप्त विज्ञप्ति में कहा गया है, 'नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खास तौर पर असम और त्रिपुरा में हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में वहां जाने वालों को एहतियात बरतनी चाहिए।' फ्रांस ने अपने नागरिकों को पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा के साथ ही प्रदूषण की वजह से दिल्ली जाने को लेकर भी आगाह किया है।

पूर्वोत्तर में असंतोष बरकरार, कई जगहों पर कर्फ्यू

नई दिल्ली, प्रेट्र/एएनआइ : संसद से पारित होने के बाद कानून बन चुके नागरिकता संशोधन का विरोध अभी तक जारी है। पूर्वोत्तर के कई नेताओं ने जहां असंतोष जताया है, वहीं दक्षिण के दो राज्यों में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। असम एवं पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन और हिंसक हो गया है। स्थिति संभालने के लिए कई जगहों पर सेना तैनात की गई और कर्फ्यू लागू किया गया है।

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि राज्य में स्थिति आपातकाल के समय से भी ज्यादा गंभीर है। दो लोग मारे गए जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इंटरनेट बंद है, ट्रेनें रुकी हुई हैं और विमान उड़ान नहीं भर रहे। ऐसी स्थिति तो आपातकाल में भी देखने को नहीं मिली थी।

नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता अगाथा के सांगमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे पूर्वोत्तर को संशोधित नागरिकता कानून के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। गुरुवार रात पीएम को लिखे गए पत्र में उन्होंने क्षेत्र में शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए यह मांग की है।

भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान भाइचुंग भुटिया ने संशोधित नागरिकता कानून पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर की तरह सिक्किम को छूट में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिक्किम 1975 में भारत का अंग बना और इस राज्य को अनुच्छेद 371एफ के तहत विशेष प्रावधान हासिल है। हम इस राज्य को भी छूट चाहते हैं। जारी विरोध प्रदर्शन को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कहा।

कलबुर्गी में धारा 144 लागू

कर्नाटक में कलबुर्गी के उपायुक्त ने शुक्रवार को शाम छह बजे तक शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। यह कदम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन टालने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया

द्रमुक की युवा शाखा के सचिव उदयनिधि स्टालिन और करीब 500 पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लोग संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

गुवाहाटी में जरूरी सामान इकट्ठा करने में जुटे लोग

गुवाहाटी, प्रेट्र : पूर्वोत्तर राज्यों असम और मेघालय में हालात सामान्य होने लगे हैं। शुक्रवार को असम के शहर गुवाहाटी से हिंसक घटना की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि वहां कुछ शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर हुए। राज्य के एक अन्य शहर डिब्रूगढ़ और मेघालय की राजधानी शिलांग में कर्फ्यू में ढील दी गई। जबकि गुवाहाटी में बेमियादी कर्फ्यू दूसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन इससे बेपरवाह लोग जरूरी सामान जुटाने में लगे रहे। इसी के चलते किराने की दुकानों, एटीएम और पेट्रोल पंपों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। इस अफरातफरी के कारण कई चीजें बेहद महंगे दामों पर बिक रही हैं। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले।बाहरी लोगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण वाले प्रस्तावित अध्यादेश की मंजूरी मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को मेघालय के राजभवन के बाहर रैली की। लेकिन उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसमें 25 लोग घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया और विरोध रैली निकाली।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जुलूस और तोड़फोड़

जेएनएन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली में कई जमकर प्रदर्शन हुए। बंगाल में कानून के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने विभिन्न स्टेशनों में ट्रेन संचालन ठप कर दिया। रेल पटरी पर टायर जलाने के साथ ही स्टेशनों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ट्रेनों में भी पथराव किया गया।

रेल कर्मचारियों और आरपीएफ जवानों को दौड़ा कर पीटा गया। उलूबेरिया स्टेशन के टिकट काउंटर में उपद्रवियों ने धावा बोलकर करीब चार लाख की नगदी, आठ कम्प्यूटर समेत अन्य सामान लूट लिया। रेलवे ने 26 इएमयू समेत कई पैसेंजर ट्रेनों को रद कर दिया। प्रदर्शनकारियों के तेवर के आगे रेल प्रशासन भी लाचार नजर आया। पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन अंतर्गत बेलडांगा स्टेशन में भी शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को हुजूम पहुंच गया। रेल पटरी पर टायर और फर्नीचर जलाकर ट्रेन संचालन ठप कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्टेशन में तोड़फोड़ और आगजनी की गई।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव करते छात्र। प्रेट्र

प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे आरपीएफ कर्मियों और केबिन मैन को भी पीटा गया। स्टेशन मास्टर कक्ष को आग के हवाले कर दिया गया।

उप्र में भी जबरदस्त प्रदर्शन : उप्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्रों ने चौथे दिन चार घंटे प्रदर्शन किया। छात्रों ने धक्का-मुक्की भी की जिसमें डीएम चंद्रभूषण सिंह गिरने से बचे। कई अन्य जिलों में भी लोग सड़क पर निकल आए। जुमे की नमाज के चलते अलीगढ़ शहर में पुलिस ने खास सर्तकता बरती।

अलीगढ़ में गुरुवार रात 12 बजे से बंद की गई इंटरनेट सेवा शुक्रवार की देर शाम बहाल कर दी गई। सहारनपुर में जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विधेयक के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति न मिलने के कारण तकरीर आदि नहीं हुई। बुलंदशहर, बिजनौर में जमीयत-उलमा-ए-हिंद के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले तकरीर करते हुए शहर काजी जैनुस साजिदीन ने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। आगरा में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के बाजार में सुबह से ही दुकानें नहीं खुलीं। जगह-जगह काले झंडे लगाए गए।

विरोध में उतरे जामिया के छात्र-शिक्षक

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं व शिक्षकों ने मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास करने पर पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाईं तो प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर जमकर पथराव किया। कई छात्र व पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं।

नागरिकता कानून से बढ़ी पाकिस्तान की बौखलाहट

▶ कहा, मुस्लिम विरोधी, पाकिस्तान के साथ किए गए समझौतों का उल्लंघन करता है यह कानून

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान को निशाने पर रखकर भारत में बदले गए नागरिकता कानून से पड़ोसी देश बौखला गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान को अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने की भारत की नसीहत से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। इमरान ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुओं की श्रेष्ठता साबित करने के एजेंडे का अंग बताया था।

इससे पहले मंगलवार को कहा था कि भारतीय संसद में पेश किया गया विधेयक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और पाकिस्तान के साथ किए गए समझौतों का उल्लंघन है। यह आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की ओर सरकार का बढ़ता कदम है। जवाब में भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान को अनुचित और अस्वीकार्य करार दिया था। कहा था कि प्रधानमंत्री खान इस तरह की टिप्पणी करने की जगह अपने देश में अल्पसंख्यकों की दशा में सुधार करें। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि पाकिस्तान को अपने बेरहम ईश निंदा कानून पर विचार करना चाहिए, फिर भारत के अंदरूनी मामले में दखल देना चाहिए। शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश विभाग ने भारतीय प्रवक्ता के बयान को खारिज किया। कहा कि भारत के भेदभावपूर्ण नए नागरिकता कानून का कई मानवाधिकार संगठनों और भारतीय राज्यों में विरोध हो रहा है। इस कानून का चरित्र मुस्लिम विरोधी है।

इसमें पाकिस्तान और यहां की मुस्लिम आबादी पर गलत आरोप लगाए गए हैं। जबकि भारत में भाजपा सरकार आने के बाद से अल्पसंख्यकों खासतौर से मुस्लिमों की स्थिति में लगातार गिरावट आई है। इसे दुनिया भर से संगठनों ने महसूस किया है।

भाजपा देशभर में करेगी कार्यशालाओं का आयोजन

नई दिल्ली, एएनआइ : नागरिकता (संशोधन) कानून के मुद्दे पर लोगों की भ्रांतियों को दूर करने तथा इसके फायदों को बताने के लिए भाजपा ने देशभर में छह जोनल कार्यशालाओं के आयोजन का निर्णय लिया है। इसके तहत लखनऊ में 14 दिसंबर को, दिल्ली व मुंबई में 15 को, बेंगलुरु व कोलकाता में 16 को तथा गुवाहाटी में 18 को कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। भाजपा मुख्यालय की तरफ से सभी प्रदेशों के प्रभारियों, अध्यक्षों, महासचिवों व अन्य को भेजे गए पत्र के अनुसार, 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार, इस कानून के प्रावधानों को जनता तक पहुंचाने के लिए छह जोनल कार्यशालाओं के आयोजन का फैसला किया गया है। इनमें लोगों के सामने यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह कानून किस प्रकार पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाते हुए भारतीय नागरिकता प्रदान करने में मदद करेगा।'

अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा कर रही है कांग्रेस : नितिन गडकरी

▶ केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को देश हित में जरूरी बताया

▶ दुष्कर्म पर राहुल गांधी के बयान को निंदनीय बताया

नीलू रंजन, रांची

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागरिकता संशोधन कानून पर हो रही हिंसा के लिए सीधे तौर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। गडकरी के अनुसार अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा करना कांग्रेस की राजनीति बन गई है। संशोधित नागरिकता कानून को राष्ट्रहित में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे धर्म से जोड़कर राजनीति करना ठीक नहीं है।

झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद वापस लौटते समय दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर कुछ लोगों के मन में संशय जरूर है, सरकार उसे दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रही है, जो ठीक नहीं है। उनके अनुसार इस कानून से देश के मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस इसे ऐसे पेश कर रही है, जैसे यह मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले, इसके लिए अपनी जान देने वाले सभी भारतीय हैं, चाहे उनकी उपासना पद्धति कोई भी हो। कांग्रेस ता राहुल गांधी के 'रेप इन इंडिया' टिप्पणी को दुखद बताते हुए गडकरी ने कहा कि एक पार्टी के इतने बड़े नेता का बयान न सिर्फ शर्मनाक, बल्कि निंदनीय भी है। इस बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी ने इस बयान से न सिर्फ देश, समाज, महिलाओं, लोकतंत्र और राजनीति का अपमान किया है, बल्कि अपनी पार्टी का भी नुकसान किया है। राहुल गांधी को निश्चित रूप से इस बयान को वापस लेना चाहिए।

महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने और हरियाणा में किसी तरह बचाने के बाद भी नितिन गडकरी ने झारखंड में भाजपा की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में रघुवरदास के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए बहुत काम हुआ है और जमीनी स्तर पर इसे देखा जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि झारखंड की जनता इस बार सकारात्मक सोच के साथ मतदान करेगी। झारखंड में पार्टी में मतभेदों और नेताओं में नाराजगी को तरजीह नहीं देते हुए गडकरी ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें कभी-कभी किसी की नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ता है।

मप्र और राजस्थान भी लागू नहीं करेंगे नागरिकता संशोधन कानून

जेएनएन, नई दिल्ली : राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध जारी है। बंगाल, केरल और पंजाब के बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान ने भी इस कानून को लागू करने से इन्कार कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को नया नागरिकता कानून प्रदेश में लागू नहीं करने का संकेत दिया। नई दिल्ली में इंडियन वुमेन प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, 'हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो विभाजनकारी हो।'

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लागू करने से मना कर दिया है। गहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी मुद्दे को लेकर पिछले दो दिन में राज्य के गृह एवं विधि विभाग के अधिकारियों के साथ ही अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। कानून पर सरकार का संसद में समर्थन करने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने राज्य में एनआरसी लागू करने से इन्कार कर दिया है।

जदयू महासचिव ने पूछा-कौन हैं प्रशांत किशोर

राज्य ब्यूरो, पटना

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए-सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट) का विरोध कर रहे प्रशांत किशोर पर शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) आरसीपी सिंह खूब भड़के। बोले-ये अनुकंपा वाले लोग हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे वह पार्टी में काम करने वाले लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे। पर ट्वीट करने और लेख लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से इस मसले पर बात करते हुए आरसीपी ने साफ-साफ कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे जदयू नेताओं के लिए बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। पार्टी का इस मसले पर जो स्टैंड है, वह संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट किया जा चुका है।

आरसीपी ने कहा कि कौन कर रहा है जदयू के स्टैंड का विरोध? गुस्से में यह भी कह डाला कि कौन हैं प्रशांत किशोर? अनुकंपा पर जदयू में आए थे। अगर उन्हें पार्टी का स्टैंड समझ में नहीं आता तो दरवाजा खुला है। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत ने संगठन का कौन सा काम किया

प्रशांत किशोर। फाइल

है। अभी वह किसके लिए काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने जदयू में उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया और आज वह क्या कर रहे हैं, उसे देखिए। आरसीपी से जब प्रशांत किशोर के इस रवैये पर कार्रवाई से संबंधित प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि जब प्रशांत पार्टी में कुछ हैं ही नहीं तो फिर कार्रवाई क्या होगी? अभी हाल में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ है। नई कमेटी कहां गठित हुई कि वह उपाध्यक्ष हो गए? कितने लोगों को उन्होंने पार्टी का सदस्य बनाया।

जदयू नेता ने संविधान के पहले पन्ने को फाड़ा

राज्य ब्यूरो, पटना : नागरिकता संशोधन कानून मसले पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और जदयू नेता उदय नारायण चौधरी ने शुक्रवार को जदयू के संविधान के पहले पन्ने को मीडिया के समक्ष फाड़ डाला। चौधरी ने कहा कि जदयू ने अपने संविधान के पहले पन्ने में यह कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। यह कौन सी धर्मनिरपेक्षता है कि आप नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं? जदयू को समझौता करना पड़ रहा है।

प्रशांत ने फिर किया ट्वीट

राज्य ब्यूरो, पटना : प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पुन: नागरिकता संशोधन कानून पर ट्वीट किया। कहा कि संसद में बहुमत है। न्यायपालिका से अलग अब देश के 16 गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों पर भारत की आत्मा बचाने का जिम्मा है। यह राज्यों पर है जिन्हें इस बिल का क्रियान्वयन कराना है। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहले ही इसे बिल को कह चुके हैं। अब दूसरों की बारी है कि इस मसले पर अपने स्टैंड को वह साफ करें।

जेल जाने को तैयार पर स्वीकार नहीं सीएए और एनआरसी : ममता

जासं, कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वह किसी भी कीमत पर राज्य में एनआरसी और नागरिकता संशोधित कानून लागू नहीं होने देंगी। इसके खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान करते हुए तृणमूल प्रमुख ने बंगाल में नो एनआरसी आंदोलन का आह्वान किया और कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूं लेकिन नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) को स्वीकार कर देश नहीं बटने दूंगी। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब एनआरसी, सब देश की अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट के बादल से लोगों का ध्यान भटकाने को लेकर केंद्र सरकार की साजिश है। दो दिवसीय कार्यक्रम के बाद पूर्व मेदिनीपुर जिले के पर्यटन नगरी दीघा में पत्रकारों से मुखातिब बनर्जी ने कहा कि वे नागरिकता कानून में संशोधन लागू करने के लिए राज्यों को बाध्य नहीं कर सकते।

नागरिकता संशोधन कानून पर अकाली दल के अलग दांव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

नागरिकता संशोधन कानून पर शिरोमणि अकाली दल ने अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा से अलग स्टैंड लेकर सभी को हैरत में डाल दिया है। एक ओर अकाली दल ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल का समर्थन किया है वहीं, पार्टी प्रधान व फिरोजपुर से सांसद सुखबीर सिंह बादल ने अलग बयान दिया है।

सुखबीर कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिम शब्द को शामिल किया जाए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि बाहर से आने वाले किसी मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिल सकती।

साथ में शाह ने यह भी कहा है कि भारत में रहने वाले किसी भी मुस्लिम को डरने की जरूरत नहीं है। बेशक यह बिल संसद में पास हो गया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर सुखबीर ने भाजपा से अलग स्टैंड क्यों लिया है? क्या वह सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी की वजह से ऐसा कर रहे हैं या फिर उनका भाजपा पर दबाव बनाने का कोई दांव है। सुखबीर बादल का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम शब्द का जिक्र बिल में होना चाहिए। जो लोग बरसों पहले अपना घर छोड़कर भारत में आए हैं, उनका घर जरूर भारत में होना चाहिए। इस बात की शिअद हिमायत करता है।

भाजपा पर दबाव बनाए रखने के लिए अलग-अलग तरह के तरीके अकाली दल पहले भी अपनाता रहा है। यह अलग बात है कि बाद में वह भाजपा की लाइन पर ही चलता है। पंजाब में लोकसभा सीटों की अदलाबदली की बात को ही ले लिया जाए। अकाली दल लंबे समय से मांग कर रहा है कि लुधियाना और अमृतसर की लोकसभा सीटों को आपस में बदल लिया जाए।

अभी अमृतसर सीट पर भाजपा लड़ती है, जबकि लुधियाना सीट पर अकाली दल। दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता इस मांग को लेकर एक दूसरे पर शाब्दिक हमले करने से भी बाज नहीं आते, लेकिन बाद में दोनों पार्टियां पुरानी सीटों पर ही लड़ती हैं। अकाली दल वाली नीति कई बार भाजपा भी अपनाती आई है।

लालू ने किया ट्वीट- मायूस मत होना अभी बीमार जिंदा है

राज्य ब्यूरो, पटना : नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के ट्विटर हैंडलर पर उनकी ओर से चार लाइन का एक शेर पोस्ट किया है। शेर है- अभी आंखों की शमाएं जल रही हैं, उसूल जिंदा है, आप लोग मायूस मत होना अभी बीमार जिंदा है, हजारों जख्म खाकर भी मैं दुश्मनों के मुकाबिल हूं, खुदा का शुक्र अब तक दिल-ए-खुद्दार जिंदा है।

लालू प्रसाद के इस पोस्ट के साथ उनके एक पुराने भाषण के वीडियो को भी डाला गया है। उक्त वीडियो में लालू प्रसाद मुसलमानों के लिए बातें कर रहे हैं। इसमें वह कह रहे कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र में रख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं वह भयभीत क्यों हैं?

35 से 40 हजार लोगों के बेरोजगार होने का दावा किया है कश्मीर में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआइ) ने इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से। मांग की गई है कि सरकार जल्द इंटरनेट सेवा बहाल करे।

पहाड़ों पर हिमपात और मैदान में बारिश से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड

मौसम का हाल ▶ उत्तराखंड में दो सौ गांवों का संपर्क मुख्यालयों से कटा, उप्र में गई नौ की जान

कश्मीर का सड़क संपर्क देश से कटा, सैकड़ों वाहन फंसे

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत में गुरुवार को पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई तेज बारिश व ओलावृष्टि के बाद ठंड बढ़ गई है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तो कई इलाकों में दो फुट से लेकर पांच फुट तक बर्फबारी हुई है। वहीं, दिल्ली में भी बारिश से कई रिकॉर्ड टूटे हैं। पालम में बारिश ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तीन दिसंबर 1967 में यहां 33.7 मिमी. बारिश हुई थी जबकि गुरुवार को 40.2 मिमी. बारिश हुई। इससे दिल्ली ही नहीं एनसीआर में भी ठंड बढ़ गई है।

उप्र में ठंड और बारिश से गई नौ की जान : शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। आलू, सरसों आदि फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जहां केवल बारिश हुई है, वहां मसूल और गेहूं की फसल को फायदा पहुंचा है। ठंड से जहां तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं बिजली गिरने से तीन बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई और तीन लोग झुलस गए। बारिश से पेड़ और मकान गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।

पटना में 6 डिग्री गिरा तापमान : पटना में शुक्रवार को बारिश के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवा के कारण अधिकतम तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री और अधिकतम 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

उत्तराखंड में दूसरे दिन भी नहीं थमी बर्फबारी :उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। सीजन में पहली बार मसूरी में भी बर्फ गिरी। इस बीच बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक-रुक कर बर्फबारी होती रही। इससे दो दर्जन संपर्क मार्गों पर भी आवाजाही ठप हो गई है। प्रदेश में करीब दो सौ गांव जिला मुख्यालयों से कट गए हैं।

जम्मू-कश्मीर में आठ दिन से ठप है हवाई सेवा: श्रीनगर, माता वैष्णो देवी भवन, पत्नीटॉप, नत्थाटॉप के अलावा डोडा, भद्रवाह के उच्च पर्वतीय इलाकों में दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी हुई। जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद होने से कश्मीर का सड़क संपर्क देश से कटा रहा। सैकड़ों वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंस कर रह गए हैं। उधर, कश्मीर को जम्मू संभाग से जोड़ने वाला मुगल रोड और श्रीनगर-लेह हाईवे भी बंद है।

हिमाचल में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट: हिमाचल में दो दिन से बर्फबारी व भारी बारिश के कारण जनजीवन ठप हो गया है। प्रदेश की 298 सड़कों पर यातायात थम गया है। डोडरा क्वार सहित ऊपरी शिमला का संपर्क कट गया है। भारी बर्फबारी के कारण 1049 ट्रांसफार्मर बंद है।

बर्फबारी के बीच बरात...: उत्तराखंड में शुक्रवार को चमोली जिले के रामणी गांव से राजेंद्र सिंह नेगी की बरात चरबंग के लिए रवाना हुई, लेकिन बर्फीली राह में बरातियों को खासी मुश्किलें झेलनी पड़ीं। यहां तक कि घोड़ी पर सवार दूल्हे को भी कई स्थानों पर पैदल चलना पड़ा। वह तो गनीमत रही कि रास्ते में बर्फ बहुत ज्यादा नहीं थी, अन्यथा बरात का पहुंचना मुश्किल हो जाता। **साभार –ग्रामीण सूरत सिंह पंवार**

कश्मीर में फंसे लद्दाखियों को निकालने के लिए वायुसेना तैयार

राज्य ब्यूरो, जम्मू

भारी बर्फबारी से श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला पास बंद होने के कारण कश्मीर के सोनमर्ग, गांदरबल और गगनगीर में फंसे लद्दाखियों को निकालने के लिए वायुसेना तैयार हो गई है। केवल मौसम ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। चूंकि मौसम खराब रहने से पिछले आठ दिन से श्रीनगर से कोई उड़ान नहीं भरी जा सकी है। ऐसे में वायुसेना के लिए भी लद्दाख के लोगों को एयरलिफ्ट करना संभव नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला मौका है जब लद्दाख के लोगों की आवाज इतनी जल्दी केंद्र तक पहुंची और रक्षा मंत्रालय ने भी हामी भरने में देर नहीं की। ऐसा लद्दाख के उपराज्यपाल आके माथुर के हस्तक्षेप से संभव हो पाया है। उन्होंने ही गृह मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय से लद्दाख के लोगों को निकालने का आग्रह किया था।

वहीं, दूसरी ओर फंसे यात्रियों को निकालने को लेकर कश्मीर प्रशासन का रवैया उदासीन ही रहा। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान ने साफ कहा कि फंसे लद्दाखियों को लेह और कारगिल भेजना अभी संभव नहीं है। मौसम ठीक होने के बाद ही लद्दाखियों को भेजने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लद्दाखियों को एयरलिफ्ट करने का मुद्दा वायुसेना से उठाना लद्दाख प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि लद्दाख के उप राज्यपाल की ओर से फंसे लद्दाखियों को निकालने के संबंध में उन्हें कोई पत्र मिला है।

जोजिला पास बंद होने से फंसे 300 वाहन

इस बीच, लद्दाख अटानमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्याल पी वांग्लाय का कहना है कि हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि गांदरबल व गगनगीर में फंसे लद्दाख के लोगों को मुश्किलें न आएं। इसके लिए श्रीनगर स्थित कारगिल हाउस के नोडल अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि जोजिला पास बंद होने से करीब 300 वाहन फंसे हुए हैं। इन वाहनों में सवार यात्रियों को कश्मीर के सोनमर्ग, गांदरबल व गगनगीर में ठहराया गया है।

इसी बीच, कश्मीर प्रशासन की ओर से जोजिला पास को अचानक बंद करने से उपजे हालात को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल ने लेह में शुक्रवार को भी प्रशासन के साथ बैठक की। इसमें सलाहकार उमंग नरूला के साथ आयुक्त सचिव रिगजिन सैंफल ने फंसे लद्दाखियों को लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया।

उप राज्यपाल के निर्देश पर लद्दाख प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लद्दाखियों को वहां से अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। शुक्रवार को लद्दाख के आयुक्त सचिव रिगजिन सैंफल ने लद्दाखियों को एयरलिफ्ट करने का मुद्दा वायुसेना से उठाया।

दूसरे बिल को आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक नाम दिया गया

प्रथम पृष्ठ से आगे

आंध्र प्रदेश महिला एवं बच्चों के खिलाफ विशेष अपराध के लिए विशेष कोर्ट विधेयक–2019 का नाम दिया गया है। इसके तहत सरकार को महिला व बच्चों के साथ विशेष अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट की स्थापना का अधिकार होगा। विधेयक में बच्चों के साथ दूसरे यौन अपराधों में भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें सोशल मीडिया के जरिये महिला का पहली बार उत्पीड़न पर दो साल व इसके बाद चार साल की सजा का प्रावधान है। त्वरित सुनवाई के लिए सरकार प्रदेश के सभी 13 जिलों में विशेष कोर्ट का गठन करेगी। इनमें महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों (दुष्कर्म, एसिड अटैक, पीछा करना, ताकझांक करना, सोशल मीडिया पर महिला का उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों) की सुनवाई होगी। राज्य सरकार ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पुलिस दल का गठन करते हुए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। सरकार महिला व बच्चों के साथ अपराध करने वालों का डाटा तैयार करते हुए उसे जांच एजेंसियों व आम लोगों के लिए सार्वजनिक करेगी। गृहमंत्री एम. सुचारिता ने कहा कि बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों में भी सुनवाई की तय अवधि एक साल से घटाकर 21 दिन कर दी गई है।

पाक सेना की गोलाबारी में दो जवान घायल

जासं, राजौरी : पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार शाम फिर नियंत्रण रेखा पर राजौरी के केरी सेक्टर में भारी गोलाबारी की। इसमें भारतीय सेना के दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। देर शाम तक दोनों तरफ से गोलाबारी जारी थी।

पाकिस्तानी सेना पिछले चार दिन से लगातार सीमा पर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों में गोलाबारी कर रही है। गत गुरुवार को भी पाकिस्तान ने पुंछ के किरनी सेक्टर के गांव को निशाना बनाया था। शुक्रवार शाम पाक सेना ने एकाएक राजौरी के केरी सेक्टर में मोर्टार दागने शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाक सेना ने रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर शुरू कर दिए। गोलाबारी के दौरान सेना के दो जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पास के सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं, भारतीय सेना ने भी पाक सेना को करारा जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार, पाक सेना खराब मौसम का लाभ उठाने के लिए गोलाबारी की आड़ में आतंकियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास कर रही है, जिसे सीमा पर तैनात भारतीय सेना सफल नहीं होने दे रही है।

कोलकाता में चार दिवसीय विजय दिवस समारोह शुरू

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत को किया याद

▶ सैन्य बैंड के धुनों ने मोहा मन, हजारों लोग बने ऐतिहासिक क्षण का गवाह

1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में पूर्वी सेना कमान मुख्यालय की ओर से हर साल मनाए जाने वाला विजय दिवस समारोह का शुक्रवार को कोलकाता में भव्य आगाज हुआ। कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर सेना की बैंड टुकड़ी द्वारा प्रस्तुत शानदार मिलिट्री बैंड कंसर्ट के साथ समारोह की शुरुआत हुई। रंग-बिरंगी रोशनी के बीच दुल्हन की तरह सजाए गए ऐतिहासिक प्रिंसेप मेमोरियल पर बैंड टुकड़ी ने पारंपरिक सैन्य बैंड के धुनों को प्रदर्शित कर लोगों का मन मोह लिया और देशभक्ति से ओत-पोत कर दिया।शाम छह से साढ़े सात बजे तक प्रस्तुत किए जाने वाले बैंड कंसर्ट को देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। शानदार सैन्य बैंड के जरिए यहां 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्वी कमान की ओर से हर साल विजय दिवस समारोह के तहत यहां चार दिनों तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 13 से 16 दिसंबर तक होने वाले समारोह के दौरान विविध कार्यक्रम होंगे।

आज सेना के जांबाज दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब

समारोह के तहत 14 व 15 दिसंबर को रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब (आरसीटीसी) ग्राउंड में भव्य मिलिट्री टैटू का आयोजन होगा, जिसमें सेना के जांबाज हैरतअंगेज प्रदर्शन कर अपनी शौर्य व ताकत का परिचय देंगे। शनिवार व रविवार को दोपहर ढाई से चार बजे तक आयोजित होने वाले मिलिट्री टैटू में हेलीकॉप्टर शो, घोड़ा दौड़, डॉग शो, मार्च पास्ट, मोटरसाइकिल करतब आदि का प्रदर्शन कर पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस भव्य कार्यक्रम को आम लोग भी देख सकेंगे, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है।

झारखंड में नक्सलियों के आइईडी धमाके में ग्रामीण की मौत

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : झारखंड के लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल-बीछबिंधी जंगल में गुरुवार देर शाम नक्सलियों के आइईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार आधा दर्जन ग्रामीण सूप बनाने के लिए बांस लेने बुलबुल जंगल गए हुए थे। पुलिस को लक्ष्य कर नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आइईडी बम की चपेट में दो ग्रामीण आ गए। इसमें लातेहार के नरेशगढ़ गांव निवासी एतवा परहिया (35) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि घघरी गांव निवासी सूरज परहिया (22)गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात में चार ग्रामीण बाल-बाल बच गए। धमाके के बाद भाकपा माओवादी का रिजनल कमेटी सदस्य और 15 लाख का इनामी रविंद्र गंझू का शस्त्र दस्ता पहुंच गया। नक्सलियों ने घायलों को काफी देर तक जंगल मे ही बंधक बनाए रखा। नक्सली इस इंतजार में थे कि पुलिस या कोई इनकी सहायता के लिए आता है तो वे बड़ी घटना को अंजाम दे सकें। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो ग्रामीणों को मुक्त कर वहां से चले गए।

जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की तीन और कंपनियां वापस भेजी गईं

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ इन कंपनियों के जवानों को असम और त्रिपुरा में तैनात किया जाएगा

शीतकालीन राजधानी जम्मू से केंद्रीय अर्धसैनिकबलों की तीन और कंपनियों को विशेष विमान से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भेज दिया गया है। इन कंपनियों के जवानों को असम और त्रिपुरा में तैनात किया जाएगा। बीते तीन दिनों में जम्मू-कश्मीर से पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या लगभग 50 हो गई है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीआइएसएफ, एसएसबी और आइटीबी की अतिरिक्त टुकड़ियों को जम्मू-कश्मीर में तैनात किया था। अब हालात में बेहतरी के आधार पर गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को गत माह वापस उनके मूल नियुक्ति स्थलों पर फिर से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गत 25 नवंबर से तीन दिसंबर तक करीब 20 कंपनियों को झारखंड, कर्नाटक समेत पूर्वोत्तर में भेजा गया था। इनके अलावा 30 और कंपनियों को 31 दिसंबर तक भेजा जाना तय हुआ था, लेकिन पूर्वोत्तर में स्थिति को बिगड़ते देख न सिर्फ गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से हटाए जाने वाले अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाई है बल्कि इस प्रक्रिया को तेज भी कर दिया है। गत बुधवार को अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां को रवाना किया गया था और उसके बाद लगभग एक दर्जन कंपनियों को गत गुरुवार को रवाना किया गया है।

जम्मू संभाग में तैनात थीं तीनों कंपनियां : जम्मू से भेजी जाने वाली केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की इन तीनों कंपनियों के तीन सौ जवान जम्मू संभाग के जिला सांबा, कठुआ, राजौरी, उधमपुर व रियासी में तैनात थे। इन सभी को शुक्रवार की सुबह जम्मू एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए भेजा गया है।

प्रतीकात्मक

आतंकरोधी अभियानों पर कोई असर नहीं

अर्धसैनिक बलों को हटाए जाने से आतंकरोधी अभियानों पर किसी तरह के नकारात्मक प्रभाव से इन्कार करते हुए नोडल अधिकारी ने कहा कि जिन सुरक्षाबलों को यहां जुलाई–अगस्त माह के दौरान बुलाया गया था, उन्हें आतंकरोधी अभियानों में नहीं रखा गया था। उन्हें सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए ही बुलाया था। आतंकरोधी अभियानों के लिए तैनात जवानों में कोई कटौती नहीं की गई है।

कश्मीर में दमदमा साहिब गुरुद्वारा होगा स्थानांतरित

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

अक्सर सड़क विस्तारीकरण में धार्मिक स्थल आने पर भारी हल्ला शुरू हो जाता है, लेकिन कश्मीर में सिख समुदाय ने मिसाल कायम की है। श्रीनगर-बारामुला मार्ग पर दमदमा साहिब गुरुद्वारे को दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति राजी हो गई है। प्रशासन ने गुरुद्वारे के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी है।

सड़क चौड़ीकरण की परियोजना 2007 में हुई थी शुरू: 120 किलोमीटर लंबे श्रीनगर-बारामुला- उड़ी मार्ग को चौड़ा करने की परियोजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। सड़क चौड़ा करने का जिम्मा सड़क संगठन ने संभाला था, लेकिन भूमि अधिग्रहण, श्रमिकों की उपलब्धता समेत कई मुद्दों के चलते सड़क का काम कई जगहों पर रुक गया। छह साल तक यह काम बंद रहा। 2017 में दोबारा गति दी गई।

श्रीनगर के बाहर परिंपोरा-नारबल सेक्शन में भूमि अधिग्रहण के मामलों के चलते काम नहीं हो पा रहा था। सबसे ज्यादा दिक्कत जैनकोट में सड़क किनारे गुरुद्वारा दमदमा साहिब की जमीन को लेकर हो रही थी। यह गुरुद्वारा सड़क के बीच आ रहा था। सड़क चौड़ा करने के लिए इसका एक हिस्सा ढहाने की जरूरत थी। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने गुरुद्वारे की जमीन के अधिगृहण के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर रखी थी। वर्ष 2015 से मामला अदालत में चल रहा था। सड़क का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था।

सिख समुदाय के आभारी हैं

जिला उपायुक्त (डीसी) श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मामले को कोर्ट के बाहर हल करने की कोशिश की और कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि हम सिख संगत के आभारी हैं कि उन्होंने इस मामले में पूरा लचीला रवैया अपनाते हुए आम लोगों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए गुरुद्वारे की जमीन देने पर सहमति दे दी। अब इस जगह संबंधित निर्माण एजेंसी भी काम शुरू कर चुकी है।

छत्तीसगढ़ के सारकेगुड़ा में सुरक्षा बलों ने चलाई थीं 298 राउंड गोलियां

नईदुनिया, जगदलपुर

▶ एनआइए की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ फोर्स ने चलाई थीं गोलियां

▶ न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल

सारकेगुड़ा की पुलिस जांच में कोई गड़बड़ी नहीं थी। कोर्ट में केस को साबित करना पड़ता है। थोड़ा भी संदेह हो तो न्यायालय आरोपित को बरी कर देता है। नक्सल मामलों में सजा की दर इसीलिए कम होती है क्योंकि साबित करना आसान नहीं होता। न्यायिक आयोग ने जांच के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को दी हैं। अभी शासन स्तर से इसमें आगे की कार्रवाई के संबंध में कोई निर्देश नहीं आया है।
–सुंदरराज पी, आइजी बस्तर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में नक्सली मुठभेड़ के नाम पर 17 ग्रामीणों की हत्या की बात न्यायिक जांच में सामने आने के बाद अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट भी खंगाली जाने लगी है। बीजापुर और दंतेवाड़ा कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच 1 सितंबर 2015 को यह मामला एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को सौंपा गया था।

एनआइए की विशेष अदालत ने 7 जुलाई 2017 को मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार दो कथित नक्सलियों को रिहा करने के आदेश दिए थे। एनआइए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक सारकेगुड़ा में 296 राउंड गोलियां चली थीं। जस्टिस वीके अग्रवाल के नेतृत्व वाले विशेष न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 30 गोलियां एके-47 से चलाई गईं जबकि बाकी अन्य हथियारों से। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि सारकेगुड़ा में सिर्फ फोर्स ने गोलियां चलाईं जबकि एनआइए कोर्ट में जो मामला चला उसमें मौके से भरमार बंदूक, छर्रा, डेटोनेटर आदि की बरामदगी दिखाई गई है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच की सत्यता संदेह के दायरे में आ गई है।

सीजेएम कोर्ट बीजापुर और फिर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनआइए एक्ट अनुसूचित अपराध बस्तर को सौंपी गई पुलिस की रिपोर्ट में घटनास्थल से बरामद सामग्री की सूची सौंपी गई है। इसमें भरमार बंदूक, एक नग टिफिन बम, एक नग पाइप बम, काले रंग का पिठ्ठू बैग, हरे रंग की शर्ट पेंट, एक वायरलेस सेट, डेटोनेटर, फ्यूज, डायरी, नक्सली साहित्य, बारूद, तीर-धनुष, एके-47 रायफल के 23 और इसांस रायफल के 18 नग खोखे, भरमार बंदूक के छर्रे मिलने की बात कही गई है। इधर, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में ग्रामीणों की बैठक में नक्सलियों की मौजूदगी का दावा खारिज करने और ग्रामीणों की ओर से गोलीबारी नहीं किए जाने बल्कि फोर्स पर ग्रामीणों के ऊपर अकारण गोलीबारी करने संबंधी तथ्य सामने आए हैं। आयोग ने रिपोर्ट में ग्रामीणों की बैठक में नक्सलियों की मौजूदगी से भी इन्कार किया है ऐसी स्थिति में घटनास्थल से नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्रियां कहां से मिली, इसे लेकर संदेह गहरा गया है। उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में 28-29 जून को हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ में 17 ग्रामीण मारे गए थे। विशेष न्यायिक जांच आयोग ने 17 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है।

शिरडी से लापता हुए 88 लोग कोर्ट को मानव तस्करी का संदेह

▶ बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने दिए जांच के आदेश

▶ लापता श्रद्धालुओं में ज्यादातर महिलाएं

मुंबई, प्रेट्र : शिरडी से एक साल में 88 से भी ज्यादा लोगों के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता लोगों में कुछ का तो पता चल गया, लेकिन बाकी की कोई जानकारी नहीं है। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो दर्शन के लिए शिरडी पहुंची थीं। बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को मानव या मानव अंग तस्करी के नजरिये से मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

जस्टिस टीवी नालावडे व एसएम गवान्हे की पीठ ने वर्ष 2018 में मनोज कुमार की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने यह आदेश दिया। मनोज की पत्नी वर्ष 2017 में शिरडी से लापता हो गई थी। कोर्ट ने कहा, 'एक साल में 88 से ज्यादा लोगों के गुम होने की सूचना है। इनमें ज्यादातर साईंबाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए थे। जब कोई गरीब लापता हो जाता है तो उसका परिवार असहाय हो जाता है। ज्यादातर पुलिस से शिकायत नहीं करते और शायद ही कोई मामला कोर्ट तक पहुंच पाता है।' कोर्ट ने पुलिस को मानव व मानव अंग तस्करी के नजरिये से मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

पीठ ने कहा, 'इसलिए यह आशंका है कि रिकॉर्ड में दर्ज 88 से भी ज्यादा लोग लापता हुए हों। इस आशंका के मद्देनजर कोर्ट अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच के लिए विशेष इकाई के गठन का आदेश देता है। साथ ही आदेश देता है कि मानव व मानव अंग तस्करी में लिप्त लोगों पर कानूनसंगत कार्रवाई की जाए।'

उल्लेखनीय है कि शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यहां स्थित साईं मंदिर में देश-दुनिया के भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह देश के संपन्न मंदिरों में से एक है।

बांबे हाई कोर्ट। फाइल

अल्पसंख्यक दर्जे के लिए इंतजार के मूड में नहीं सिख

मांग

उपराज्यपाल से जल्द हक दिलाने की मांग करेंगे सिख संगठन, आनंद मैरिज एक्ट और पंजाबी भाषा के दर्जे की भी मांग

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ जम्मू–कश्मीर का सिख समुदाय सात दशक से अपने अधिकारों से वंचित है

▶ अधिकारियों द्वारा स्थिति स्पष्ट न करने से उन्हें फिर से चिंता सताने लगी है

सात दशक से अपने अधिकारों से वंचित जम्मू-कश्मीर का सिख समुदाय अब अलपसंख्यक दर्जे के लिए और इंतजार करने के मूड में नहीं है। राज्य के पुनर्गठन के बाद अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाना है। फिलहाल अभी यह तय नहीं हो पाया है कि राज्य का अपना आयोग गठित होगा या केंद्रीय आयोग के तहत ही अल्पसंख्यकों को सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह आनंद मैरिज एक्ट पर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने मसले को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के समक्ष उठाने की तैयारी शुरू कर दी है।

इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के नाम पर सिख समुदाय को उनके हकों से वंचित रखा गया। यहां तक की अल्पसंख्यक का दर्जा भी नहीं मिल पाया। साथ ही आनंद मैरिज एक्ट लागू करने, पंजाबी भाषा को लागू करने समेत कई मांगे कभी पूरी नहीं हुई। राज्य के पुनर्गठन के बाद अब उनकी उम्मीदें भी तेजी से बढ़ी हैं और आशा है कि उन्हें हक मिलेगा। बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा स्थिति स्पष्ट न करने से उन्हें फिर से चिंता सताने लगी है।

फारूक, मुफ्ती और मनमोहन के समक्ष उठाया था मसला : सिख संगठन इस मसले पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस मामले को बार-बार उठाया पर हर बार आश्वासन ही मिले। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद के समक्ष भी इस मसले को उठाया। उन्होंने जल्द समाधान के वादे किए पर कुछ संभव नहीं हो सका। सिख संगठनों के अनुसार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष भी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी।

अभी काम आरंभ नहीं हुआ : ऑल पार्टी सिख कोर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि केंद्र कह रही है कि अल्पसंख्यकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का फायदा अभी तक जम्मू-कश्मीर को नहीं मिला है। भाषाओं के नए फार्मूले में पंजाबी भाषा को स्थान नहीं दिया जा रहा है।

घाटी के सिखों के लिए भी मांगी कश्मीरी विस्थापितों के समकक्ष सुविधाएं

ऑल पार्टीज सिख कोर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि कश्मीरी विस्थापितों की तर्ज कश्मीर में रहने वाले पंडितों को पैकेज का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कश्मीर के सिखों को वंचित रखा गया है। कश्मीर में सिख समुदाय को भी समकक्ष सुविधाएं मिलनी चाहिएं।

जम्मू में खुले आयोग का कार्यालय

सिख नेता मंजीत सिंह का कहना है कि अगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को लाया जाता है तो जम्मू में इसका कार्यालय खोला जाए। सिख प्रतिनिधियों को इस में शामिल किया जाए। आनंद मैरिज एक्ट को दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है और इसे जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जाए। नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन वीरेंद्र जीत सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग और आनंद मैरिज एक्ट पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए जल्द उपराज्यपाल से मिलेंगे। जम्मू–कश्मीर में अब भी शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं हो रही है।

सांबा में घुसपैठिया किया ढेर पाकिस्तान ने नहीं लिया शव

संवाद सहयोगी, सांबा

जम्मू संभाग के सांबा सेक्टर के मंगूचक इलाके में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर आए एक पाकिस्तानी को मार गिराया। गुरुवार व शुक्रवार की मध्यरात्रि को पाकिस्तानी की ओर से मंगूचक पोस्ट के सामने से एक घुसपैठिया भारतीय क्षेत्र की ओर आ रहा था। बीएसएफ की 143वीं वाहिनी के जवानों ने उसे पहले ललकारा, लेकिन जब वह तब भी नहीं रुका तो उसे वहीं पर ढेर कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजरों से संपर्क कर शव को ले जाने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तानी रेंजरों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके देश का नागरिक ही नहीं है। काफी इंतजार के बाद शुक्रवार देर शाम को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शव को अपने कब्जे में लिया। सीमा सुरक्षा बल के उच्च अधिकारी भी मंगूचक में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मृतक की उम्र लगभग पचास वर्ष बताई जा रही है। इससे अधिक उसकी पहचान नहीं हुई है। उससे कोई हथियार या गोलाबारूद नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक मारा गया संदिग्ध आतंकवादियों का गाइड हो सकता है, जो आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करवाने की कोशिश में था।

घुसपैठ करवाने की फिराक में पाकिस्तान: सांबाः सर्दी में धुंध की आड़ में पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ की पूरी ताक में रहता है। इस बार भी पाकिस्तान ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। पिछले कुछ दिनों से सीमा के उस पार कई गतिविधियां दिखाई दे रही थीं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार तीन से चार के ग्रुप में कुछ संदिग्ध इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए जा रहे थे।

9000 मेगावाट क्षमता के 12 नए रिएक्टरों के लिए सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में परमाणु राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। वर्तमान में नौ रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।

रिमझिम बौछार के बीच खिला संवाद का इंद्रधनुष

संवादी उत्सव अभिव्यक्ति का...

दुर्गा शर्मा, लखनऊ

- जागरण संवादी का छठा संस्करण भारतेंदु नाट्य अकादमी में शुरू
- 15 दिसंबर तक वैविध्य विचारों के सागर में डूबिए-उतरिए

लखनऊ में शुक्रवार को भारतेंदु नाट्य अकादमी में दैनिक जागरण के संवादी कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित (दाएं), दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी (बीच में) और वरिष्ठ महाप्रबंधक (ब्रांड) विनोद श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित किया। जागरण

संवादी ने कहा... हो जा सतरंगी रे! तो प्रकृति भी रंग गई, संवाद करने लगी। अभिव्यक्ति के स्वर सजने लगे। अंबर से धरती पर प्यार बरसता रहा। रिमझिम बौछार के बीच संवाद का इंद्रधनुष सजा। विदा लेती दोपहर में हवा सर्द थी पर 'क्षेत्रीय राजनीति का भविष्य' पर चर्चा गर्म। कोई नरमी से बात कह रहा था तो किसी को तल्खी का साथ सही लगा। सत्र समापन की ओर था, लेकिन दर्शक दीर्घा से सवाल जारी रहे। सहमति-असहमति के बीच बातचीत की खूबसूरती बनी रही। सुखद ये था कि मंच और दर्शक दीर्घा के बीच की दीवार टूटी। शाम हुई तो वैविध्य विचारों के इस मंच पर अवध की मिट्टी से उठती धुन गूंजने लगी। पद्मश्री मालिनी अवस्थी की आवाज पाकर ये धुनें तालियों का साज पा गईं। 'बनरा बुलाए बनरी नहीं आए, चली आओ बनरी रे अटरिया सूनी पड़ी... से लेकर सैंया मिले लरकइया... सुनते हुए वक्त कब बीता अहसास न हुआ।

लखनऊ में गोमती नगर स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी में दैनिक जागरण के आयोजन 'संवादी' के छठे संस्करण की भव्य शुरुआत शुक्रवार को हुई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन कर संवाद का उजियारा किया। इसके बाद सत्र दर सत्र विचारों की गहमागहमी बढ़ती रही।

मधुर होता गया संवाद : उद्घाटन सत्र में उप्र के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से अरुण माहेश्वरी की बातचीत ने 'ज्ञान का ज्ञान' समझाया। विधानसभा अध्यक्ष की किताब पर चर्चा के साथ संवाद मधुर होता गया। पहले सत्र 'हिंदी का फैलता दायरा' में भारतीय भाषाओं के बीच संवाद जरूरी का प्रबल संदेश दिया गया। 'हिंदी दस, कंप्लशन नो' की पुरजोर आवाज उठी।

वक्ता एकमत हुए कि हिंदी को बड़ी बहन और बाकी को मौसी मानना होगा। अगला सत्र 'महिला होने का दंश' था। चूंकि, विषय गहन और गंभीर था तो चर्चा भी उसी रौ में होती गई। सभी महिला वक्ताओं ने एक सुर में कहा, सहनशीलता नहीं, विरोध करना जरूरी। तीसरे सत्र में 'हौसले का हिमालय' दिखा तो चौथे सत्र में 'क्षेत्रीय राजनीति का भविष्य' पर गहमागहमी रही। पांचवे सत्र 'सुनहले पर्दे का ख्वाब' में अभिनेत्री महिमा चौधरी को सामने देख दर्शक दीर्घा में मोबाइल के फ्लैश चमकने लगे। इससे पहले दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ल ने अतिथियों और श्रोताओं का स्वागत किया।

विचारों का खजाना है संवादी : विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि समाज या दुनिया का गठन संवाद से होता है। संवाद उपयोगी है, अध्ययन का विषय भी है। आकाश में गंगा बहा देना संवाद की ही विशेषता है। हम गंगा को माता कहकर पुकारते हैं, ऐसा संवाद कहीं और नहीं मिलता है। ये दुनिया संवाद की है। संवाद धर्म है। हर कोई प्रीत पूर्ण संवाद करे। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि संवादी विचारों का खजाना है।

साहित्य, समाज, संस्कृति, सिनेमा समेत तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा का मंच है। इस संवाद के उत्सव के रंग में रंग जाइए। एसोसिएट एडिटर अनंत विजय ने कहा कि ये अभिव्यक्ति का उत्सव है, कोई लिटरेचर फेस्टिवल नहीं। देश का सबसे बड़ा अखबार होने के नाते पाठकों को अभिव्यक्ति से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हम हर बार संवादी में मौजू विषयों को लेकर आते हैं।

पौष मेले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करे विश्वभारती

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दीर्घकालिक निगरानी के लिए नोडल एजेंसी

फाइल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वभारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों व बीरभूम जिला प्रशासन से दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित होने वाले वार्षिक पौष मेला के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। बता दें 23 दिसंबर से मेले का आयोजन शुरू होना है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारी संख्या में देश व दुनिया से लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

11 दिसंबर को एनजीटी विश्वविद्यालय को पहले के आदेश की याद दिलाते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को कहा। एनजीटी ने कहा कि आवेदक सुभाष दत्ता ने पीठ को सूचित किया है कि परिसर में पूरे वर्ष में 6,500 छात्र व 520 फैकल्टी सदस्य रहते हैं। इसके अलावा एनजीटी ने राज्य के मुख्य सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति, बीरभूम जिला मजिस्ट्रेट और बोलपुर नगरपालिका, शांति निकेतन ट्रस्ट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक नई समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

निर्देश में कहा गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दीर्घकालिक निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगा। हालांकि इससे पहले ट्रिब्यूनल ने पौष मेला को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं की देखरेख व निगरानी को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। यह समिति पौष मेले जैसे आयोजनों के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी को बनाई गई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठाकर पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया जा सकता है।

सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश देने से इन्कार

बड़ा मामला ▸ दो महिलाओं ने की है मंदिर में सुरक्षा में प्रवेश की मांग

पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सात जजों की संविधान पीठ का गठन जल्द

- कोर्ट ने कहा, यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, नहीं चाहते कि स्थिति विस्फोटक हो
- मामला अभी भी सात जजों की संविधान पीठ के पास लंबित है
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को दी थी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में पुलिस सुरक्षा में प्रवेश की मांग करने वाली दो महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और वह नहीं चाहते की स्थिति विस्फोटक हो जाए।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश नहीं है, क्योंकि मामला अभी भी सात जजों की संविधान पीठ के पास लंबित है। जब तक सात जजों की संविधान पीठ इस मामले में अपना कोई फैसला नहीं देती है, तब तक हम कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते।

सीजेआइ ने सबरीमाला जाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बिंदू अम्मिनी और रेहाना फातिमा को सुरक्षा देने से इन्कार करते हुए कहा कि मंदिर में प्रार्थना करने के लिए महिलाओं का अगर राजी खुशी स्वागत होता है तो कोई समस्या ही नहीं है। वैसे इस मामले इस साल जनवरी में पारित में पुराने आदेश को ही माना जाएगा। इस पूरे मामले को सात जजों की बेंच को सौंपा गया है और जल्द ही इस बेंच का गठन किया जाएगा। बिंदू ने पिछले साल भी मंदिर जाने का प्रयास किया था और किसी श्रद्धालु ने उन पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया था।

चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ विषय देश में ऐसे भी होते है, जो बहुत विस्फोटक होते हैं। ये उन्हीं में से एक हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआइ ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर भी चिंता जताई।

गौरतलब है कि सबरीमाला का दो महीनों का त्योहार पिछले हफ्ते औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। हजारों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमाला पहुंचना शुरू हो गए हैं।

16 नवंबर को मंडल पूजा उत्सव के लिए सबरीमाला मंदिर के कपाट खोले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी थी। हालांकि, इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सात जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया था।

मतों में विसंगतियों की जांच की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने दो एनजीओ की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। एनजीओ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 347 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोट और गिने गए मतों की संख्या के बीच विसंगतियों की जांच की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों एनजीओ की याचिका को लंबित के साथ टैग करते हुए फरवरी 2020 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज द्वारा दाखिल याचिका में चुनाव आयोग को भविष्य के सभी चुनावों में विसंगतियों की जांच के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। एडीआर ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदान के आंकड़े और गिने गए मतों की संख्या में विसंगतियां पाई गई। एडीआर ने कहा है कि यह विसंगति एक से लेकर 1,01,323 मतों तक है जो कुल मतों का 10.49 फीसद है। याचिका में कहा गया है कि छह निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां मतों में विसंगतियां जीत के अंतर से ज्यादा हैं। याचिका में मांग की गई है कि किसी भी चुनाव में परिणाम घोषित करने से पहले आंकड़े का सटीक मिलान होना चाहिए। एनजीओ ने चुनाव आयोग को 17सी, 20, 21सी, 21डी और 21ई वैधानिक फार्म में इस साल के लोकसभा चुनाव और भविष्य के चुनाव की सूचना सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की है।

इस्लामिक बैंकिंग पोंजी घोटाले में 10 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक बैंकिंग या हलाल इनवेस्टमेंट पोंजी स्कीम घोटाले में बेंगलुरु स्थित एक कंपनी की 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई।

- कर्नाटक में कंपनी ने बेहतर रिटर्न का भरोसा देकर कराया था निवेश

ईडी के बयान के अनुसार, एंबिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रवर्तकों ने हज व उमरा योजना के तहत इस्लामिक बैंकिंग व हलाल इनवेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठा किए। आरोप है कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने लोगों को निवेश पर प्रति माह 15 फीसद तक रिटर्न का भरोसा दिया था। कंपनी फंड इकट्ठा करने के लिए अधिकृत नहीं थी, क्योंकि इसका आरबीआइ या सेबी में पंजीकरण नहीं था। शुरुआत में तो कंपनी ने रिटर्न दिए, लेकिन बाद में मूलधन भी देना बंद कर दिया। ईडी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने बेंगलुरु में स्थित 8.8 करोड़ रुपये की अचल व 1.4 करोड़ की चल संपत्तियां जब्त की हैं। यह घोटाला पिछले साल प्रकाश में आया था और इसी साल फरवरी में ईडी ने मामला दर्ज किया था।

बैंक कर्ज धोखाधड़ी में राजस्थान की कंपनी की 20 करोड़ की संपत्तियां जब्त : बैंक कर्ज धोखाधड़ी में ईडी ने राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। केंद्रीय एजेंसी ने एम्पी केबल्स एंड कम्युनिकेशन और इसके निदेशकों श्रीपाल चौधरी, अनुराधा चौधरी, अभिनव चौधरी व अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

ईडी ने एक बयान में बताया कि कंपनी ने श्रीपाल चौधरी की मुखौटा कंपनियों रिलायंस इंटरनेशनल, न्यू जेनरेशन आइएनसी व कंडोई मेटल पाउडर से फर्जी खरीद-बिक्री दिखाई। 90 फीसद माल के परिवहन के लिए एक ही वाहन का इस्तेमाल किया गया, जिसे एक ही समय में अलग-अलग लोकेशन पर उपलब्ध दिखाया गया। इस प्रकार उन्होंने देना बैंक व अन्य के साथ धोखाधड़ी की। कंपनी की जब्त संपत्तियों में दो आवास, एक फैक्ट्री, पांच ऑफिस, दो प्लॉट, कृषि भूमि और जयपुर स्थित जीआइटी कॉलेज का छात्रावास शामिल है। इन अचल संपत्तियों की कीमत लगभग 18.93 करोड़ है। करीब 1.42 करोड़ की चल संपत्तियों में बैंक बैलेंस, प्लांट, मशीनरी और तीन कारें शामिल हैं।

कौशल विकास मंत्रालय को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस

नईदुनिया, बिलासपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना में अधिकारियों की लापरवाही का मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया है। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को पांच साल बाद भी मंत्रालय से प्रमाणपत्र जारी न किए जाने पर हाई कोर्ट ने कौशल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पी सैम कोशी ने कौशल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता युवाओं को 45 दिनों के भीतर स्थाई प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि दामन ध्रुव, ओमप्रकाश, अजय कुमार साहू, पूरनलाल साहू व अन्य युवाओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आरंग जिला रायपुर से वर्ष 2012-14 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित ट्रेड का दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया। पास आउट होने के बाद संस्थान द्वारा सभी छात्रों को अस्थायी प्रमाणपत्र जारी किया गया था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरंग ने पास आउट छात्रों के प्रांक का विवरण तकनीकी शिक्षा विभाग को वर्ष 2014 में ही भेज दिया गया था। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने आज तक प्रशिक्षित युवाओं को स्थाई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। याचिका के अनुसार कई बार संस्था से संपर्क किए जाने व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के बावजूद आजतक स्थाई राष्ट्रीय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को विशेष बल देने की मांग पर केंद्र को नोटिस भेजा

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से देश भर की अदालतों को विशेष बल देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अपना जवाब सौंपने के लिए कहा है। याचिका में सभी कोर्ट, न्यायाधीशों, वकीलों, वाद दायर करने वालों और गवाहों की पूर्ण सुरक्षा देने के लिए विशेष बल की मांग की गई है।

जस्टिस एनम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। यह याचिका वकील दुर्गा दत्त ने अपने साथी करुणाकर महालिक की ओर से दायर की है। शीर्ष कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 जनवरी तय की है।

याची ने कहा है कि स्थानीय पुलिस की सुरक्षा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरपर्सन की हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत परिसरों और यहां तक कि कोर्ट रूम में भी हिंसा, फायरिंग होती है जिससे जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। याचिका में कहा गया है कि असामाजिक तत्व कोर्ट परिसर के वातावरण के लिए अत्यंत नुकसानदेह होते हैं।

मप्र से गिरफ्तार आइएम का एजाज खोलेगा मुंबई धमाकों के राज

नईदुनिया, बुरहानपुर

13 साल से महाराष्ट्र सीमा से सटे बुरहानपुर में काट रहा था फरारी

2006 के मुंबई बम धमाकों के बाद से फरार चल रहे प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सक्रिय सदस्य एजाज को गुरुवार शाम खंडवा एटीएस ने बुरहानपुर के पाला बाजार से गिरफ्तार कर मुंबई एटीएस के हवाले कर दिया है। एजाज पर मुंबई धमाकों के बाद एटीएस ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत मामला दर्ज कि या था। तब से वह फरार था और बुरहानपुर में रह रहा था। मुंबई एटीएस की पूछताछ में एजाज मुंबई बम धमाकों से जुड़े कुछ राज भी खोल सकता है।

बुरहानपुर पुलिस नाकाम रही: इसे बुरहानपुर पुलिस की नाकामी भी कहा जा सकता है कि करीब 13 साल से शहर में फरारी काट रहे आतंकी संगठन के सदस्य को पुलिस नहीं पकड़ पाई। बुरहानपुर महाराष्ट्र की सीमा से सटा मध्य प्रदेश का जिला है। ज्ञात हो कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 209 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

इंदौर में सौंपा मुंबई एटीएस को गिरफ्तारी के बाद गुरुवार देर शाम एजाज को सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे 16 दिसंबर तक की ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया है। खंडवा एटीएस उसे लेकर इंदौर पहुंची जहां मुंबई एटीएस के हवाले कर दिया गया। बुरहानपुर के जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मुंबई एटीएस को 16 दिसंबर से पहले एजाज को मुंबई की कोर्ट में पेश करना होगा। इसके बाद वह उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकेगी।

सिमी व आइएम के तार बुरहानपुर से जुड़े रहे हैं : ज्ञात हो कि इससे पहले भी प्रतिबंधित संगठन सिमी के तार बुरहानपुर से जुड़े रहे हैं। शहर के कुछ क्षेत्रों में सिमी और आइएम के आतंकी पनाह भी पाते रहे हैं। पाला बाजार निवासी जिस एजाज को एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसकी माली हालत काफी मजबूत बताई जा रही है। उसकी दूध डेयरी के अलावा ई-रिक्शा की एजेंसी और खेतिहर जमीन भी है।

खफा खेमका चले टकराव की राह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी पीएम मोदी से मिलने की अनुमति मांगी
- 28 साल के कॅरियर में 53 तबादले झेल चुके हैं खेमका

हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अशोक खेमका एक बार फिर सरकार से टकराव की राह चल पड़े हैं। बार-बार के तबादलों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है। साथ ही प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की अनुमति मांगी है। खेमका का दावा है कि उनके कई तबादले जनहित में नहीं थे।

यह पहली बार है जब खेमका ने अपने तबादलों पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री को अर्ध सरकारी पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि शासन अब सेवा नहीं है, यह एक व्यवसाय है। मेरे जैसे कुछ मूर्ख लोग ही शासन में आने की सोचेंगे और जनता के विश्वास के भरोसे काम करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री चिट्ठी को कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे।

अपने अधिकतर तबादलों को आइएएस (कैडर) के नियमों का उल्लंघन करार देते हुए खेमका ने कहा कि मुझे हमेशा समय से पहले तबादलों का सामना करना पड़ा है। मेरे आत्म संयम को दूसरे रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा के आधार पर स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम मेरे अधिकतर तबादले गैर पारदर्शी, प्रबंधित और बाहरी व व्यक्तिगत विचारों पर आधारित हैं।

अशोक खेमका। फाइल

27 नवंबर को अपने अंतिम स्थानांतरण पर खेमका ने कहा कि मैं आपसे अपने स्तर पर फाइल पर सावधानीपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। कुछ विभागों में जीआइएस से संबंधित निविदाओं के लिए वित्तीय भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। 28 साल के कॅरियर में 53 तबादले झेल चुके 1991 बैच के आइएएस खेमका को हाल ही में अभिलेख, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभागों का प्रधान सचिव बनाया गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था।

ट्वीट में भी झलक चुका अशोक खेमका का दर्द

53वें तबादले पर खेमका ने बाकायदा ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व नियमों को तोड़े जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने यह कह कर दर्द बयां कि 'फिर तबादला। लौट कर फिर वहीं। कुछ प्रसन्न होंगे। अंतिम ठिकाने जो लगा। ईमानदारी का इनाम जलालत।' **एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी पर हाई कोर्ट चले गए थे :** मनोहर सरकार की पहली पारी में भी खेमका ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में नंबर काटने के खिलाफ बगावत कर दी थी। पिछले साल मुख्य सचिव ने खेमका की एसीआर में 10 में से 8.22 नंबर दिए जिसे बेंच मंत्री अनिल विज ने बढ़ाकर 9.92 कर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नंबर काट कर फिर नौ करते हुए प्रतिकूल टिप्पणी कर दी तो खेमका हाई कोर्ट पहुंच गए थे। अब सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है।

सुरक्षित रखे जाएं हैदराबाद मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपितों के शव

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेटनरी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपितों के शवों को उसके अगले आदेश तक सुरक्षित रखा जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से इस संबंध में राज्य को दिया गया आदेश बरकरार रहेगा। चारों आरोपित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे।

शीर्ष अदालत ने मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है। साथ ही यह साफ कर दिया है कि जब तक मुठभेड़ की न्यायिक जांच चलेगी, तब तक कोई और कोर्ट या प्राधिकार इसकी जांच नहीं करेगा। कोर्ट ने आयोग को छह महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा, 'चारों आरोपितों के शवों को सुरक्षित रखने संबंधित हाई कोर्ट का आदेश शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।' शीर्ष अदालत ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए दो स्वतंत्र याचिकाओं पर विचार करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

नमामि गंगे

गंगाजल की निर्मलता के प्रयासों को आज परखेंगे मोदी

कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की समीक्षा के बाद करेंगे नए एक्शन प्लान की घोषणा, गंगा तट पर करेंगे पूजन-अर्चन, स्टीमर से देखेंगे नमामि गंगे में हुए कार्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री भी होंगे साथ

जागरण संवाददाता, कानपुर

मां गंगा को अविरल और निर्मल करने के वादे पर किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी कसौटी पर परखेंगे। कानपुर में गंगा से आच्छादित पांच राज्यों में से दो के मुख्यमंत्री, एक के उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में वह राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में गंगा स्वच्छता से जुड़े कामों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद नए एक्शन प्लान की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री के भ्रमण में अटल घाट गंगा बैराज पर गंगा पूजन और उसके बाद स्टीमर से नमामि गंगे के कार्यों का निरीक्षण भी शामिल है।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में समीक्षा बैठक को लेकर दिन भर तैयारियां चलती रहीं। सीएसए से कंपनी बाग होते हुए अटल घाट तक दीवारों पर गोमुख से गंगासागर तक प्रमुख गंगा तीर्थों को दर्शाते हुए चित्रांकन किया गया है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे सीएसए पहुंचेंगे। दस मिनट तक नमामि गंगे परियोजना संबंधी कार्यों की प्रदर्शनी देखेंगे। इसके उनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नौ केंद्रीय कैबिनेट व राज्यमंत्री शामिल होंगे। झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार से बैठक में प्रतिभाग करने संबंधी कोई सूचना नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विशिष्ट जनों का स्वागत करेंगे। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठक की भूमिका रखेंगे।

कानपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर अटल घाट पर तैयार किया फ्लोटिंग प्लेटफार्म। जागरण

केंद्रीय मंत्री बैठक में होंगे : केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ग्राम्य विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन, पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यटन एवं सांस्कृतिक राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, ऊर्जा राज्यमंत्री राजकुमार सिंह, आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप पुरी, जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडवीया।

कानपुर में विजेता की छवि को और पुख्ता करेंगे मोदी

चंद वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में असंभव को संभव बनाने वाली अपनी छवि गढ़ी है। अनुच्छेद 370 के खात्मे से नागरिक संशोधन विधेयक, एनआरसी इसके बड़े उदाहरण है। गंगा स्वच्छता की मुहिम, वह भी कानपुर में एक ऐसा ही लक्ष्य था। इसे नमामि गंगे ने काफी हद तक सफल बना दिया है। कानपुर में गंगा किनारे आयोजन संदेश देगा कि भारतीय संस्कृति की जड़ों को सींचने में प्रधानमंत्री निष्काम भाव से जुटे हैं। इसका राजनीतिक असर गोमुख से गंगासागर ही नहीं वरन् गंगा में आस्था रखने वाले हर भारतवंशी तक पहुंचेगा।

मीरजापुर में एक किलो चावल में 35 आशाओं को परोस दिया भोजन

जागरण संवाददाता, मीरजापुर

- मीरजापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण अधिकारी बोले-सपरिवार आईं थी आशा कार्यकर्ता

> मामले की जानकारी मिली है, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी से मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
> – डॉ. ओपी तिवारी, सीएमओ, मीरजापुर

अभी तक मिड डे मील की अनियमितता को लेकर ही सुर्खियों में रहे जिले में शुक्रवार को एक नया मामला उजागर हुआ। मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कैंप के पहले दिन एक किलो चावल पकाकर आशाओं में परोसा जाने लगा, जिसे देख महिलाओं ने विरोध किया और हंगामा किया।

विरोध कर रहीं आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुबह का नाश्ता को कौन कहे, पहले दिन से भोजन ही घटिया दिया गया। एक ओर सरकार पोलीथिन पर रोक लगा रही है वहीं आशाओं को दिया जाने वाला भोजन पोलीथिन में भरकर दिया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब शुक्रवार को मात्र एक किलो चावल और आधी किलो दाल में प्रशिक्षण ले रहीं 35 आशाओं को परोसा जाने लगा। खाने की कमी देख प्रशिक्षुओं ने भोजन और ट्रेनिंग दोनों का बहिष्कार कर दिया। अधिकारियों के मान-मनौव्वल के बाद कुछ आशाओं ने भोजन किया। प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कई आशा कार्यकर्ता अपने साथ उनके पति भी थे जिससे भोजन की कमी हो गई। चिकित्साधिकारी मड़िहान कौशल कुमार मौर्य ने बताया कि आशाओं द्वारा ट्रेनिंग बहिष्कार और भोजन छोड़ने की जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी को दे दी गई।

दैनिक जागरण
अंधेरे की शिकायत करने से बेहतर है मोमबत्ती जलाना

शालीनता से परहेज

लगता है राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वह रह-रह कर बेतुके बयान देते ही रहेंगे। चंद दिनों पहले जब उन्होंने भारत को दुष्कर्म की राजधानी कहा था तब भी उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। अब उन्होंने मेक इन इंडिया का हवाला देते हुए यह कह दिया कि आज जहां देखो वहीं रेप इन इंडिया नजर आता है। यह एक अभद्र टिप्पणी है। उनके जैसे नेता को ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती, लेकिन शायद वह यह मान बैठे हैं कि अमर्यादित भाषा ही उनकी राजनीति को धार देती है। हैरानी नहीं कि उनके सलाहकार भी ऐसा ही सोचते हों, क्योंकि यह पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हो। उनकी भाषा किस तरह बिगड़ती चली जा रही है, यह सर्जिकल स्ट्राइक के समय खून की दलाली वाले बयान से भी साबित हुआ था और फिर आम चुनाव के वक्त उनकी ओर से उछाले गए चौकीदार चोर है नारे से भी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह प्रधानमंत्री के लिए बोलता है, देखता है जैसी शब्दावली इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करते। वैसे तो अपने देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय देने से इन्कार करते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं की जाती कि यही काम राहुल गांधी भी करें और वह भी बिना किसी शर्म-संकोच। आखिर वह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं?

यदि राहुल गांधी अपनी राजनीति से कोई उम्मीद नहीं जगा पा रहे तो उसका एक बड़ा कारण उनके छिछले बयान भी हैं। उन्होंने रेप इन इंडिया वाले अपने बयान के लिए माफी मांगने से इस तरह इन्कार किया, मानो कोई बहादुरी का काम कर दिखाया हो। उन्होंने माफी मांगने से इन्कार करते हुए यह आड़ ली कि एक समय नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के बारे में ऐसा ही कुछ कहा था। क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि वह मोदी का अनुसरण करना पसंद कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस शासित राज्य और खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान उनकी ओर से परिभाषित किए गए रेप इन इंडिया का हिस्सा नहीं रह गए हैं? निःसंदेह दुष्कर्म के मामले गहन चिंता का विषय हैं, लेकिन यह कहना सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कि दल विशेष के कारण ऐसा हो रहा है। एक गंभीर सामाजिक समस्या पर ऐसी सतही सोच हैरान करती है। आखिर राहुल गांधी यह कैसे भूल सकते हैं कि निर्भया कांड किसके शासनकाल में हुआ था? उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाएं किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं हैं।

आत्मचिंतन जरूरी

महज छह माह पूर्व इसी बंगाल में भाजपा ने 18 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया है कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू कम नहीं हुआ है। विधानसभा उपचुनाव में खड़गपुर सदर, कालियागंज और करीमपुर, तीनों ही सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद अब प्रदेश भाजपा नेतृत्व को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जिस तरह से भाजपा में पिछले कुछ समय में गुटबाजी देखने को मिली है और नेताओं ने बयान दिए हैं, उसे लोगों ने सही तरीके से नहीं लिया है। शायद इसी का नतीजा है कि तृणमूल कांग्रेस को तीनों सीटों पर जीत मिली है। बंगाल भाजपा नेतृत्व को गंभीरता से समीक्षा करनी होगी कि आखिर चूक कहां हुई? इस तरह की हार से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं पर असर दिखा था। विस उपचुनाव में मिली जीत ने तृणमूल को नई संजीवनी दे दी है। भाजपा को तृणमूल से बेहतर रणनीति और कार्यों के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। यही वजह है कि इस हार के बाद सबसे पहले प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने संगठन की कमजोरी और खामियों को लेकर बात करना शुरू किया है। उनका कहना है कि भाजपा को अब राज्य विशेष के लिए योजना बनानी चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती पर अखिल भारतीय रणनीति कारगर साबित नहीं होगी। बोस ने एनआरसी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाए जाने पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि बंगाल के लिए एनआरसी कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल इस पर शोर मचाने की जरूरत नहीं थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पहले नागरिक संशोधन कानून बनेगा, उसके बाद ही बंगाल में एनआरसी लागू होगा। यह घुसपैठियों को पहचानने की प्रक्रिया है। यह भारत के नागरिकों के लिए चिंता का विषय नहीं है। बोस ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी के बारे में लोगों को भ्रमित कर राजनीतिक फायदा उठाया। यही नहीं, बोस ने यह भी कहा कि बंगाल भाजपा का शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण से उनका तात्पर्य सांगठनिक चुनाव को सही तरीके से कराया जाना और पार्टी में योग्य व्यक्तियों को शामिल करना था।

जिस तरह से भाजपा में पिछले कुछ समय में गुटबाजी देखने को मिली है और नेताओं ने बयान दिए हैं, उसे लोगों ने सही तरीके से नहीं लिया है

डर के माहौल की हकीकत

बैजयंत जय पांडा

सरकार के बारे में यह कहना किसी विडंबना से कम नहीं कि वह आलोचना नहीं सुन सकती या फिर वह असहिष्णु हो गई है

कुछ दिन पहले मुंबई में एक आर्थिक जलसा हुआ। वहां देश के एक जानेमाने उद्योगपति ने गृहमंत्री अमित शाह से देश में कथित तौर पर डर के माहौल को लेकर सवाल किया। उनका यह सवाल पूछना था कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में इस मसले पर तूफान खड़ा हो गया। उसके केंद्र में वही मसला था कि मौजूदा मोदी सरकार के दौर में देश में कथित तौर पर खौफ का माहौल पसरा हुआ है जहां सरकार को किसी भी सूरत में अपनी आलोचना स्वीकार्य नहीं। इस वाकये और बीते पांच वर्षों के दौरान इससे मिलते-जुलते मामलों के बीच एक खास पहलू देखने को मिला और वह यह कि जब भी ऐसे सवाल किए गए तब सैकड़ों लोग इसके साक्षी रहे। तमाम लोगों के बीच पूछे गए इन सवालों को देश-विदेश में टेलीविजन प्रसारण के दौरान लाखों-करोड़ों दर्शकों ने देखा भी। वास्तव में गाहे-बगाहे ऐसे आरोप बेहद आम रहे हैं जिन पर मीडिया मुख्य रूप से टीवी परिचर्चाओं, अखबारी स्तंभों, साहित्यिक आयोजनों, आर्थिक सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में खासी चर्चा हुई।

जिन देशों में तानाशाह सरकारें होती हैं वहां कभी ऐसे सवाल नहीं किए जा सकते। ऐसे देशों या सरकारों में जहां लोग वाकई डरे होते हैं वहां ऐसी बातें चोरी-छिपे दबे स्वरों में और अमूमन बंद दरवाजों के भीतर होती हैं। वहां अक्सर छोटे-छोटे समूह ही ऐसी चर्चा करते हैं। वे खुलेआम मुखर होकर अपनी आवाज नहीं उठाते। मीडिया और यहां तक कि किसी सम्मेलन के मंच से तो ऐसी बातें उठाने का सवाल ही नहीं उठता।

भारत में आखिर कब ऐसी तानाशाह-अधिनायक वादी सरकार रही है? यदि इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तब आपकी तलाश आपातकाल के दौर पर जाकर ठहरेगी। उसी खौफनाक दौर में ऐसे डर की अभिव्यक्ति हो सकती थी। तब भयाक्रांत लोग मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर नहीं, बल्कि निजी बातचीत में ही ऐसी भावनाएं व्यक्त करते थे। तब मीडिया पर भी सरकारी सेंसर की तलवार लटकी हुई थी। मौजूदा भारत सरकार के बारे में ऐसी बातें कहना न केवल अतिशयोक्ति होगी, बल्कि यह वास्तविकता को अपनी सुविधानुसार तोड़ने-मरोड़ने का मामला अधिक प्रतीत होता है, फिर भी जो लोग ऐसे डर की बात कर रहे हैं उसे समझना एवं उसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह कि यह पूरी तरह से शहरी कुलीन वर्ग के दिमाग की उपज है। अगर आप इन कुलीन बस्तियों से दूर निकलकर आम लोगों की तरफ जाएंगे तो ऐसे सुर नहीं सुनाई पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आम लोगों की बड़ी आबादी वाली इन बस्तियों में किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं होता। यहां असल में लोगों को सुरक्षा खासतौर से परिवार की बच्चियों और महिलाओं की परवाह ज्यादा परेशान करती है कि रात में अकेले चलने पर वे किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। उनकी सुरक्षा उनके लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके उलट अगर उनसे मोदी सरकार को लेकर किसी सामान्य डर की बात को लेकर सवाल किया जाएगा तो जवाब यकीनन 'नहीं' में आएगा। आम शहरी नागरिकों में भी आपको कभी ऐसी चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर शहरी कुलीन वर्ग के कुछ लोग डर को लेकर ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? इनमें कई चोटी के उद्योगपति भी शामिल हैं। असल में ये उस जमात के लोग हैं जिनके सामने पूरे का पूरा ढांचा ही बदल रहा है जो उन्हें बहुत असहज करने वाला है। यदि आप इस पर विचार करते हैं तो शहरी कुलीन वर्ग के शीर्ष पर कायम ऐसे लोगों में डर की भावना को बखूबी समझ सकते हैं। दशकों से वे उन असमान्य चीजों को सामान्य मानकर खुद को उनके मुताबिक ढालते और तरक्की करते आए हैं, लेकिन अब उनकी वह दुनिया एकदम बदल रही है।

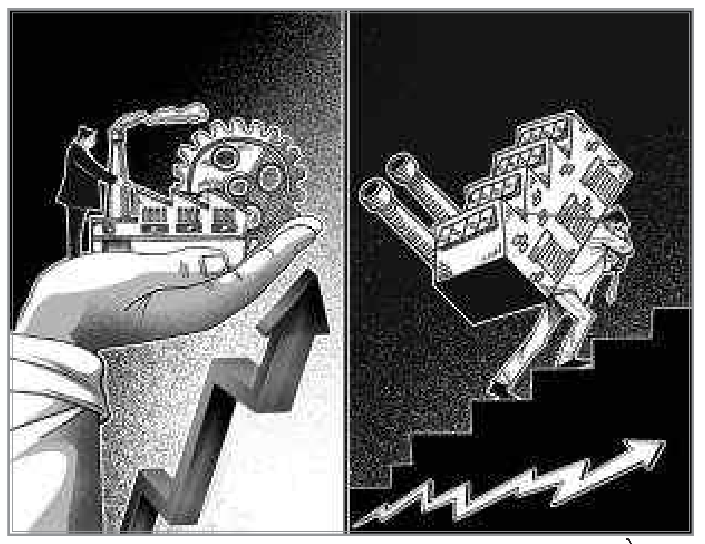

अवधेश राजपूत

मैं इसे विस्तार से समझाता हूं। यह कुलीन तबका भ्रष्टाचार जैसी बुराई को भी 'सामान्य' मानकर उसे उचित ठहराता रहा है। चाहे सामान्य स्वीकृतियों या मंजूरियों के मामले हों या फिर प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों को अपने मुताबिक बदलवाने के लिए भारी-भरकम रकम की घूस देने के उन्हें ऐसे तौर-तरीकों से कोई एतराज नहीं रहा। अपनी काली करतूतों के लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सरकारी विभागों के साथ उनकी साठगांठ चलती रही। इसके दम पर ही वे फलते-फूलते रहे। इससे उन्हें खास किस्म का आत्मविश्वास मिलता था जो अब बदलती व्यवस्था के दौर में ध्वस्त हो गया है।

आज कई बुनियादी बदलाव हो रहे हैं। सख्त कायदे-कानून बनाए जा रहे हैं। उन्हें कड़ाई से लागू भी किया जा रहा है। उन्हें तोड़ना-मरोड़ना भी मुश्किल है। इस बदलते और आकार लेते नए भारत में जहां ये नियम लागू हो रहे हैं, वहां उनके लिए वास्तविकता से ताल मिलाना बहुत कठिन साबित हो रहा है।

यह खासतौर से उन विशिष्ट कारोबारी जनों पर बहुत भारी पड़ रहा है जो पहले तंत्र को अपने हिसाब से हांकने में सक्षम थे। अपना जुगाड़ बैठाने में नाकामी उनके लिए दुखदायी साबित हो रही है। वे दशकों से जिस परिपाटी के अभ्यस्त थे, उसमें व्यापक बदलाव उन पर भारी पड़ रहा है। ऐसे तंत्र के भरभराकर गिरने से उनके आत्मविश्वास पर भी गहरी चोट हुई है जिसका अस्थाई रूप से असर शायद उनके निवेश पर भी पड़ रहा हो। उनके लिए ये स्थितियां बदल सकती हैं, यदि वे उन नए परिवर्तन से ताल मिला लें, जो सबके लिए समान आधार उपलब्ध कराती हैं।

पुरानी शैली के कारोबारियों में अधिक व्यावहारिक उद्यमी उस पुराने दौर एवं परिपाटी की वापसी को लेकर कोई उम्मीद नहीं कर रहे। वे तंत्र को प्रभावित करने वाले पुराने चलन से पीछा छुड़ाकर वास्तव में नए तौर-तरीकों को अपनाने के प्रयास में हैं। वे उन प्रक्रियागत परिवर्तन के साथ स्वयं को समायोजित कर रहे हैं जो केवल उन्हें नहीं, बल्कि सभी के लिए बेहतर कारोबारी परिवेश उपलब्ध कराए।

सरकार के बारे में यह कहना किसी विडंबना से कम नहीं कि वह आलोचना नहीं सुन सकती या वह असहिष्णु है। खासतौर से तब जब गृहमंत्री ने उनके प्रश्न का बहुत विनम्रतापूर्वक और आश्वस्त करने वाला जवाब दिया हो, मगर मीडिया में सवाल को जितनी प्रमुखता दी गई, उतनी उनके जवाब को नहीं मिली।

भारत में विभिन्न प्रकाशक एवं प्रसारक समूहों के रूप में भारतीय मीडिया के मुखरित स्वर देश के समृद्ध लोकतंत्र के जीवंत प्रमाण हैं। वास्तव में किसी भी सार्वजनिक मंच, टेलीविजन, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बिना किसी डर के सरकार पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना इसकी जीती-जागती मिसाल है कि भारतीय लोकतंत्र किस स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

प्याज संकट की दास्तान

गोपाल कृष्ण गांधी

प्याज हर इंसान की जेब के अनुकूल होता है। उसे सस्ता भोजन कहा जा सकता है, लेकिन...सामान्य दिनों में

कच्चा प्याज अगर चार टुकड़ों में छुरी से काटा या हथेली से तोड़ा जाए तो नमक-मिर्च के साथ रोटी का जो संग करता है, उसका क्या बयान करें! रूखी-सूखी हो रोटी या फिर गरम फुल्का, बाजरे के आटे के साथ मिले गेहूं के आटे से बनी हो या फिर मकई की हो, प्याज अगर उसको मिल जाए तो वाह...रोटी रोटी न रहकर कुछ और ही बन जाती है। वह एक पकवान नहीं, अनुभव बन जाती है। गेहूं में धरती की महक होती है, प्याज में जड़ी-बूटियों का सार। दोनों का मिश्रण खेती और बागवानी का पूरक बन जाता है और फिर उन पर नमक का छिड़काव...आह, कृषि पर खनिज की इनायत। ऊपर से लाल मिर्च की झीनी परत, आह-आह, इनायत पर मेहरबानी। अगर प्याज को सिरका मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। प्याज पर एक लालिमा आ जाती है, जैसे उसको कुछ शरम लगी हो खुद की खूबियों पर। और फिर वह कुछ नर्म होकर जल्द रोटी का स्पर्श चाहता है। प्याज पकने पर भी हर पकवान की जान बन जाता है। गरीब की रसोई में कच्चा-रूप, रईस की रसोई में पका हुआ प्याज। प्याज सबका दोस्त है, हर थाली का बंधु। प्याज हर इंसान की जेब के अनुकूल होता है। उसे सस्ता भोजन कहा जा सकता है, लेकिन...सामान्य दिनों में।

तब नहीं (जैसे अब) जब प्याज का दाम उछलता-कूदता आसमान तक पहुंच जाता है। असामयिक वर्षा की वजह से खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में जहां प्याज का भारी उत्पादन है, वहां उसकी उपज को इंतहा नुकसान पहुंचा है। यह संकट बार-बार आता है। 2013 में प्याज-समस्या आई थी। राजनीति परखने वाले कहेंगे, उस संकट का असर 2014 के चुनाव पर पड़ा था।

मुझे यकीन है कि इस बार सरकार संकट को काबू में ले आएगी। हालांकि चुनौती जटिल है। ऐसे समय में हमारा, प्याज-रसिकों का, कर्तव्य क्या बनता है? प्याज के दाम जब तक सामान्य न हो जाएं, तब तक क्या हम प्याज से दूर रहें? नहीं! कम मात्रा में सही, अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक, थोड़ा-बहुत प्याज अपनी रसोई में लाते रहें, प्याज-संस्कृति के, प्याज दुकानदार के और प्याज किसान के हित में। गलती उन दोनों की नहीं है। गलती मौसम की बेपरवाही की है। एक और जरूरी बात। प्याज के जमाखोरों को अपने किए का फायदा नहीं मिलने देना चाहिए। प्याज के दाम का हिस्सा किसान को जाना चाहिए। दास्तान-ए-प्याज के चार हिस्से हैं- आसमान, किसान, दुकान, पकवान। जब आसमान मेहरबान न हो और बारिश कम हो या फिर असामयिक या बहुत हो जाए तो यह फसल बेकार हो जाती है, किसान लाचार हो जाता है, दुकान मायूस हो जाती है व पकवान फीके पड़ जाते हैं।

प्याज की मुसीबतें आज खबरों में हैं। समाधान नहीं मिल रहा, पर आज नहीं तो कल, मिलेगा जरूर। प्याज हमसे इतना जुड़ जो गया है। इस बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि वह प्याज नहीं खातीं, न ही उनका परिवार। उनके कथन की आलोचना हुई है। उनके कथन में आहार का गर्व देखा गया। अपने खुद के और प्याज के रिश्ते के बारे में वह खामोश रहकर प्याज संकट पर मात्र अपना बयान रखतीं तो इस आलोचना से बची रहतीं। खैर! यह घटना भी प्याज संकट का एक हिस्सा है, लेकिन उससे दो सबक सीखने को मिलते हैं। हर एक की अपनी आहार-प्रणाली होती है। हर एक की अपनी आहार पसंदगी-नापसंदगी होती है। हर एक को यह मुबारक। उनको लेकर हंसना या हंसी करना शोभनीय नहीं। जैन कंद-मूल नहीं खाते। प्याज ही नहीं, आलू, शलजम, चुकंदर भी नहीं। उनका मानना है कि जब यह पौधे जमीन से उखाड़े जाते हैं तब छोटे जीव-जंतुओं को हानि पहुंचती है। इतना ही नहीं, वे यह भी मानते हैं कि प्याज एक कली होने के नाते, उखाड़े जाने पर भी जीवित रहता है। इस विचार को हमें आदर भाव से लेना चाहिए। अगर किसी की प्याज-प्रियता पर मजाक उचित नहीं तो फिर वैसे ही किसी और की प्याज-अप्रियता का भी अपना स्थान है।

प्याज की किल्लत, उसकी कीमत, उसकी महक, उसका स्वाद, उसका दाम, उसकी चाहत, उसकी नापसंदगी, उसका परहेज, उसके निषेध, उसकी परंपराएं भारत के बहु-आयामी स्वरूप की परिचायक हैं। प्याज भारत की खुशहाली और उसकी गरीबी, दोनों का परिचायक है। प्याज दरअसल एक साज है, उसमें नाज न भी हो, हमें उसके चरित्र का अहसास होना चाहिए।

(लेखक पूर्व राजनयिक एवं राज्यपाल हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

उम्मीद

आप कभी-कभार सोचते होंगे कि आप इतना दबाव, इतनी परेशानियां, इतनी असफलताएं बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन हालात काबू से बाहर हैं। इसके लिए कतई जरूरी नहीं कि आप तुरंत कुछ करें ही। नहीं सूझ रहा है तो रुक जाने में भी कोई बुराई नहीं। नई आशा और उम्मीदों की धूप, देर-सबेर खुद भी पहुंच जाएगी। ताजी हवा व रोशनी आ सके, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखें। उन पर भय, आशंका की कड़वी धूल को जमने न दें।

मन भी छोटा करने की जरूरत नहीं। जीवन तो हर पल नया भी हो रहा है और पुराना भी। हम जिस पल में नए हो जाते हैं, उस पल से हमारी जिंदगी नई होने लगती है। चुनौतियां रास्ते की रुकावटें नहीं हैं, रास्ता ही हैं। संघर्ष एवं असफलता केवल निराश ही नहीं करते, बहुत कुछ सिखाते भी हैं। नाउम्मीद में ही उम्मीद छिपी होती है। बीती बातों से सीख कर ही उबरा जा सकता है। मनोविज्ञानी कहते हैं कि हम इसी जाल में फंस कर रह जाते हैं कि या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। और यह सोच हमारा संतुलन बिगाड़ देती है। कई बार कम रोशनी में ही चीजें गहराई से समझ आती हैं। धुंधलापन नई कहानियों को जन्म देता है। दिमाग साफ हो और हम धुंध का मजा लेने के लिए तैयार हों तो कहानियां अच्छी बनती हैं।सफलता सिर पर जल्दी चढ़ती है और असफलता दिल पर। जीत के नशे में झूमते हुए को हार नहीं दिखती और हारे हुए को जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन असली जीत उनकी होती है जो सफलता को सिर नहीं चढ़ने देते व हार को दिल से नहीं लगाते। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कहती हैं, 'हार हो या जीत, मैं अपना सौ प्रतिशत देने पर ध्यान देती हूं। जो करती हूं, पूरे मन से करती हूं।' आपकी सफलता का दरवाजा भी खुलेगा जरूर, आप वांछित पाएंगे जरूर, कभी-कभी दरवाजा जब ज्यादा मजबूती से बंद होता है तो उसे खोलने के प्रयत्न भी उतनी ही मजबूती से करने होते हैं। तो झुंझलाहट क्यों?

ललित गर्ग

तथ्य-कथ्य | रसोई गैस कनेक्शन की घरों तक पहुंच

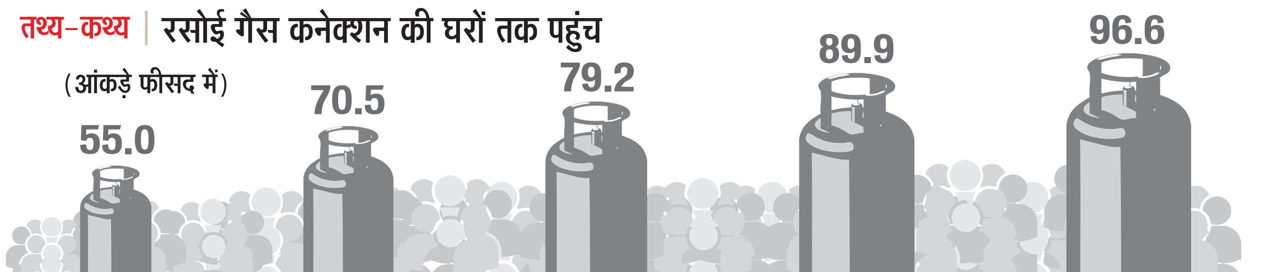

फिनलैंड से क्या सीखे भारत

मनीषा सिंह

पश्चिमी देशों के समाज इतने खुले हैं कि वहां राजनीति में पति या पत्नी में कोई एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे नहीं छूट जाता

फिनलैंड में 34 वर्षीय सना मारिन प्रधानमंत्री बनी हैं। वह दुनिया में सबसे कम उम्र में इस पद पर पहुंचने वाली महिला हैं। पांच पार्टियों के मध्य-वामपंथी गठबंधन का नेतृत्व कर रहीं और हाल तक फिनलैंड की परिवहन मंत्री रहीं सना को प्रधानमंत्री एंटी रिना के इस्तीफे के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। जिन पांच पार्टियों के गठबंधन की वह प्रमुख हैं, उन सभी पार्टियों की अध्यक्ष महिलाएं हैं। हाल में डाक हड़ताल से निपटने के मामले में गठबंधन का विश्वास खो देने के बाद एंटी रिना के इस्तीफे से वे स्थितियां बनीं जिनके चलते सना मारिन को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का मौका मिला है। स्कैंडिनेवियन देशों में सना तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न हैं व यूक्रेन में ओलेक्सी होंचरुक राष्ट्राध्यक्ष हैं।

फिनलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने महिलाओं को 1907 में संसद भेजा था। यह यूरोप का पहला देश है जिसने 1906 में महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। फिनलैंड में 2000 में पहली महिला राष्ट्रपति बनी थीं और 2003 में पहली महिला प्रधानमंत्री। इस साल फिनलैंड में 93 सीटों पर महिलाएं जीतकर संसद पहुंची हैं। 200 सीटों वाली संसद में 47 प्रतिशत महिलाएं हैं, लेकिन दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड के इन उदाहरणों से हम क्या सीखें। यूं भारत के पक्ष में एक बात जाती है। वह यह कि भारत उन पांच देशों में शामिल है, जहां पर एक महिला (इंदिरा गांधी) ने एक दशक से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन कुछ अपवादों (जयललिता, मायावती, ममता, सुषमा स्वराज आदि) को छोड़कर भारतीय राजनीति में ज्यादातर स्वतंत्र महिलाओं और राजनेताओं की पत्नियों का पदार्पण किसी वंशवादी मजबूरी में ही हुआ है। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को वह सामाजिक स्वीकार्यता और हैसियत नहीं मिल सकी, जिससे वे एक योग्य लीडर के रूप में स्थापित हो पातीं। अक्सर ऐसे मामलों में उन्हें अपने पति या किसी पुरुष राजनेता की सिर्फ छाया बनकर रहने को मजबूर होना पड़ा है। ये हालात तब हैं जब अतीत में कई महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को देखकर कहा जा सकता है कि राजनेताओं की पत्नियां सिर्फ अपने पत्नी धर्म का निर्वहन कर रही हैं और पति की छाया में रहने को अपनी सफलता मानती हैं।

भारत से उलट यूरोपीय-अमेरिकी आदि देशों के समाज इतने खुले और विकसित हैं कि वहां राजनीति में पति या पत्नी में कोई एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे नहीं छूट जाता। वहां यह सामंजस्य इसीलिए बन पाता है, क्योंकि वहां महिलाओं को राजनीति में किसी से हीन नहीं समझा जाता है और उन्हें आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर मुहैया कराया जाता है। काश, राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर बड़ी भूमिकाएं निभाने वाले पुरुष देख पाएं कि फिनलैंड की सना मारिन परिवार की तरह ही हमारे यहां भी महिलाएं देश संभालने के योग्य हैं, बशर्ते देश का पुरुष समाज उन्हें ये भूमिकाएं निभाने दे।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सही सुझाव

'स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बने रामकथा' शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने भारतवर्ष के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का चित्र प्रस्तुत किया है। यह सत्य है कि प्राचीन भारत की 'स्वीकार्यता की संस्कृति' समय-समय पर भारतीय समाज को संबल प्रदान करती रही है, जिसके सहारे व्यक्ति तथा समाज अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह करते रहे हैं। लेखक द्वारा वर्णित देश की प्राथमिकताएं जिनमें शिक्षा, कौशल विकास, जनसंख्या, रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भुखमरी तथा कुपोषण आदि ज्वलंत समस्याएं हैं। आज अनेक क्षेत्रों में शिखरोन्मुख नए भारत की संकल्पना इन समस्याओं से निजात पाए बिना अधूरी रहेगी। निश्चित रूप से रामायण-महाभारत तथा भारतीय परंपरा के गौरव ग्रंथ व्यक्ति निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, जिनकी समय-समय पर राजनीतिक तथा वैचारिक कारणों से उपेक्षा की गई। जबकि इन ग्रंथों में व्यक्ति तथा समाज की पूर्णता के विविध आयाम विद्यमान हैं। तथाकथित आधुनिकता की होड़ में हमने उन्हें भुला दिया। वर्तमान परिदृश्य में भारतवर्ष के गौरवशाली तथा महत्वपूर्ण साहित्य, इतिहास तथा परंपराओं और उनकी शिक्षाओं की पाठ्यक्रमों में नितांत आवश्यकता है। इनके सहारे एक ऐसे व्यक्ति, समाज का निर्माण हो सकेगा जो मानवता के कल्याण के लिए चिंतित तथा प्रयासरत होगा।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

पृथ्वी को बचाएं, नहीं तो...

स्पेन की राजधानी मेड्रिड में कॉप 25 सम्मेलन से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 57 देश जो सबसे ज्यादा कार्बन उगल रहे थे, उनमें से 21 देश उसे कम करने के लिए ईमानदारी से सार्थक प्रयास करते दिख रहे हैं। वे गैरपरंपरागत उर्जा श्रोतों जैसे सौर उर्जा और पवन उर्जा से अपना काम चलाने का सद् प्रयास कर रहे हैं। इन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 देशों में स्वीडन, डेनमार्क और भारत के साथ मोरक्को जैसे छोटे देश ने भी अपना उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अमीर और ताकतवर समझे जाने वाले देशों यथा आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देश वैश्विक पर्यावरण संतुलन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के मामले में अपना गैरजिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ये देश अगर यह सोचते हैं कि वैश्विक पर्यावरण के ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले दुष्प्रभाव से वे अछूते रहेंगे, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अमेरिका के ही कुछ वैज्ञानिकों ने समूचे विश्व को चेतावनी देते हुए यह बताया है कि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन से पैदा ग्लोबल वार्मिंग का इस दुनिया पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। वैश्विक पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को अगर सुधारने का समय से यथेष्ठ प्रयास नहीं किया गया, तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। अतः हम समस्त मानवों का यह परम् कर्तव्य है कि हम अपनी भरण-पोषण करने वाली पृथ्वी को बचाने के लिए वे सारे कर्तव्य करें, जो उसे और अधिक प्रदूषित न करें।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

प्रशंसनीय आचरण

भारत में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी जब स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा काले रंग का बंद गले का कोट तथा कुर्ते के साथ सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद धोती पहन कर रखी थी। संयुक्त रूप से उनकी पत्नी भी इस नोबेल से नवाजी गई थीं। एस्था डुफ्लो जो फ्रांसीसी हैं, उन्होंने भी इस शुभ अवसर पर नीली साड़ी और लाल ब्लाउज पहनकर माथे पर बिंदी लगा रखी थी। आज भारत में एक वर्ग ऐसा भी है, जो यज्ञोपवीत, कलावा, तिलक एवं चोटी के धारण करने को पुरातन एवं पिछड़ापन मानता है। ऐसे लोगों के लिए बनर्जी का उपरोक्त आचरण उत्तर देता प्रतीत होता है। आज हम अपनी परंपरा व संस्कृति से बढ़ते पाश्चात्ययीकरण के कारण विमुख होते जा रहे हैं, और पश्चिम कभी विश्व गुरु रहे भारत में शांति और संतोष खोजता घूम रहा है। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हममें हमारे पुरातन संस्कृति, इतिहास व परंपरा की चूलें हिलाकर रख दी हैं। हमें किसी की भी अच्छी चीजों को आत्मसात करना चाहिए। रुढ़ीवादी नहीं बनना चाहिए, लेकिन परंपराएं, जो वैज्ञानिक, सामाजिक तथा समय एवं सांस्कृतिक कसौटी पर खरी उतरी हों, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे में बनर्जी का यह आचरण प्रशंसनीय तथा धारणीय है।

डा. मनोज कुमार शर्मा, स्याना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असम के संगठनों के साथ असम समझौता किया था जिसके तहत राज्य से घुसपैठियों को बाहर करने की बात हुई थी, पर इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाए गए।

आजकल

राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ता असम

डॉ. नीलम महेंद्र
वरिष्ठ स्तंभकार

नागरिकता संशोधन कानून के अस्तित्व में आने के बाद से असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश इलाकों में अनेक समूहों द्वारा निरंतर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस कानून के संबंध में अनेक विपक्षी दलों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण ये राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना समीचीन होगा कि इस कानून के संदर्भ में विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है

प्रतीकात्मक

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से ही असम समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में इसका विरोध हो रहा है। इसमें यह प्राविधान किया गया है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले 'अल्पसंख्यक समुदाय' जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग यदि भारत में शरण लेते हैं तो उनके लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो गया है।

हालांकि कानून बन चुका यह विधेयक उन लोगों पर लागू होगा जिन्हें उपरोक्त उल्लेखित तीन देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाने के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट वाले भौगोलिक क्षेत्रों (जहां प्रवेश से पहले बाहरी व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है) और छठी अनुसूची के क्षेत्रों को नागरिकता संशोधन कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के कई इलाकों में यह कानून लागू नहीं होगा। इसलिए देखा जाए तो इस बिल में 'विवाद' अथवा 'विरोध' जैसा कुछ नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में धर्मनिरपेक्ष और संविधान के नाम पर इस कानून का विरोध किया और देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, उनका यह आचरण अपने आप में विपक्ष की भूमिका पर ही कई सवाल खड़े कर गया है।

गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में शरण : संविधान के नाम पर धार्मिक आधार पर अत्याचार की हद तक प्रताड़ित होकर भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों के प्रति विपक्षी दलों की इस संवेदनहीनता ने उनकी स्वार्थ की राजनीति को देश के सामने रख दिया। लेकिन इससे इतर जिन मुद्दों पर अनेक विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, उससे तर्कों की कमी को लेकर उनकी बेबसी भी सामने आई। विपक्ष को अब यह समझना चाहिए कि उनके द्वारा सरकार पर बार बार 'संविधान के साथ खिलवाड़' और 'लोकतंत्र की हत्या' जैसे रटे रटाए आरोपों से जनता अब ऊब चुकी है। विरोध के लिए जनता अब कुछ ठोस और न्यायसंगत तर्कों की अपेक्षा करती है।

आज जब समूचा विपक्ष संविधान का सहारा लेकर इस बिल का विरोध करते हुए धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव से पीड़ित इन देशों के अल्पसंख्यकों से अधिक चिंता अपने देश के अल्पसंख्यकों या फिर अपने वोट बैंक की कर रहा है, तो ना सिर्फ उनके सेक्युलरिज्म की हकीकत, बल्कि उनका दोहरा राजनीतिक चरित्र भी दृष्टिगोचर हुआ है, क्योंकि जब बात तीन ऐसे देशों की हो रही हो जहां का राज धर्म ही इस्लाम हो, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हों, और जिन देशों में गैर मुस्लिम परिवारों पर होने वाले अत्याचार दुनिया के सामने आ गए हों, जब आंकड़े बताते हों कि इन वर्षों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या निरंतर सिमटती जा रही हो, तब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विपक्ष का इस बिल के लिए विरोध समझ से परे हो जाता है।

देश के प्रति दायित्व बोध का ख्याल : यह वाकई में खेद का विषय है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के आगे विपक्ष को देश के प्रति अपने दायित्वों का भी बोध नहीं रहता। इसे क्या कहा जाए कि जब इस विधेयक में पूर्वोत्तर के राज्यों के अनेक इलाकों को शामिल ही नहीं किया गया है, फिर भी पूर्वोत्तर के राज्यों में इस कानून को लेकर लोग आक्रोशित ही नहीं, बल्कि हिंसक होने की हद तक भ्रमित हैं? दुष्प्रचार और अफवाहों की भीड़ में सच कैसे कहीं खो जाता है, असम इसका जीता जागता उदाहरण है। और जब अपने राजनीतिक स्वार्थों की खातिर भोले भाले छात्रों को आंदोलन की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया जाता है तो राजनीति का कुत्सित चेहरा सामने आ जाता है।

घुसपैठियों की समस्या से मिल सकती है मुक्ति : दरअसल असम में घुसपैठियों की समस्या बहुत पुरानी है। वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार ने भी घुसपैठ की समस्या खत्म करने के लिए वहां के संगठनों से असम समझौता किया था, लेकिन समझौते के बावजूद सरकार द्वारा इतने वर्षों तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। मौजूदा सरकार ने वहां इसी समस्या को खत्म करने के लिए एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) यानी राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को लागू किया गया था, ताकि वहां के मूल निवासियों और घुसपैठियों की पहचान की जा सके। एनआरसी के बनते ही असम में लगभग 19 लाख लोगों पर नागरिकता का संकट आ गया। अब असम के लोगों को डर है कि नये नागरिकता संशोधन कानून का सहारा लेकर एनआरसी से बाहर हुए लोग नागरिकता हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी से वह घुसपैठियों की पहचान करके उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। सरकार यह भी घोषणा कर चुकी है कि वह असम समझौते की धारा छह के अनुरूप ही असम के लोगों के संवैधानिक, राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनआरसी और सीएएल यानी नागरिकता संशोधन कानून, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं और इनमें नागरिकता हासिल करने के कानूनी पहलू भी अलग अलग हैं।

यहां यह समझना आवश्यक है कि एनआरसी में जो लोग छूट गए हैं, उन्होंने आवेदन तो किया होगा, लेकिन कागजातों के अभाव में उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। इस आवेदन में उन्होंने यह घोषणा की होगी कि वे भारत के ही नागरिक हैं और इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए होंगे जिसके आधार पर वो अपना नाम एनआरसी में जुड़वाना चाहते होंगे। जबकि सीएबी के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदक को यह कहना होगा कि वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान का नागरिक है। इसलिए दोनों मुद्दों को मिलाने की कोशिश करना संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बावजूद असम में इस बिल का हिंसक विरोध निराशजनक है।

पीड़ितों को राहत देने की पहल

प्रवीण गुगनानी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाला प्राविधान यानी नागरिकता संशोधन कानून स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे इन तीनों देशों में अत्याचार सह रहे हिंदुओं के भारत आने व यहां वैध नागरिकता प्राप्त करने का स्वप्न साकार हो सकेगा।

हमें समझना होगा कि कई राष्ट्रवादी नेताओं के मत की अनदेखी करके नेहरू ने लियाकत अली खान के साथ जो समझौता किया था वह प्रारंभ से ही दरक गया था। इस समझौते के अनुसार कभी भी हिंदुओं को पाकिस्तान में किसी प्रकार की सुरक्षा या संरक्षण नहीं मिला और विगत सात दशकों में भारतीय सरकारों ने भी कभी इन देशों में छूट गए हिंदुओं की चिंता नहीं की। यहां छूट गए हिंदू अत्याचार सहते सहते या तो धर्मांतरण को मजबूर हुए या भगोड़े बनकर दूसरे देशों में अवैध नागरिक कहलाने लगे।

वस्तुतः देश का विभाजन ही गलत माहौल में किया गया था। जब गांधीजी की देश में अति विश्वसनीयता थी, तब उस कालखंड में गांधीजी बोलते थे कि 'देश विभाजन मेरी लाश पर होगा'। उसी समय जिन्ना मुस्लिम समुदाय को विश्वास दिलाते थे कि मुस्लिमों का पाकिस्तान बनेगा। देश भर के हिंदुओं में गांधीजी की विश्वसनीयता व उनकी राजनीतिक शक्तियों के कारण हिंदू समाज आश्वस्त था कि विभाजन नहीं होगा, अतः वर्तमान पाकिस्तान में बसा हिंदू समाज लापरवाह था। उसने अपनी संपत्तियों, व्यवसाय, रिश्तेदारों के प्रति इस आश्वस्ति के कारण कोई व्यवस्था नहीं बनाई, जबकि वर्तमान भारत में बसे मुस्लिम समुदाय ने अपनी संपत्ति, व्यवसाय व रिश्तेदारियों को व्यवस्थित व स्थानांतरित करने की योजना बना रखी थी। इस प्रकार विभाजन में सबसे बड़ी हानि हिंदुओं की हुई। वर्तमान पाकिस्तान में उस समय की अधिकांश संपत्तियों, व्यवसाय व संसाधनों पर हिंदुओं का ही स्वामित्व था, वहीं मुस्लिमों की स्थिति निर्धनता की थी, अतः विभाजन हिंदुओं हेतु हानिकारक रहा, वहीं मुस्लिमों को बनी बनाई संपत्तियों, व्यवसाय आदि कब्जा करने को मिला। आजादी के बाद जो हिंदू पाक में बच गए थे, वे प्रताड़ित होते रहे व उनके संसाधन छीने गए जबकि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति व संख्या सुदृढ़ होती गई। वस्तुतः सीएबी विभाजन के अधूरे कार्य को पूर्ण करने का ही विधिक मार्ग है जिससे तब के दीन हीन हिंदुओं को इन तीनों देशों के नारकीय जीवन से बाहर निकलने का सम्मानपूर्ण मार्ग निकल सकेगा।

विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था व तब बड़ी संख्या में इस आधार पर ही जनसंख्या की अदला-बदली भी हुई थी, किंतु बड़ी संख्या में मुस्लिम भारत में छूट गए जो सम्मानपूर्वक नागरिक जीवन जीते रहे, जबकि पाकिस्तान में छूटे हुए हिंदू अत्याचारों व बलपूर्वक धर्मांतरण का शिकार हुए जिससे आज दयनीय दशा में आ गए हैं। पाकिस्तान से जो हिंदू अब तक भारत आकर रह रहे थे, उन्हें वैध नागरिक नहीं माना जा रहा था। अब इस प्रकार के उपेक्षित हिंदू बंधुओं को भारत में सम्मान पूर्ण जीवन मिलेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में अत्याचारों से तंग होकर बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश कर चुके हिंदू अवैध प्रवासी माने जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अपने पहले कार्यकाल में कार्य प्रारंभ कर दिया था और वर्ष 2015 व 2016 में कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को छूट दे दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको न तो जेल में डाला जा सकता है और न उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं।

खरी-खरी

खामोश... मैं बंद हूं!

सुनील जैन 'राही'

मोहल्ले की खुशी का अहसास स्कूल की छुट्टी से हो जाता है। आज फिर स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मास्टरजी ने कहा- आज शहर में जुलूस निकलेगा, इसलिए छुट्टी की जाती है। बच्चे गेट से बाहर हो गए। मास्टरजी के जाते ही दरवाजा बंद हुआ और स्कूल के गजट में छुट्टी हुई। लेकिन नोटिफिकेशन में कोई कारण नहीं लिखा था।

जब सड़कों पर झंडे दिखे, तब लगा मास्टरजी ने घोषणा पत्र में किए सारे वादे पूरे कर दिए। जुलूस में जोश था। कंधों पर प्रशासन की लाश थी। यह तय होना बाकी था कि प्रशासन की लाश किस तबके की थी? यह आयोजन किस पार्टी द्वारा किया गया था? लाश सरकारी दफ्तरों में बैठी-बैठी इतनी बेशर्म हो चुकी थी कि जूते खाकर भी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट और रोने में आज तक कोई फर्क नहीं कर पाया। प्रशासन लाश की ही तरह होता है, ज्यादा जोर लगाओ तो अकड़ जाता है।

अंततः कुछ देर तक 'प्रशासन हाय-हाय' चला, फोटू खींचे गए और प्रदूषण की चिंता किए बिना लाश को चौराहे पर फूंक दिया गया। लेकिन प्रशासन न जलता है, न फुंकता है, ना ही उसे दफनाया जा सकता है। प्रशासन के पास जीने के लिए समस्याओं का अमृत है जिसे पीकर, हर चौराहे पर जूते खाकर, जल कर, दफनाए जाने के बाद भी वह जी उठता है। प्रशासन को जूते मार, फूंक कर भीड़ अपने घरों में घुस गई।

अखबारों ने प्रशासन को लताड़ा। चैनलों ने प्रशासन की नाकामियों को नंगा कर दिया। प्रशासन यह सब देख फिर लाश की तरह अकड़ गया।

शहर आज फिर खामोश हो गया। स्कूल की छुट्टी हो गई। जुलूस सड़कों पर था। चार कंधों पर प्रशासन की लाश थी। हाय-हाय करने वाले भी वे ही थे, जो प्रशासन को निकम्मा और लापरवाह बता रहे थे। प्रशासन की लाश को फिर जलाया गया, दफनाया गया और भीड़ घरों में घुसकर प्रशासनिक लाल कार्रवाई पर बहस कर रही थी। पहले भी बंद सफल था, आज भी कोई हल्ला नहीं। जो नहीं किया वह अच्छा था, जो किया वह भी अच्छा। भीड़ में शामिल लोग प्रशासन का हिस्सा थे, और रहेंगे। हर बार प्रशासन मरता है, लापरवाही का जूता खाता है, फिर जिंदा हो उठता है।

स्कूल की छुट्टी हो गई थी। मास्टरजी चाय पी रहे थे, भीड़ जुलूस में थी। चैनल पर बहस हो रही थे। अखबार में एक लाइन लिखी थी- यह ठीक नहीं है?

खामोश.... बंद चहक रहा है।

ट्वीट-ट्वीट

संसद में बहुमत की आवाज ही सुनी गई। अब न्यायपालिका के अतिरिक्त भारत की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी 16 गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर है, जिनको कैब को लागू करना है। पंजाब, केरल, बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने तो कैब और एनआरसी को ना कह दिया है। अन्य को भी रुख स्पष्ट करना चाहिए।
प्रशांत किशोर@PrashantKishor

आपको यह बात पता होगी कि एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश-निर्देश में शुरू की गई और कैब संसद से पारित होने वाला कानून है। इसे लागू करने से इन्कार करने वाले राज्य स्वत: अनुच्छेद 356 के दायरे में आ जाएंगे और बर्खास्तगी की स्थिति में पहुंच जाएंगे।
अभिजीत अय्यर मित्रा@Iyervval

एबी शिंजो का दौरा स्थगित होना असम के लिए क्षति है। यह सम्मेलन एशिया को एकजुट करने में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका उभारने वाला था। लोगों को सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा को लेकर चिंता करने का हक है, पर हिंसा हल नहीं है। ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

जागरण जनमत

कल का परिणाम

डाटा प्रोटेक्शन कानून से लोगों की निजी सूचनाओं में सेंधमारी पर अंकुश लगेगा?

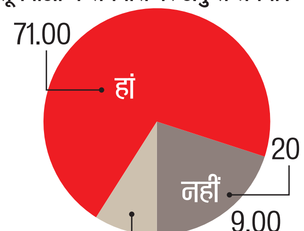

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर के कुछ लोगों का विरोध उचित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बोलें जो वे खुद नहीं जान रहे जब अर्थ,
फिर क्यों अपनी खोपड़ी फोड़ें उसपर व्यर्थ।
फोड़ें उसपर व्यर्थ अभी मानुष है कच्चा,
अड़तालीस की उम्र मगर दिल तो है बच्चा!
करि विपक्ष पर वार पोल अपनी ही खोलें
फंसते राहुल भ्रात बिना सोचे जब बोलें।
- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

आखिर इतने परेशान क्यों हैं पीके?

मनोज झा
स्थानीय संपादक, बिहार

राजनीति में ऐसे कई मौके आते हैं, जब देश और समाज के दीर्घकालिक या बड़े हित को देखते हुए आपको दूसरों के भी किसी वादे के पूरा होने में मददगार बनना पड़ता है। चाहे वह मुद्दा आपके एजेंडे में न भी हो, लेकिन तब आपको सियासी चश्मा उतार व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। समाज के कमजोर तबके को दस फीसद आरक्षण या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति ऐसे ही कुछ हालिया मामले हैं। बेशक इन फैसलों की पहल केंद्र सरकार ने की, पर सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर के भी कई दलों ने इनका समर्थन किया।

ताजा मामला नागरिकता संशोधन कानून का है। इसे संसद से पारित कराने में राजग से बाहर की भी कई अन्य पार्टियों ने सरकार का साथ दिया। राजग का घटक होने के नाते नीतीश कुमार की अगुआई वाले जनता दल (यू) और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने भी स्वाभाविक रूप से विधेयक के पक्ष में मतदान किया। हालांकि जदयू के अंदर ही विरोध के कुछ स्वर उभर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व की ओर से उन्हें संदेश दिया जा रहा है कि विधेयक का समर्थन आनन-फानन नहीं, बल्कि सोच-समझकर किया गया है। पार्टी ने इस नजरिये का समर्थन किया है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं, देश में वर्षों से रह रहे विदेशी अल्पसंख्यक शरणार्थियों के आंसू पोंछने का प्रयास भर है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बिहार की सियासत में भी दो पाले खिंच गए हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ राजग है, जो कानून के समर्थन में है तो दूसरी ओर विपक्ष का महागठबंधन है। राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन सत्तारूढ़ जदयू के अंदर के कुछ विरोधी सुर जरूर चौंका रहे हैं। संसद में इस बिल पर बहस के दौरान जदयू नेता आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने अपने वक्तव्य में साफ कहा कि इस कानून के जरिये लंबे समय से भारत में शरणार्थी का जीवन जी रहे लोगों को राहत मिल जाएगी। भला इस बात में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बावजूद इसके, प्रशांत किशोर जैसे कुछ लोग इस मुद्दे पर पार्टी का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्हें पार्टी की ओर से हिदायतें भी दी जा रही हैं, लेकिन इसका कोई असर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या विरोध के बहाने कहीं यह नये सियासी ठौर-ठिकाने की तलाश तो नहीं? जाहिर है कि पीके की छवि नेता से ज्यादा चुनावी प्रबंधक की है। वह नारे गढ़ सकते हैं, दलों की आपसी बातचीत में मध्यस्थ बन सकते हैं, लेकिन जहां तक वोटरों के दिल में जगह बनाने की बात है तो फिलहाल जदयू में वह कूवत तो नीतीश कुमार के पास ही है। नीतीश ने यह माद्दा चुनाव-दर-चुनाव दिखाया भी है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और तमाम दल अपनी-अपनी पेशबंदियों में जुट गए हैं। इन पेशबंदियों के बीच पीके की निगाह कहां और निशाना कहां है, यह तो वह ही बता सकते हैं, लेकिन इतना साफ है कि उनके तेवर पार्टी के हित में तो कतई नहीं हैं।

जदयू नेता प्रशांत किशोर। फाइल फोटो

पीके सुलझे हुए हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि वह नागरिकता संशोधन कानून के प्रभाव- दुष्प्रभाव से अनभिज्ञ हैं। पीके या उन जैसे अन्य को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर कौन-सा मुसलमान जान-आबरू बचाते हुए भारत आया हुआ है। कानून के विरोधियों को इसके चंद उदाहरण भी पेश करना चाहिए। यह सभी को पता है कि बांग्लादेश के लाखों मुस्लिम शरणार्थी सिर्फ और सिर्फ बेहतर जीवन-यापन की तलाश में भारत आए हैं। दूसरी ओर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थी हैं, जिनका इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। ये अपने देश से जान और इज्जत बचाकर यहां आए हैं। पाकिस्तान में गैर-इस्लामी समाज की युवतियों का आए दिन अपहरण, दुष्कर्म या जबरन विवाह या फिर ईशनिंदा में सजा देने जैसी घटनाएं इसका जीता-जागता प्रमाण है। कानून का विरोध कर रहे लोगों को ही यह बताना चाहिए इनमें से मदद किन्हें मिलनी चाहिए?

क्या उन्हें, जो अपने देश की भ्रष्ट और अपंग व्यवस्था का शिकार होकर रोजी-रोटी की तलाश में यहां आए हैं या फिर उन्हें, जिनका गैर-मुसलमान होना ही अकेला गुनाह है। क्या देश में मौजूद लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को सिर्फ इसलिए भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, क्योंकि वे वोटबैंक बन सकते हैं। क्या देश के संसाधनों पर उनका भी हमारी तरह बराबर का हक है?

जाहिर है कि विरोध करने वाले इन तमाम सवालों से बचना चाहते हैं। दरअसल, उनके पास जवाब है भी नहीं। चूंकि इस मुद्दे से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसे शब्द जुड़े हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक बताने में आसानी हो रही है। जबकि यह पूरी तरह से मानवीय और सामाजिक मुद्दा है। अभी इसका विरोध राजनीति के लिहाज से तो कइयों के लिए मुफीद हो सकता है, लेकिन जहां तक देश और समाज का सवाल है तो कालांतर में यह नासूर भी बन सकता है। जहां तक जदयू का प्रश्न है तो उसने इस कानून का समर्थन कर अपनी सियासी दूरदर्शिता और परिपक्वता का ही संदेश दिया है। साथ ही यह संदेश भी कि बिहार में राजग की एकता फिलहाल चट्टान की तरह मजबूत है और आगामी चुनावी में विपक्ष को इसी एकजुटता से लोहा लेना पड़ेगा।

चिंताजनक

सभी मुठभेड़ की होनी चाहिए जांच

विजय कपूर
स्वतंत्र टिप्पणीकार

एक आयोग द्वारा हाल में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में आज से सात वर्ष पहले सुरक्षाबलों ने एक फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया था। ऐसे में इस तरह की सभी घटनाओं की जांच जरूरी हो जाती है

प्रतीकात्मक

छत्तीसगढ़ के सर्केगुडा व कोट्टागुडा गांव के 17 निहत्थे ग्रामीण 28 जून 2012 को सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए थे। तब सरकार ने इसे 'सबसे बड़ी माओवादी मुठभेड़' कहा था। लेकिन अब जस्टिस वीके अग्रवाल आयोग ने स्थापित किया है कि इस घटना के बारे में सीआरपीएफ व पुलिस ने जो कहानी सुनाई थी, वह गलत और झूठी थी। 15 ग्रामीणों को 'अनावश्यक बल प्रयोग' से करीब से मारा गया। एक व्यक्ति की अगली सुबह उसके घर में हत्या की गई, जबकि एक की बाद में अस्पताल में मृत्यु हुई। आयोग के अनुसार, सुरक्षाबलों को लगीं तथाकथित चोटें दिखावे के लिए आपस में मारी गईं।

हालांकि सरकार का दावा है कि वह धीरे-धीरे, लेकिन माओवादी लड़ाकों के विरुद्ध 'युद्ध' जीत रही है और मानवाधिकार उल्लंघनों को माओवादियों या उनके समर्थकों का प्रोपगेंडा कहकर खारिज करती है। साथ ही उसने इन क्षेत्रों में काम कर रहे वकीलों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर भविष्य के संभावित आरोपों पर विराम लगाने का भी प्रयास किया है। लेकिन स्वयं सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट आरोपों की विश्वसनीयता की पुष्टि करती है, इसलिए सभी एक्स्ट्रा-जुडिशियल हत्याकांडों यानी सरकारी संरक्षण में अवैध तरीके से की गई हत्या की जांच करने के लिए एक पैनल गठित किया जाए।

यह कोई पहला अवसर नहीं है जब बस्तर की घटनाओं के सिलसिले में किसी आयोग ने सुरक्षाबलों को दोषी पाया है। मार्च 2011 में ताडमेटला, मोरपल्ली व तिम्मापुरम के गांवों में सुरक्षाबलों ने 160 से अधिक घरों में आग लगाई और तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआइ को सौंपी, जिसने 2016 में दी गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस की इस बात का खंडन किया कि गांवों में माओवादियों ने आग लगाई थी। इस घटना के लिए सुरक्षाकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया और सात विशेष पुलिस अधिकारियों को चार्जशीट किया गया। मई 2011 में जांच के लिए जस्टिस टीपी शर्मा आयोग भी गठित किया गया था। इसी तरह अक्टूबर 2015 में बीजापुर जिले के पेदागेल्लुर व चिन्नागेल्लुर गांवों की तीस से अधिक महिलाओं ने सुरक्षाबलों पर यौन हिंसा का आरोप लगाया। यह खबर जब अखबारों में छपी तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और जनवरी 2017 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि प्रथम द्रष्टया प्रतीत होता है कि 16 महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा हुई और आयोग ने अन्य 20 महिलाओं के बयान रिकॉर्ड करने का भी आदेश दिया। कुछ अन्य घटनाएं भी हैं जिनमें अभी जांच चल रही है, जैसे मई 2013 में झीरम में कांग्रेस नेताओं महेंद्र करमा, विद्याचरण शुक्ल व नंद कुमार पटेल सहित 27 व्यक्तियों की हत्या।

इसकी एनआइए को जांच सौंपी गई। उसने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, लेकिन जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की जांच इसमें अभी जारी है। दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार ने इस हमले की जांच के लिए एसआइटी की घोषणा की। मई 2013 में एडेस्मेटा में एक सीआरपीएफ का जवान व आठ तथाकथित माओवादी 'मुठभेड़' में मारे गए। अग्रवाल आयोग इसकी भी जांच कर रहा है। अगस्त 2018 में सुरक्षाबलों ने सुकमा में 'मुठभेड़' में 15 लोग मारे। सिविल लिबर्टीज कमिशन ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए एक लिखित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जो अभी विचाराधीन है।

सर्केगुडा व कोट्टागुडा मामले में बचाव पक्ष के वकीलों का यह तर्क था कि ग्रामीणों ने अपनी गवाही देर से दी और उन्होंने एफआइआर भी दर्ज नहीं कराई। लेकिन आयोग ने ग्रामीणों की गवाही को पारिस्थितिकीय साक्ष्यों, जिनके आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट दी, के अनुरूप पाया। एफआइआर दर्ज न करने से यही साबित होता है कि ग्रामीणों को पुलिस पर भरोसा नहीं था, खासकर इसलिए कि पुलिस ने ही तो हत्याएं की थीं। दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन सलवा जूडुम मामले में सरकार के अपने एफिडेविट्स स्थापित करते हैं कि पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायतों पर कभी कार्रवाई नहीं की है। आयोग ने ग्रामीणों की सिर्फ एक बात को नहीं माना कि रात में बैठक बीज-रोपण उत्सव की तैयारी में हो रही थी। हालांकि इस बात का जिक्र है कि उसमें 'आपराधिक रिकॉर्ड' के कुछ लोग शामिल थे। लेकिन जिस क्षेत्र में किसी पर भी कुछ भी आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है, उसमें 'आपराधिक रिकॉर्ड' वाले लोग तो दर्जनों मिल जाएंगे।

जहां तक पुलिस का तर्क है तो इस क्षेत्र में हर कोई 'विद्रोही' है, यह जानते हुए भी कि इसमें तीन बच्चे स्कूल जाते थे जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच थी। डीआइजी एस एलांगो ने अपने शपथपत्र में दावा किया कि 16 विद्रोही मारे गए हैं। लेकिन हैरत यह है कि आयोग ने 'दोषियों' पर मुकदमा चलाने या पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की कोई सिफारिश नहीं की।

आश्चर्य इस पर भी है कि कांग्रेस जब छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थी तो उसने सर्केगुडा व कोट्टागुडा हत्याकांड और ताडमेटला आगजनी, दुष्कर्म मामलों को उठाया था, लेकिन इस दिशा में कुछ किया नहीं है। कांग्रेस ने आदिवासी कैदियों को रिहा करने व पत्रकारों के उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए समितियां गठित की हैं पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, फर्जी मुठभेड़, दुष्कर्म आदि समस्याओं को संबोधित करने के लिए कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। जबकि इस संदर्भ में 2008 की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट व 2011 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिन्हें वहां की सरकारें अनदेखा करती आ रही हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी एक्स्ट्रा-जुडिशियल हत्याओं की जांच के लिए एक पैनल गठित करे ताकि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले।

- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

2018 में देश में 4,29,928 मामले मलेरिया के, जबकि 1,01,192 मामले डेंगू के सामने आए थे। 2017 में डेंगू और मलेरिया के क्रमश: 8,44,558 व 1,88,401 मामले रिकॉर्ड किए गए थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 दिसंबर 2019

दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में
निर्मला सीतारमण 34वें पायदान पर

शुक्रवार को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सौ शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इस बार तीन भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। इस सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल की सीईओ रोशनी मल्होत्रा नादर और बायकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने क्रमश: 34वीं, 54वीं और 65वीं रैंक हासिल की है। वहीं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर रहीं। 2019 की इस सूची में विश्व भर की उन महिलाओं को चुना गया हैं, जो सरकार, बिजनेस, जनसरोकार और मीडिया में नेतृत्व कर रही हैं और एक्शन ले रही हैं।

देश की पहली महिला वित्त मंत्री

सूची में 34वां स्थान बनाने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। वह पूर्णकालिक रूप से यह मंत्रालय संभालने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला था।

रोशनी मल्होत्रा नादर >>

54वां स्थान पाने वाली रोशनी मल्होत्रा नादर 8.9 अरब डॉलर वाली टेक कंपनी एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ के रूप में सभी रणनीतिक निर्णयों लिए उत्तरदायी हैं।

ग्रेटा थनबर्ग, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, 100 >>

रिहाना, गायिका, (61 रैंक)

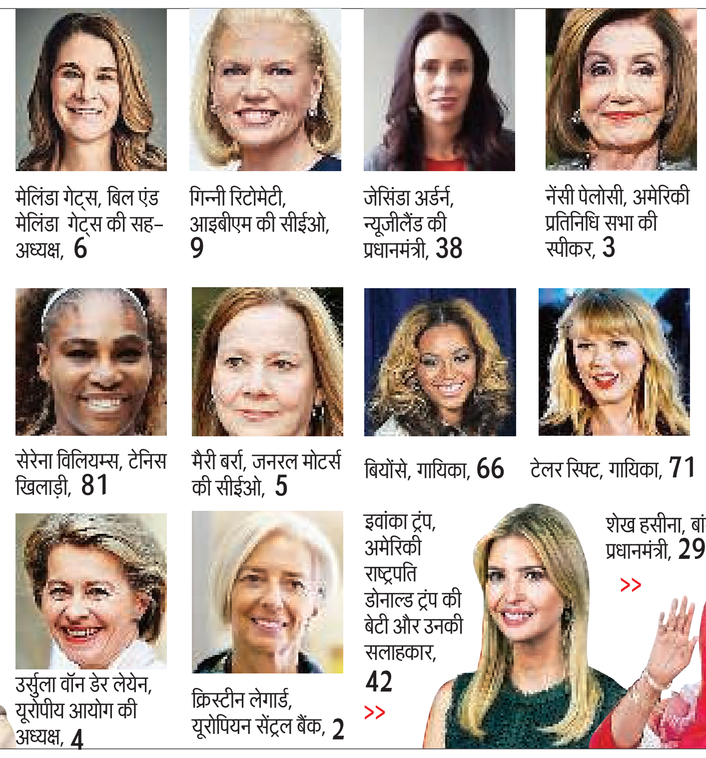

मेलिंडा गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की सह-अध्यक्ष, 6

गिन्नी रिटोमेटी, आइबीएम की सीईओ, 9

जेसिंडा अर्डर्न, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, 38

नेंसी पेलोसी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर, 3

सेरेना विलियम्स, टेनिस खिलाड़ी, 81

मैरी बर्रा, जनरल मोटर्स की सीईओ, 5

बियोंसे, गायिका, 66

टेलर स्विफ्ट, गायिका, 71

उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, 4

क्रिस्टीन लेगार्ड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, 2

किरण मजूमदार शॉ >>

सूची में 65वें स्थान पर किरण भारत की सबसे अमीर स्व-निर्मित महिला हैं और 1978 में देश की सबसे बड़ी बायो फार्मास्युटिकल फर्म बायोकॉन की संस्थापक हैं।

शेरिल सैंडबर्ग, फेसबुक के सीईओ, 18

इवांका ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनकी सलाहकार, 42 >>

शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, 29 >>

एंजेला मर्केल, जर्मन चांसलर, 1 >>

बोर्ड में 80 फीसद अंक लाओ हवाई सैर का मौका पाओ

हवाई सैर कर मुंबई पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुसुरपुट्टा गांव के मेधावी बच्चे गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटो खिंचाते हुए। सौजन्य : कर्मचारी जन्मभूमि प्रकोष्ठ मुसुरपुट्टा

जागरण विशेष

संदीप तिवारी, रायपुर

> छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव मुसुरपुट्टा की रोचक पहल, बोर्ड परीक्षा के मेधावियों को गांव वाले चंदा जोड़ कराते हैं हवाई यात्रा

छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव मुसुरपुट्टा की यह पहल बदलते भारत की एक अलग तस्वीर पेश करती दिखती है। गांव के बच्चों में शिक्षा के प्रति लगन पैदा हो और तमाम दुश्वारियों को पीछे छोड़ सफलता की उड़ान भरने का जज्बा उनमें जागे इसके पीछ मकसद सिर्फ इतना है। लिहाजा, गांव वालों ने मिलजुल कर यह अनूठी युक्ति खोजी। तय किया कि गांव का जो भी बच्चा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाएगा, उसे हवाईजहाज में उड़ान भरने का मौका मिलेगा।

साल 2008 से शुरू हुई इस पहल का परिणाम गांव के बच्चों के बेहतर होते रिजल्ट के रूप में सामने है। तब से 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। परीक्षा परिणाम करीब दोगुने बढ़ गया है। गांव वाले अपने वादे पर खरे हैं और हर साल ऐसे सभी बच्चों को हवाईजहाज से मुंबई, दिल्ली, आगरा जैसे चुनिंदा स्थानों तक भ्रमण को ले जाया जा रहा है। टॉपर्स को तो नेपाल और भूटान तक भी। बड़ी बात यह कि यह धनाड्यों का गांव नहीं है, वरन साधारण किसान और कुछ नौकरीपेशा परिवारों का गांव है। मेधावी बच्चों को इन्होंने आपस में चंदा जोड़कर हवाई सैर कराने का सिलसिला शुरू किया। पूछने पर कहते हैं, बच्चों का भविष्य तो संवर ही रहा है, शिक्षा से पूरे समाज में आए बड़े बदलाव को भी आप यहां देख सकते हैं...।

कांकेर के दुधावा स्थित गांव मुसुरपुट्टा से परवान भरती यह बड़ी सोच समूचे ग्रामीण भारत के लिए मानो एक बड़ा संदेश भी है। सरकारी स्कूल में शिक्षण स्तर की शिकायत, शिक्षकों और पुस्तकों की कमी की शिकायत, मिडडे मील में गुणवत्ता की शिकायत, दाल में गिरते चूहे और कॉकरोच की शिकायत, शालेय गणवेश और जूते न मिल पाने की शिकायत, स्कूल की जर्जर होती इमारत की शिकायत..., भारत के गांवों में शिकायतें तमाम रही आई हैं। लेकिन मुसुरपुट्टा के ग्रामीणों ने शिकायतों और दुश्वारियों को पीछे छोड़ पढ़ने, बढ़ने और उड़ने का प्रभावी संदेश दिया है। मुसुरपुट्टा के इस जज्बे के पीछे ग्रामीण भारत की उस बेचैनी को भी महसूस किया जा सकता है, जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के दशकों पुराने अधूरे सपने से उपजी है। मुसुरपुट्टा इस अधूरे सपने को आंखें खोलकर देखने और पूरा करने का जतन कर रहा है। बीते 12 साल से इस गांव के बच्चों की हवाई उड़ान का सफर बदस्तूर जारी है। हर साल संख्या बढ़ती जाती है। मेधावी बच्चों को अब तक दिल्ली, आगरा, मथुरा, अमृतसर, जम्मू-कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई जैसे स्थानों का भ्रमण कराया जा चुका है। बोर्ड की प्रवीणता सूची में जगह बनाने वाले गांव के बच्चों को तो विदेश यात्रा (नेपाल और भूटान) भी भेजा गया। बच्चों के साथ उनके स्वजन भी हवाई यात्रा करते हैं। इसका खर्च गांव के ही लोग उठाते हैं, जिसके लिए उन्होंने जन्मभूमि प्रकोष्ठ नामक समिति बनाई है।

12 साल में 50 से 92 पर पहुंचा रिजल्ट

गांव की आबादी दो हजार है। इसमें से करीब 100 परिवारों में कोई एक सदस्य सरकारी नौकरी में है, कुछ लोग अन्य काम-धंधा करते हैं, जबकि शेष किसान हैं। गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। प्राइमरी के बाद बच्चे आसपास के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। पहले इन स्कूलों में परिणाम प्रतिशत 50 तक सीमित था, लेकिन वर्तमान में यह 80 से 92 प्रतिशत तक जा पहुंचा है।

इस बार सिंगापुर

बीते एक दशक में गांव के इन मेधावी बच्चों ने सफलता का डंका पीटा है। इंजीनियर और डॉक्टर से लेकर अन्य उच्च पदों तक उड़ान भरकर दिखाई है। प्रकोष्ठ के सदस्य अरविंद भारती बताते हैं कि अब हमारा काम आसान हो चला है क्योंकि गांव में सफल और सुशिक्षित पीढ़ी तैयार हो चली है, जो नई पीढ़ी को राह दिखाने में लग गई है। प्रकोष्ठ के संयोजक धनराज मरकाम (डिप्टी कलेक्टर), धनराज भास्कर, भीखम साहू, दीनानाथ नेताम, शिवराज जैसे युवाओं ने बताया कि इस बार (बोर्ड परीक्षा 2019-20) में राज्य की टॉपटेन सूची में जगह बनाने वाले बच्चों को सिंगापुर और स्कूल स्तर पर टॉप करने वाले मेधावियों को विदेश भ्रमण कराया जाएगा।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

प्लास्टिक वेस्ट से तैयार टाइल्स से संवारे जाएंगे घर

तलाशी राह ▸ 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल लेंगी ये टाइल्स

भार वहन की क्षमता 3.5 टन पानी से भी नहीं होंगी खराब

जागरण संवाददाता, रूपनगर

प्लास्टिक वेस्ट वर्तमान में दुनियाभर में एक बड़ी समस्या बना हुआ है। दुनियाभर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इससे निपटने के रास्ते तलाश रहे हैं। इस कड़ी में पंजाब की रयात बाहरा यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चार छात्रों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से ऐसी टाइल्स तैयार की हैं, जो 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल सकती हैं। साथ ही इनकी भार वहन की क्षमता 3.5 टन है।

रयात बाहरा यूनिवर्सिटी के छात्र साहिल, ऋत्विक, शुभम और विकास ने यूनिवर्सिटी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा किया। इसके बाद टाइल्स बनाने पर काम शुरू किया। प्लास्टिक वेस्ट से टाइलें बनाने का विचार उनके प्रोजेक्ट गाइड और विभाग के प्रमुख इंजीनियर अभिनव ए त्रिपाठी से मिला।

छात्रों का कहना है कि ये टाइल्स एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबायल हैं।

पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित रयात बाहरा यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की तरफ से प्लास्टिक वेस्ट से तैयार की गईं टाइल्स। जागरण

वजन में हल्की मजबूती भरपूर

एक प्लास्टिक टाइल का वजन 700 ग्राम है, जबकि सामान्य टाइल का वजन डेढ़ किलो से ढाई किलोग्राम तक होता है। हालांकि, इनकी मजबूती सामान्य टाइल्स जितनी ही होगी।

टाइल की भार वहन क्षमता 3.5 टन है। यह 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भी झेल लेगी। टाइल को दो दिन तक पानी में रखने पर भी इसके आकार या भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन टाइल्स को खराब होने पर दोबारा निर्माण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टाइल्स सीमेंट वाली फर्श टाइल्स की तुलना में सस्ती पड़ेंगी। इनके निर्माण के लिए सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें शैंपू की प्लास्टिक बोतलें, दूध की थैलियां, टूटे कप, नान कारबोनेटड पीने की बोतलों का प्रयोग ही किया गया है।

चार से पांच रुपये है एक टाइल पर खर्च : छात्र साहिल का कहना है कि वेस्ट प्लास्टिक को ओपन हर्थ फरेंस में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर टाइल्स बनाई जा रही हैं। फरेंस में स्टीम कोल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा रहा है। एक किलो कोल जलाने से चार से पांच टाइल्स बन जाती हैं। स्टीम कोल 20 रुपये किलो में मिल जाता है। ऐसे में एक टाइल पर कुल चार से पांच रुपये खर्च आता है। मार्केट में सामान्य टाइल 10 से 15 रुपये में मिलती हैं।

खोई और शीरे से इथेनॉल और बिजली बनाना सीखेगा चीन

- चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ना प्रबंधन तकनीक का प्रशिक्षण
- नाइजीरिया, श्रीलंका व मिस्र में हाईटेक लैब का भी करार
- एनएसआइ टीम अगले साल से तीनों देशों में शुरू कर देगी काम

गन्ना प्रबंधन में चीन ने मांगी है भारत की मदद। प्रतीकात्मक

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

शीरा व खोई जैसे गन्ने के सह उत्पादों से इथेनॉल व बिजली बनाने की तकनीक सीखने के लिए चीन ने भारत से तकनीकी सहयोग मांगा है। कानपुर स्थित एशिया के इकलौते सरकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) से पहले चरण की बातचीत हो चुकी है।

खपत के मुकाबले चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ना प्रबंधन में भी चीन ने मदद मांगी है। संस्थान हाल ही में नाइजीरिया, श्रीलंका व मिस्र में हाईटेक लैब स्थापित कराने व उनके तकनीशियन को प्रशिक्षित करने का करार कर चुका है। एनएसआइ के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन बताते हैं कि चीन में गन्ने के सह उत्पादों का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। गन्ने की प्रोसेसिंग व चीनी बनाने की तकनीक में भी वह हमसे बहुत पीछे है। इसी कारण चीन के गोऑक्सी शुगर डेवलपमेंट ऑफिस ने हमसे चीनी का उत्पादन बढ़ाने व गन्ना प्रबंधन के लिए सहयोग मांगा है।

भारत में गन्ने से चीनी की रिकवरी 11-12 फीसद तक है, जबकि चीन में 8.5 फीसद ही है। चीन में 150 से 160 लाख टन चीनी की सालाना खपत है। यहां की कुल 233 मिलों से 100 से 110 लाख टन ही चीनी का उत्पादन हो पाता है। इनमें भी 37 मिलें चुकंदर से चीनी बनाती हैं। चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए संस्थान चीन को गन्ने की उन्नतशील प्रजातियां बताते हुए खेती के तरीके सुझाएगा। एनएसआइ गन्ने की पेराई से निकली बेगास से बायोगैस, इथेनॉल व साबुन बनाने की तकनीक भी चीन को देगा।

मिस्र, श्रीलंका व नाइजीरिया से एनएसआइ पहले ही करार कर चुका है। श्रीलंका में शुगर केन रिसर्च सेंटर व मिस्र में शुगर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को अत्याधुनिक व हाईटेक लैब बनाने में संस्थान मदद देगा। नाइजीरिया में शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है।

पहाड़ी माल्टा पर भारी पड़ रहा पंजाब का कीनू

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी : पहाड़ का माल्टा अपने रसीलेपन के लिए खास पहचान रखता है, लेकिन इस पहचान का सही ढंग से संरक्षण न होने के कारण पहाड़ में पंजाब का कीनू कब्जा जमा रहा है। अकेले उत्तरकाशी जिले में रोजाना दो टन कीनू की खपत हो रही है।

उत्तरकाशी जिले के पुरोला, भटवाड़ी, चिन्यालीसौड़, डुंडा व नौगांव क्षेत्र में माल्टा का अच्छा-खासा उत्पादन होता हैं, जबकि पूरे जिले में माल्टा का औसत उत्पादन 469.64 मीट्रिक टन है। सबसे अधिक उत्पादन चिन्यालीसौड़ में होता है, लेकिन सही दाम न मिल पाने के कारण माल्टा गांवों से बाजार नहीं आ पा रहा। जो माल्टा बाजार में उपलब्ध है भी उसे बेहद छोटा होने के कारण लोग पसंद नहीं कर रहे, जिस कारण बाजार में कीनू की मांग बढ़ गई है।

उत्तरकाशी में कीनू 50 रुपये किलो के भाव बिक रहा है। शहर के प्रमुख फल-सब्जी विक्रेता तस्दीक खान ने बताया कि केवल उत्तरकाशी जिले में ऋषिकेश से रोजाना दो टन कीनू पहुंच रहा है। कीनू की पैदावार सबसे अधिक पंजाब व हरियाणा के निचले हिस्से में होती है। माल्टा की तरह की कीनू भी खट्टा-मीठा होता है, लेकिन माल्टा की तरह अधिक रसीला नहीं। हां, कीनू के बाहरी छिलके को हटाने में आसानी जरूर होती है।

महिला शौचालयों में पैड मुहैया करा रहा यह 'पैड हीरो'

कोलकाता नगर निगम के 70 शौचालयों में लगा चुके हैं सैनेटरी पैड बॉक्स, पैड रखने का जिम्मा भी संभाल रहे

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

- महिला सहकर्मी की परेशानी देखकर शुरू की मुहिम
- ब्रांडेड सैनेटरी पैड के लिए सिर्फ तीन रुपये देने पड़ते हैं
- जिन शौचालयों में पैड बॉक्स हैं, उनकी सूचना एप पर रहती है उपलब्ध

कोलकाता में सार्वजनिक महिला शौचालय में लगाए गए बक्से में सैनेटरी पैड भरते शोभन मुखर्जी। बिमल कर्मकार

कोलकाता नगर निगम के सार्वजनिक शौचालयों के गेट पर आपको छोटा सा लकड़ी का बक्सा टंगा दिखेगा। लगेगा कि लेटर बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर पत्र नहीं, सैनेटरी पैड हैं। यह व्यवस्था उन महिलाओं के लिए सहूलियत का सबब बन गई है, जिन्हें घर से बाहर रहने और अचानक पीरियड्स की स्थिति में परेशान होना पड़ सकता था।

महिलाओं की इस परेशानी को शहर के एक युवा ने महसूस किया और इसके समाधान को ठोस कदम भी उठाया।

स्वस्थ समाज

ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज निगम के 70 सार्वजनिक शौचालयों में ऐसे बॉक्स लगे हैं, जहां आसानी से सैनेटरी पैड उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, यहां ब्रांडेड सैनेटरी पैड के लिए सिर्फ तीन रुपये देने पड़ते हैं, जो बाजार में मिलने वाले इन्हीं पैड के मुकाबले कहीं कम है। उन्होंने बंधन सैनेटरी पैड नामक एप भी बनवाया है, जिसमें इस सुविधा वाले शौचालयों के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध हैं।

कोलकाता में 23 साल के शोभन मुखर्जी अब पैड मैन के रूप में मशहूर हो चले हैं। उनकी बदौलत कामकाजी महिलाओं के 'मुश्किल दिन' आसान हो गए हैं। उन्होंने इस बक्से को 'बंधन' नाम दिया है। बकौल शोभन, महिलाओं की इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए मानव बंधन तैयार करना होगा, इसलिए मैंने इस प्रयास को बंधन नाम दिया है। दक्षिण कोलकाता के बांसद्रोणी इलाके के रहने वाले शोभन ने बताया, मैंने अक्टूबर, 2017 में अपनी एक महिला सहकर्मी को कार्यस्थल पर बेहद परेशानी का अनुभव करते देखा था। तभी से यह ठान लिया कि इसके समाधान को कुछ करूंगा। मैंने पहले 50 महिलाओं पर सर्वे किया, जिसमें 42 महिलाओं ने समय पर पैड न मिलने जैसी समस्या बताई। इसके बाद मैंने अपने खुद कुछ रुपये लगाकर एक हजार सैनेटरी पैड खरीदे और बांसद्रोणी के एक सार्वजनिक शौचालय में उन्हें टेबल पर रखवा दिया। यह पूरी तरह निश्शुल्क था। उसके बाद जब देखा कि वाकई इनकी जरूरत महिलाओं को पड़ती है, तब वहां बक्सा लगाकर उसमें सैनेटरी पैड भर दिए। अपनी जेब से हर महीने निश्शुल्क पैड बांटना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन मेरे प्रयास की जानकारी मिलने पर एक सैनेटरी पैड वितरक मेरी मदद को आगे आए। वे उत्पादन लागत पर मुझे पैड मुहैया करा रहे हैं। मुझे 3.30 रुपये में एक ब्रांडेड पैड देते हैं, जिसे मैं तीन रुपये में इन बक्सों के जरिए उपलब्ध कराता हूं। प्रत्येक पैड पर 30 पैसे की जो अतिरिक्त लागत आती है, वह मैं अपनी जेब से देता हूं। 70 शौचालयों से एक दिन में करीब हजार पैड का इस्तेमाल हो जाता है। प्रत्येक बक्से में 100 पैड रखे जाते हैं। शोभन अपनी स्कूटी पर पैड का बंडल लादकर सुबह और शाम एक-एक चक्कर लगाते हैं, जिस शौचालय में पैड खत्म होने की खबर मिलती है, वहां पहुंच जाते हैं।

शोभन को इस काम में परिवार का पूरा समर्थन मिला। उनके पिता सत्येंद्र मुखर्जी बैंक कर्मी व मां सुतपा मुखर्जी गृहिणी हैं। शोभन ने एमएससी तक की पढ़ाई की है। अपने प्रयास को वह अब बंगाल के ग्रामीण इलाकों में ले जाना चाहते हैं।

बंगाल में पहला ट्रांसजेंडर शौचालय खोलने का भी श्रेय

बंगाल में पहला ट्रांसजेंडर शौचालय खोलने का श्रेय भी शोभन को जाता है। उनके अथक प्रयास से ही अगस्त, 2017 में बांसद्रोणी में निगम के शौचालय में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई थी। शोभन ने अपनी उस पहल को त्रिधारा नाम दिया था। आज कोलकाता के गोलपार्क, गरिया, नाकतल्ला समेत विभिन्न इलाकों में 15 ट्रांसजेंडर शौचालय हैं। बता दें कि देश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय भोपाल में खुला था।

अक्षय कुमार ने दिया अवार्ड

शोभन के काम की तारीफ बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी कर चुके हैं। उन्होंने शोभन को 'पैड हीरो अवार्ड' से सम्मानित करने मुंबई भी आमंत्रित किया था।

सूरजकुंड मेला

एक से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा मेला, ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का दीदार कराएगा पर्यटन विभाग

पर्यटकों को कुंड से जोड़ने को उकेरी जाएंगी सूर्य की प्रतिकृतियां

अनिल बेताब, फरीदाबाद

नए वर्ष में एक से 16 फरवरी तक लगने वाले 34वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में देश-विदेश के पर्यटकों को कुंड से जोड़ने के लिए सूर्य देव की प्रतिकृतियां उकेरी जाएंगी। पर्यटकों का सूरजकुंड के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए सूरजकुंड मेला प्राधिकरण इस बार इस तरह से तैयारियों में जुटा है, जिसमें परिसर के अलग-अलग कोने में सूरजकुंड का इतिहास नजर आए। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर रितु बेरी ने इसके लिए प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण ने रितु बेरी को मेले के लिए मानद सलाहकार बनाया है।

बता दें कि पहले तोमर कुल के राजा सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी में यह कुंड बनवाया था। वह सूर्य देव के उपासक थे। इस कुंड का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। इस कुंड के पीछे एक सूर्य मंदिर था, लेकिन हैरत की बात है कि पिछले वर्षों तक आयोजित किए गए सूरजकुंड मेले में पर्यटन विभाग ने इस कुंड के प्रचार-प्रसार पर ध्यान ही नहीं दिया और न ही लोगों को इसका इतिहास बताने के प्रयास किए गए। दैनिक जागरण ने कई बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि सूरजकुंड के नाम पर शुरू किए जाने मेले में आने वाले पर्यटकों को इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। इसलिए अब पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन के प्रयासों से मेला परिसर में अलग-अलग जगह कहीं पेंटिंग तो कहीं सूर्य देव की प्रतिकृति से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।

सूरजकुंड में सूर्य उपासक महाराजा सूरज पाल की ओर से बनाया गया कुंड। फाइल

> फैशन डिजाइनर रितु बेरी के प्लान के मुताबिक पर्यटन विभाग की ओर से मेला परिसर में इंटीरियर का काम किया जाना है। हम प्रयास करेंगे कि हर पर्यटक को सूरजकुंड के इतिहास के बारे में जानकारी दें। कहीं तस्वीरें, कहीं पेंटिंग तो कहीं इंटीरियर से सूर्य देव की प्रतिकृति को दिखाया जाएगा। मकसद सिर्फ पर्यटक को आकर्षित करके उस कुंड तक लाना है, जो सूर्य उपासक राजा सूरजपाल ने बनवाया था।
>
> **-राजेश जून, नोडल अधिकारी, सूरजकुंड मेला**

अब कोहरे में भी 75 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

- इंजन में आधुनिक फॉग डिवाइस लगाई, कलर लाइट सिग्नल सिस्टम का किया जाएगा प्रयोग
- सेटेलाइट से संचालित होने वाली डिवाइस चालक को उपलब्ध कराएगी सूचना

कोहरे में भी तेज गति से ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। रेल प्रबंधन ने 75 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाना तय किया है। हर साल कोहरे में ट्रेनें 24-24 घंटे तक देरी से चलती थीं। इसमें सुधार करने के लिए रेल प्रशासन ने आधुनिक फॉग डिवाइस और कलर लाइट सिग्नल को हथियार बनाया है। रेलवे ने कोहरे वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनों के इंजन में सेटेलाइट से संचालित होने वाली आधुनिक फॉग डिवाइस लगाई है, जो चालक को सिग्नल की सूचना उपलब्ध कराएगी। कलर लाइट सिग्नल सिस्टम में तेज रोशनी व कोहरे में भी दूर तक रोशन देने वाला बल्ब लगाया है।

रेलवे ने फॉग हट की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। जहां फॉग हट बनायी जाती है, वहां से रेललाइन की बीच के क्षेत्र को सफेद रंग से रंगा गया है। कोहरे में ट्रेन की लाइट पड़ने पर यह चमकने लगेगा। पिछले साल तक रेलवे कोहरे वाले क्षेत्रों में ट्रेनों की अधिकतम गति 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित करता था। इस साल इसकी गति बढ़ाकर 75 किमी प्रति घंटा निर्धारित की है। इससे कोहरे में ट्रेनें अधिकतम एक से दो घंटे देरी से चलेंगी। प्रवर मंडल संरक्षा अधिकारी आरके तायल ने बताया कि कोहरे में ट्रेन चलाने के बारे में चालकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही विवेक के आधार पर ट्रेन चलाने का आदेश दिया है। ताकि कोहरे में ट्रेनें कम से कम लेट हों।

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...
नई दिल्ली, शनिवार, 14 दिसंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें: sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

अब्दाली के कत्लेआम का शिकार हुई थी दिल्ली

दिल्ली की देहरी

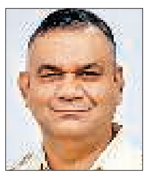

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहदों की तरफ से विदेशी अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हुए, जिसका सिलसिला सन् 1748 से शुरू होकर लगभग बीस साल तक जारी रहा। लगातार इन हमलों से और हिंदुस्तान के अंदर परस्पर गृह युद्धों से दिल्ली ऐसी तबाह और बर्बाद हुई कि फिर डेढ़-दो सौ बरस तक आबाद न हो सकी। यह बात कम जानी है कि अब्दाली ने कुल आठ बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। पहला हमला वर्ष 1748 के आरंभ में किया। उसके बाद तो मानों हमलों की झड़ी लग गई। प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध 'स्वतंत्रता संघर्ष इतिहास' में लिखते हैं कि तब देश विभिन्न राज्यों में बंट गया था और उनमें काफी प्रतिद्विंद्विता और टकराव था। इस टकराव ने किसी हद तक सांप्रदायिकता का रूप धारण किया। जब मराठाओं ने हिंदू पादशाही का नारा लगाया और शाह वलीउल्लाह ने मराठा काफिरों को दिल्ली से मार भगाने के लिए अफगानिस्तान के अब्दाली को आमंत्रित किया। अब्दाली के सैनिकों ने जब दिल्ली लूटनी शुरू की तब उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को बुरी तरह सताया, दोनों पर अत्याचार किए, यहां तक कि शाह वलीउल्लाह को भी घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। अब्दाली के अत्याचारों से परेशान होकर दिल्ली छोड़ने वाले लोगों में मियां नजीर भी थे। उस समय उनकी आयु 22-23 वर्ष थी।

सन् 1756-57 में मराठा सेनापति रघुनाथ राव की अनुपस्थिति में अब्दाली ने न केवल दिल्ली को लूटा बल्कि अपनी लूटपाट का दायरा मथुरा, गोकुल और वृंदावन तक फैला दिया। मुगल बादशाह आलमगीर के शासनकाल के दूसरे वर्ष में अब्दाली ने दूसरी बार सिंधु नदी को पार किया। मुगल वजीर गाजीउद्दीन ने नरेला में अब्दाली के सन्मुख अपना आत्म-समर्पण कर दिया।

दिल्ली आने पर उसको डटकर लूटा गया, उसे एक करोड़ रुपया देना पड़ा और अपना वजीर पद छोड़ना पड़ा। अब्दाली दिल्ली के तख्त (29 जनवरी 1757) पर बैठ गया तथा उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। मराठों की गैर-हाजिरी में इमाद-उल-मुल्क को अब्दाली से समझौता करना पड़ा, जो नजीबुद्दौला को मीर बक्शी और व्यवहारतः दिल्ली दरबार में अपना प्रतिनिधि बनाकर लौटा गया। अब्दाली को जिस एक मात्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा वह था जाट राजा का प्रतिरोध, जो डीग और भरतपुर के अपने शक्तिशाली किलों में दृढ़ता से डटा रहा।

कितने ही हंगामे दिल्ली में उर्दू के मशहूर शायर मीर तकी मीर की आंखों के सामने हुए और कितनी ही बार मौज-ए-खून उनके सर से गुजर गई। अब्दाली के पहले हमले के वक्त वर्ष 1748 मीर रिआयत खां के साथ लाहौर में मौजूद थे और पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 के भी दर्शक थे। दिल्ली में इस विदेशी विजेता और देश के अंतर गृह युद्ध करने वालों ने लूटमार मचाई। इसमें मीर का घर भी बर्बाद हुआ। इस युग के माली नुकसानों और नैतिक पतन की भयानक तस्वीरें, मीर की शायरी और आपबीती 'जिक्र-ए-मीर' में सुरक्षित हैं।

जिक्र-ए-मीर में अब्दाली की फौजों के हाथों दिल्ली की यह तस्वीर है-बंदा अपनी इज्जत थामे शहर में बैठा रहा। शाम के बाद मुनादी हुई कि बादशाह ने अमान दे दी है। रिआया को चाहिए कि परेशान न हो मगर जब घड़ी भर रात गुजरी तो गारतगरों ने जुल्म-ओ-सितम ढाना शुरू किए। शहर को आग लगा दी। सुबह, जो कि कयामत की सुबह थी, तमाम शाही फौज और रोहिल्ले टूट पड़े और कत्ल व गारत में लग गए। मैं कि फकीर था अब और ज्यादा दरिद्र हो गया, सड़क के किनारे जो मकान था वह भी ढहकर बराबर हो गया।

पानीपत में विजय प्राप्त करने के उपरांत अब्दाली ने विजयोल्लास के साथ दिल्ली में प्रवेश किया तथा उसने सूरजमल के विरुद्ध अभियान करने के संबंध में विचार किया क्योंकि उसने मराठाओं को शरण दी थी। दिल्ली से शाह के प्रस्थान के पांच दिन पूर्व समाचार प्राप्त हुआ कि सूरजमल ने अकबराबाद (आगरा) के किलेदार को किला खाली करने पर विवश कर दिया है, और किले में प्रवेश पा चुका है। अब्दाली की संतुष्टि के लिए उसने (सूरजमल) उसे एक लाख रुपया दिया तथा पांच लाख रुपया बाद में देने का वादा किया, जो कभी नहीं दिए गए। वर्षा ऋतु आ पहुंची थी तथा पृष्ठ भाग में सिखों ने अपना सिर उठाना आरंभ कर दिया, अब्दाली हठी जाट से इतना भर पाकर प्रसन्न था। 21 मई 1761 को वह शालीमार बाग (दिल्ली के बाहर) से अपने देश के लिए रवाना हुआ।

दिल्ली के इतिहास की परतों को पलटेंगे तो उस पर अग्रवाल समाज का गौरवशाली इतिहास सजा नजर आएगा। एक के बाद एक आए शासकों में तो दिल्ली की सत्ता हासिल करने की लालसा रही लेकिन अग्रवाल समाज ने दिल्ली को हर तरह समृद्ध, संपन्न व सम्मानित किया। सबरंग के इस अंक में अग्रवाल समाज किस तरह दिल्ली की धरोहर है इसी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

दिल्ली की नींव में कुछ अंश अग्रवाल समाज के

सामाजिक धरोहर

दिल्ली का बुनियादी विकास हो या धर्म, कर्म, कला, साहित्य, राजनीति और चिकित्सा हर जगह अग्रवाल समाज की उपस्थिति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दिखी। सामाजिक सरोकार से जुड़ी दिखी। तभी दिल्ली की गलियों में आज भी इनके किस्से सुनाए जाते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उप्र, बिहार तक में विकास कार्यों में जिम्मेदारी निभाई। मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया।

अग्रोतक होती थी राजधानी: दिल्ली में अग्रवाल समाज का लिखित इतिहास 900 साल पुराना पता चलता है। अग्रवाल जाति के लोग भगवान अग्रसेन के वंशज हैं। इनकी राजधानी अग्रोतक थी, जिसका वर्तमान नाम अग्रोहा है। यह हरियाणा के हिसार में स्थित है। मुहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद अग्रवाल यहां से निकलने शुरू हुए और आसपास के क्षेत्रों में निवास स्थान बनाए। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्या प्रमाण हैं? दरअसल दिल्ली निवासी मोहित अग्रवाल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अग्रवाल समाज पर किताब लिख रहे हैं। निकटवर्ती दिल्ली, हरियाणा के ही विविध हिस्सों, पश्चिमी उप्र और राजस्थान समेत पंजाब में भी गए। अग्रवालों की प्रारंभिक बस्तियां इन्हीं इलाकों में मिलती हैं। दिल्ली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जब राजपूत काल चल रहा था तो पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर के एक मंत्री नट्टल साहू थे। इन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध कवि विबुद्ध श्रीधर से पार्श्वनाथ चरित्र की रचना करवाई। नट्टल साहू अग्रवाल जैन थे। यह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इसी में सबसे पहले हरियाणा स्थित दिल्ली का वर्णन किया गया है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली, हरियाणा का भाग था और उसकी राजधानी भी। इसमें राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल में प्रशासन, राजनीति, समाज सुधार, उद्योग, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अग्रवालों के योगदान के बारे में बताया गया है।

बकौल मोहित अग्रवाल नट्टल साहू पहले ज्ञान अग्रवाल मंत्री हैं। मुगल काल में राय रामप्रताप मंत्री बने। ये एरंग गोत्र के थे। ये पहले थे जिन्हें मुगलों ने जनाना महल का मंत्री बनाया। अकबर द्वितीय ने इन्हें आली खानदान की उपाधि दी थी। राम प्रताप मूलरूप से गुड़गांव अब गुरुग्राम के रहने वाले थे। इनकी वंश परंपरा को राय की भी उपाधि मिली थी। इन्हीं की पीढ़ी से राय इंद्रमणि हुए। जिन्हें बिहार में दीवान पद सुशोभित किया। इन्हें बाद में वहां राजा भी बनाया गया। इंद्रमणि के बाद इनके परिवार के ख्याली राम थे। जो गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष थे। इनके बाद पटनिमल का जिक्र आता है। इनके नाम से पुरानी दिल्ली के पहाड़ी धीरज में पटनिमल गली और खिड़की है। बकौल मोहित ये बादशाहों के खजांची ज्यादा थे शाहजहां के समय में खंजाची बनने शुरू हुए थे और ब्रिटिश काल में भी खजांची थे।

ख्याली राम शाहजहां के समय में गुप्तचर रहे : इसी तरह एक सेठ सीताराम थे जो मुहम्मद शाह रंगीला के समय खजांची थे। इनके नाम पर सीताराम बाजार है। सीताराम ने मुहम्मद शाह रंगीला को 5 लाख रुपये उधार दिए थे। दरअसल नादिरशाह के हमले के बाद बादशाह का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। उस समय सेठ ने मदद की थी। बदले में बादशाह ने इनके निवास स्थान को सीताराम और इनके दो भाइयों के नाम पर कूचा घासी राम, कूचा पातीराम नाम रखा। ये ऐरन गोत्रीय थे। इन्होंने भिवानी के पास स्थित चरखी दादरी में एक लाख रुपये से एक 50 फीट गहरा तालाब बनवाया। हरियाणा सरकार ने इसके सुंदरीकरण पर 10 करोड़ खर्च किए। मुगल काल में दिल्ली में पांच ऐसे स्थान हैं जो अग्रवालों के नाम पर हैं। कूचा पाती राम, घासी राम, सीताराम बाजार, पटनिमल खिड़की व गली, कूचा ख्याली राम।

अग्रसेन की बावली: दिल्ली में अग्रवाल समाज की पुरानी विरासतों का जिक्र करें तो अग्रसेन की बावली सर्वप्रथम आती है। बाराखंभा स्थित यह बावली 800 साल से ज्यादा पुरानी है। बलुआ पत्थर, चूने के पत्थरों से बनी यह बावली व्हेल के आकार की है। इसमें 108 सीढ़ियां हैं। बकौल मोहित नट्टल साहू ने इस बावली का पुनरुद्धार करवाया था।

हिंदू कॉलेज।

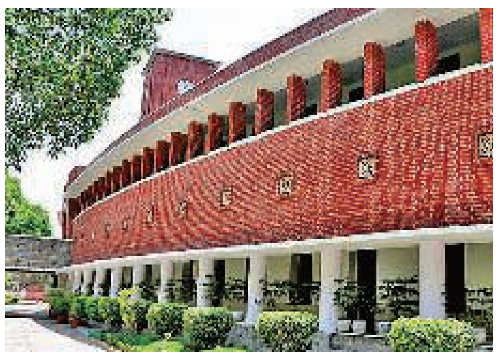

श्रीराम कॉलेज ऑफ कामर्स।

अग्रसेन की बावली।

दिगंबर जैन मंदिर

सभी फोटो : जागरण

कई बड़े कॉलेज भी इनकी देन : शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। जामा मस्जिद इलाके में स्थित इंद्रप्रस्थ गर्ल्स स्कूल के संस्थापकों में रहे सोसायटी के सेक्रेटरी लाला युगल किशोर थे। मारवाड़ी पुस्तकालय का जिक्र भी जरूरी है। यह दिल्ली के मारवाड़ी अग्रवाल द्वारा स्थापित है, जिसके केदारनाथ गोयनका संस्थापक थे। पुरानी दिल्ली में ही एक बनवारी लाल आयुर्वेद औषधालय भी था। कोतवाल वाले खानदान ने इसे स्थापित किया था। 1938 तक इससे पढ़कर 1500से अधिक वैद्य निकले थे। लाला श्रीराम की मेहनत और लगन की मिसाल आज तक दी जाती है। इन्होंने दिल्ली कमर्शियल कॉलेज की स्थापना की थी जो आजकल श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से प्रसिद्ध है। एक लेडी श्री राम कॉलेज भी है जो उनकी पत्नी के नाम पर है। इन्होंने एक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीटयूट भी बनवाया था। 1899 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कृष्णदास गुड़वाले द्वारा की गई थी।

पहले स्पीकर चरती राम गोयल बने : जिस समय दिल्ली में विधानसभा नहीं थी, उस समय दिल्ली पंजाब का हिस्सा थी। 1910 में पंजाब की विधान परिषद थी। उसमें सुल्तान सिंह जैन, राय बहादुर, देशबंधु गुप्ता, प्यारेलाल सदस्य बने। दिल्ली की पहली विधानसभा में लाला जगन्नाथ, देशबंधु गुप्ता सदस्य थे। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नगर पालिका में भी अग्रवाल लगातार सदस्य बने। रामलाल खेमका 3 बार सदस्य बने। श्यामनाथ मार्ग से दिल्ली के लोग गुजरते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो लाल श्यामनाथ के नाम पर है। दिल्ली में विधानसभा के पहले महानगर परिषद होती थी। उसका प्रमुख चीफ काउंसलर होता था। जो वर्तमान सीएम के बराबर होता था। इस पद को राधा रमण अग्रवाल ने सुशोभित किया था। विधानसभा बनी तो पहले स्पीकर भी चरती राम गोयल बने।

प्रमुख कारोबारी
मोहित कहते हैं कि वर्तमान में जयपुरिया परिवार, जिंदल ग्रुप, डीसीएम ग्रुप, बिकानेर, हल्दीराम, हेवेल्स, राजधानी बेसन वाले सरीखे बड़े कारोबारी इसी समाज के हैं।

धनवानों में दिल्ली के अग्रवालों का दबदबा: मोहित कहते हैं कि किताब लिखने के दौरान कई दिलचस्प घटनाओं और जानकारियों से रूबरू होने का अवसर मिला। उसमें धनवानों का जिक्र भी आता है। लाला सुल्तान सिंह की चालीस हजार गज से ज्यादा जमीन कश्मीरी गेट पर थी। अपने समय के बहुत बड़े धनवान थे। अंग्रेज अधिकारी भी इनके यहां आते थे। 1920 में इनके बेटे रघुबीर सिंह ने मार्डन स्कूल की स्थापना की। स्कूल अब 100 साल का सफर पूरा करने वाला है। दिल्ली के सबसे बड़े धनवान व नगर श्रेष्ठ गुड़वाले थे। रामदास जी गुड़वाले मालीवाड़ा में रहते थे। 1857 के पहले भारत के चार सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में इनकी गिनती थी। 1857 के पहले बादशाह बहादुर शाह जफर के विश्वास पात्रों में से एक थे। रामदास के पूर्वजों के नाम के साथ गुड़वाले शब्द जुड़ने का भी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल, ये लोग बहुत दानी थे। यात्रियों के लिए जगह जगह पानी और गुड़ की व्यवस्था करते थे। इसलिए गुड़वाले नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। ये हुंडी पर्ची का काम करते थे। हुंडी पर्ची को दिखाकर पूरे देश में कैश कराया जा सकता था। बादशाह हर दिवाली, ईद इनके आवास पर आते थे और ये, उन्हें एक लाख अशर्फी उपहार में देते थे। इनकी हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 12 दरवाजे थे। कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बादशाह को इन्होंने 3 करोड़ रुपये उधार दिए थे। विद्रोह विफल होने के बाद लाला रामदास पर अंग्रेजों ने कुत्ता छोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। जब बाद में अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इनके बेटे को मजिस्ट्रेट, दिल्ली नगर परिषद का सदस्य बनवाया। मोहित कहते हैं कि उनके पास बादशाह का फरमान भी है। रामदास जी किस कदर शक्तिशाली थे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस समय के जारी कई शाही सिक्कों पर एक तरफ बादशाह तो दूसरी तरफ उनके चित्र थे। गुड़वाले के नाम पर करोल बाग में एक गुड़वाली गली भी है। दिल्ली ट्राम चलाने वाली कंपनी में इसी गुड़वाले के खानदान के लाला श्रीदास डायरेक्टर भी रहे थे।

कोतवालों का खानदान: लाला श्रीराम का परिवार कोतवालों के खानदान के रूप में प्रसिद्ध है। इनके पूर्वज दिल्ली के कोतवाल थे। 1882 के आसपास गुड़वाले, कोतवालों के खान और चुनामल के खत्री परिवार ने मिलकर साझेदारी में दिल्ली क्लॉथ मिल की स्थापना की। जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी क्लॉथ मिल थी। 1857 में लाला बद्रीदास दिल्ली और फिरोजपुर के कोतवाल बने। 1865- 84 तक ये बैंक ऑफ बंगाल, लाहौर के मुख्य कार्यालय के खजांची भी रहे। फिरोजपुर छावनी भी इन्होंने ही बसाई। इन्हीं के समय में कोतवालों का खानदान कहना शुरू हुआ।

मुगल बादशाह के खजांची शाहदीप चंद : ये मुगल बादशाह शाहजहां के समय में खजांची थे। ये हिसार से दिल्ली आए थे। इन्हें दरीबाकलां में 5 बीघा जमीन दी गईं थी ताकि इनका परिवार रह सके। कहते हैं, उस समय दरबार में सात तरह के सम्मान से नवाजा जाता था। जामा मतलब गाउन, पाजामा, चद्दर, पगड़ी, कलतुर्रे वाली कली आदि। शाहदीप को इन सातों से नवाजा गया था।

सोने के छत्र वाला मंदिर

पुरानी दिल्ली स्थित धर्मपुरा में 200 साल पुराना मंदिर है। जिसे अग्रवाल जैनियों ने बनवाया था। इसे नया मंदिर भी कहते है। यह मंदिर उस समय 8 लाख रुपये में बनवाया गया था। इसमें गर्भ गृह की छत सोने की है। हरसुख राय के लड़के सुगन राय बादशाह के खजांची थे। इन्होंने 7 लाख रुपये तो खुद दिए जबकि 1 लाख समाज के लोगों से चंदा इक्ट्ठा किया गया था। इसे बनवाने के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। उस समय मुगल मंदिर नहीं बनाने देते थे, खासतौर पर शिखर वाले मंदिर। चूंकि ये खजांची थे तो इन्होंने बादशाह से विशेष अनुमति लेकर मंदिर निर्माण शुरू करवाया। सात लाख रुपये खर्च हो जाने के बाद भी जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो एक लाख रुपये चंदा एकत्र किया गया। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद इसे पंचायती घोषित कर दिया गया था। इसमें कहीं भी लाइटिंग नहीं है। मंदिर दिन में एक बार सिर्फ सुबह खुलता है। राजा हरसुख राय और सगुन चंद्र ने देशभर में 51 मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया। अकेले दिल्ली में सात मंदिर थे। जिसमें धर्मपुरा, पटपड़गंज, जयसिंहपुरा स्थित मंदिर हैं। इसी तरह राजा पटनिमल ने कालकाजी मंदिर में भी सेवा कार्य किया। 1810 में 50 हजार रुपये दिए थे। इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा का खिताब दिया था।

दिल्ली के पुराने अग्रवाल संगठन

प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत: यह बहुत बड़ी पंचायत है। जिसमें दिल्ली, पानीपत, हिसार की पंचायतें हैं, यह 250 साल पुरानी है। अग्रवाल जैन इसके सदस्य थे। यह पंचायत 22 मंदिरों का प्रबंधन है। जिसमें दिल्ली के भी कई मंदिर हैं।

बड़ी पंचायत: 1890 के आसपास इस संस्था की स्थापना हुई। यह निगमबोध घाट का प्रबंधन देखती है। यहां विकास कार्य, मूर्तियां समेत अन्य काम करवाते हैं। सीताराम बाजार में इसका ऑफिस है।

दिल्ली अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन: यह 1976 से चल रहा है। अग्रवालों के बीच मेल जोल बढ़ाने, समाज में बेहतर कार्य करना मकसद है।

लाजवाब है रमेश वैष्णों ढाबा की मलाई चाप

जायका

ढाबों पर राजमा-चावल, दाल मखनी मिक्स वेज और तंदूरी रोटी का स्वाद तो अक्सर लेते होंगे, लेकिन एक ढाबा ऐसा है जहां एक दो नहीं दर्जनों प्रकार के चाप का स्वाद ले सकेंगे। मलाई चाप, अफगानी चाप, हरियाली चाप, तवा चाप...सब के सब इतने लाजवाब कि अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। पटपड़गंज रोड शिवपुरी स्थित रमेश वैष्णों ढाबा पर शाम के समय आप पहुंच भर जाएं, चाप खाने वालों की लंबी कतार दिख जाएगी। दिल्ली ही नहीं चाप खाने पानीपत, सोनीपत व लुधियाना से भी लोग आते हैं। अगर आपको यहां चाप का स्वाद लेना है तो केवल शाम छह से रात 11 बजे के बीच ही पहुंचे, क्योंकि दिन में यहां केवल आपको रोटी, दाल, सब्जी आदि व्यंजन ही मिलेंगे।

लोगों की जुबान पर कुछ यूं चस्पा मलाई चाप : करीब 27 साल पहले यमुनापार के लोगों को मलाई चाप का स्वाद रमेश ने ही चखाया था। लोगों की जुबान पर उनके हाथ का यह स्वाद कुछ ऐसे चढ़ा कि दक्षिणी दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक से लोग उनके पास केवल चाप खाने आने लगे। अब तो इनकी लोकप्रियता ऐसी हो गई है कि दूर-दूर से लोग इस सर्द मौसम में चाप का आनंद लेने पहुंचते हैं। जब रमेश के पिता ढाबा चलाते थे तब केवल दाल, सब्जी, रोटी जैसे व्यंजन ही बनाते थे, लेकिन जब उन्होंने मलाई चाप बनाना शुरू किया तब उनका काम खूब चलने लगा। चाप की इतनी मांग होने लगी कि उन्होंने मलाई चाप के साथ चाप की दर्जनभर वैरायटी बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में तो 50-60 रुपये प्लेट चाप मिलती थी, लेकिन अब इसका सुस्वाद लेने के लिए आपको 190 रुपये खर्च करने होंगे।

अफगानी चाप के दीवाने भी कम नहीं: रमेश अफगानी चाप भी बेहद उम्दा बनाते हैं, जिसे लोग चटखारे ले लेकर खाते हैं। इसे क्रीम व मियोनी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा स्टफ मलाई चाप भी खास है। 15 से 17 मसालों के साथ पनीर की स्टफिंग की जाती है। उसके बाद उसे अच्छी तरह भून कर पकाया जाता है। चाप तैयार होने के बाद उस पर मसाले व बटर की स्टफिंग कर ग्राहकों को परोसा जाता है। मसाले घर पर ही तैयार करते हैं ताकि स्वाद से कोई समझौता न हो। मलाई चाप के अलावा यहां आप मलाई चाप टिक्का, हरियाली चाप, सोया चाप टिक्का, चिल्ली चाप, बटर चाप, आचारी टिक्का, तवा चाप का भी स्वाद ले सकते हैं। दाल मखनी, पालक छोले, प्याज की रोटी, प्याज की मिस्सी भी काफी लाजवाब बनाते हैं।

गायक व मंत्री भी कायल: आम ग्राहक ही नहीं, बड़े-बड़े नेता और गायक भी इस चाप के कायल हैं। गायक नरेंद्र चंचल, पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली, डॉ. एके वालिया जैसे नेता बड़े शौक से यहां चाप खाने आते हैं। रमेश कहते हैं नवरात्रों में भी लोग चाप का स्वाद ले सकें इसके लिए नौ दिनों तक बिना लहसून-प्याज के चाप बनाते हैं। शाम होते ही इनके ढाबे के बाहर चाप खाने वालों की इतनी भीड़ लग जाती है कि सड़क पर जाम लगने लग जाता है। बिग बॉस के पूर्व विजेता आशुतोष कौशिक भी करीब एक माह पहले यहां चाप खाने आए थे।

पिता के काम को बेटों ने दी पहचान: रमेश के बेटे सनी बतरा व प्रिंस भी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि शिवपुरी से चलकर चाप का स्वाद अब कड़कड़डूमा व झील पर पहुंच चुका है।

–रितु राणा

वाह, मजा आ गया। वाकई में इस मलाई चाप का कोई जवाब नहीं। चाप का सुस्वाद लेता परिवार जागरण

सोयाबीन व मशरूम चाप। जागरण

नजदीकी मेट्रो स्टेशन : निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से ऑटो या रिक्शा लेकर रमेश वैष्णों ढाबा तक पहुंचा जा सकता है।
खुलने का समय : दोपहर 12 से दो व शाम 6 से रात 12 बजे तक।

सदियों पुरानी परंपरा यहां आज भी जीवंत

शहर के गांव

दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित गाजीपुर गांव आज भी अपने 300 वर्ष पुराने इतिहास व संस्कृति को संजोय हुए है। आज भी महिलाएं यहां घूंघट की ओट से झांकती हैं तो तीज-त्योहार में एक जगह इकट्ठा हो लोकगीत गाती हैं। छोटे-मोटे मामले गांव की चौपाल में ही सुलझा लिए जाते हैं। गांव की मिट्टी की सुगंध ही है जो यहां रहने वालों को उनके इतिहास व परंपराओं को भूलने नहीं देती है। इस गांव को पार करते ही उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। सन् 1908 तक यह गांव मेरठ का हिस्सा हुआ करता था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उनके पिता व दादा बताते थे कि यह गांव बाबा पैमराज ने बसाया था। हम सभी उनके वंशज हैं, लेकिन गांव का इतिहास इतना पुराना है कि इसके गाजीपुर नाम रखने के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। उनके दादा के जमाने से इसे गाजीपुर गांव के नाम से ही जाना जा रहा है।

गुजरात से आए बाबा पैमराज ने बसाया गाजीपुर: गुर्जर विकास परिषद (गुर्जर भवन) के संरक्षक व पूर्व अध्यक्ष चौधरी प्रकाश वर्मा कहते हैं कि गाजीपुर गांव को सन् 1729 में बाबा पैमराज ने बसाया था। बाबा पैमराज मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। पहले पहल वह मंडावली में रहे, उसके बाद उन्होंने गाजीपुर गांव बसाया। आज पैमराज के तीन बेटों की पीढ़ियां यहां रह रही हैं। इसके अलावा दो पीढ़ी ब्राह्मणों की है। उनके बेटे केसरी सिंह की पीढ़ी को (मौले), जीत सिंह की पीढ़ी को (लौंडे मोहल्ला) व गुलाब सिंह की पीढ़ी को (बूचे) के नाम से जाना जाता है। चौधरी उदय सिंह डेढ़ा ने बताया सन् 1908 तक यह गांव मेरठ का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद यह गांव मेरठ से अलग हो गया और 1911 में इसे दिल्ली में शामिल किया गया। वर्ष 1947 में जब यहां बाढ़ आई थी तब यह गांव लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद लोग ऊंचे टीले पर चले गए थे। फिर जब बाढ़ का प्रकोप कम हुआ तो लोग वापस गांव में आ गए।

300 वर्ष पुरानी धरोहर आज भी सुरक्षित: 300 वर्ष पुराना इतिहास लिए यह गांव आज भी अपनी परंपराओं को संजोय हुए है। पंडित बदले सिंह ने बताया कि गांव की बसावट के साथ ही यहां खेड़ा देवता मंदिर स्थापित किया गया था जो आज भी गांव में विराजित है। इस मंदिर से गांव के लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक पुरानी चौपाल भी है। लोगों ने बताया कि पहले यहां पांच कुएं थे, लेकिन अब केवल दो कुएं ही रह गए हैं।

समय के साथ कुछ बदलाव भी आए: पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता नसीब सिंह ने बताया कि उनके दादा, परदादा भी इसी गांव में जन्में थे। अंग्रेजों के समय में जेलदारी प्रथा हुआ करती थी। जिले में जेलदार व गांव में नंबरदार नियुक्त किए जाते थे। आजादी से पूर्व इस गांव के निवासी बीखाराम को अंग्रेजों ने आर्मी के कैप्टन व जेलदार नियुक्त किया था। जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध में भी भाग लिया था। 1965 से 1971 तक दिल्ली में ब्लॉक कमेटी हुआ करती थी, जिसमें पांच ब्लॉक (शाहदरा, अलीपुर, महरौली, नजफगढ़, नरेला) शामिल थे। इसके अंतर्गत 360 गांव आते थे। हमारे पिता चौधरी भगत सिंह इस कमेटी के प्रधान भी रह चुके थे।

वहीं चौधरी जयचंद ठेकेदार कहते हैं कि यह गुर्जर बाहुल गांव है। जिसमें डेढ़ा गुर्जर व कुछ पंडित भी रहते हैं। इसके अलावा हरिजन व अन्य जातियों का भी यह गांव है। किसी की भी शादी हो पूरा गांव उसमें शामिल होता है। वर्ष 1965 तक यहां खेत व जंगल हुआ करता था। पहले यहां खूब खेतीबाड़ी व पशुपालन होता था, लेकिन अब लोग पढ़-लिखकर विभिन्न व्यवसायों में जा रहे हैं। 1959 में इस गांव की जमीन को अधिकृत कर सरकार ने सब्जी मंडी, फूल मंडी, बूचड़खाना, देसी फार्म व मुर्गा मंडी बसा दी।

पारंपरिक वेशभूषा व खान-पान आज भी है जीवित: पहनावे की अगर बात करें तो आज भी यहां पुरुष धोती-कुर्ता पहनते हैं तो महिलाएं औन्ना व सलवार में नजर आती हैं। आधुनिक समाज में बेशक गैस चूल्हे का चलन हो, पर यहां आज भी खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है। होली-दीवाली समेत सभी त्योहार पारंपरिक तरीके से ही मनाए जाते हैं। गांव के लोग पुलिस व कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। छोटे-मोटे मतभेद पंचायत द्वारा ही निपटाए जाते हैं। सास हो या बहू करवा चौथ का व्रत सब साथ मिलकर ही करती हैं। गांव में एक पुराना बारात घर है गांव वाले वहीं शादी-ब्याह का आयोजन करते हैं।

–रितु राणा

कोर्ट-कचहरी क्यों जाएं जब चौपाल पर ही सभी मामले सुलझ जाते हैं। गांव की चौपाल में बैठकी कर विचार-विमर्श करते लोग। जागरण

त्योहार पर एकत्र हो लोकगीत के जरिये कुछ इसी तरह संस्कृति की खुशबू बिखेरतीं हैं महिलाएं। जागरण

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बिजनेस
शनिवार 14 दिसंबर 2019
www.jagran.com

डीओटी ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए मंगाई निविदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित कराने के लिए एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। चुनी गई एजेंसी 8526 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी आयोजित कराएगी। इस दौरान नीलाम होने वाले स्पेक्ट्रम की कुल कीमत करीब 4.98 लाख करोड़ रुपये है। डीओटी की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 13 जनवरी है। यह निविदाएं 24 जनवरी को खोली जाएंगी।

कंपनी कानूनों में आपराधिक मामले की गुंजाइश बिल्कुल खत्म कर दी जानी चाहिए। इस तरह के प्रावधानों से स्वतंत्र निदेशकों को बड़ी दिक्कत हो रही है।

— कल्पना मोरपाड़िया, दक्षिण एशिया परिचालन प्रमुख, जेपी मोर्गन

सेंसेक्स	41,009.71	▲ 428
निफ्टी	12,086.70	▲ 114.90
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 38,486	▼ ₹232
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 45,189	▼ ₹7
डॉलर	₹ 70.83	बदलाव नहीं
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 65.19	

न्यूज गैलरी

एंबिट कैपिटल ने सेबी को चुकाए छह करोड़ रुपये

नई दिल्ली : ब्रोकरेज कंपनी एंबिट कैपिटल ने मण्णपुरम फाइनेंस के साथ कथित इनसाइडर मामले में सेबी को छह करोड़ रुपये का भुगतान किया है। एंबिट कैपिटल ने तर्क दिया है कि वह तथ्यों को बिना नकारे और बिना स्वीकारे समझौता कर रहा है। सेबी ने कहा है कि समझौते को लेकर दिए आदेश में आवेदक एंबिट कैपिटल के साथ न्यायिक फैसले से पूर्व की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एंबिट कैपिटल पर आरोप था कि वह यूपीएसआइ के माध्यम से मण्णपुरम फाइनेंस के तिमाही परिणामों को उसके ग्राहकों के बीच नकारात्मक तरीके से पेश कर रही थी। मण्णपुरम की शिकायत के बाद सेबी ने पूरे मामले की जांच कराई, जिसमें एंबिट कैपिटल को दोषी पाया गया। (प्रेट्र)

डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के आयकर रिफंड जारी

नई दिल्ली : आयकर विभाग इस वित्त वर्ष में 15 नवंबर तक 1.57 लाख करोड़ रुपये के आयकर रिफंड का भुगतान कर चुका है। पिछले पूरे वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1.23 लाख करोड़ रुपये था। वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में टैक्स रिफंड मामले 17 प्रतिशत बढ़कर 2.16 करोड़ पहुंच चुके हैं और आयकर में 27 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि इस साल आइजीएसटी रिफंड के रूप में 38,988 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। (प्रेट्र)

स्पाइसजेट ने तीन मालवाहक विमान सेवा से हटाए

नई दिल्ली : निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा है कि उसने अपने तीन 737 मालवाहक विमानों को सेवा से हटा दिया है। उसने यह कदम इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आइएआइ) की सलाह पर उठाया है। इसी कंपनी ने इन्हें मालवाहक विमानों में तब्दील किया था। जांच के दौरान कंपनी को पता चला है कि इनके निर्माण में इस्तेमाल किए गए 9-जी बैरियर में खामी है। स्पाइसजेट के पास इस समय चार मालवाहक विमान हैं। चौथा विमान किसी दूसरी कंपनी ने बनाया था। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। (प्रेट्र)

जेपी का घर खरीदार संगठन एनबीसीसी के पक्ष में

नई दिल्ली : जेपी इन्फ्राटेक के घर खरीदारों के संगठन ने सभी फ्लैट मालिकों और कर्जदाताओं से सरकारी कंपनी एनबीसीसी की बोली के पक्ष में वोट देने की अपील की है। जेपी इन्फ्रा की मौजूदा इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी कंपनी दौड़ में हैं। कर्जदाताओं की समिति ने सात दिसंबर को निर्णय लिया था कि जेपी इन्फ्रा के लिए एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी दोनों की बोलियों पर मतदान साथ-साथ 16 दिसंबर तक चलेगा। (प्रेट्र)

अमेरिकी लॉ फर्म की याचिका असामान्य नहीं : इन्फोसिस

मुंबई : देश की दूसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी इन्फोसिस ने कहा है कि अमेरिकी लॉ फर्म की ओर से उसके खिलाफ दायर याचिका हैरान करने वाली नहीं है। अमेरिकी कंपनियां पहले भी ऐसा करती रही हैं। इस तरह की कानूनी सलाहकार कंपनियां अखबारों, चिट्ठियों और अन्य संचार माध्यमों से लोगों को संबंधित कंपनी के खिलाफ शिकायत के लिए प्रेरित करती है। इन्फोसिस पर आरोप था कि उसके अनुचित व्यवहार के कारण अमेरिका में उसके निवेशकों को नुकसान हुआ है। (आइएएनएस)

सोना 232 रुपये गिरा, चांदी लगभग सपाट

नई दिल्ली : शुक्रवार को नई दिल्ली के सराफा बाजारों में गिरावट का रुख रहा। इस दौरान सोना 232 रुपये गिरकर 38,486 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं चांदी सात रुपये की मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट रही। यह 45,189 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। सोने के अंतरराष्ट्रीय भाव में गिरावट के चलते सोने के भाव में नरमी देखी गई। (प्रेट्र)

जरूरत के हिसाब से कदम उठाती रहेगी सरकार

दो-टूक ▸ वित्त मंत्री ने कहा - जीएसटी बढ़ोतरी पर मंत्रालय में चर्चा नहीं, सुधार के कदम जारी रहेंगे

इकोनॉमी की दशा में सुधार कब तक दिखेगा, इस पर नहीं दिया कोई जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विकास दर को गति देने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी देतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बाएं से कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन, अजय भूषण पांडेय और अतनु चक्रवर्ती। प्रेट्र

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इकोनॉमी में जब जैसी जरूरत होगी, सरकार कदम उठाएगी। अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए अब तक कदमों का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वह स्थिति में सुधार की दिशा में काम करने की इच्छुक हैं।

संसद सत्र समाप्त होने के बाद संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा, 'मैं यह चर्चा करने की इच्छुक नहीं हूं कि इकोनॉमी की मौजूदा स्थिति कैसी है। मैं स्थितियों में सुधार को लेकर काम कर रही हूं।' हालांकि उन्होंने इन सवालों का जवाब देने से इन्कार कर दिया कि इकोनॉमी की दशा में वह कब तक सुधार की गुंजाइश देख रही हैं।

जीएसटी की आगामी बैठक और जीएसटी दरों में संशोधन को लेकर हो रही चर्चा के संबंध में पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा 'हर जगह यह चर्चा है, लेकिन मेरे ऑफिस में इसकी कहीं सुगबुगाहट भी नहीं है। मैंने अभी तक जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर अपनी टीम (सभी सचिवों) से बात भी नहीं की है।' संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी जिनमें रेवेन्यू सचिव अजय भूषण पांडेय, आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती, विशेष सचिव रवि मित्तल और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन उपस्थित थे।

माना जा रहा है कि जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ाने के उपाय तलाशने को गठित अधिकारियों का समूह जीएसटी की मौजूदा दरों में संशोधन अथवा उनके पुनर्गठन पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल 18 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में रेवेन्यू बढ़ाने जैसे अहम मसलों पर विचार करेगा। बैठक में जीएसटी कंपेंसेशन के बकाया के भुगतान को लेकर भी चर्चा होगी।

इससे पूर्व रेवेन्यू सचिव पांडेय और मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमणियन ने अलग-अलग प्रजेंटेशन देकर अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में सरकार की तरफ से उठाये गए कदमों का ब्योरा दिया। पांडेय ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से रेवेन्यू पर हुए असर का सही आकलन 15 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। इस तारीख तक कंपनियों को अग्रिम कर का भुगतान करना होता है। पांडेय ने कहा कि रेवेन्यू का अनुमान इसके बाद ही लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने लोकसभा में बताया था कि चालू वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के 13.35 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 31 अक्टूबर तक 5.18 करोड़ रुपये का ही रेवेन्यू मिला था। इसी तरह जीएसटी के मद में अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में 3.26 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, जबकि लक्ष्य 6.63 लाख करोड़ रुपये था।

लोकसभा में गुरुवार को पेश इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन प्रस्तावों के बारे में कॉरपोरेट अफेयर सचिव ने कहा कि ये सभी प्रस्ताव उसी तारीख से लागू होंगे जब यह विधेयक पारित होगा। विधेयक में किसी कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया में उसकी सफल बोली लगाने वाले दावेदार या प्रमोटर पर पुरानी कंपनी या प्रमोटर पर चल रहे मामले हस्तांतरित नहीं करने का प्रावधान शामिल किया गया है। विधेयक में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदकों की संख्या निश्चित करने का प्रावधान भी रखा गया है। इस विधेयक पर अब बजट सत्र में चर्चा होगी। हालांकि सूत्र इन प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं कर रहे हैं।

अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर खींचते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने प्रजेंटेशन ने बताया कि सरकार बजट में अनुमानित 3.38 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के 66 परसेंट का उपयोग कर चुकी है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए कदमों के तहत बैंकों के कर्जों को रेपो के साथ लिंक किया गया। इसके बाद 27 नवंबर तक 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज दिये जा चुके हैं। सरकार के कदमों की वजह से एफडीआइ में वृद्धि हुई है और पहली छमाही में 35 अरब डॉलर का एफडीआइ आया है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में एफडीआइ की राशि 31 अरब डॉलर की थी।

कैग ने गुजरात के जीएसटी कलेक्शन में पाई खामियां

अहमदाबाद, प्रेट्र : राज्यों द्वारा जीएसटी के मामले में गड़बड़झाले का एक नमूना गुजरात में सामने आया है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) ने गुजरात सरकार द्वारा किए गए जीएसटी असेसमेंट और कलेक्शन में कई खामियां और अनियमितताएं पाई हैं। कैग ने पाया कि वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) से जीएसटी के अंतर्गत लाए गए करदाताओं की संख्या में गड़बड़ी हुई है। जीएसटी लागू होने से पहले जो करदाता वैट के अंतर्गत आते थे उनमें से करीब 10 परसेंट को जीएसटी के तहत रजिस्टर ही नहीं किया गया। कैग ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रेवेन्यू की ऑडिटिंग की है। इस दौरान कुल 18,093 असेसमेंट की जांच की गई, इसमें से 537 मामलों में अनियमितताएं पाई हैं। इनमें गलत टैक्स रेट, गणना की त्रुटियां, गलत तरीके से दी गई छूट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत वितरण जैसी खामियां शामिल हैं।

अमेरिका-चीन में हुई पहले चरण की डील

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका और चीन ने लगभग डेढ़ वर्षों के आपसी ट्रेड वार पर रुख नरम करते हुए पहले चरण की ऐतिहासिक कारोबारी डील कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सिलसिलेवार ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। वहीं, चीन के उप वाणिज्य मंत्री वैंग शॉवेन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहले चरण की डील के लिए दोनों पक्ष कारोबारी बातचीत के महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचने पर सहमत हो गए हैं।

पहले चरण की बातचीत के तहत चीन अपने आर्थिक व कारोबारी व्यवस्था में बौद्धिक संपदा, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, कृषि, वित्तीय सेवाओं और मुद्रा व फॉरेन एक्सचेंज जैसे मुद्दों पर बदलाव के लिए राजी हो गया है। चीन ने इस पर भी सहमति जताई है कि वह आने वाले वर्षों में अमेरिका से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में भारी इजाफा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश एक बेहद मजबूत विवाद निपटान तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं, जिसके माध्यम से विवादों का यथाशीघ्र और प्रभावी निपटान किया जाएगा।

दोनों देशों के कारोबारी समझौते पर पहुंच जाने की वजह से अमेरिका ने अपने कारोबारी कानूनों में बड़े बदलाव के प्रति भी सहमति जता दी है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा, 'हम पहले चरण की विशाल डील के लिए सहमत हो गए हैं। कृषि उत्पादों, एनर्जी, उत्पादित सामानों और कई अन्य क्षेत्रों में अमेरिका से बड़ी मात्रा में खरीदारी के लिए चीन अपने कानूनों में संरचनात्मक बदलाव को राजी हो गया है।'

मूडीज, डीबीएस ने घटाया विकास दर का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुनिया की दो प्रमुख एजेंसियों मूडीज और डीबीएस ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। मूडीज इंवेस्टर्स सर्विसेज ने 2019 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया है।

सिंगापुर की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी डीबीएस बैंकिंग समूह ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर का अनुमान 5.5 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने भी देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.1 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था।

मूडीज ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि रोजगार की धीमी वृद्धि दर का खपत पर असर दिख रहा है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि 2020 और 2021 में विकास दर क्रमशः 6.6 और 6.7 प्रतिशत रह सकती है।

- **मूडीज के मुताबिक रोजगार में कमी का दिख रही खपत पर असर**
- **डीबीएस ने फाइनेंशियल सेक्टर की चुनौतियों को बताया इकोनॉमी पर भारी**

फाइनेंशियल सेक्टर में चुनौतियां : डीबीएस ने अपनी रिपोर्ट 'भारत वार्षिक परिदृश्य 2020' में कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट और फाइनेंशियल सेक्टर में बनी चुनौतियां हावी रही हैं। उसने कहा, 'यह नरमी कई कारकों के कारण है। इससे लगता है कि 2020 में भी सुधार की गति धीमी रह सकती है।' डीबीएस ने कहा कि अनुकूल मूलभूत प्रभाव और आसान मौद्रिक स्थितियां मांग को समर्थन दे सकती हैं।

डीबीएस ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत पर आ सकती है।

आइएलएफएस की बेहतरी के लिए हो रहे प्रयास संतोषजनक

नई दिल्ली, प्रेट्र : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का कहना है कि वह इस सप्ताह इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएफएस) से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है। पिछले वर्ष इस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में संकट आने के बाद मंत्रालय ने इसके बोर्ड को भंग किया और इसकी बेहतरी की दिशा में प्रयास शुरू किए थे।

इस साल अक्टूबर में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक को आइएलएफएस के प्रमुख के रूप में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था। आइएलएफएस पर करीब 94,000 करोड़ रुपये का कर्ज होने का अनुमान है। मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि वे इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट हैं। इसकी बेहतरी के प्रयासों के तहत नया बोर्ड इसकी परिसंपत्तियों को बेच चुका है।

बड़े आकार के वाहनों को मिलेगी मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बड़े आकार के वाहनों से परिवहन लागत में कमी के मद्देनजर सरकार ने सभी प्रकार के वाहनों, खासकर टू-एक्सल बसों के आकार में बढ़ोतरी को मंजूरी देने का फैसला किया है। पहली बार दोपहिया वाहनों के आकार भी तय किए जा रहे हैं। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं। हालांकि परिवहन विशेषज्ञ इस कदम से हैरत में हैं और उन्होंने इससे सड़कों पर जोखिम बढ़ने की आशंका जताई है।

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 93 में संशोधन के लिए जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार एल-1 श्रेणी के दोपहिया वाहनों की अधिकतम चौड़ाई एक मीटर, लंबाई चार मीटर तथा ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। जबकि एल-2 वर्ग के दोपहिया वाहन अधिकतम दो मीटर चौड़े, चार मीटर लंबे और 2.5 मीटर तक ऊंचे होंगे।

इसी प्रकार एल-5 श्रेणी तिपहिया वाहनों के लिए अधिकतम चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 1.6, 4.0 और 2.5 मीटर, जबकि ई-रिक्शा/ई-कार्ट के 1.1, 3.2 और 1.8 मीटर होंगी। कंटेनर परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एन-श्रेणी के मालवाहक वाहनों की ऊंचाई में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जबकि एम-श्रेणी के पैसेंजर वाहनों यानी बसों की ऊंचाई को बढ़ाकर चार मीटर किया जाएगा। एयरपोर्ट पैसेंजर बसों की ऊंचाई 3.8 मीटर ही बनी रहेगी। आठ से अधिक सीटों वाली एम-3 श्रेणी की टू-एक्सल बसों की लंबाई में संशोधन कर उसे 13.5 मीटर करने का प्रस्ताव है।

एन-श्रेणी के मालवाहक वाहनों की अधिकतम ऊंचाई को बढ़ाकर चार मीटर किया जाएगा। परंतु एन-1 श्रेणी के 3.5 टन ग्रॉस व्हीकल वेट (जीवीडब्ल्यू) तक के यूटिलिटी वाहनों की ऊंचाई तीन मीटर से ज्यादा नहीं होगी। अधिक ऊंचाई होने की स्थिति में गुरुत्व केंद्र ऊपर उठता है जिससे स्थिरता प्रभावित होती है और वाहन के पलटने का खतरा बढ़ जाता है।

मसौदा अधिसूचना में आइएसओ मानक वाले नए 45 फीट के कंटेनरों को ढोने में सक्षम बनाने के लिए ट्रेलरों की लंबाई को बढ़ाकर 18.75 मीटर करने का प्रस्ताव है। कुछ मामलों को छोड़कर ऐसे ट्रेलर्स की ऊंचाई को भी बढ़ाकर चार मीटर किया जा रहा है।

डबल डेक पैसेंजर वाहनों की अधिकतम ऊंचाई 4.75 मीटर रखी जाएगी। ऐसे वाहनों के चारों तरफ समुचित दृश्यता के लिए क्लोज सर्किट टीवी तथा इंटरकॉम प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। सड़क मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि वाहनों के आकार में बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर की जा रही है। माल व यात्री परिवहन क्षमता बढ़ने से परिवहन लागत में कमी आएगी। हालांकि इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च के संयोजक एसपी सिंह ने कहा कि भारत में बड़े आकार के ट्रेलर सड़क सुरक्षा के लिए पहले ही खतरा बने हुए हैं।

जलवायु की चुनौतियों से मिलकर लड़ेंगे नाबार्ड और आइसीएआर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

साझा पहल

- **माइक्रो इरिगेशन व इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जल्द होगा गठित : नाबार्ड**
- **लैब टू लैंड स्कीम में भारी अंतर को भरने में नाबार्ड होगा सहायक**

जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली नित नई चुनौतियों से लड़ने के लिए नाबार्ड और आइसीएआर ने हाथ मिलाया है। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए दोनों संस्थाएं एक साथ कार्य करेंगी। नाबार्ड के चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला ने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य के लिए आइसीएआर की मदद की जरूरत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गठित 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह को सक्रिय करने में कृषि संस्थान काफी मुफीद साबित होंगे।

नाबार्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के बीच शुक्रवार को एक समझौता हुआ, जिसमें 'एक्शन रिसर्च' पर काम करने पर सहमति बनी है। दोनों संस्थानों के प्रमुखों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि अगले महीने तक एक संयुक्त कार्यदल का गठन कर लिया जाएगा, जो जल्द ही काम शुरू कर देगा। यह कार्यदल कृषि क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से अनुसंधान पर जोर देगा। भानवाला ने कहा कि नाबार्ड जल्दी माइक्रो इरिगेशन फंड और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करेगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड पहले से ही हर खेत को पानी और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' यानी 'हर बूंद ज्यादा फसल' की अवधारणा को पूरा करने के लिए शुरू की गई योजनाओं को वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है।

आइसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने इस मौके पर कहा कि लैब टू लैंड जैसी योजनाओं में हर किसान तक पहुंचने की चुनौती है। इसमें नाबार्ड की एक्सटेंशन प्रणाली बहुत सहायक साबित हो सकती है। महापात्र ने कहा कि दोनों संस्थाएं ग्रामीण विकास और किसानों के हित में काम करती हैं। लेकिन पहली बार दोनों साझा तौर पर कार्य करने उतरने जा रही हैं।

महापात्र ने कहा कि मिट्टी और जल संरक्षण की दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। डेयरी सेक्टर में सहकारी क्षेत्र को छोड़कर बाकी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश में हरा चारा और साइलेज नहीं हैं। कुछ राज्यों में इसकी नीति तो बना ली गई है। लेकिन अभी जमीनी स्तर पर बहुत कुछ करना बाकी है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, जिससे किसानों की माली हालत में सुधार हो सकता है।

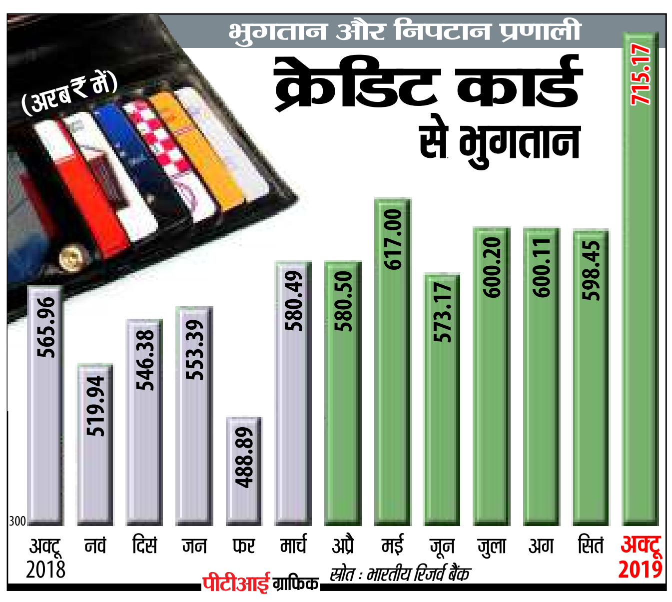

आयशर-242 को ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड

नई दिल्ली (वि): आयशर ट्रैक्टर्स के आयशर-242 को 30-एचपी श्रेणी में ट्रैक्टर ऑफ द ईयर, 2019 अवार्ड मिला है। आयशर-242 एक अत्यंत ही दमदार एवं शक्तिशाली ट्रैक्टर है। यह सभी प्रकार के कृषि उपकरणों के उपयोग के लिए सर्वोत्तम है। यह ट्रैक्टर सर्वाधिक डीजल बचत, हाई रिसेल वैल्यू के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं सब विशेषताओं के चलते आयशर-242 को किसान का कमाऊ बेटा भी कहा जाता है।

अब 3,000 हेक्टेयर में हीरा खोजेगी मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बंदर हीरा खदान की उम्मीद से अधिक बोली लगने से उत्साहित राज्य सरकार अब इस इलाके की तीन हजार हेक्टेयर भूमि में हीरा खोजेगी। इसे लेकर खनिज साधन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया के दौरान हीरे की खोज का जिम्मा किसे सौंपा जाए, इस कार्य को किन शर्तों पर कंपनी को दिया जाए सहित अन्य मुद्दों पर परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करने वाले उपक्रम एनएमडीसी को भी यह जिम्मा सौंपे जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा खोजने आई कंपनी रियो टिंटो के काम छोड़ने के बाद दो साल से बंदर हीरा खदान खाली पड़ी थी। इससे राज्य सरकार को करीब 23 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद जगी है। तीन दिन पहले खदान की नीलामी में सर्वाधिक (लाभ में 30.05 प्रतिशत की हिस्सेदारी) की बोली लगाकर बिड़ला समूह ने 50 साल के लिए खदान लीज पर ली है। खदान से अच्छा खासा राजस्व मिलने सरकार खासा उत्साहित है। उसने तीन हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। विभाग इसके लिए पूरी प्रक्रिया तय करेगा और फिर मापदंड तय किए जाएंगे। इसमें एक साल का समय लगने की संभावना है। इसके बाद क्षेत्र में हीरा खोजने का काम फिर से शुरू होगा।

50 किमी में हीरे का भंडार : पन्ना जिले में 50 किलोमीटर क्षेत्र में हीरे का अकूत भंडार बताया जाता है। राज्य सरकार ने भी चार हजार हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया है। इसमें से 954 हेक्टेयर क्षेत्र में हीरा खोजने का काम रियो टिंटो कंपनी को सौंपा गया था। इस कंपनी को 2004-05 में यह जिम्मेदारी सौंपी थी और कंपनी ने वर्ष 2007 में काम शुरू किया, लेकिन प्रदेश में ही हीरे की नीलामी और कटिंग-पॉलिशिंग की शर्त के चलते कंपनी ने वर्ष 2017 में काम छोड़ दिया था। उसके बाद से ही यह खदान बंद है।

लेखाजोखा

सेंसेक्स में 428 अंक की तेजी, निफ्टी भी 12 हजार के पार, ट्रेड-वार के खात्मे के संकेत और ब्रिटेन के घटनाक्रमों से बना माहौल

उत्साहजनक ग्लोबल संकेतों से झूमे घरेलू शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : शुक्रवार को लगातार तीसरे सत्र में प्रमुख भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड समझौते से जुड़ी सकारात्मक खबरें और ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के चुनाव जीतने का असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा। इससे भारतीय शेयर बाजारों में भी जोरदार खरीद-फरोख्त हुई। सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 428 अंक यानी 1.05 परसेंट उछलकर 41,009.71 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 114.90 अंक की तेजी आई। यह 12 हजार के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार करते हुए 12,086.70 पर बंद हुआ।

जानकारों के मुताबिक ट्रेड-वार खत्म होने की उम्मीद और ब्रिटेन के आम चुनाव में बोरिस जॉनसन को मिले स्पष्ट बहुमत से दुनियाभर के शेयर बाजारों में जोश की लहर देखी गई। दूसरी तरफ, सूचना यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड समझौते को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

प्रतीकात्मक

शुक्रवार को सेंसेक्स पैक में एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। यह 4.21 परसेंट उछाल के साथ बंद हुए। इसके अलावा वेदांता, एसबीआइ, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक और यस बैंक के शेयरों में 3.75 परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया। दूसरी ओर भारती एयरटेल, कोटक बैंक, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और एचयूएल के शेयर 1.98 परसेंट तक गिरावट के साथ बंद हुए। इस सप्ताह कुल मिलाकर सेंसेक्स 564.56 और निफ्टी 165.20 अंक की तेजी दर्ज करने में सफल रहा। एशिया के अन्य शेयर बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सियोल हरे निशान पर बंद हुए।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

बैंक ऑफ बड़ौदा : अंसा मर्चेंट बैंक के साथ शेयर खरीद समझौते के बाद बैंक के शेयरों में चार परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। बीएसई में इसके शेयर 3.93 परसेंट उछलकर 101.75 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में यह 4.14 परसेंट की तेजी दर्ज करने में सफल रहे। यहां बैंक के शेयर 101.95 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक : शुक्रवार को इसके शेयरों में गिरावट का रुख रहा। बीएसई में इस बैंक के शेयर 6.89 परसेंट गिरकर 52.05 रुपये पर बंद हुए। वही एनएसई में इसके शेयर छह परसेंट गिरावट के साथ 52.55 रुपये पर बिके। गौरतलब है कि बैंक पिछले गुरुवार को ही शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हुआ था। पहले दिन इसके शेयर 51 परसेंट से अधिक की तेजी दर्ज करने में सफल रहे थे।

विदेशी मुद्रा भंडार में तेज उछाल

मुंबई, प्रेट्र : इस सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज उछाल दर्ज किया गया। आरबीआइ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस सप्ताह फॉरेक्स रिजर्व 230 करोड़ डॉलर बढ़कर 45,342.2 करोड़ डॉलर (करीब 31 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गया। यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पिछले सप्ताह इसमें 240 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ था। इसके साथ ही इस सप्ताह गोल्ड रिजर्व में भी 43 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। यह कुल मिलाकर 2,707.8 करोड़ डॉलर (करीब दो लाख करोड़ रुपये) रहा।

मेटल स्टॉक्स चमके

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका-चीन में चल रहे ट्रेड वार के खात्मे के संकेत मिलने से भारतीय मेटल स्टॉक्स में चमक देखी गई। शुक्रवार के कारोबार में मेटल स्टॉक्स में चार परेसट तक की तेजी आई। इस दौरान बीएसई में वेदांता 3.75, हिंडाल्को 3.63, कोल इंडिया 3.07 और टाटा स्टील के शेयरों में 2.39 परसेंट की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी के शेयर भी 2.01 परसेंट तक के उछाल के साथ बंद हुए। इन स्टॉक्स के बल पर बीएसई का मेटल इंडेक्स 2.30 परसेंट की तेजी के साथ 9,788.75 केस्तर पर बंद हुआ।

10 लाख पौधे लगाएगी अमेरिकी सिख संस्था भारत में। अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी सिखों की संस्था इकोसिख ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए वह भारत में पंजाब समेत कई राज्यों में 100 वन क्षेत्र स्थापित करने की योजना पर काम करेगी।

नई पारी ▸ ब्रिटेन के आम चुनाव में पीएम बोरिस जॉनसन की अगुआई में कंजरवेटिव पार्टी को मिली प्रचंड जीत

भारत-ब्रिटेन रिश्तों में भी खास गर्माहट आने के आसार

प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टी का बढ़ता जा रहा था पाकिस्तान प्रेम

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में पीएम बोरिस जॉनसन की अगुआई में कंजरवेटिव पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत को वैश्विक कूटनीतिक विशेषज्ञ चाहे जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन भारत के हितों के लिए यह चुनाव परिणाम मुफीद साबित हो सकता है। ब्रेक्जिट के चक्कर में राजनीतिक तौर पर उलझा ब्रिटेन पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के साथ अपने रिश्तों को खास तवज्जो नहीं दे पाया था। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टी का पाकिस्तान प्रेम बढ़ता जा रहा था। ऐसे में भारत के साथ खास रिश्तों की हमेशा से वकालत करने वाले जॉनसन के दोबारा पूरे कार्यकाल के लिए पीएम बनने से द्विपक्षीय रिश्तों की सुस्त गाड़ी की रफ्तार बढ़ना तय है। भारत भी ब्रिटेन के साथ अपने रिश्तों में नई गर्माहट भरने को तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉनसन को तुरंत बधाई दे कर अपनी मंशा साफ कर दी है।

जॉनसन की जीत से भारत ने इसलिए भी राहत की सांस ली है कि प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टी ने हाल के महीनों में बेहद कड़ा भारत विरोधी स्टैंड ले रखा था। लेबर पार्टी के पाकिस्तान समर्थक रुख से भारत संशकित था। खास तौर पर अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद जिस तरह से लेबर पार्टी भारत की नीतियों पर सवाल उठा रही थी और ब्रिटेन में भारत विरोधी रैलियों का समर्थन कर रही थी उससे नई दिल्ली की चिंताएं बढ़ी थीं। लेबर पार्टी के राजनीतिक दबाव के बावजूद जॉनसन ने कश्मीर मुद्दे पर राजनीति नहीं की और उन्होंने भारत विरोधी बयान नहीं दिया। यही देखते हुए ब्रिटेन के भारतवंशियों ने भी कंजरवेटिव पार्टी का समर्थन किया है। ऐसे में भारत को उम्मीद है कि जॉनसन की अगुआई में नई सरकार कश्मीर के साथ ही खालिस्तान के मुद्दों को भड़काने में जुटे वर्ग को भी कोई बढ़ावा नहीं देगी।

लंदन में शुक्रवार को आम चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री आवास (10, डाउनिंग स्ट्रीट) पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टनर कैरी साइमंड अभिवादन करते हुए। रायटर

कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक, सबसे अहम बात यह है कि पीएम मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष जॉनसन के बीच पहले से ही संवाद कायम है। मोदी और जॉनसन के बीच मुलाकात भी जल्द हो सकती है। दोनों के बीच पहली व अंतिम मुलाकात फ्रांस में ग्रूप-7 देशों की बैठक के दौरान अगस्त में हुई थी। अब दोनों नेता कम से कम अगले साढ़े चार वर्षों तक एक साथ काम कर सकते हैं। इससे द्विपक्षीय रिश्ते को आगे बढ़ाने में स्थायी नेतृत्व मिलेगा। चाहे दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बात हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र में नए सहयोग की शुरुआत करने की बात हो, इन पर तेजी से फैसला हो सकता है।चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से बोरिस जॉनसन ने 31 जनवरी, 2020 से यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रियाएं पूरी होने की बात कही है, उससे भारत के व्यापारिक हितों पर असर पड़ेगा। ब्रिटेन किन शर्तों के साथ यूरोपीय संघ से अलग होता है उसके आधार पर भारत दोनों क्षेत्रों के लिए भावी कारोबारी नीति तैयार करेगा। ब्रिटेन में कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियां भी ब्रेक्जिट पर वहां की सरकार के फैसले का इंतजार कर रही हैं।

ब्रिटेन की नई सरकार से भारत को एक बड़ी उम्मीद यह है कि वहां शरण पाए आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की राह आसान होगी। भारत के दो सबसे बड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या और नीरव मोदी अभी ब्रिटेन में हैं। वहां वे प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका भविष्य बहुत कुछ नई सरकार के गृह मंत्रालय के हाथ में होगा।

इसी तरह से ब्रिटेन में शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को लेकर वहां की सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी का मुद्दा भी भारत लगातार उठाता रहा है। वैसे कंजरवेटिव पार्टी का रुख बाहर से आने वालों को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं है, ऐसे में देखना होगा कि वह भारतीय छात्रों को शिक्षा के बाद रोजगार देने के मुद्दे पर नरमी अपनाती है या नहीं।

क्यों भारत के लिए अहम है जॉनसन की जीत

- कश्मीर को लेकर उनकी सरकार भारत के रुख को लेकर दिखाएगी समझ
- खालिस्तान समर्थन की आड़ में भारत विरोधी भावनाओं पर लगेगी लगाम
- भारतीय छात्रों व पेशेवरों को हतोत्साहित करने वाली नीति में होगा संशोधन
- आर्थिक अपराधी विजय माल्या, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में मिल सकती है मदद

ब्रिटिश संसद में बढ़ा भारतवंशियों का कुनबा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के सांसदों का कुनबा बढ़ गया है। गुरुवार को हुए चुनाव में भारतीय मूल के 11 सांसद दोबारा चुनाव जीतने में सफल रहे। चार नए चेहरे भी संसद पहुंचे हैं। 2017 के चुनाव में 12 भारतवंशी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी।

पहली बार चुनाव जीतने वालों में गगन मोहिंदर, क्लेयर कूटिन्हो, नवेंद्रु मिश्रा और मुनीरा विल्सन हैं। मोहिंदर ने कंजरवेटिव पार्टी के टिकट पर हार्टफोर्डशायर साउथ वेस्ट सीट से जीत दर्ज की। इसी पार्टी की उम्मीदवार और गोवा से ताल्लुक रखने वाली क्लेयर ने सरे ईस्ट सीट से बड़े अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को हराया। नवेंद्रु लेबर पार्टी से स्टॉकपोर्ट सीट से चुनाव जीते हैं। जबकि विल्सन लिबरल डेमोक्रेट्स के टिकट पर साउथ-वेस्ट लंदन की सीट से निर्वाचित हुईं।

आसान जीत के साथ दोबारा संसद पहुंचने वाले भारतीय मूल के कंजरवेटिव उम्मीदवारों में प्रीति पटेल भी शामिल हैं। इसी पार्टी से इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक और आलोक शर्मा भी दोबारा संसद पहुंचे। शैलेस वारा ने नॉर्थ वेस्ट कैंब्रिजशायर और गोवा मूल की सुएला ब्रावरमैन ने फेयरहम सीट से जीत दर्ज की। आम चुनाव में हालांकि विपक्षी लेबर पार्टी ने अपने कई गढ़ गंवा दिए लेकिन इस पार्टी के टिकट पर पिछली बार संसद पहुंचने वाले सभी भारतवंशी उम्मीदवार इस बार भी जीत गए। पिछले चुनाव में पहली सिख महिला के तौर पर संसद पहुंचने का रिकार्ड बनाने वाली प्रीत कौर गिल बर्मिंघम एजबेस्टन सीट से फिर चुनी गई हैं। तनमनजीत सिंह ढेसी दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड की स्लफ सीट से भारतीय मूल के ही कंजरवेटिव उम्मीदवार कंवल तूर गिल को हराकर दोबारा संसद पहुंचे। वीरेंद्र शर्मा ने ईलिंग साउथहाल सीट से आसान जीत दर्ज की। लीजा नंदी विगान सीट और सीमा मल्होत्रा फेल्थम एंड हेस्टन सीट से दोबारा निर्वाचित हुईं। पूर्व सांसद कीथ वाज की बहन वेलरी वाज ने वाल्सल साउथ सीट पर भारतीय मूल के कंजरवेटिव उम्मीदवार गुरजीत बैंस को परास्त किया।

▸ **आम चुनाव में चार नए चेहरों समेत भारतीय मूल के 15 उम्मीदवार जीते**

प्रीति पटेल।

क्लेयर कूटिन्हो।

मुनीरा विल्सन

नवेंद्रु मिश्रा।

गगन मोहिंदर (बाएं) और शैलेस। सभी फाइल

प्रीति पटेल को अहम ओहदा मिलने की उम्मीद : एसेक्स की विथम सीट से चुनाव जीतने पर पटेल ने कहा, 'कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत में लाने के लिए यह बेहद कठिन चुनाव जीतना अहम था। हम बेक्जिट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह हमारी प्राथमिकता है।' माना जा रहा है कि जॉनसन कैबिनेट में प्रीति को फिर अहम ओहदा मिल सकता है। वह पिछली सरकार में गृह मंत्री थीं।

63 भारतीयों ने लड़ा था चुनाव : भारतीय मूल के 63 लोगों ने चुनाव लड़ा था। इनमें 25 को कंजरवेटिव पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। लेबर पार्टी से 13, ब्रेक्जिट पार्टी से 12 और लिबरल डेमोक्रेट्स से आठ भारतवंशियों ने चुनाव लड़ा था। बाकी अन्य दलों के उम्मीदवार या निर्दलीय रहे। इनमें से कंजरवेटिव और लेबर पार्टी से सात-सात भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स से एक भारतवंशी को जीत मिली।

ब्रेक्जिट पर वार्ता के लिए ईयू तैयार

ब्रसेल्स, एएफपी : ब्रिटेन के आम चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जीत के बाद यूरोपीय यूनियन (ईयू) के नेताओं ने कहा कि वे ब्रेक्जिट पर अगले चरण की वार्ता के लिए तैयार हैं। ईयू के नेता शुक्रवार को यहां जमा हुए। वे 28 सदस्यीय ईयू से ब्रिटेन के बाहर होने के मसले पर चर्चा करेंगे। इस मौके पर ईयू अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा, 'मेरी बात एकदम स्पष्ट है। हम तैयार हैं। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छी बातचीत होगी।' जबकि ब्रेक्जिट वार्ता की निगरानी करने वाले यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन ने कहा, 'हम पूरी तरह तैयार हैं।'

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, जॉनसन की जीत पर चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिज ने कहा कि यह यूरोप के लिए बुरी खबर है। वह जीत गए और ईयू से बाहर हो जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सदन में आया

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की कानूनी मामलों की समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गुरुवार को 14 घंटे चली बहस के बाद शुक्रवार को समिति में पार्टीलाइन पर मतदान हुआ और 23-17 के बहुमत से प्रस्ताव को सदन की राय के लिए भेज दिया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले सदन में अगले सप्ताह प्रस्ताव रखकर महाभियोग चलाने पर सांसदों की राय जानी जाएगी। उम्मीद है कि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले सदन में ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। महाभियोग का सामना करने वाले ट्रंप अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति होंगे।

कानूनी मामलों की संसदीय समिति में 23 डेमोक्रेटिक सदस्य जहां ट्रंप के सत्ता के दुरुपयोग के आरोप के साथ थे, वहीं 17 रिपब्लिकन सदस्य राष्ट्रपति के बचाव में थे। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नेंसी पेलोसी पूर्व में ही इसकी संभावना जता चुकी हैं और उन्होंने क्रिसमस के करीब महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान का भी एलान कर दिया है। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित भी हो सकता है लेकिन उच्च सदन सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, वहां पर महाभियोग प्रस्ताव गिर सकता है। इसलिए ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर बने रहने की संभावना प्रबल है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की स्थितियां जुलाई में उनकी अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन वार्ता के बाद बनीं। आरोप है कि ट्रंप ने इसमें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू कराने के लिए दबाव बनाया, जो राष्ट्रपति के तौर पर पद का दुरुपयोग था।

वाशिंगटन में वार्षिक ह्वाइट हाउस कांग्रेसनल बॉल समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ने अपने स्टाइलिश अंदाज से लोगों को विस्मित कर दिया। इस मौके पर मेलानिया द्वारा पहना गया आकर्षक और कीमती सफेद गाउन इसकी एक प्रमुख वजह बना और सभी की नजरें उन पर टिक गईं। दरअसल, मेलानिया ने लेबनानी डिजाइनर रीम अक्रा का क्रिस्टल जड़ित गाउन पहना, जिसकी कीमत चार हजार डॉलर (करीब तीन लाख रुपये) है। रीम अक्रा ब्राइडल डिजाइनर के तौर पर मशहूर हैं। एपी

न्यूज गैलरी

चार भारतीय डीएससी साहित्य पुरस्कार के लिए नामित

पोखरा : इस साल के डीएससी प्राइज पुरस्कार के लिए नामित छह लेखकों में चार भारतीय हैं। 25 हजार डॉलर (करीब 17 लाख रुपये) की इनामी राशि वाला यह पुरस्कार हर साल दक्षिण एशियाई क्षेत्र और लोगों पर अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। भारत के अमिताभ बागची (हाफ द नाइट इज गॉन), माधुरी विजय (द फार फील्ड), राज कमल झा (द सिटी एंड द सी) और मनोरंजन व्यापारी (देयर इज गनपाउडर इन द एयर) के अलावा सादिया अब्बास (द एंपटी रूम) और जमील जन कोचाई (99 नाइट्स इन लोगर) इस पुरस्कार की होड़ में हैं। (प्रेट्र)

ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की कमान महिला अधिकारी को

सिडनी : अगले साल फरवरी से ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टोरेट (एएसडी) की कमान महिला अधिकारी रशेल नोबल संभालेंगी। वह ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी की बागडोर संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने शुक्रवार को एएसडी के महानिदेशक पद पर रशेल की नियुक्ति की घोषणा की। (रायटर)

इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनीं परवेज

इस्लामाबाद : लुब्ना सलीम परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं। उन्हें शुक्रवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। इससे पहले वह सिंध हाई कोर्ट में डिप्टी जनरल थीं। (आइएएनएस)

पाकिस्तान में बस में लगी आग से 15 की मौत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को बस और तेल से लदी वैन की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद वैन और बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर तस्करी का तेल लेकर जा रहा था और सामने से आ रही बस से जा टकराया। (आइएएनएस)

अफगानिस्तान में बम धमाके में 10 की गई जान

काबुल : अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में शुक्रवार को सड़क किनारे रखे एक बम के धमाके से चार महिलाओं और एक बच्चे समेत दस नागरिकों की मौत हो गई। यह सभी लोग एक वैन में सवार होकर गजनी शहर जा रहे थे। (एपी)

आतंकवाद की हर बड़ी घटना से जुड़े पाक के तार : भारत

▸ **संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा एनआरसी और नागरिकता विधेयक जैसे मुद्दे उठाने पर भारत ने किया पलटवार**

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की हर बड़ी घटना का कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ाव है। यही वह देश है जहां बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में नागरिकता बिल और जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दे उठाए जाने के बाद भारत ने गुरुवार को यह तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

'शांति की संस्कृति' विषय पर अपनी बात रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सबसे जूनियर सदस्य पालोमी त्रिपाठी ने कहा, 'सहयोग शांति की संस्कृति का मूल तत्व है। इसका प्रयोग राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। हमें उस समय विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है जब लोमड़ी मुर्गियों की रखवाली कर रही हो।' पालोमी पाकिस्तान के स्थानीय प्रतिनिधि मुनीर अकरम की टिप्पणियों का जवाब दे रही थीं। अकरम ने अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 की समाप्ति, नागरिकता संशोधन विधेयक, एनआरसी और अयोध्या विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां की थीं। पाक पर जोरदार पलटवार करते हुए पालोमी ने कहा, 'इस देश में बच्चों और युवाओं को किताबों के बदले बंदूक दी जाती हैं। महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है और अल्पसंख्यकों को सताया जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में आधारहीन आरोप लगाता है। इस तरह के आरोपों पर भारत की स्थिति जगजाहिर है। हम इन आरोपों को पूरी दृढ़ता से खारिज करते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस तरह के दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए।'

पालोमी त्रिपाठी। फाइल

चीन बोला, दुनिया के लिए परेशानी पैदा करने वाला देश है अमेरिका

▸ **विदेश मंत्री ने कहा, मतभेद सुलझाने को तैयार लेकिन एकतरफा प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेंगे**

बीजिंग, एपी : कई अंतरराष्ट्रीय संधियों से ट्रंप प्रशासन के हटने का हवाला देते हुए चीन ने अमेरिका को दुनिया के लिए परेशानी पैदा करने वाला देश करार दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को यहां कहा, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व के अपने अधिकार को लेकर हमेशा अडिग रहता है और यही वह एकमात्र कारण है जिसने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर क्षति पहुंचाई है।

विदेश मंत्री ने कहा, 'हम समानता और आपसी सम्मान के आधार पर संवाद और चर्चा के माध्यम से अमेरिका के साथ मतभेदों को हल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम किसी भी एकतरफा प्रतिबंध या डराने-धमकाने की किसी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगे।' वांग के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका के हटने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने कई समस्याएं आ खड़ी हुई हैं और वर्तमान परिपेक्ष्य में अमेरिका दुनिया के लिए समस्या पैदा करने वाला देश बन गया है। वांग की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब व्यापार समझौते, राजनीति और चीन पर बौद्धिक संपदा चोरी के आरोपों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन की विदेश नीति पर आयोजित एक कांफ्रेंस में वांग ने कहा, चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय गरिमा और मूल हितों से संबंधित मुद्दों को लेकर अमेरिका लगातार जानबूझकर हमलावर रुख अपनाए है।

बीजिंग में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्थिति और चीन की कूटनीति पर वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते चीनी विदेश मंत्री वांग यी। रायटर

ताइवान के चुनाव में दखल ना दे चीन : अमेरिका

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका ने चीन से कहा है कि वह अगले महीने ताइवान में होने वाले चुनाव में दखल ना दे। एशिया मामलों से जुड़े शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डेविड स्टिलवेल ने गुरुवार को यहां कहा, ताइवान में चुनाव को पड़ोसी देश चीन द्वारा प्रभावित करने की कोशिश पहले भी की जाती रही है। 11 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए इसकी चिंता इस बार भी बनी हुई है। चीन को इससे बचना चाहिए।

ताइवान के इस चुनाव में चीन विरोधी राष्ट्रपति साई इंग-वेन का मुकाबला चीन समर्थक राष्ट्रपति उम्मीदवार से है। कहा जा रहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से चीन, ताइवान के नजदीक अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाने में लगा है। अमेरिका का कहना है कि चीन को स्वायत्तशासी ताइवान के साथ किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए हिंसा या धमकी के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।

भारत, अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने में टू प्लस टू वार्ता अहम

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता से पहले एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के तहत दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को बढ़ाने में इसकी भूमिका अहम हो गई है। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्षों माइक पोंपियो और मार्क एस्पर के साथ दूसरे दौर की टू प्लस टू वार्ता के लिए अगले सप्ताह यहां आने वाले हैं। बता दें कि पहले दौर की वार्ता पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में हुई थी।

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक विदेश सचिव एलिस जी वेल्स ने कहा कि 2018 में मंत्रिस्तरीय वार्ता के पहले दौर की सफलता इस साल की बैठक में परिलक्षित होगी। उन्होंने कहा कि हालांकि भातर और अमेरिका के रिश्तों में बीते कुछ वर्षों में काफी मजबूती आई है। अब इस साल की वार्ता में द्विपक्षीय सामरिक और रक्षा संबंध बढ़ाने, वैश्विक गतिविधियों पर विचारों का आदान-प्रदान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

दिखाई ताकत

इंटरमीडियट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से अलग होने के बाद दूसरी बार किया प्रक्षेपण, रूस ने कहा-रहेंगे सतर्क

अमेरिका ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी सेना ने जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस के साथ आइएनएफ संधि के तहत इस तरह की मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगी थी। लेकिन हाल में दोनों देश इस संधि से अलग हो गए थे। इस परीक्षण पर रूस ने कहा है कि वह भविष्य में इससे सतर्क रहेगा।

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि वायुसेना ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे वांडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, समुद्र में गिरने से पहले मिसाइल ने खुले आकाश में 500 किमी से अधिक की उड़ान भरी। पेंटागन ने कहा है कि इस परीक्षण से प्राप्त डाटा का उपयोग भविष्य में होने वाले परीक्षणों में किया जाएगा। आइएनएफ (इंटरमीडियट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी) संधि से हटने के बाद अमेरिका द्वारा किया गया यह दूसरा मिसाइल परीक्षण है। अमेरिकी सेना ने इससे पहले गत अगस्त में नौसेना के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था।

कैलिफोर्निया स्थित वांडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। एएफपी

क्या है आइएनएफ संधि : शीत युद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ ने यूरोपीय देशों को निशाना बनाने के मकसद से अपने सीमावर्ती इलाकों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात कर दी थीं। मध्यम दूरी की ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थीं। वर्ष 1987 में शीत युद्ध की स्थिति को खत्म करने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और अंतिम सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने एक संधि की थी। इसे ही आइएनएफ संधि नाम दिया गया। इस संधि के तहत परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम जमीन से 500 से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों के निर्माण पर रोक थी। इस संधि से पश्चिमी देशों पर सोवियत संघ के परमाणु हमले का खतरा खत्म हो गया था। लेकिन इस साल अगस्त में अमेरिका और रूस इससे अलग हो गए थे।

पाक के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी दो करोड़ की जमानत पर रिहा

इस्लामाबाद, आइएएनएस : भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में चल रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को खराब स्वास्थ्य के आधार पर उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में पाकिस्तान के आयुर्विज्ञान संस्थान में जरदारी का इलाज चल रहा था। जमानत के मुचलके के तौर पर जरदारी को दो करोड़ रुपये जमा करने पड़े हैं।

अस्पताल से निकलते ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जरदारी को इस्लामाबाद स्थित उनके घर ले जाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए कराची ले जाए जाने की खबर है। फर्जी बैंक खाते के जरिये भ्रष्टाचार को अंजाम देने के आरोप में पाकिस्तानी जांच एजेंसी एनएबी ने जरदारी को जून में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत पर अदियाला जेल भेज दिया गया था।

अमेरिका ने तालिबान के साथ वार्ता फिर स्थगित की

वाशिंगटन, एएफपी : अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी एयरबेस के पास हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत फिर स्थगित कर दी है। अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा, 'तालिबान नेताओं से मुलाकात में मैंने बगराम पर हुए हमले के बारे में नाराजगी व्यक्त की। तालिबान को दुनिया को यह दिखाना होगा कि वह अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के प्रति गंभीर है।'

अफगानिस्तान में बीते बुधवार को अमेरिकी सेना के अहम सैन्य ठिकाने बगराम के पास एक अस्पताल की इमारत के बाहर आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरे वाहन को उड़ा दिया था। इस हमले में दो नागरिकों की मौत हो गई थी।

तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले से कुछ ही दिन पहले अमेरिका और आतंकी संगठन के बीच बातचीत फिर शुरू हुई थी। इस साल की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता हुई थी। लेकिन काबुल में एक हमले के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में अचानक वार्ता रद कर दी थी। पिछले महीने उन्होंने वार्ता फिर शुरू करने की घोषणा करते हुए संघर्ष विराम की जरूरत पर जोर दिया था।

खलीलजाद से मिले पाक विदेश मंत्री कुरैशी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान ईमानदारी से अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में सहयोग देना जारी रखेगा। कुरैशी ने शुक्रवार को यहां खलीलजाद से मुलाकात की। बैठक में कुरैशी ने पाकिस्तान के इस रुख को दोहराया कि अफगानिस्तान के मुद्दे का कोई सैन्य समाधान नहीं है।

मुझे पाकिस्तान की टीम का स्पिन गेंदबाजी सलाहकार बनाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टीम को इससे फायदा मिले।
— मुश्ताक अहमद, पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर

विश्व टूर फाइनल्स का आखिरी मैच जीत सिंधू ने बचाया सम्मान

गुआंगझाओ (चीन) : भारत की पीवी सिंधू शुक्रवार को बीडब्ल्यूएफ के ग्रुप-ए के अपने आखिरी मैच को जीतने में सफल रहीं। उन्होंने महिला सिंगल्स के इस मैच में चीन की हीर बिंगजियाओ को मात दे टूर्नामेंट से विजयी विदाई ली है। इस टूर्नामेंट में खेले गए तीन मैचों में सिंधू को सिर्फ यही जीत मिली है। वह शुरुआती दो मैच हार कर पहले ही टूर्नामेंट के अगले दौर में जाने की रेस से बाहर हो गई थीं।

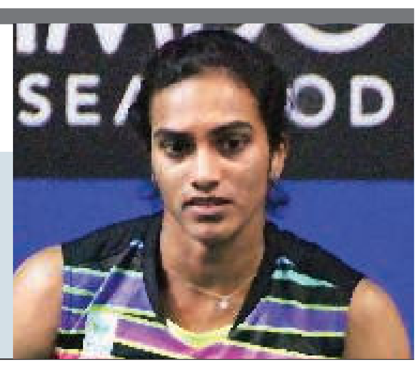

आइपीएल नीलामी में युवा प्रियम गर्ग पर रहेंगी सबकी नजरें

कोलकाता में गुरुवार को सजेगा आइपीएल का बाजार, 332 खिलाड़ियों में से 73 स्थानों के लिए आठ टीमों के बीच होगी जोर-आजमाइश

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के 12वें संस्करण के लिए होने वाली नीलामी में 332 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आइपीएल 2020 के लिए इस बार कोलकाता में 19 दिसंबर को लीग की आठों फ्रेंचाइजियां अपनी-अपनी टीमों में बाकी बचे स्थानों के लिए बोली लगाएंगी। इस लीग में एंट्री करने के इरादे से इस बार 997 खिलाड़ियों ने अपने नाम रजिस्टर कराए थे। इन नामों में आठों फ्रेंचाइजियों ने इन खिलाड़ियों में अपने पसंदीदा क्रिकेटरों के नाम दिए थे, जिनके बाद 332 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस बार नीलामी में कुल 73 खाली जगहों को भरा जाना है।

कोलकाता में गुरुवार (19 दिसंबर) को होने जा रही यह नीलामी दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगी। इस बार नीलामी में कुल 186 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि 143 विदेशी खिलाड़ी होंगे। इनमें से तीन खिलाड़ी असोसिएट्स देशों में से हैं।

अंडर-19 खिलाड़ियों पर बड़ी बोली की उम्मीद : उत्तर प्रदेश के मेरठ के प्रियम गर्ग सहित अंडर-19 भारतीय टीम के खिलाड़ियों को नीलामी में बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में अगले वर्ष 17 जनवरी से होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए प्रियम को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। प्रियम पिछले एक वर्ष से अंडर-19 टीम की कप्तानी कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी पदार्पण में शतक लगाने वाले प्रियम ने अपने करियर में अब तक सभी बोर्ड ट्रॉफी में मिलाकर कुल 10 दोहरे शतक लगाए हैं। प्रियम के अलावा हापुड़ के ही तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी, मुंबई के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी नीलामी में बड़ी रकम मिल सकती है। मालूम हो कि 2018 में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य पृथ्वी शॉ, शुभम मावी, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने आइपीएल नीलामी में हाथों हाथ लिया था।

दो करोड़ आधार मूल्य में सभी विदेशी: इस बार बोली का सबसे शीर्ष रिजर्व आधार मूल्य दो करोड़ है, जिसमें शामिल सभी सातों खिलाड़ी विदेशी हैं। दो करोड़ की स्लैब में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है। इन सात विदेशी खिलाड़ियों में पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, क्रिस लिन, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल (सभी ऑस्ट्रेलिया), डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका) और एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका) शामिल हैं।

भारतीयों में उथप्पा का आधार मूल्य सबसे ज्यादा : नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रिजर्व आधार मूल्य रॉबिन उथप्पा का है। रॉबिन नीलामी की दूसरी सबसे महंगी रिजर्व स्लैब 1.5 करोड़ में शामिल हैं। रॉबिन के बाद भारतीय सितारों में पीयूष चावला, यूसुफ पठान और जयदेव उनादकट का नाम एक करोड़ के आधार मूल्य वाली स्लैब में शामिल हैं।

घरेलू खिलाड़ियों का दावा : घरेलू खिलाड़ियों में 183 खिलाड़ी (167 भारतीय व 16 विदेशी) 20 लाख आधार मूल्य स्लैब में, सात खिलाड़ी (एक भारतीय व सात विदेशी) 40 लाख आधार मूल्य स्लैब में और आठ खिलाड़ी (पांच भारतीय व तीन विदेशी) 30 लाख की आधार मूल्य स्लैब में शामिल हैं।

सर्वाधिक आधार मूल्य वाले शीर्ष चार भारतीय

रॉबिन उथप्पा ● फाइल फोटो, ट्विटर

रॉबिन उथप्पा (1.5 करोड़)
कोलकाता नाइटराइडर्स ने इस बार रॉबिन उथप्पा को रिलीज कर दिया है। दो बार की चैंपियन टीम ने इस बार कई खिलाड़ियों को रिलीज किया, जिसमें उथप्पा भी शामिल थे। बीता सत्र इस भारतीय बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 12 पारियों में उन्होंने 115 के करीब के स्ट्राइक रेट से 282 रन बनाए।

पीयूष चावला (1 करोड़)
पीयूष चावला उन चार गेंदबाजों में शामिल हैं जिनके नाम आइपीएल में 150 विकेट हैं। कोलकाता नाइटराइडर्स ने इस सत्र में इस लेग स्पिनर को भी रिलीज कर दिया है। उनके अनुभव के चलते कई टीमें चावला को अपना हिस्सा बनाना चाहेंगी।

यूसुफ पठान (1 करोड़)
यूसुफ पठान पिछले सत्र में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेले थे। मध्य क्रम के धाकड़ बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर पठान को खरीदने में टीमें कितनी दिलचस्पी दिखाती हैं, यह देखना रोचक होगा।

जयदेव उनादकट (1 करोड़) : बायें हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट की फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में रही है। उन्होंने खुद को एक करोड़ रुपये के आधार मूल्य की कीमत में रजिस्टर किया है। हालांकि, बीते दो सत्रों में सौराष्ट्र के इस गेंदबाज पर अप्रत्याशित बोली लगी है, लेकिन अगले सत्र में क्या होता है यह काफी रोचक होने वाला है।

किसके पास कितने स्थान

टीम	बची रकम	कुल स्थान	विदेशी
रॉयल चैलेंजर बेंगलूर	27.90 करोड़	12	6
कोलकाता नाइटराइडर्स	35.65 करोड़	11	4
राजस्थान रॉयल्स	28.90 करोड़	11	4
दिल्ली कैपिटल्स	27.85 करोड़	11	5
किंग्स इलेवन पंजाब	42.70 करोड़	9	4
सनराइजर्स हैदराबाद	17.00 करोड़	7	2
मुंबई इंडियंस	13.05 करोड़	7	2
चेन्नई सुपरकिंग्स	14.60 करोड़	5	2

50 लाख रुपये के आधार मूल्य वाले भारतीय

भारतीय टेस्ट टीम के विशेषज्ञ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी का आधार मूल्य 50 लाख रुपये है। पुजारा को बीते साल की नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा था, वहीं विहारी दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। उन्हें इस फ्रेंचाइजी टीम ने इस बार रिलीज कर दिया है। इनके अलावा ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी, तेज गेंदबाज मोहित शर्मा और बरिंदर सरां, बल्लेबाज मनोज तिवारी एवं सौरभ तिवारी और विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा का भी आधार मूल्य 50 लाख रुपये है।

सबसे उम्रदराज और सबसे युवा खिलाड़ी

भारत के प्रवीण तांबे नीलामी की सूची में शामिल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इस लेग स्पिनर की मौजूदा उम्र 48 साल है। उन्होंने 61 टी-20 मुकाबलों में 67 विकेट लिए हैं। विदेशी खिलाड़ियों में सबसे उम्रदराज ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर फवाद अहमद हैं। 37 साल के इस गेंदबाज ने 88 टी-20 मैचों में 91 विकेट लिए है। वहीं, अफगानिस्तान के बायें हाथ के चाइनामैन गेंदबाज नूर अहमद सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वह 14 साल के हैं। उन्होंने सात टी-20 मैचों में आठ विकेट लिए है।

प्रियम गर्ग ● फाइल फोटो, ट्विटर

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

आधार मूल्य	कुल	भारतीय	विदेशी
2 करोड़	7	–	7
1.5 करोड़	10	1	9
1 करोड़	23	3	20
75 लाख	16	–	16
50 लाख	78	9	69

घरेलू खिलाड़ी

आधार मूल्य	कुल	भारतीय	विदेशी
40 लाख	7	1	6
30 लाख	8	5	3
20 लाख	183	167	16

02 करोड़ के आधार मूल्य में सात खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पांच खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं

1.5 करोड़ के आधार मूल्य में कुल 10 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें सर्वाधिक चार इंग्लैंड (इयोन मोर्गन, जेसन रॉय, क्रिस वोक्स व डेविड विली) के हैं, तीन ऑस्ट्रेलिया (एडम जांपा, शॉन मार्श, केन रिचर्डसन) के हैं, जबकि दो दक्षिण अफ्रीका (काइली एबॉट व क्रिस मौरिस) के हैं। इस सूची में इकलौते भारतीय रॉबिन उथप्पा हैं

01 करोड़ के आधार मूल्य में कुल 23 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें तीन भारतीय व 20 विदेशी खिलाड़ी हैं

75 लाख के आधार मूल्य में कुल 16 खिलाड़ी शामिल हैं और ये सभी विदेशी हैं

50 लाख के आधार मूल्य में कुल 78 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें नौ भारतीय और 69 विदेशी हैं

198 घरेलू खिलाड़ी भी नीलामी में शामिल हैं, जिन्हें 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख के तीन आधार मूल्य वर्गों में बांटा गया है

विदेशी खिलाड़ियों में बड़े नाम

खिलाड़ी	टीम	आधार मूल्य
क्रिस लिन	ऑस्ट्रेलिया	2 करोड़
पैट कमिंस	ऑस्ट्रेलिया	2 करोड़
ग्लेन मैक्सवेल	ऑस्ट्रेलिया	2 करोड़
डेल स्टेन	द.अफ्रीका	2 करोड़
मिशेल मार्श	ऑस्ट्रेलिया	2 करोड़
जोश हेजलवुड	ऑस्ट्रेलिया	2 करोड़
एंजेलो मैथ्यूज	श्रीलंका	2 करोड़

अंडर-19 विश्व कप टीम के खिलाड़ी

प्रियम गर्ग	उत्तर प्रदेश	20 लाख
यशस्वी	मुंबई	20 लाख
कार्तिक त्यागी	उत्तर प्रदेश	20 लाख
रवि बिश्नोई	राजस्थान	20 लाख
शुभांग हेगडे	कर्नाटक	20 लाख

घरेलू क्रिकेट के दमदार खिलाड़ी

विराट सिंह	झारखंड	20 लाख
शाह रुख खान	कर्नाटक	20 लाख
इशान पोरेल	बंगाल	20 लाख
अभिमन्यु	बंगाल	20 लाख
कर्णवीर सिंह	उत्तराखंड	20 लाख
प्रियांक पांचाल	गुजरात	20 लाख

आइपीएल के ओल्ड इज गोल्ड

रॉबिन उथप्पा	भारत	1.5 करोड़
क्रिस मॉरिस	द.अफ्रीका	1.5 करोड़
इविन लुइस	वेस्टइंडीज	1 करोड़
सैम कुर्रन	इंग्लैंड	1 करोड़
यूसुफ पठान	भारत	1 करोड़
पीयूष चावला	भारत	1 करोड़
उनादकट	भारत	1 करोड़
डेविड मिलर	द.अफ्रीका	75 लाख
स्टुअर्ट बिन्नी	भारत	50 लाख
हेटमायर	वेस्टइंडीज	50 लाख

अफगान क्रिकेट के माफियाओं की पोल खोलूंगा : नायब

काबुल, आइएएनएस: इंग्लैंड में आयोजित आइसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे गुलबदीन नायब ने आरोप लगाए हैं अफगान क्रिकेट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नायब ने कहा है कि वह अफगान क्रिकेट के माफिया गिरोह की पोल खोल सकते हैं। नायब ने यह भी कहा कि इसी माफिया गिरोह के कारण अफगान क्रिकेट लाखों देशवासियों को धोखा दे रहा है।

नायब ने गुरुवार को ट्वीट किया कि मेरे प्यारे अफगानियों। मैंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान इसलिए दिया क्योंकि मुझे किसी खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं जल्द ही उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करने वाला हूं, जो भ्रष्टाचार एवं अन्य गलत कार्यों में लिप्त है और इसके कारण लाखों-करोड़ों देशवासी धोखे में हैं। नायब ने यह भी कहा कि कुछ खिलाड़ी जानबूझकर विश्व कप में खराब खेले। अफगान टीम विश्व कप में अपने सभी नौ मैच हार गया। इसका कारण यह था कि विश्व कप से ठीक पहले नायब को टीम का कप्तान बनाया गया था और जो खिलाड़ी जानबूझकर खराब खेले, उन्होंने बोर्ड के सामने यह सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था। नायब ने ट्वीट किया कि जो लोग खराब खेले, सरकार में उनकी दखल है। ये प्रबंधन के करीबी हैं। ये मेरी कप्तानी में अच्छा नहीं खेलना चाहते थे।

भुवनेश्वर चोट के चलते बाहर, शार्दुल टीम में शामिल

वनडे सीरीज

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वन-डे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मुंबई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने उनकी जगह ली है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भुवनेश्वर चोटिल हो गए और उन्हें वनडे टीम से बाहर होना पड़ा। हालांकि, उनकी चोट कितनी गंभीर है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हो सकता है कि टी-20 सीरीज के दौरान भुवनेश्वर को मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हुई, जो अब गहरा गई है। चोट की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि विश्व कप के दौरान उन्हें परेशान करने वाले मांसपेशियों के खिंचाव से इसका कोई संबंध नहीं है। चयनकर्ता आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद भुवनेश्वर की जगह नए खिलाड़ी के नाम की घोषणा की जाएगी।

भुवनेश्वर बीते कुछ समय से लगातार चोटिल हो रहे हैं। विश्व कप में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच में समस्या हुई थी। उन्होंने सेमीफाइनल में वापसी की थी, लेकिन फिर घरेलू सीरीज में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेले। यदि भुवनेश्वर टीम से बाहर होते हैं तो चोट के कारण टीम से हटने वाले वह शिखर धवन के बाद दूसरे खिलाड़ी होंगे। धवन को मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान चोट लगी थी। टी-20 टीम में उनकी जगह संजू सैमसन ने, जबकि वनडे टीम में मयंक अग्रवाल ने ली थी।

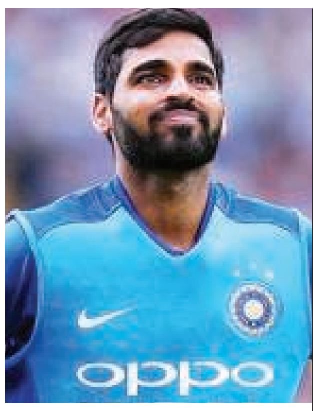

भुवनेश्वर कुमार ● फाइल फोटो, प्रेट्र

दूसरे वनडे से पहले नेट अभ्यास करेंगे बुमराह : कमर की चोट से उबर चुके भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले नेट पर भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज की शुरुआत से ही टीम से बाहर हैं। वह हालांकि अब ठीक होने की राह पर हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि अगले साल न्यूजीलैंड दौरे से पहले वह फिट हो जाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया कि बुमराह भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। अब यह परंपरा बन गई है। टीम प्रबंधन ने भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस भी इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट से पहले परखी थी। हालांकि, वह टीम का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह बुमराह की फिटनेस को आजमाया जाएगा। अब यही परंपरा बन गई है कि जब कोई खिलाड़ी फिट होता नजर आता है तो टीम प्रबंधन, फिजियो अभ्यास में उन्हें परखते हैं।

आत्मविश्वास बढ़ने से बेहतर ऑलराउंडर बनेंगे दुबे : अरुण

चेन्नई, प्रेट्र : भारतीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा कि शिवम दुबे में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अच्छे ऑलराउंडर बनने के गुण हैं क्योंकि प्रत्येक मैच के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। दुबे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 30 गेंद में 54 रन की पारी के दौरान बड़े शॉट खेलकर सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने इस पारी में चार छक्के लगाए। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। अरुण ने कहा कि वह अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि हर मैच के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अगर आप उनकी गेंदबाजी भी देखेंगे तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में अपना पहला ओवर डालने के बाद जिस तरह वापसी की, वह शानदार था। महंगे ओवर के बाद भी विराट ने उन पर भरोसा दिखाया, ताकि वह अच्छा स्पैल डाल सकें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है वह हमारे लिए शानदार प्रतिभा हैं। जैसे-जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा वह अच्छे ऑलराउंडर बनेंगे। भारतीय गेंदबाजी कोच ने इस मौके पर तेज गेंदबाज दीपक चाहर की भी तारीफ करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनके पास सब कुछ है। उन्होंने कहा कि दीपक ने आइपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद को दोनों ओर स्विंग कर सकते हैं। वह काफी कौशल वाले गेंदबाज हैं, जो धीमी बाउंसर और यॉर्कर फेंक सकते है। इतनी प्रतिभा के साथ उनके पास वो सब कुछ है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए चाहिए। विश्व कप के बाद से कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह चहल एक साथ टीम में नहीं दिखे है। अरुण ने कहा कि हम एक आदर्श संयोजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो टीम को पूर्ण संतुलन प्रदान करे। हमारे पास रवींद्र जडेजा को ऑलराउंडर की तरह इस्तेमाल करने का विकल्प होगा। इससे हमें काफी मदद मिलेगी। वनडे सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के लिए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पिछले तीन में से जो दो मैच हम जीते हैं उसमें गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा है।

कोहली की तरह कड़ी मेहनत करें हमारे खिलाड़ी : एस्टविक

चेन्नई, प्रेट्र : वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम सहायक कोच रोडी एस्टविक ने विराट कोहली को 'पैमाना' बताते हुए कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए उनकी टीम के सभी खिलाड़ियों को भारतीय कप्तान की तरह कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एस्टविक ने कहा कि शिमरोन हेटमायर और निकोलस पूरन जैसे टीम के युवा खिलाड़ियों को विरोधी टीम के कप्तान कोहली से सीख लेनी चाहिए।

उन्होंने शुक्रवार को कहा कि टीम में हेटमायर, पूरन और होप जैसे खिलाड़ियों के होने से यह हमारे लिए रोमांचक समय है। हमें ऐसे युवा बल्लेबाज मिले हैं, जो बेहतर प्रगति कर रहे हैं। अहम बात यह है कि आप कड़ी मेहनत करने के लिए कैसे तैयार होते हैं। आपको विराट कोहली में एक पैमाना मिला है। वह ऐसा खिलाड़ी है जो जिम में काफी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे काफी खिलाड़ी सीख सकते हैं। तभी हमारे लिए मौका होगा। कड़ी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी। कड़ी मेहनत कई बार उबाऊ होती है लेकिन इससे आपको सफलता मिलेगी। एक बार जब वे काम करना शुरू करेंगे और इस प्रक्रिया से जूझेंगे तब उनके पास मौका होगा।

ब्रावो ने संन्यास से वापस लौटने की घोषणा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ मतभेदों के कारण खेल को अलविदा कहने वाले ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का एलान किया। ब्रावो ने कहा कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की सत्ता में बदलाव के कारण उन्होंने मन बदला है। पूर्व टीम मैनेजर रिकी स्केरिट अब डेव कैमरन की जगह बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ब्रावो ने कहा कि आज मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की घोषणा करता हूं। मैंने यह फैसला प्रशासनिक स्तर पर बोर्ड में हुए बदलाव के बाद लिया है। मैं कुछ समय से इस बारे में सोच रहा था और सकारात्मक बदलावों ने मेरे फैसले को मजबूत किया। ब्रावो का कैमरन के साथ झगड़ा हुआ था जिन पर उसने करियर तबाह करने का आरोप लगाया था। यह 2014 में हुआ था जब ब्रावो की अगुआई वाली टीम बोर्ड के साथ भुगतान विवाद के कारण भारत दौरा बीच में छोड़कर चली गई थी। ब्रावो ने वेस्टइंडीज के लिए 40 टेस्ट, 164 वनडे और 66 टी-20 खेले।

अफरीदी ने बनाया शून्य पर आउट होने का शतक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक अनोखा शतक लगाया है। यह शतक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में शून्य पर आउट होने का है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) टी-20 टूर्नामेंट में ढाका प्लाटूंस की ओर से राजशाही रॉयल्स के खिलाफ ढाका में गुरुवार को खेले गए मैच में शून्य पर आउट होते ही उन्होंने यह बदनाम सा रिकॉर्ड बना दिया।

अफरीदी भले ही वर्षों पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन विभिन्न देशों में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ढाका टीम की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे अफरीदी को रवि बोपारा ने पहली ही गेंद पर विकेटकीपर लिटन दास के हाथों कैच कराया। मैच में ढाका की टीम नौ विकेट पर सिर्फ 134 रन ही बना सकी। जवाब में रॉयल्स की टीम ने 10 गेंद शेष रहते एक विकेट खोकर लक्ष्य पा लिया। हजरतउल्लाह जाजई ने 47 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाए। लिटन दास ने 39 और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक ने 36 रनों का योगदान दिया।

अफरीदी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने के मामले में संयुक्त नौवें स्थान पर हैं। वह कुल 44 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इस मामले में वह जहीर खान और शेन वार्न की बराबरी पर हैं। इसके अलावा अफरीदी 56 बार लिस्ट-ए, प्रथमश्रेणी और टी-20 मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं। श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 59 बार शून्य पर आउट होकर इस मामले में शीर्ष पर हैं।

दिनभर में फेंकी जा सकीं सिर्फ 32 गेंद

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पाकिस्तान 10 साल में पहली बार टेस्ट की मेजबानी करने में तो सफल रहा, लेकिन खेल पर मौसम की मार जारी है, जिसकी वजह से खेल में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को सिर्फ 32 गेंद यानी 5.2 ओवर का ही खेल संभव हो सका। इस दौरान श्रीलंका ने बिना किसी नुकसान के 19 रन बनाए। खराब रोशनी के कारण खेल समाप्त किए जाने के समय श्रीलंका ने पहली पारी में 91.5 ओवर में छह विकेट पर 282 रन बना लिए थे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट

बल्लेबाज	मैच	शून्य
मुथैया मुरलीधरन	495	59
कोर्टनी वाल्श	337	54
सनथ जयसूर्या	586	53
ग्लेन मैक्ग्रा	376	49
महेला जयवर्धने	652	47
डेनियल विटोरी	442	46
स्टुअर्ट ब्रॉड	311	45
वसीम अकरम	460	45
जहीर खान	309	44
शेन वॉर्न	339	44
शाहिद अफरीदी	524	44

स्टार्क ने बनाया ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

डे-नाइट टेस्ट
- न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 109 गंवाए पांच विकेट
- स्टार्क ने झटके चार विकेट, ऑस्ट्रेलिया 307 रन आगे

पर्थ, रायटर: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजीक्रम को बिखेरते हुए मेजबान टीम का दबदबा बनाया। डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 416 रनों पर समाप्त हुई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 32 ओवर में 109 रनों पर पांच विकेट गंवा दिए। मेहमान टीम अभी भी पहली पारी में 307 रन पीछे है, जबकि उसके सिर्फ पांच विकेट शेष हैं। दिन का खेल खत्म होने के समय रॉस टेलर (नाबाद 66) के साथ बीजे वाटलिंग क्रीज पर मौजूद थे। वाटलिंग ने अभी खाता नहीं खोला था।

कीवी टीम की पहली पारी में स्टार्क ने चार विकेट झटके, जिसमें मेहमान कप्तान केन विलियमसन का अहम विकेट भी शामिल है, जो 34 रनों पर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड ने अपने दोनों ओपनर 10 गेंदों के भीतर गंवाए। विकेटों की पतझड़ की शुरुआत पांचवीं गेंद से हुई जब ओपनर टॉम लॉथम ने खाता खोले बिना स्टार्क को रिटर्न कैच थमाया। अगले ही ओवर में जोस हेजलवुड ने जीत रावल को बोल्ड कर दिया। हालांकि, अगले ही ओवर में हेजलवुड के बायें पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच में फिर मोड़ आया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के पास सीमित विकल्प होने से पार्ट टाइम गेंदबाज मैथ्यू वेड को गेंद थमाई, लेकिन उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। विलियम्सन और टेलर ने मौके का फायदा उठाते हुए 76 रनों की भागीदारी कर पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्मिथ ने दूसरी स्लिप में विलियमसन का डाइव लगाते हुए खूबसूरत कैच लपका। इस विकेट के बाद मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वापसी की।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी चार विकेट पर 248 रनों से आगे बढ़ाई। मार्नस लाबुशाने (143) और ट्रेविस हेड (56) के अलावा टिम पैन (39) ने भी उपयोगी योगदान दिया। कीवी तेज गेंदबाजों नील वैगनर और टिम साउथी ने चार-चार विकेट लिए। वैगनर की राउंड विकेट फेंकी 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद स्विंग होते हुए लाबुशाने के स्टंप बिखेर गई। इसके साथ ही वह लगातार तीन बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बनने से सात रन दूर रह गए। दिन में तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस रहा।

व्यवस्था सुधरे तो निकलेंगे ग्रैंडस्लैम स्तर के खिलाड़ी : साकेत

भारत में टेनिस का स्तर गिरता जा रहा है। खिलाड़ी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन नतीजे उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। डेविस कप में पाकिस्तान जैसी अदनी टीम के खिलाफ हम जीतकर इतरा सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे खेल का स्तर पिछड़ा हुआ है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी साकेत मायनेनी देश में इस खेल के पिछड़ेपन के लिए व्यवस्ता को जिम्मेदार मान रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके **साकेत मायनेनी** से **विकास पांडेय** ने भारत में टेनिस के हालात पर विस्तार से चर्चा की। पेश हैं प्रमुख अंश...

साक्षात्कार

- **आप पेशेवर सर्किट पर करीब आठ साल से खेल रहे हैं। अब तक का सफर आपके लिए कितना संतोषजनक रहा है?**

-2011 में जो सफर शुरू हुआ था आज वह बहुत आगे निकल आया है। देश के लिए खेलना मेरे लिए हमेशा से फक्र की बात रही है। जब मुझे पहली बार भारतीय टीम से खेलने का न्योता मिला था, उस समय मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझ रहा था। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि भारतीय टीम की जर्सी में मुझे राष्ट्रीय चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और दूसरे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खेलने का मौका मिला। इस दौरान मुझे अलग-अलग संस्कृतियों को जानने और लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।

- **पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप मुकाबले से पहले भारतीय टेनिस में कई तरह के विवादों ने सुर्खियां बटोरीं। क्या आपको लगता है कि ऐसे विवादों का खराब असर भारतीय टेनिस पर पड़ रहा है?**

-हमेशा से मेरा मानना रहा है कि कोर्ट से बाहर के विवादों से ज्यादा मैच के नतीजे मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे विवादों को कम करने की जरूरत है लेकिन फिर भी लोगों को टेनिस में खिलाड़ी कैसे नतीजे देते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में बहुत कुछ हासिल किया है।

- **आप सिंगल्स और डबल्स दोनों में खेलते हैं, लेकिन डबल्स में आप ज्यादा कामयाब रहे हैं। आपको सिंगल्स में खेलना ज्यादा पसंद है या डबल्स में?**

-मुझे हमेशा सिंगल्स में खेलना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं डबल्स में ज्यादा सफल रहा हूं। सिंगल्स में खेलने की बदौलत ही डबल्स में मेरी पहचान बनी है। आज डबल्स में मेरी जो भी कामयाबी है वह सिंगल्स की बदौलत ही हासिल हुई है। मुझे सिंगल्स और डबल्स दोनों में खेलना पसंद है।

- **सिंगल्स के मुकाबले डबल्स में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। आखिर भारत सिंगल्स में ग्रैंडस्लैम स्तर के खिलाड़ी क्यों नहीं तैयार कर पा रहा है?**

-मुझे लगता है कि इसके लिए हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। सिंगल्स में आपको ग्रैंडस्लैम चैंपियन के स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए सही व्यवस्था होनी जरूरी है। हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

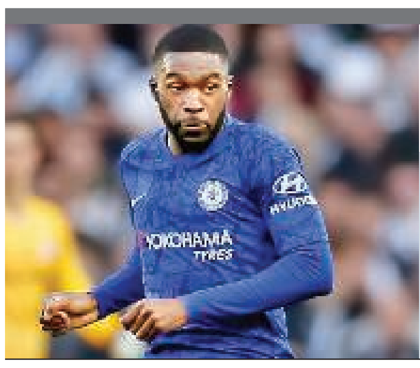

टोमोरी ने चेल्सी के साथ किया पांच साल का करार

लंदन, आइएएनएस : डिफेंडर फिकायो टोमोरी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी के साथ नया पांच साल का करार किया है। इस सत्र में टोमोरी 16 बार चेल्सी के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। वह चैंपियंस लीग में भी क्लब के लिए खेल चुके हैं। टोमोरी ने लोन पर डर्बी काउंटी क्लब के लिए खेलते हुए बीते सीजन में 55 मैच खेले थे। अंडर-8 एज ग्रुप में चेल्सी के साथ करार करने वाले टोमोरी टैमी अब्राहम के नाम से यूथ टीम के लिए 10 साल तक खेले और फिर सीनियर टीम का रुख किया।

> अजेटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोन मेसी खास हैं, जबकि माराडोना दूसरे ग्रह के हैं।
> – हेर्नान क्रेस्पो, पूर्व अर्जेंटीनी स्ट्राइकर

न्यूज गैलरी

एफआइएच की नई रैंकिंग प्रणाली का अनावरण

लुसाने : अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने शुक्रवार को 2020 के लिए नई विश्व रैंकिंग प्रणाली का अनावरण किया, जिसमें रैंकिंग का निर्धारण टूर्नामेंट के आधार पर नहीं, बल्कि मैच के आधार पर होगा। नई व्यवस्था अगले साल एक जनवरी से लागू होगी। एफआइएच ने कहा कि 12 महीने के गहन शोध, विश्लेषण और परीक्षण के बाद यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। वर्ष 2003 से जारी एफआइएच विश्व रैंकिंग प्रणाली मूल रूप से टूर्नामेंटों में टीमों को पूल में बांटने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत टीमों को साल में दो या तीन बार रैंकिंग अंक बनाने का मौका मिलता था। (प्रेट्र)

लोवर डिबांग वैली में जेके टायर ऑरेंज 4 गुणा 4 फ्यूरी शुरू

दांबुक (अरुणाचल प्रदेश) : देश की सबसे कठिन और सबसे रोमांचक ऑफ रोडिंग प्रतियोगिताओं में से एक जेके टायर ऑरेंज 4 गुणा 4 फ्यूरी का शुक्रवार को यहां लोवर डिबांग वैली से आगाज हुआ। इस चैंपियनशिप में देश भर की 21 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4 गुणा 4 फ्यूरी का आयोजन 'ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक' के साथ होता है। इस चैंपियनशिप में चालकों को लंबे और चुनौतीपूर्ण चरणों से गुजरना होता है। इस चैंपियनशिप में पहली बार इस तरह का प्रारूप आजमाया जा रहा है। मौजूदा चैंपियन मानाभूम ऑफरोडर्स क्लब ऑफ अरुणाचल देश के श्रेष्ठ ऑफ रोड चालकों की मौजूदगी के बावजूद इस साल अपने खिताब की रक्षा को आतुर है। (जेएनएन)

मैकगुर्क ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के कप्तान

मेलबर्न : विक्टोरिया के जैक फ्रेजर-मैकगुर्क को 17 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान बनाया गया है। क्रिस रोजर्स इस टीम के कोच हैं जबकि रियान हैरिस उनके सहायक हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की यूथ चयन समिति ने अंडर-19 पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद इस टीम का चयन किया। पैट्रिक रोव को टीम का विकेटकीपर चुना गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है। यह टीम 18 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। टीम : कूपर कोनोली, ओलीवर डेविस, सैम फेनिंग, जैक फ्रेजर मैकगर्क, मैकेंजी हार्वे, लाचलान हीयर्न, कोरी केली, लियाम मार्शल, टॉड मर्फी, पैट्रिक रोव, तनवीर सांघा, लियाम स्काट, ब्रैडली सिंपसन, सुली, विलियन। (आइएएनएस)

फुटबॉल डायरी ▸ यूरोपा लीग में ग्रीनवुड के दो गोल की मदद से जीता युनाइटेड

युनाइटेड–आर्सेनल के सितारों ने बिखेरी चमक

18 वर्षीय साका ने आर्सेनल को हार से बचाया

पेरिस, एएफपी : यूएफा यूरोपा लीग में गुरुवार को मैनचेस्टर युनाइटेड और आर्सेनल के युवा सितारों ने चमक बिखेरी। 18 वर्षीय युवा मैसन ग्रीनवुड ने मिले मौकों को भुनाते हुए दो गोल दागे, जिसकी बदौलत ग्रुप-एल के मुकाबले में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड ने डच क्लब एजेड अल्कमार को 4-0 से हरा दिया।

ओल्ड ट्रैफर्ड में अल्कमार के खिलाफ मुकाबले में एश्ले यंग ने खेल के 53वें मिनट में गोल करके युनाइटेड को बढ़त दिलाई। इसके बाद ग्रीनवुड (58वें व 64वें मिनट) ने छह मिनट के अंदर दो गोल करके युनाइटेड को जीत की ओर अग्रसर किया। इसके अलावा जुआन माटा (62वें मिनट) ने भी पेनाल्टी किक के जरिये एक गोल दागा। मुकाबले के बाद युनाइटेड के मैनेजर ओले गनर सोल्सकजेर ने कहा कि मैसन (ग्रीनवुड) एक खास तरह के फिनिशर हैं। वह जगह बनाने और दायें पैर से मौके तैयार करने में माहिर हैं। युनाइटेड अपने ग्रुप में 13 अंक लेकर शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा।

इससे पहले ग्रुप-एफ में आर्सेनल ने दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्टैंडर्ड लीग को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। इस ड्रॉ मुकाबले की बदौलत उसने ग्रुप विजेता के तौर पर अंतिम-32 में प्रवेश किया। आर्सेनल की ओर से एलेक्जेंडर लोकाज्ते और 18 वर्षीय बुकायो साका ने दूसरे हाफ में गोल करके 0-2 से पिछड़ रही अपनी टीम को बराबरी दिलाई। ग्रुप-एफ में इट्रिच्ट फ्रैंकफर्ट को ग्यूमेरेस के खिलाफ 2-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। पुर्तगाली क्लब ग्यूमेरेस ने आखिरी पांच मिनटों में दो गोल करके जीत दर्ज की। उधर, ग्रुप-आइ में वोल्व्स ने सेंट एस्टिन को 1-0 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बनाई। साथ ही ग्रुप-जी में पोर्तो ने फेयेनोर्ड को 3-2 से हरा दिया, जहां मुकाबले के पांचों गोल शुरुआती 33 मिनट के अंदर किए गए।

गोल करने के बाद जश्न मनाते मैनचेस्टर युनाइटेड के 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी मैसन ग्रीनवुड। एएफपी

क्रिस्मस की छुट्टियों को यादगार बनाने उतरेंगे लिवरपूल और लीसेस्टर

लंदन, एएफपी : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में शनिवार को लिवरपूल की टीम वाटफोर्ड से भिड़ेगी, जहां उसकी कोशिश जीत के साथ क्रिस्मस की छुट्टियों पर जाने की होगी। वहीं, शनिवार को ही लीसेस्टर सिटी की भिड़ंत नॉर्विक सिटी से होगी। इस मुकाबले में लीसेस्टर जीत के साथ खिताबी दौड़ में बने रहने की कोशिश करेगा। लीसेस्टर की टीम ने इस सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें जैमी वार्डी की अहम भूमिका रही है। वह 16 मुकाबलों में 16 गोल के साथ सत्र के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। मैनेजर जुर्जेनल क्लोप की लिवरपूल टीम अंक तालिका में फिलहाल दूसरे स्थान पर काबिज लीसेस्टर से आठ अंक आगे है। उधर, शनिवार को ही फ्रैंक लैंपार्ड की चेल्सी बॉर्नेमाउथ का सामना करने उतरेगी। देखना होगा कि इन मुकाबलों में कौन जीत दर्ज करता है।

ऑस्ट्रेलिया–न्यूजीलैंड पेश करेंगे महिला विश्व कप की मेजबानी का दावा

मेलबर्न, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी का संयुक्त दावा पेश करने का फैसला किया है। दोनों फुटबॉल संघों ने अपने-अपने क्षेत्र में महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के खेल मंत्री रिचर्ड कोलबेक ने कहा कि हमारा खेलों की एकल या संयुक्त मेजबानी का सफल इतिहास रहा है। हमारे पास फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने के लिए आधारभूत संरचनाएं, महारत और जोश है। अब तक आठ देशों ने 2023 विश्व कप की मेजबानी के लिए अपनी इच्छाएं जाहिर की है। इनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। फ्रांस में हुए पिछले विश्व कप में 24 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन फुटबॉल की विश्व संस्था फीफा अगले आयोजन से टीमों की संख्या 32 करने की योजना बना रहा है।

अय्यर को वनडे में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए : कुंबले

अनिल कुंबले। फाइल फोटो, प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले का मानना है कि श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। उनका मानना है कि भारतीय गेंदबाजों के लिए यह सीरीज चुनौतीपूर्ण होगी।

कुंबले ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों को वेस्टइंडीज के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शिखर के नहीं होने से केएल राहुल को पारी के आगाज का मौका मिला है। अय्यर काफी परिपक्व बल्लेबाज हैं। मैं चाहूंगा कि वह चौथे नंबर पर उतरें। वेस्टइंडीज के सामने गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण होगी। उनके पास दमदार हिटर हैं। विकेट भी बल्लेबाजी के अनुकूल है तो गेंदबाजों को उम्दा प्रदर्शन करना होगा।

फिर याद आए पुराने दिन...

बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली शुक्रवार को सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण ठाकुर के साथ इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर पहुंचे। गांगुली ने यह तस्वीर ट्विटर पर साझा की। ट्विटर

इंग्लैंड की टी–20 टीम से बाहर किए गए रूट

क्रिकेट डायरी

लंदन, एएफपी : इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को टी-20 से बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए जिस टी-20 टीम का एलान किया, उसमें रूट का नाम नहीं है। चयनकर्ता अगले साल ऑस्ट्रेलिया में टी-20 विश्व कप की तैयारी के लिए अन्य खिलाड़ियों को भी परखना चाहते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि रूट टी-20 विश्व कप के लिए रणनीति का हिस्सा हैं। तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है, जबकि टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने वाले हरफनमौला खिलाड़ी मोइन अली को दोनों टीमों में जगह मिली है। इंग्लैंड ने पैट ब्राउन, मैथ्यू पर्किंसन, साकिब महमूद और टॉम बेनटन को पहली बार टीम में मौका दिया है। वनडे टीम से जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, मार्क वुड को आराम दिया गया है, लेकिन टी-20 टीम में इन तीनों को रखा गया है।

वनडे टीम : इयोन मोर्गन (कप्तान), मोइन अली, जॉनी बेयरस्टो, टॉम बेनटन, पैट ब्राउन, सैम कुर्रन, टॉम कुर्रन, जो डेनले, क्रिस जोर्डन, साकिब महमूद, डेविड मलान, मैथ्यू पार्किंसन, आदिल राशिद, जो रूट, जेसन रॉय, क्रिस वोक्स।

टी-20 टीम : इयोन मोर्गन (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर, पैट ब्राउन, सैम कुर्रन, टॉम कुर्रन, जो डेनली, क्रिस जोर्डन, डेविड मलान, मैथ्यू पार्किंसन, आदिल राशिद, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, मार्क वुड।

मानसिक थकान को खत्म कर वापसी को तैयार ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल

मेलबर्न, एएफपी : मानसिक थकान को मिटाने के लिए ब्रेक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल बिग बैश लीग से क्रिकेट में वापसी करने को तैयार हैं। इसी साल अक्टूबर में श्रीलंका के साथ खेली गई टी-20 सीरीज में से मानसिक थकान के कारण नाम वापस लेने वाले मैक्सवेल ने गुरुवार को मेलबर्न स्टार्स के सत्र से पहले लगाए जा रहे शिविर में हिस्सा लिया।

मैक्सवेल ने कहा कि जब मैंने फैसला किया कि मैं छुट्टी लूंगा तब मैं काफी थक चुका था। सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी थक चुका था। मैं आठ महीने से लगातार खेल रहा था। इन सभी ने मुझे परेशान कर दिया था। ब्रेक के शुरुआती सप्ताह में आप भावनाओं की कई बयारों में बहते हो, वो पहला सप्ताह बेहद मुश्किल होता है। इससे पहले भी मैक्सवेल ने शेफील्ड शील्ड में विक्टोरिया के साथ अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था।

पीसीबी का अशरफ, शिनवारी को एनओसी देने से इन्कार

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हरफनमौला फहीम अशरफ और तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी को ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) देने से इन्कार कर दिया। अशरफ और शिनवारी ने हाल ही में बीबीएल के साथ करार किया था। अशरफ ने मई के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। उनके साथ मेलबर्न रेनेगेडेस ने करार किया था जबकि शिनवारी को इसी टीम ने पहले पांच मैचों के लिए अनुबंधित किया है।

विविध

काले हिरन और सारस को किया जाएगा संरक्षित

जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के दस किलोमीटर के दायरे में वन्य जीवों की मौजूदगी का हुआ अध्ययन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए काले हिरन व सारस को संरक्षित किया जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान इनके संरक्षण की योजना तैयार कर रहा है। अगले सप्ताह में भारतीय वन्य जीव संस्थान अपनी रिपोर्ट यमुना प्राधिकरण को सौंप देगा। एयरपोर्ट के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया, उस पर मौजूद तालाबों को दूसरी जगह बनाया जाएगा। इसकी योजना तैयार की जा रही है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के असर से पर्यावरण को होने वाली क्षति की भरपाई के लिए योजना तैयार हो रही है। एयरपोर्ट के लिए छह गांव दयानतपुर, किशोरपुर, रोही, पारोही, बनबारीवास, रन्हेरा की 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एयरपोर्ट के प्रस्तावित क्षेत्र के दस किमी के दायरे में संरक्षित श्रेणी में आने वाले काले हिरन व सारस की मौजूदगी है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम ने पिछले करीब डेढ़ से दो माह तक यहां रहकर जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में वन्य जीवों की मौजूदगी का अध्ययन किया। संस्थान इनके संरक्षण की योजना तैयार कर रहा है। अगले सप्ताह यह योजना प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संस्थान को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वन्य जीवों के संरक्षण प्लान के आधार पर ही जेवर एयरपोर्ट को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति मिलेगी।

> एयरपोर्ट क्षेत्र में काले हिरन व सारस की मौजूदगी पाई गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान इनके संरक्षण की योजना तैयार कर रहा है। क्षेत्र में मौजूद नहरें व तालाबों को दूसरी जगह शिफ्ट कर संरक्षित किया जाएगा।
> –डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण एवं नियाल

जेवर एयरपोर्ट से वह तालाब नजर आएंगे, जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। सरकारी दस्तावेज में इस क्षेत्र में 14 तालाब दर्ज हैं, जबकि मौजूदगी केवल आठ की ही है। शेष तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं या तो लोगों ने उन पर अवैध कब्जा कर लिया है या फिर तालाबों को समतल कर खेती की जा रही है। यमुना प्राधिकरण ने दस्तावेजों में दर्ज सभी तालाबों को एयरपोर्ट क्षेत्र के बाहर आस-पास के गांवों में बनाने का फैसला किया है। ये तालाब मौजूदा क्षेत्रफल से दोगुना बड़े होंगे। इस पर आने वाला खर्च यमुना प्राधिकरण वहन करेगा। हालांकि बाद में यह धनराशि नियाल के वसूल की जाएगी।

एयरपोर्ट के लिए बदलेगा तीन नहरों का रास्ता : एयरपोर्ट क्षेत्र से होकर तीन नहरें बह रही हैं। इनका उपयोग इलाके में खेतों की सिंचाई के लिए होता है। एयरपोर्ट क्षेत्र से इन नहरों को बाहर करने के लिए इनका रास्ता बदलता जाएगा। इसकी योजना सिंचाई विभाग तैयार कर शासन को सौंप चुका है। यह कार्य सिंचाई विभाग अपने व्यय पर करेगा। जिन नहरों का रास्ता बदला जाएगा, उसमें किशोरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, करौली व बझौता माइनर शामिल हैं।

तीस हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा वन क्षेत्र : जेवर एयरपोर्ट के कारण हजारों पेड़ काटे जाएंगे। इनकी जगह पर तीस हेक्टेयर क्षेत्र में दस गुना अधिक पौधे रोपे जाएंगे। ये पौधे फलदार होंगे जो मनुष्य व जीव जंतुओं के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण ने गठित की समिति : जेवर एयरपोर्ट के लिए वन विभाग ने करीब छह हजार पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। लेकिन अलग-अलग स्तर से तैयार की गई रिपोर्ट में पेड़ों की संख्या में अंतर है। वन विभाग को छह हजार पेड़ों की जानकारी भेजी गई है, जबकि करीब 6800 पेड़ काटने के लिए बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 20038 पेड़ों की सूची भी वन विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। पेड़ों की अलग-अलग संख्या को देखते हुए सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने एक समिति गठित की है। इसमें वन विभाग व प्राधिकरण के अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो एयरपोर्ट क्षेत्र की जमीन पर लगे पेड़ों की वास्तविक गणना कर अपनी रिपोर्ट देंगे।

पिता ने तीन बच्चों को नहर में फेंका, मौत

जागरण संवाददाता, सोनीपत : आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह से जूझ रहे एक व्यक्ति ने अपने तीन बच्चों को नहर में फेंक कर मार दिया। परिजन बच्चों को लापता मानकर उनकी तलाश करते रहे, जबकि आरोपित छिपता रहा। बाद में नौ दिसंबर को आरोपित अपनी ससुराल पहुंचा और जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जहर खाने के बाद उसने बच्चों को नहर में फेंकने की जानकारी दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। नहर में फेंके गए तीन बच्चों में से दो के शव बरामद हो चुके हैं, तीसरे की तलाश जारी है।

मूलरूप से गांव थरिया व हाल में दिल्ली के नांगल ठाकरान निवासी मुश्ताक अली 23 नवंबर को सलीमसर माजरा में साले की शादी में आया था। वह पत्नी समीना से शादी समारोह के बाद गांव थरिया जाने की बात कहकर बेटे सोहिल (13), बेटी शाइना (11) और सुहानी (3) को लेकर निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। पत्नी ने मुश्ताक व अपने तीन बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत सदर थाना पुलिस को दी। इसी बीच मुश्ताक 9 दिसंबर को अपनी ससुराल पहुंचा और बताया कि उसने जहर खा लिया है। इस पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली के चिड़ियाघर में महंगा हो जाएगा वन्यजीवों का दीदार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी के चर्चित पर्यटन स्थलों में शुमार राष्ट्रीय चिड़ियाघर में नए साल में वन्यजीवों का दीदार महंगा हो जाएगा। वर्तमान में यहां पर 40 रुपये की टिकट है। इसमें दोगुनी वृद्धि करते हुए अब टिकट का दाम 80 रुपये किया जा रहा है। वहीं, पर्यटक अब चिड़ियाघर के भीतर चार घंटे तक ही रह सकते हैं। इससे ज्यादा रुकने पर पर्यटकों को हर्जाना भरना पड़ेगा, जिसकी रकम 80 रुपये तय की गई है। पिछले पांच सालों के बाद चिड़ियाघर में टिकट का दाम बढ़ाया जा रहा है। टिकट की नई दरें जनवरी में कभी भी लागू की जा सकती हैं।

चिड़ियाघर के एक अधिकारी के अनुसार, इसे लेकर प्रशासन की ओर से एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सेंट्रल जू ऑथिरिटी) के पास भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलते ही इस प्रणाली को 2020 में लागू कर दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि यह देखने में आता है कि सप्ताहांत पर चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसे में पर्यटक सारा दिन यहीं जमे रहते हैं। इसे देखते हुए चिड़ियाघर में चार घंटे रहने की समय सीमा तय की गई है।

अधिकारी ने बताया कि नए साल में बैट्री कार की सुविधा भी मंहगी होने जा रही है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति इसका किराया 70 रुपये है, जो चिड़ियाघर में प्रमुख वन्यजीवों का दीदार कराती है। किराया वृद्धि के बाद इसका किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाएगा। बता दें कि वर्तमान में चिड़ियाघर में 10 से भी अधिक बैट्री कार संचालित होती हैं।

चिड़ियाघर में भ्रमण करते हिरण। फाइल

नए साल में चिड़ियाघर में हो रहे बदलावों में यह भी खास है कि प्रशासन टिकट प्रणाली को कागजरहित करने जा रहा है। इसमें नए साल में चिड़ियाघर में टिकट के लिए वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। पर्यटक वेंडिंग मशीन में रुपये डालकर टिकट ले सकेंगे। इसमें प्रवेश का समय भी अंकित होगा। चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर ऑटोमेटिक गेट लगेंगे। यहां पर टिकट (टोकन) लगाते ही द्वार अपने आप खुल जाएंगे। निकासी के समय टोकन जमा कराना होगा।

बच्चों व बुजुर्गों को टिकट में मिलेगी रियायत : टिकट पर बच्चों व बुजुर्गों को छूट भी देने के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि, यह छूट कितनी रहेगी, इस बारे में बाद में ही स्पष्ट हो सकेगा। अधिकारी ने कहा कि चिड़ियाघर में शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी स्कूली बच्चे पहुंचते हैं, जिनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है।

ओरा बुल्डवेल बिल्डर को वापस देना होगा खरीदारों का पैसा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

> खरीदार बोले, दो साल बाद भी परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने की नहीं उम्मीद

उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में शुक्रवार को विभिन्न बिल्डरों के मामलों में सुनवाई हुई। तीनों पीठों में पुराने वाद के साथ नए शिकायती पत्रों को सुना गया। पीठ एक में 46, पीठ दो में 47 व न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में 13 प्रकरणों पर सुनवाई हुई।

पीठ दो में ओरा बुल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, देविका गोल्ड, अर्थ गिरीसिया, इंडस वेली, केडीपी इंफ्रास्ट्रेक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्री कुंज बिहारी समेत विभिन्न बिल्डरों से जुड़े मामले सुने गए। वहीं, ओरा बुल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के सबसे ज्यादा 18 प्रकरण सामने आए। जिनमें से आठ प्रकरणों में यूपी रेरा सदस्य बलविंदर कुमार ने रिफंड का आदेश जारी किया है। पीठ के सम्मुख सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित परियोजना में वर्ष 2013-14 में फ्लैट बुक किए थे। बिल्डर ने 2018 तक परियोजना को पूरा कर फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया था। परियोजना से जुड़े शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि आने वाले दो सालों में भी परियोजना का काम पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आरोप है कि बिल्डर को कई बार निर्माण कार्य शुरू करने की अपील की जा चुकी है। लेकिन अब बिल्डर खरीदारों द्वारा की गई कॉल व ईमेल से भी बचते नजर आ रहे है। परियोजना के निर्माण कार्य में पांच महीने से अधिक की देरी हुई है। सुनवाई के दौरान खरीदारों ने ब्याज समेत पैसा वापस दिलाने की मांग पीठ सदस्य बलविंदर कुमार से सुनवाई के दौरान की।

यमुना एक्सप्रेस–वे पर फास्टैग लागू होने में लग सकता है एक माह

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर पंद्रह दिसंबर से फास्टैग व्यवस्था लागू होने पर संशय है। एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग के लिए जरूरी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो सकी हैं। प्रबंधन ने दावा किया है कि करीब एक माह में एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग की सुविधा लागू हो जाएगी।

यमुना प्राधिकरण एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग सुविधा लागू करने के लिए पहले ही जेपी इंफ्राटेक को निर्देश दे चुका है। शुरुआत में एक्सप्रेस-वे के दोनों मार्ग पर एक-एक लेन फास्टैग के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। देशभर में पंद्रह दिसंबर से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग की सुविधा लागू हो जाएगी। लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हो सका है। एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग सुविधा लागू करने के लिए संचालक कंपनी संबंधित कंपनियों के साथ वार्ता कर रही है।

सहारनपुर में किशोरी ने छेड़छाड़ से आहत होकर दी जान

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

दो दिन पूर्व किशोरी ने छेड़छाड़ से आहत होकर जान दे दी थी। मकान मालिक पर छेड़छाड़ करने का आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के गांव की 16 वर्षीय किशोरी ने बुधवार को घर में जान दे दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पीड़िता के कमरे से सुसाइड नोट मिला।

इंस्पेक्टर सदर बाजार पंकज कुमार पंत ने बताया कि सुसाइड नोट में पीड़िता ने मकान मालिक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह इसी से आहत होकर जान दे रही है। पीड़िता के परिवार द्वारा मुकदमा दर्ज कराने से इन्कार करने पर दारोगा मनोज कुमार की ओर से आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो व जान देने के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या में सात माह में दोषी करार

जागरण संवाददाता, रामपुर : गंभीर अपराधों की सुनवाई को बनी विशेष अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए सात माह में मुकदमे का निस्तारण कर दिया। अब 18 दिसंबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। मामला उप्र के रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। यहां छह साल की बच्ची 7 मई 2019 को घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी। डेढ़ माह बाद उसका शव कालोनी के पीछे एक अर्द्धनिर्मित मकान में मिला था। मुहल्ले का ही एक युवक बच्ची को बहाने से वहां ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पहचान के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।

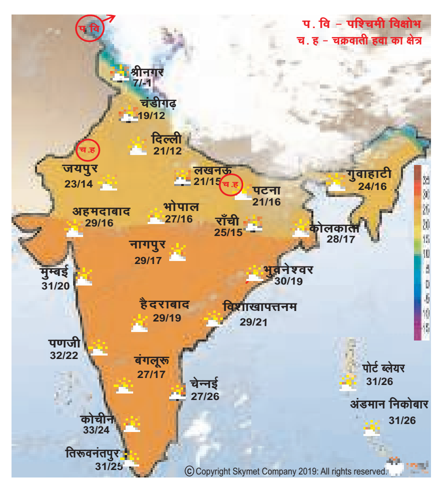

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की तीव्रता में कमी आएगी लेकिन बर्फबारी जारी रहेगी। जम्मू पंजाब, उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर दिन सर्द बना रहने की संभावना है। सुबह कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा संभव है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर काफी खराब रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमानः

शहर		शहर	
मुम्बई	31/19/आंबा	अहमदाबाद	26/12/आंबा
कोलकाता	28/18/सा	बड़ौदा	28/14/सा
चेन्नई	30/22/व	नागपुर	28/16/आंबा
हैदराबाद	28/19/सा	इन्दौर	24/09/आंबा
बंगलूरू	27/16/सा	राँची	23/14/सा
त्रिवेन्द्रम	31/25/सा	पटना	25/12/व
गुवाहाटी	24/16/आंबा	जमशेदपुर	25/17/आंबा
गंगटोक	04/-9/आंबा	पुणे	30/17/आंबा

धरती के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचा इंसान

1911 में आज ही नॉर्वे के खोजी यात्री रोआल्ड आमुन्सन अपने दल के साथ धरती के दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। यही नहीं, 1926 में उत्तरी ध्रुव पर भी पहुंचने वाले वह पहले व्यक्ति थे। उन्होंने ही उत्तर-पश्चिम मार्ग की पहली यात्रा की।

उड़ने की कोशिश ने किया हवाई जहाज का आविष्कार

1903 में आज ही अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में राइट बंधुओं ने राइट फ्लायर नाम के हवाई जहाज से पहली बार उड़ान भरने की कोशिश की थी। ऑरविल और विल्बर राइट को हवाई जहाज का अविष्कारक माना जाता है। 17 दिसंबर 1903 को दोनों ने सबसे पहली सफल हवाई उड़ान भरी थी।

हिंदी सिनेमा के शोमैन थे राज कपूर

हिंदी सिनेमा को अलग पहचान देने वाले अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर का जन्म 1924 में आज ही पेशावर (अब पाकिस्तान) में हुआ था। 1935 में मात्र 10 साल की उम्र में फिल्म इंकलाब से अभिनय की शुरुआत की। मेरा नाम जोकर, संगम, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में रहीं। बॉबी, राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन भी किया। वर्ष 1971 में पद्मभूषण और 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2 जून 1988 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

इधर-उधर की

ब्रिटेन की महारानी को चाहिए सोशल मीडिया मैनेजर

लंदन, एजेंसी : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत है। नौकरी के लिए रॉयल फैमिली की ओर से जॉब लिस्टिंग वेबसाइट पर विज्ञापन दिया गया है। जॉब लिस्टिंग वेबसाइट के मुताबिक, 'डिजिटल कम्युनिकेशंस ऑफिसर' को महारानी के लिए काम करना होगा। उन्हें महारानी की मौजूदगी को सार्वजनिक और वैश्विक मंच पर बनाए रखने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफिसर की सैलरी 30 हजार पाउंड (करीब 26 लाख 58 हजार रु.) सालाना होगी। उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक हफ्ते में 37.5 घंटे काम करना होगा। साल में 33 दिन की छुट्टी और दिन में मुफ्त खाना मिलेगा। यह नौकरी बकिंघम पैलेस के लिए होगी।

तेजी से पिघल रही है ग्रीनलैंड की बर्फ

चिंताजनक ▶ इस सदी के अंत तक खतरे में पड़ सकता है चार करोड़ लोगों का भविष्य

यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के शोधकर्ताओं ने 11 उपग्रहों की मदद से किया अध्ययन

लंदन, प्रेट्र : पिछली सदी के आखिरी दशक के मुकाबले वर्तमान में ग्रीनलैंड सात गुना तेजी से पिघल रहा है। ध्रुवीय द्वीपों (आइलैंड) पर जलवायु परिवर्तन के खतरों का आकलन करने वाले एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से इस सदी के अंत तक तटीय क्षेत्रों के डूबने से लगभग चार करोड़ लोग प्रभावित होंगे।

यह अध्ययन ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के शोधकर्ताओं ने 50 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर किया है। इस अध्ययन के लिए शोधार्थियों ने वर्ष 1992 से 2018 के बीच ग्रीनलैंड में बर्फ की चादरों पर आए बदलावों का आकलन किया। इसके लिए 26 अलग-अलग सर्वेक्षणों का सहारा लिया गया। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 11 अलग-अलग सेटेलाइटों के डाटा का भी उपयोग किया,

जलवायु परिवर्तन के कारण सात गुना तेजी से पिघल रहा है ग्रीनलैंड। प्रतीकात्मक

जिसमें बर्फ की चादरों की बदलती मात्रा, प्रवाह और गुरुत्वाकर्षण की माप शामिल थी। नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 1992 से अब तक ग्रीनलैंड से 3.8 ट्रिलियन टन बर्फ गायब हो चुकी है, जो वैश्विक रूप से समुद्र का स्तर 10.6 मिलीमीटर बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'पिछली सदी के अंतिम दशक में बर्फ पिघलने की दर प्रतिवर्ष 33 बिलियन टन रही है, जो पिछले दशक में बढ़कर 254 बिलियन टन हो गई। इसका अर्थ है पिछले तीन दशकों में लगभग सात गुना वृद्धि हुई है।

पुराने अनुमानों को बताया धता : अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 2013 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) ने वैश्विक रूप से 2100 तक समुद्र का स्तर 60 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान लगाया था, जिससे 36 करोड़ लोगों को सालाना तटीय बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं का कहना है समुद्र का स्तर पुराने अनुमानों का धता बताते हुए और तेजी से बढ़ सकता है। जलवायु के परिदृश्यों पर नजर रखने वाले आइपीसीसी का भी अनुमान है कि समुद्र का स्तर पूर्वानुमान से 7 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ सकता है।

10 करोड़ लोग होंगे प्रभावित : लीड्स यूनिवर्सिटी के सह-लेखक एंड्रयू शेफर्ड ने कहा, 'वैश्विक रूप से समुद्र के स्तर में एक सेंटीमीटर वृद्धि का मतलब है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे।' उन्होंने कहा कि मौजूदा रुझान बताते हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से सदी के अंत तक हर साल 10 करोड़ लोगों को बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ेगा।

उठाने होंगे प्रभावी कदम : शोधकर्ताओं ने कहा, 'यदि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाते तो हो सकता है यह स्थिति और भी विनाशकारी हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि मिलजुल कर अपने भविष्य और भावी पीढ़ियों के लिए अच्छी और स्वस्थ पृथ्वी छोड़कर जाएं।

शोध अनुसंधान

ज्यादा मीठा खाना बन सकता है डिप्रेशन का कारण

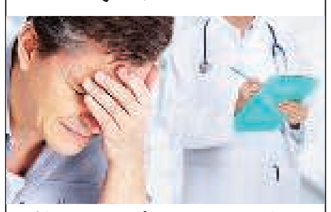

मीठे खाद्य पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करने वाले लोग सचेत हो जाएं। एक नए अध्ययन में आगाह किया गया है कि ज्यादा मात्रा में मीठा खाना डिप्रेशन (अवसाद) का कारण बन सकता है। छुट्टियों के दौरान इस तरह का खानपान आम बात है। अमेरिका की कंसास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, सर्दी के मौसम में धूप में कम रहने और नींद की गड़बड़ी के साथ मीठे खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन हितकर नहीं है। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इससे बचाव के लिए अनाज और हरी सब्जियों के साथ ही ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर आहार के सेवन की सलाह दी है। इस तरह का खानपान मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। प्रमुख शोधकर्ता और कंसास के एसोसिएट प्रोफेसर स्टीफन इलार्डी ने कहा, 'सर्दी में धूप में कम रहने से सर्केडियन रिदम और नींद बिगड़ सकती है। यह स्थिति डिप्रेशन का कारण बन सकती है।' -प्रेट्र

लार से हो सकेगी मुंह और गले के कैंसर की जांच

वैज्ञानिकों ने पाया है कि लार की जांच से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस-16 की पहचान हो सकती है। इस वायरस का संबंध ओरोफारिंगल कैंसर (ओपीसी) से होता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसकी मदद से प्रारंभिक अवस्था में ही मुंह और गले के कैंसर की पहचान हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह नई जांच ओपीसी की पहचान के लिए कुछ रोगियों पर आजमाई गई। इसमें करीब 80 फीसद ओपीसी रोगियों की पुष्टि हुई। इस जांच से डॉक्टर यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि किस रोगी में रेडियेशन थेरेपी की सही प्रतिक्रिया मिल सकती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता टोनी जून हुआंग ने कहा, 'यह जांच बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में बेहतर पहचान के लिए विकसित की गई है।' -आइएएनएस

इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप की गुफा में मिली दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी

जकार्ता, एएफपी : इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप की एक गुफा में 44 हजार साल पुरानी चित्रकारी मिली है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह विश्व की सबसे प्राचीन चित्रकारी है। नेचर पत्रिका में छपे एक शोध कार्य में इसका पूरा विवरण दिया गया है।

13 फीट चौड़ी इस चित्रकारी में गहरे लाल रंग में बने आदिमानवों के हाथ में भाला और रस्सी लेकर जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कलाकृति का पता दो साल पहले चला था। इसके बाद शोधकर्ताओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल कर इसके समय काल का पता लगाया गया। शोध में पता चला कि यह चित्रकारी 44 हजार साल पहले की गई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह न सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी है, बल्कि संदेश के लिए मानवों द्वारा अपनाए जाने वाली तकनीक का सबसे पुराना नमूना भी है। इससे पहले इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप की एक गुफा के भीतर 40 हजार साल पुरानी चित्रकारी का पता चला था। इससे पहले यूरोप के कई गुफाओं में 14 हजार से लेकर 21 हजार साल पहले की कलाकृतियों की खोज हुई थी और उन्हें अब तक दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी का दर्जा हासिल था, लेकिन हालिया खोज में दोगुना से भी ज्यादा पुरानी चित्रकारी का पता लगाया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'ये चित्रकारी हमारी जानकारी में सबसे पुराना रिकॉर्ड है, यानी ये दुनिया का सबसे प्राचीन कलाकृति है।'

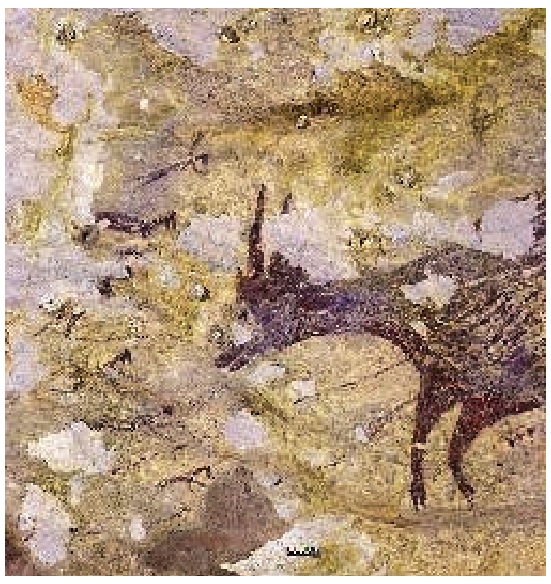

इंडोनेशिया की गुफाओं में मिली चित्रकारी 44 हजार साल पुरानी है। रायटर

मारियाना ट्रेंच में मिला प्लास्टिक का कचरा

टोक्यो, आइएएनएस : इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का असर समुद्र में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से रहा है। इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान जलीय जीव-जंतुओं को होता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की सबसे गहरी समुद्री गर्त मानी जाने वाली मारियाना ट्रेंच में भारी मात्रा में प्लास्टिक, जूते-चप्पल और बैग बरामद किए हैं। मारियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर है। मनुष्यों के लिए यह दुर्गम स्थानों में से एक है। इसमें कई स्थान ऐसे हैं कि जहां आसानी से नहीं घुसा जा सकता है।

जापान एजेंसी फॉर मरीन-अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बीते तीन दशकों में मारियाना ट्रेंच में मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न कचरे की पहचान की है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मारियान ट्रेंच के एक गहरे हिस्से 'चेलेंजर डीप' में प्लास्टिक की थैलियों के अवशेष मिले हैं और 10 हजार मीटर से ज्यादा गहरे हिस्सों में चप्पल, जूते, कार के पहिये भी खोजे हैं।

जापान का सक्रिय ज्वालामुखी

जापान के कुमामोटो प्रांत में एसो शहर के पास एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत से उठते धुएं और आग की लपटों ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी किसी भी समय भयानक रूप लेते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है। यह पर्वत क्यूशू द्वीप के दक्षिण-पश्चिमी में स्थित है। बता दें कि बीते दिनों न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड पर स्थित ज्वालामुखी के सक्रिय होने से आठ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। एएफपी

जर्मनी में धमाके से एक की मौत, 25 घायल

जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक में शुक्रवार सुबह हुए तेज धमाके में एक की मौत हो गई और 25 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना के पीछे गैस सिलेंडर के फटने की आशंका जताई है। विस्फोट इतना तेज था कि अपार्टमेंट के छोटे-छोटे टुकड़े 200 फीट दूर तक गिरे, जिससे वहां गुजर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। (एपी)

फिल्म रिव्यू

संकुचित मानसिकता पर प्रहार

★★★

मर्दानी 2

मुख्य कलाकार : रानी मुखर्जी, विशाल जेठवा

लेखक और निर्देशक : गोपी पुथरन

अवधि : 1 घंटा 45 मिनट

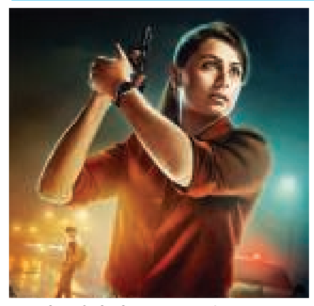

वर्ष 2014 में रिलीज प्रदीप सरकार निर्देशित 'मर्दानी' की कहानी गोपी पुथरन ने लिखी थी। पांच साल बाद आई उसकी सीक्वल 'मर्दानी 2' का लेखन, स्क्रीनप्ले, डायलॉग और निर्देशन गोपी पुथरन ने ही किया है। हिंदी सिनेमा में पहली बार नायिका प्रधान फिल्म की सीरीज बन रही है। 'मर्दानी' के केंद्र में बाल तस्करी का मुद्दा था। 'मर्दानी 2' के केंद्र में बलात्कार, कुंठित सोच, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह, असमानता जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है।

फिल्म में दिलेर एसपी शिवानी शिवाजी राव (रानी मुखर्जी) की नियुक्ति कोटा में होती है। मेरठ से आया सिरफिरा व मनोरोगी सनी (विशाल जेठवा) उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, जिन्हें वह 'नकचढ़ी लौंडिया' कहता है। ये वे लड़कियां हैं, जो नखरे दिखाने वाली और तेजतर्रार मिजाज की होती हैं। वह दशहरे के दिन मेले से एक लड़की को धोखे से अगवा कर उसके साथ बर्बरतापूर्वक दुष्कर्म करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर देता है। शिवानी उसे कॉलर से घसीटकर अदालत में लाने का एलान करती है। यह बात कातिल को नागवार गुजरती है। उसकी सोच है कि औरत को हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह शिवानी को चुनौती देता है।

बलात्कार के इर्दगिर्द कई फिल्में बनी हैं, जो अपराधी की मानसिकता और अपराध के कारणों में नहीं जातीं। लेकिन 'मर्दानी 2' ने आपराधिक मानसिकता की वजहों में भी जाने का प्रयास किया है। यह फिल्म महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव, असमानता, उनके प्रति रुढ़िवादी सोच और पितृसत्तात्मक समाज पर भी प्रहार करती है। 'ऐसी छोरियों... मॉडर्न लड़कियों का एक ब्वॉयफ्रेंड से काम कहां चलता है? इस तरह का शौक पालेगी तो ऊंचनीच होगी ही' - फिल्म में एक पुलिस अधिकारी द्वारा बोला गया यह डायलॉग समाज के उस वर्ग की संकुचित और कुंठित सोच को बताता है, जो महिलाओं की आजादी और प्रगति के विरुद्ध है।

पुलिस और अपराधी के बीच रस्साकशी का खेल कहानी के साथ बांधकर रखता है, लेकिन स्क्रीनप्ले में कुछ कमजोर कड़ियां हैं। वर्तमान में जब लड़कियों से जुड़े अपराध की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं, ऐसे में लड़की का आंख मूंदकर अनजान शख्स पर यकीन कर लेना और उसके साथ चल देना हजम नहीं होता। इसी तरह बच्चे के बाथरूम से गायब होने के दृश्य को सिनेमाई लिबर्टी के तहत लिया जा सकता है। सनी और शिवानी के बीच सुनसान रास्ते में मुलाकात का सीन सपाट तरीके से आता है। लेखक को पुलिस की कार्यप्रणाली में गहराई से उतरने की आवश्यकता थी।

फिल्म का दारोमदार पूरी तरह रानी मुखर्जी के कंधों पर है। रानी कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। एक तरफ दिलेर पुलिस अधिकारी और दूसरी ओर भावनात्मक इंसान के तौर पर उन्होंने किरदार में संतुलन कायम रखा है। उनकी निजी जिंदगी में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं दिखी है। उनका किरदार महिला कर्मचारियों के साथ कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव, असमानता और मानसिकता को बीच-बीच में उठाता रहता है। फिल्म महिलाओं को बराबरी का दर्जा और सम्मान देने की वकालत करती है। मूल फिल्म की तरह इस बार भी रानी को खलनायक से अकेले भिड़ने का मौका मिला है। 'मर्दानी' में खलनायक के रूप में ताहिर राज भसीन को पुख्ता पहचान मिली। 'मर्दानी 2' में सनी के किरदार में विशाल जेठवा अपनी अदायगी से ध्यान खींचते हैं।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

एडल्ट कॉमेडी फिल्म करने में अक्षय खन्ना को कोई दिक्कत नहीं

कई कलाकार प्रयोग करते रहने में यकीन रखते हैं। अक्षय खन्ना भी उन्हीं कलाकारों में हैं। इस वर्ष अक्षय की दो फिल्में रिलीज हुई थीं- 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' और 'सेक्शन 375'। दोनों ही फिल्मों में अक्षय का किरदार उनके पिछली फिल्मों में निभाए किरदारों से काफी अलग रहा है। अगले वर्ष अक्षय की फिल्म 'सब कुशल मंगल है' रिलीज होगी। लंबे समय बाद अक्षय कॉमेडी करते नजर आएंगे। 'हंगामा', 'हलचल', 'नो प्रॉब्लम' जैसी फिल्मों में अब तक अक्षय साफ-सुथरी कॉमेडी ही करते आए हैं। उन्होंने एक भी एडल्ट कॉमेडी फिल्म नहीं की है। इसकी वजह बताते हुए अक्षय कहते हैं, 'मैंने एडल्ट और डबल मीनिंग वाली फिल्में इसलिए नहीं की हैं, क्योंकि मुझे कभी उस जॉनर की फिल्में ऑफर ही नहीं हुई हैं। मुझे इसकी वजह नहीं पता कि क्यों यह फिल्में ऑफर नहीं की गईं।' हर तरह की फिल्मों में काम करने की इच्छा रखने वाले अक्षय का मानना है कि इस तरह की कॉमेडी फिल्मों को करने में कोई बुराई नहीं है। एडल्ट कॉमेडी प्रसिद्ध जॉनर है और उसका अलग दर्शक वर्ग है। अक्षय का कहना है कि अगर उन्हें इस तरह की फिल्में ऑफर होती हैं, तो हो सकता है कि वह उस मिजाज की फिल्म कर लें।

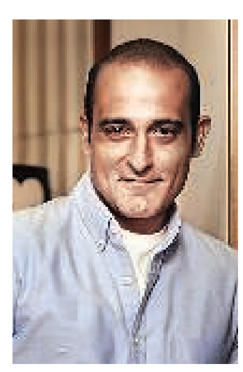

भंसाली भी बनाएंगे बालाकोट हमले पर फिल्म

देश को गौरवान्वित कराने वाली घटनाओं पर फिल्म बनाने में फिल्ममेकर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी साल जनवरी में भारतीय सेना द्वारा 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' को काफी पसंद किया गया था। इस कड़ी में 'पद्मावत', 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्मकार संजय लीला भंसाली का नाम भी जुड़ गया है। भूषण कुमार, महावीर जैन और प्रज्ञा कपूर के साथ मिलकर वह बालाकोट हवाई हमले पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। टी-सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की

जानकारी साझा की। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिषेक कपूर करेंगे। अभिषेक द्वारा निर्देशित फिल्म 'रॉक ऑन' को साल 2009 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए भूषण कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'धैर्य, दृढ़ संकल्प और वीरता की एक कहानी। हमारे देश के बहादुर नौजवानों को समर्पित 2019 बालाकोट एयरस्ट्राइक की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है।' इसी साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में 12 दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया था। गुलाम कश्मीर के बालाकोट इलाके पर किए गए इस हवाई हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। इस हमले के बाद से ही कई फिल्मकारों ने इस घटना पर फिल्म बनाने के लिए उत्सुकता दिखाई थी। अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी इस हमले पर आधारित फिल्म 'बालाकोट द ट्रू स्टोरी' बनाने की घोषणा कर चुके हैं।

तैमूर के साथ सख्ती से पेश आने का काम सैफ को सौंपा : करीना

आगामी 20 दिसंबर को करीना और सैफ अली खान के बेटे तैमूर तीन साल के हो जाएंगे। वह सेलिब्रिटी स्टार किड के तौर पर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। करीना उन्हें शूटिंग के दौरान फिल्मों के सेट पर भी ले जाती हैं। करीना ने बताया कि वह और सैफ तैमूर के साथ वक्त बिताने के लिए, अपना काम समय पर खत्म करने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक, सैफ कभी उनसे काम के बारे में नहीं पूछते, वह चाहते हैं कि तैमूर को अपने मां-बाप के साथ पर्याप्त समय मिले। तैमूर को समय देने के लिए करीना हर काम टाइम टेबल के अनुसार करती हैं। यही वजह है कि वह आठ घंटे की शूटिंग करने को प्राथमिकता देती हैं। करीना के मुताबिक बड़े होने के साथ तैमूर की शरारतें भी बढ़ रही हैं। वह कहती हैं, 'मैं और सैफ तैमूर को डराने की कोशिश करते हैं, पर वह किसी से नहीं डरता। उसे डांटने के बाद मुझे तकलीफ होती है, इसलिए तैमूर के साथ सख्ती से पेश आने का काम मैंने सैफ को दिया है। वह तीन बच्चों के पिता हैं। उनके पास पैरेंटिंग का मुझसे बेहतर अनुभव है।' सैफ के अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह से बेटी सारा और बेटा इब्राहीम हैं। सारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। करीना इन दिनों अपनी फिल्म 'गुड न्यूज' के प्रमोशन में व्यस्त हैं।

आमिर को पसंद आया 'लाल सिंह चड्ढा' का संगीत

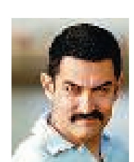

आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के संगीत के लिए संगीत निर्देशक प्रीतम व लेखक अमिताभ भट्टाचार्य कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आमिर फिल्म से जुड़ी हर छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान दे रहे हैं। खबर है कि उन्होंने खुद फिल्म के संगीत को सुना और उन्हें यह पसंद आया। हाल ही में आमिर का फोटो वायरल हो रहा था, जिसमें वह अपने किरदार लाल सिंह चड्ढा के लुक में नजर आ रहे थे। फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी।

अजय ने खत्म किया 'मैदान' का तीसरा शूटिंग शेड्यूल

एक्टर अजय देवगन ने अमित रवींद्रनाथ शर्मा की फिल्म 'मैदान' की शूटिंग का तीसरा शेड्यूल कोलकाता में पूरा कर लिया है। यह फिल्म भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम इतिहास पर बन रही है। इसमें अजय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। सैयद अब्दुल रहीम फुटबॉल कोच थे, साथ ही राष्ट्रीय टीम के मैनेजर भी रहे। उन्हें मॉडर्न इंडियन फुटबॉल का जनक भी कहा जाता है।

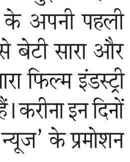

अध्ययन

तंत्रिका के ऐसे सर्किट की पहचान की है, जो बार-बार भोजन की तलब पैदा करता है, इनके नियंत्रण के लिए के लिए प्रभावी दवाएं तैयार करने की उम्मीद बढ़ गई है

वैज्ञानिकों ने ज्यादा भूख से बचाने का खोजा रास्ता

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में विभिन्न तंत्रिकाओं (नर्व) के ऐसे सर्किट की पहचान की है, जो व्यक्ति में बार-बार खाने की तलब पैदा करता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ लोग बिना सोचे किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यही स्वभाव जरूरत से ज्यादा या बार-बार खाने और मोटापे का कारण बनता है। इसके कारण नशे या जुए की लत का भी खतरा रहता है। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग की तंत्रिकाओं के उस सर्किट को पहचानने में सफलता पाई है, जो इसका कारण बनता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, हार्मोन के स्राव से लेकर शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने तक में अहम भूमिका निभाने वाले दिमाग के महत्वपूर्ण हिस्से हाइपोथेलेमस में कुछ कोशिकाएं बिना विचार किए प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करती हैं। शोध के नतीजों से ऐसी दवा ईजाद करने की उम्मीद बनी है, जिससे इस स्वभाव को नियंत्रित करना संभव हो सकता है।

अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन के परिणाम वैज्ञानिकों को ऐसी दवाएं विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे, जो बिना सोच-समझे

प्रतीकात्मक

प्रतिक्रिया देने के स्वभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस शोध से भविष्य में डॉक्टरों को ओवर ईटिंग यानी ज्यादा भोजन करने की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद मिलेगी। यूजीए कॉलेज ऑफ फैमिली एंड कंज्यूमर साइंसेज की प्रमुख एमिली नोबल का कहना है, हम विशेष तरीकों से उस सर्किट को एक्टिवेट कर अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने चूहे के मॉडल का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क की उन कोशिकाओं पर ध्यान दिया जो मेलनिन कंसंट्रेटिंग हॉर्मोन (एमसीएच) पैदा करती है।

एआइ करेगी मस्तिष्क की गंभीर चोटों का इलाज

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) आधारित एक नई प्रणाली विकसित की है, जिससे मस्तिष्क की घातक चोट का पता लगाया जा सकता है। इससे डॉक्टरों को टीबीआइ यानी ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी के रोगियों का समय रहते उपचार करने में मदद मिलेगी। टीबीआइ मृत्यु का एक प्रमुख वैश्विक कारण माना जाता है। फिनलैंड की हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, 'टीबीआइ के मरीज अक्सर बेहोशी में रहते हैं, जिससे डॉक्टरों के लिए इलाज के दौरान उनकी स्थिति का सही आकलन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है।' इस समस्या से निपटने के लिए शोधकर्ताओं ने एआइ आधारित एल्गोरिदम विकसित की है, जो मरीजों की ब्रेन इंजरी का अनुमान लगाता है और उनकी स्थिति के बारे में डाटा एकत्र करता है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है।